संपादकीय

महंगाई की फ़िक्र

ऐसे वक्त में जब केंद्रीय बैंक खुदरा मुद्रास्फीति को काबू पाने के मिशन में कामयाबी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा था, प्रतिकूल मौसमी हालात तथा बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों ने चिंता बढ़ायी है। यही वजह है कि निर्धारित चार फीसदी तक मुद्रास्फीति नियंत्रण के लक्ष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हुई है। दरअसल, बीते माह में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 4.9 फीसदी रहने पर केंद्रीय बैंक समेत आर्थिक विशेषज्ञ उत्साहित थे कि अब चार फीसदी के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। दरअसल, इसी मकसद से केंद्रीय बैंक ने अप्रैल 2023 के बाद से रेपो दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। केंद्रीय बैंक को आशंका थी कि रेपो दरों में बदलाव से महंगाई बढ़ सकती है। ऐसे में आरबीआई मुद्रा स्फीति की मौजूदा स्थिति को लेकर आशावान है। लेकिन साथ ही चिंतित है कि मौसम के मिजाज में लगातार आ रहे बदलाव तथा दो साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध व हालिया गाजा संकट से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ सकती है। जिसका असर भारत पर पड़ना लाजिमी है। इन्हीं आशंकाओं के चलते केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति को नहीं बदला है। वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पैनी निगाह रखने वाली सीएमआईई की रिपोर्ट में विश्वास जताया गया है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक खुदरा मुद्रास्फीति पांच साल के न्यूनतम स्तर तक पहुंच सकती है। लेकिन मौसमी अस्थिरता इस मार्ग में बाधक बन सकती है। दरअसल, वैश्विक मौसम संगठन के संकेत हैं कि विपरीत मौसमी स्थितियां हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। जिसका सीधा असर खाद्यान्न महंगाई पर पड़ सकता है। हालांकि, भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर के फिलहाल सात फीसदी रहने के अनुमान तमाम देशी-विदेशी आर्थिक संगठन लगा रहे हैं, लेकिन अचानक पैदा हुई प्रतिकूल परिस्थितियों के बाबत भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जरूरी है कि महंगाई पर नियंत्रण के प्रयासों के प्रति हम गंभीर रहें। जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी हमारी युवा आबादी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

बहरहाल, हमें यह स्वीकार करना होगा कि जलवायु परिवर्तन के असर पूरी दुनिया को गहरे तक प्रभावित करने लगा है। खासकर कृषि क्षेत्र के प्रभावित होने से महंगाई बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। अतिवृष्टि-अनावृष्टि और अचानक आने वाली बाढ़ दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। जिससे सारी दुनिया में खाद्यान्नों की कीमतों में तेजी आ रही है। हमने पिछले दिनों भारत में भी देखा कि जब गेहूं की फसल तैयार होकर खलिहानों तथा मंडियों तक पहुंचने लगी तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई बारिश ने काफी नुकसान किया। निश्चित रूप से गोदाम पहुंचने से पहले अनाज का भीग जाना किसान के लिये संकट का सबब बन जाता है। यह घटनाक्रम अब हर साल का हिस्सा है। हजारों टन अनाज बेमौसमी बारिश की भेंट चढ़ जाता है। जिससे अनाजों, फलों व सब्जियों की फसल खराब होने से खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था न होने के कारण बिचौलिये जमाखोरी के जरिये वस्तुओं के दामों में कृत्रिम उछाल पैदा कर देते हैं। जो कालांतर खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ने का कारण बन जाता है। जिसका सीधा असर आम आदमी की थाली पर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर रूस-यूक्रेन युद्ध, हालिया गाजा संकट एवं समुद्री जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमलों ने भी कच्चे तेल के दामों में तेजी पैदा की है। इस तरह पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में उछाल से ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। जो कालांतर महंगाई की एक वजह भी बनता है। भारत जैसे देश के लिये विशेष रूप से जहां कच्चे तेल का अधिकांश हिस्सा विदेश से आयात होता है। कुल मिलाकर युद्ध व भू-राजनीतिक तनाव भी महंगाई बढ़ने का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। इसी चिंता के चलते ही केंद्रीय बैंक को कहना पड़ा कि हम खुदरा मुद्रास्फीति को नियंत्रित तो कर सकते हैं बशर्ते अन्य बातें सामान्य रहें। यानी मौसमी उतार-चढ़ाव व वैश्विक अस्थिरता का असर हम पर कम हो। हालांकि, मौसम विभाग इस बार सामान्य मानसून की भविष्यवाणी कर रहा है, इसके बावजूद सिंचाई के वैकल्पिक साधनों को बढ़ाते रहना होगा।

वैश्विक साझेदारी से पर्यावरण संकट का समाधान

"आधुनिक विज्ञान ने जटिल प्राकृतिक तंत्र को छोटी-छोटी श्रेणियों में बांटकर, हरेक के लिए विशेषज्ञता आधारित विज्ञान का विकास करना शुरू किया ताकि छोटी से छोटी बारीकी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो। किंतु यह तरीका अंधों द्वारा हाथी की व्याख्या करने वाली कहानी जैसा है। समग्रता के परिपेक्ष में कोई नहीं देख रहा। आधुनिक दवा खोजकर्ताओं ने दवाएं और शरीर के विभिन्न अंगों को दुरुस्त करने के लिए सर्जरी के बकमाल तरीके खोजे हैं।"

'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' (तिलोर) नामक पक्षी का वजूद बचाए रखने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से मुक्त रहने को मानव के मूलभूत अधिकार जितना दर्जा दिया गया है। इस निर्णय ने नीति-निर्माताओं एवं अक्षय ऊर्जा तंत्र विकसित करने वाले निर्माताओं को विस्मित किया है। उनका कहना है कि न्यायाधीश वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सलाह को दरकिनार कर रहे हैं और इससे जलवायु परिवर्तन को दुरुस्त करने हेतु बनाए जाने वाले तंत्र की स्थापना में देरी होगी। अदालत ने माना है कि जलवायु परिवर्तन अनचाहे क्षेत्रों में भी न्यायशास्त्र की दखल करवा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से वजूद पर बने संकट को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और बेढंगे विज्ञान के मौजूदा आदर्शों द्वारा समझा और सुलझाया नहीं जा सकता।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, प्राकृतिक संपदा इसके मालिक की पूंजी है। राजा और जमींदार भूमि मालिक होते हैं और उनके इलाके की तमाम जलीय, वनीय और मत्स्य संपदा, पशु-पक्षी तक उनकी संपत्ति है। उनकी भूमि पर रह रहे और काम करने वाले नौकर या दासों द्वारा हुई उत्पादकता या पैदावार के मालिक भी वही हैं। जो मालिक अपनी मालिकाना भूमि पर घर बनाकर रहते हैं और लोगों से मेल-जोल रखते हैं, जहां उनके नौकर-चाकर पसीना बहाते हैं, वे अपनी निगरानी में वनों और फसलों को फलते-फूलते स्वयं देख सकते हैं। परंतु जो जमींदार अन्यत्र रहते हैं उन्हें कोई परवाह नहीं होती। उन्हें तो केवल मुनाफे से मतलब है फिर चाहे भूमि सूखाग्रस्त हो या बाढ़ग्रस्त, न ही नौकरों की मुश्किलों से कोई सरोकार होता है।

वस्तु मंडियों का उद्‌भव, जहां पर लाए गए पशु, खेतों में उगी फसलें, लकड़ी और खनिज इत्यादि को, व्यापारियों द्वारा तय भावों पर, मुद्रा के लेन-देन से, खरीदा-बेचा जाता है, यह ढंग प्राकृतिक पूंजी को वित्तीय पूंजी में तब्दील करता है। वित्तीय बाजारों ने पूंजीपतियों का नया वर्ग तैयार कर दिया, जिन्हें जमीनी हकीकतों की जानकारी देहात में न बसने वाले जमींदारों से भी कम होती है। वे दुनिया की स्थिति का आकलन तालिकाओं (चार्ट) या डाटा से करते हैं कि किस वस्तु या शेयर का भाव मंडियों और स्टॉक बाजारों में ऊपर चढ़ा या गिरा। जब देहात से निकलकर कोई बंदा कारखानों में बतौर मजदूर काम करने लगता है तो वहां उसका मेहनताना काम के घंटों और इस दौरान दिखाई कारगुजारी के मुताबिक मिलता है। कारखाने के मालिक के लिए उसका कौशल और श्रम भी एक खरीदने लायक वस्तु बन है।

अर्थ-व्यवस्था और न्याय-शास्त्र में जायदाद पर हक आदिकाल से एक अधिकार है। मानवाधिकार को मान्यता तो कहीं बहुत बाद में जाकर मिली, जिसकी प्राप्ति राजनीतिक आंदोलन-अधिकांशतः हिंसा के बाद हुई। उद्देश्य था दासता खत्म करना, उचित मजदूरी पाना और काम करने के लिए सुरक्षित माहौल बनवाना। 'गिग वर्क' व्यवस्था श्रम को वस्तु में बदलने का 21वीं सदी का एक तरीका है, जिसमें केवल जरूरत पड़ने पर कामगार की सेवाएं लेना, जो काम हुआ उसी का मेहनताना देना और अन्य किसी किस्म की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, यह व्यवस्था मालिकान को तो खूब रास आती है लेकिन आम लोगों के लिए खराब है।

गारेट हार्डिन की 'ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स' नामक थ्योरी निजीकरण की विचारधारा को रेखांकित करती है। इस विचार या वाद में, जो सार्वजनिक संपत्ति साझी होती है उसकी देखभाल की जिम्मेवारी कोई नहीं उठाता। अतएव, सार्वजनिक और साझी संपत्ति को निजी हाथों को सौंप दिया जाए क्योंकि वे अधिक मुनाफा बनाने की चाहना से प्रेरित होकर अपने-अपने हिस्से का प्रबंधन अच्छी तरह करेंगे। वैश्विक पर्यावरण, जो कि सबका साझा है, उसको पहुंचा नुकसान विश्व-स्तरीय उभयनिष्ठ संकट बन गया है। इसका हल संपत्ति का आगे निजीकरण करके नहीं निकल सकता। 'वैश्विक साझेदारी का वायदा' ध्येय की प्राप्ति को प्रबंधन के नए सिद्धांतों की जरूरत है।

फ्रांसिस बैकॉन ने 17वीं सदी में यूरोपियन ज्ञानोदय के जन्म पर गर्व करते हुए कहा था कि अब विज्ञान मनुष्य को बेलगाम प्रकृति पर नियंत्रण पाने की ताकत प्रदान करेगा। भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव-विज्ञान में हुई नवीनतम खोजों ने मानव के पदार्थवादी फायदे हेतु पृथ्वी की संपदा का दोहन करने के ताकतवर औजार प्रदान किए जिसके चलते तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्रों के नागरिकों का उच्च जीवन स्तर बाकियों के लिए ईर्ष्या बना। लेकिन अतिशयी दोहन ने पृथ्वी की सेहत को नुकसान पहुंचाया है। तकनीकी श्रेष्ठता के दर्प से चूर मानव ने हमारे ग्रह के पर्यावरण संतुलन और लोगों के आपसी सौहार्द्र की सततता को नष्ट कर डाला।

आधुनिक विज्ञान ने जटिल प्राकृतिक तंत्र को छोटी-छोटी श्रेणियों में बांटकर, हरेक के लिए विशेषज्ञता आधारित विज्ञान का विकास करना शुरू किया ताकि छोटी से छोटी बारीकी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो। किंतु यह तरीका अंधों द्वारा हाथी की व्याख्या करने वाली कहानी जैसा है। समग्रता के परिपेक्ष में कोई नहीं देख रहा। आधुनिक दवा खोजकर्ताओं ने दवाएं और शरीर के विभिन्न अंगों को दुरुस्त करने के लिए सर्जरी के बकमाल तरीके खोजे हैं। किंतु उपचार विधि में अंतर्निहित दुष्परिणामों से प्रभावित हुए अन्य अंगों से रोगी की हालत और बिगड़ भी जाती है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए, पूरे शारीरिक तंत्र और मानसिकता की समझ रखने वाले चिकित्सक होना लाजिमी है।

पिछली सदी में अर्थतंत्र का सरोकार बाकी सामाजिक विज्ञान से टूट गया, हर कोई अपनी-अपनी विशेषज्ञता वाले कूपों में समा गया। सकल घरेलू उत्पादक बढ़ाने के वास्ते अर्थशास्त्री प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने लगे। अर्थशास्त्रियों को यह तो पता है कि आर्थिकी का आकार कैसे बढ़े किंतु वृद्धि युक्त अर्थव्यवस्था में सबका हिस्सा कैसे सुधरे और प्राकृतिक स्रोतों की सततता बरकरार रहे, यह इल्म नहीं है।

आधुनिक वैज्ञानिक रुख को उन शक्तियों को समझ नहीं है जो परस्पर रूप से पैदा होती हैं और जिनके बीच कारकों और प्रभावों को लेकर चक्रीय नाता है। वे अर्थशास्त्री जो मानव विकास सूचकांक में सुधार लाने के हेतु स्रोतों की वृद्धि करने से पहले उच्च सकल घरेलू उत्पाद बनाने की वकालत करते हैं और जिनके लिए प्राकृतिक स्रोतों की सततता कायम रखना बाद की बात है, वे यह देखने में असफल हैं कि आर्थिक वृद्धि के लिए मानव विकास एवं प्राकृतिक स्रोत की सततता सदा से पूर्व-शर्त और नींव रही है। मिट्टी, जल तंत्र और वनस्पति, पशु, पक्षियों एवं कीटों की विभिन्न प्रजातियों सहित मनुष्य भी प्रकृति के जटिल ढांचे का एक हिस्सा मात्र है। सततता पूर्ण विकास के लिए सबकी भलाई संरक्षित होना जरूरी है। संरक्षणवादी जो व्यवस्था के केवल एक हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, वे या तो अधिक हरियाली की वकालत करते हैं या फिर किसी एक प्रजाति को बचाने की जैसे कि बाघ।

आज का इतिहास

- मैरी लैंड अमेरिकी संविधान की पुष्टि करने वाला 1788 में सातवां राज्य बना।
- यूरोपीय देश नीदरलैंड की संसद ने 1829 में नये प्रेस कानून पारित किये।
- जार्ज बी. वेशन 1847 में अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यायालय में जाने वाले पहले अश्वेत नागरिक बने।
- इंग्लैंड में क्लोड ग्राहम व्हाइट नाम के पायलट ने 1910 में पहली बार रात में विमान उड़ाया।
- अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया के एस्सेल्स इलाके में 1914 में एक कोयला खदान हादसे में 181 लोगों की मौत।
- बीजी तिलक ने 1916 में भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की।
- इंसानों के लिए पीत ज्वर का टीका विकसित करने की घोषणा 1932 में की गई।
- रूस की राजधानी मास्को में 1935 में अंडरग्राउंड ट्रेन 'मेट्रो' की शुरुआत।
- इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी, उनकी प्रेमिका क्लारा पेटाची और उनके कुछ सहयोगियो की 1945 में हत्या हुई थी।
- फ्रांस के आखिरी सैनिक ने 1956 में वियतनाम छोड़ स्वदेश वापसी की।
- जापान 1964 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) में शामिल हुआ।
- फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डी। गॉल ने 1969 को अपने पद से इस्तीफा दिया।
- जाम्बिया के एक विमान के गेबोन के लिबरविले में 1993 में दुर्घटनाग्रस्त होने से 30 फुटबाल खिलाड़ियों की मौत।
- दक्षिण कोरिया में 1995 में मेट्रो में हुए गैस विस्फोट में 103 की मौत।
- सन 1995 में श्रीलंका के पलाली में विमान दुर्घटना में 52 यात्रियों की मौत।
- अमेरिका वैज्ञानिक डाक्टर रिचर्ड सीड व्दारा 1999 में एक वर्ष के अन्दर मानव क्लोन बनाने की घोषणा।
- अमेरिकी बिजनेस मैन डेनिस एंथोनी 2001 में पहले स्?पेस टूरिस्?ट बन इतिहास रच दिया।
- पहला अंतरिक्ष सैलानी टेनिस टीटो 2001 में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना।
- बुकर पुरस्कार का 2002 में नया नाम फ्मैन प्राइज फार फिक्शनफ्र रखा गया।
- दुनिया भर में 2003 में कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया।
- थाबोम्बेकी ने 2004 में दक्षिण अफ़्रीका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली।
- श्रीलंका को हराकर 2007 में ऑस्ट्रेलिया चौथी बार विश्व चैंपियन बना।
- भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन ने 2008 में पीएसएलवी-सी9 के साथ छोड़कर एक नया इतिहास रचा।

जनसहयोग से ही हो काबू पाने के प्रयास

प्रतिवर्ष गर्मी की शुरुआत होते ही विभिन्न राज्यों में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। शुष्क मौसम के कारण उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों में भी जंगलों के धधकने का सिलसिला तेज है। जंगल में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के साथ ही इन पर नियंत्रण पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड में इस फायर सीजन में जंगलों में आग की करीब सौ घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 100 हेक्टेयर से भी ज्यादा वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है।

तापमान में बढ़ोतरी के चलते उत्तराखंड में गढ़वाल, कुमाऊं, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग सहित कई जनपदों के जंगल धधक रहे हैं। कई जगहों पर जंगलों में दावानल भड़कने के दो-तीन दिन बाद तक भी वन विभाग मौके पर पहुंचने में नाकाम रहा और जंगलों से उठती आग की लपटें सब कुछ राख करती चली गईं। विशेषज्ञों के मुताबिक जंगलों में दावानल से बड़े पैमाने पर वन संपदा तो नष्ट होती ही है, पर्यावरणीय क्षति के साथ-साथ लोगों को जलवायु परिवर्तन का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है।

गर्मियों में जंगलों में आग तेजी से फैलती है। जंगलों का पूरी तरह सूखा होना आग लगने के खतरे को बढ़ा देता है। कई बार जंगलों की आग जब आसपास के गांवों तक पहुंच जाती है तो स्थिति काफी भयावह हो जाती है। दो साल पहले उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग में अल्मोड़ा में छह गौशालाएं, लकड़ियों के टाल सहित कई घर जलकर राख हो गए थे और वहां हेलीकॉप्टरों की मदद से बड़ी मुश्किल से आग बुझाई जा सकी थी।

जंगलों में आग के कारण वनों के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को भारी नुकसान होता है। प्राणी सर्वेक्षण विभाग का मानना है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग के कारण जीव-जंतुओं की साढ़े चार हजार से ज्यादा प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। वनों में आग से पर्यावरण के साथ-साथ वन सम्पदा का जो नुकसान होता है, उसका खमियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ता है और ऐसा नुकसान साल-दर-साल बढ़ता जाता है। पिछले चार दशकों में भारत में पेड़-पौधों की अनेक प्रजातियों के खत्म हो जाने के अलावा पशु-पक्षियों की संख्या भी घटकर एक तिहाई रह गई है और इसके विभिन्न कारणों में से एक कारण जंगलों की आग रही है। जंगलों में आग के कारण वातावरण में जितनी भारी मात्रा में कार्बन पहुंचता है, वह कहीं ज्यादा गंभीर खतरा है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2017 से 2019 के बीच जंगलों में आग लगने की घटनाएं तीन गुना तक बढ़ गईं। साल 2016 में देशभर के जंगलों में आग लगने की 37 हजार से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई थी, जो 2018 में बढ़कर एक लाख से ऊपर निकल गईं। भारतीय वन सर्वेक्षण ने वर्ष 2004 में नासा के उपग्रह की मदद से राज्य सरकारों को जंगल में आग की घटनाओं की चेतावनी देना शुरू किया गया था। वर्ष 2017 में सेंसर तकनीक की मदद से रात में भी ऐसी घटनाओं की निगरानी शुरू की गई लेकिन तमाम तकनीकी मदद के बावजूद जंगलों में हर साल बड़े स्तर पर लगती भयानक आग जब सब कुछ निगलने पर आमादा दिखाई पड़ती है और वन विभाग बेबस नजर आता है, तो चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। चिंता का विषय है कि जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर सरकारों और प्रशासन के भीतर संजीदगी का अभाव दिखता है। एक दशक में हम वनों की आग से 22 हजार हेक्टेयर से भी ज्यादा जंगल खो चुके हैं। वन सर्वेक्षण संस्था की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में 2004 से 2017 के बीच वनों में आग की 3.4 लाख घटनाएं हुई थी।

जंगलों में आग कई बार प्राकृतिक तरीके से नहीं लगती बल्कि पशु तस्कर भी लगा देते हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में लोग महुआ निकालने के लिए झाड़ियों में आग लगाते हैं। वहीं वनों में प्राकृतिक तरीके से आग लगने के प्रमुख कारण मौसम में बदलाव, सूखा व भूमि कटाव हैं। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में चीड़ के वृक्ष बहुतायत में होते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ इसे वनों का कुप्रबंधन ही मानते हैं कि देश का करीब 17 फीसदी वन क्षेत्र चीड़ से ही भरा पड़ा है। चीड़ के वृक्षों का बड़ा नुकसान है कि एक तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, साथ ही ये अपने क्षेत्र में चौड़ी पत्तियों वाले अन्य वृक्षों को पनपने नहीं देते। चूंकि चीड़ के वनों में नमी नहीं होती, इसलिए जरा-सी चिंगारी भी ऐसे वनों को राख कर देती है। कभी चीड़ के सूखे पत्तों को पर्वतीय क्षेत्रों के लोग पशुओं के बिछौने के रूप में इस्तेमाल किया करते थे किन्तु रोजगार की तलाश में पहाड़ों से पलायन के चलते लोगों को अब इन पत्तियों की जरूरत ही नहीं पड़ती और जंगलों में इन सूखी पत्तियों का ढेर इकट्ठा होता रहता है, जो थोड़ी गर्मी बढ़ते ही मामूली चिंगारी से ही सुलग उठते हैं व देखते ही देखते पूरा जंगल आग के हवाले हो जाता है। जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाने में विफलता का बड़ा कारण यह भी कि वन क्षेत्रों में वनवासी अब वन संरक्षण के प्रति उदासीन हो चले हैं। वजह काफी हद तक नई वन नीतियां भी हैं। जरूरी है कि वनों के आसपास रहने वालों और उनके गांवों तक जन-जागरूकता मुहिम चलाकर वनों से उनका रिश्ता कायम करने के प्रयास किए जाएं ताकि वे वनों को अपने साथी समझें और उनके संरक्षण के लिए साथ खड़े नजर आएं।

जाति जनगणना पर राहुल का जोर

शिव सेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने अपने विश्वास पर भरोसा करते हुए दावा किया है कि इंडिया गंठबंधन 543 सदस्यीय लोकसभा में 300 से अधिक सीटें जीतेगा। महाराष्ट्र के बुलढाणा में शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार नरेंद्र खेडेकर के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी को 'नकली' कहने के लिए लोग जल्द ही भाजपा को सबक सिखाएंगे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में भारत के दलितों, ओबीसी, गरीबों की स्थिति का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग करके ओबीसी, एससी और एसटी के प्रश्न को राष्ट्रीय चर्चा की प्राथमिकता पर रखा है। राहुल गांधी ने कहा कि समाज का एक्सरे (हाशिए पर मौजूद वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रीय गणना) अब मेरे जीवन का मिशन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनिंदा 22 लोगों को दिए गए 16 लाख करोड़ में से देश के 90 प्रतिशत लोगों को थोड़ी-थोड़ी रकम वापस करने का वादा किया गया है। दिल्ली के जवाहर भवन में सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमने यह नहीं कहा कि हम पूरे 16 लाख करोड़ रुपए लौटाएंगे। हमने गणना की है और कहा है कि केवल थोड़ी सी रकम वापस की जाएगी।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना के बीच, भगवा गलियारे इन व्यापक अटकलों से भरे हुए हैं कि वरुण गांधी, जिन्हें भाजपा ने उनके पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से टिकट देने से इनकार कर दिया था, को रायबरेली से उतारा जा सकता है। वरुण गांधी के करीबी सूत्रों ने भी खुलासा किया है कि शीर्ष भाजपा नेतृत्व अब रायबरेली में ÷गांधी बनाम गांधी÷ लड़ाई बनाने पर विचार कर रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट पर अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ संभावित चुनावी मुकाबले से इनकार कर दिया है। इस बीच, यह याद किया जा सकता है कि हाल ही में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रायबरेली कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था कि पार्टी को ÷प्रियंका या गांधी परिवार के किसी अन्य सदस्य÷ को रायबरेली से मैदान में उतारना चाहिए। प्रियंका लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही हैं और अब अगर पार्टी उन्हें अनुमति देती है तो वह रायबरेली सीट से लड़ने के लिए तैयार हैं और इसके साथ ही वह नेहरू-गांधी परिवार से रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली तीसरी पीढ़ी होंगी।

शिव सेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने अपने विश्वास पर भरोसा करते हुए दावा किया है कि इंडिया गंठबंधन 543 सदस्यीय लोकसभा में 300 से अधिक सीटें जीतेगा। महाराष्ट्र के बुलढाणा में शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार नरेंद्र खेडेकर के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी को 'नकली' कहने के लिए लोग जल्द ही भाजपा को सबक सिखाएंगे। आप मेरी पार्टी को 'नकली' शिवसेना कहते हैं, लेकिन यही सेना आपको अपनी असली ताकत दिखाएगी। उन्होंने हमला जारी रखते हुए कहा, क्या मेरी शिव सेना आपकी डिग्री की तरह है जिसे आप नकली कहते हैं? लोग आपको आपकी जगह दिखाएंगे। गौरतलब है कि मोदी ने ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को ÷नकली÷ शिवसेना कहा है।

मौजूदा आम चुनावों के बीच अपने प्रतिष्ठित लोगो का रंग लाल से भगवा करने के लिए प्रसार भारती के पूर्व सीईओ और तृणमूल कांग्रेस सांसद, जवाहर सरकार ने स्वायत्त राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक, दूरदर्शन की आलोचना की है। हालांकि अपने कदम का बचाव करते हुए दूरदर्शन (डीडी) ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि इसका प्रारंभिक लोगो, जो 1959 में लांच किया गया था, वह भी भगवा रंग का था। दूरदर्शन के इस कदम को लेकर जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर सात चरणों के लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने और जीतने के लिए राष्ट्रीय संपत्तियों और प्रतीक चिह्नों का रंग भगवा करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया, जब लोग चुनावी मोड में हैं तो भारत का चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के इस भद्दे, भगवा समर्थक उल्लंघन की अनुमति कैसे दे सकता है? वहीं, 2012 से 2014 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी लोगो के रंग को लेकर आरोप लगाया कि इसे बदलना सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने की सरकार की कोशिश है।

क्या कारगर रहेगी अखिलेश की रणनीति?

सपा के पारंपरिक यादव-मुस्लिम आधार से दूर जाने की अखिलेश यादव की कोशिश यूपी के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रही है क्योंकि यह ओबीसी मतदाता समूहों पर भाजपा के आधिपत्य को सीधी चुनौती है। ये समूह 2014 के बाद से यूपी में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा की लगातार प्रचंड जीत की रीढ़ रहे हैं।

अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अपनी पुरानी रणनीति के विपरीत इस बार कम यादवों और मुसलमानों को मैदान में उतारा है और ओबीसी और दलित उम्मीदवारों को अधिक टिकट दिए हैं। जिन 62 सीटों पर वह इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ रही है, उनमें से सपा ने केवल 6 यादव और 4 मुसलमानों को चुना है। दूसरी ओर, इसने गैर-यादव ओबीसी समूहों से 25 और उच्च जातियों से 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वह निश्चित रूप से 14 आरक्षित सीटों से दलितों को मैदान में उतारेगी। लेकिन अपने मतदाता आधार का विस्तार करने के एक प्रयोग के तहत, सामान्य वर्ग की 2 सीटों पर दलित उम्मीदवारों को नामांकित करने की संभावना है।

सपा के पारंपरिक यादव-मुस्लिम आधार से दूर जाने की अखिलेश यादव की कोशिश यूपी के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रही है क्योंकि यह ओबीसी मतदाता समूहों पर भाजपा के आधिपत्य को सीधी चुनौती है। ये समूह 2014 के बाद से यूपी में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा की लगातार प्रचंड जीत की रीढ़ रहे हैं। भाजपा उम्मीदवारों की सूची का जाति विभाजन दिलचस्प है क्योंकि यह सपा सूची के ओबीसी वर्चस्व के बिल्कुल विपरीत है। बीजेपी ने 29 ओबीसी को उम्मीदवार बनाया है लेकिन 32 टिकट ऊंची जातियों के खाते में गए हैं। ब्राह्मणों और ठाकुरों का वर्चस्व ओबीसी समूहों को सशक्त बनाने में विश्वास रखने वाली पार्टी होने के उसके दावे पर संशय पैदा करता है। ऐसा लगता है कि यूपी एक दिलचस्प लड़ाई के लिए तैयार है। 2014 से भाजपा को भारी जीत दिलाने और जातिगत समीकरणों पर भारी पड़ने वाली मोदी लहर का प्रभाव अगर कम रहा तो समीकरण दिलचस्प होंगे।

कर्नाटक जैसे प्रबुद्ध दक्षिणी राज्य में यह आश्चर्य की बात है कि इसकी राजधानी बेंगलुरु ने कभी भी किसी महिला सांसद को लोकसभा में नहीं भेजा है। इस बार उम्मीद है कि ये पुरुष वर्चस्व बदल सकता है। पहली बार शहर से दो महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने बेंगलुरु दक्षिण सीट से सौम्या रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने बेंगलुरु उत्तर सीट के लिए शोभा करंदलाजे को चुना है। रेड्डी भाजपा के फायरब्रांड और मौजूदा सांसद तेजस्वी सूर्या से टक्कर लेंगी और यह एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है।

रेड्डी 2023 में बेंगलुरु दक्षिण के जयनगर विधानसभा क्षेत्र से मात्र 16 वोटों से हार गई थी और एक मजबूत उम्मीदवार हैं। निस्संदेह, सूर्या एक ओजस्वी वक्ता और प्रखर हिंदुत्ववादी हैं।करंदलाजे केंद्रीय मंत्री हैं और बेंगलुरु में एक जानी-मानी हस्ती हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के राजीव गौड़ा हैं। हालांकि बेंगलुरु उत्तर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2004 में यह भाजपा के हाथ में चला गया और तब से पार्टी के पास है। राजनीतिक हलकों का कहना है कि दोनों चुनावों का नतीजा कर्नाटक की राजधानी में मोदी लहर की ताकत पर निर्भर करता है।

पूर्वोत्तर दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार की प्रसिद्ध भाषण कला उनकी उम्मीदवारी के प्रति उनकी पार्टी की खुली उदासीनता के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। ऐसा लगता है कि कुमार को स्थानीय दिल्ली कांग्रेस नेताओं, विशेषकर दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली से बहुत कम मदद मिल रही है, और प्रचार के लिए उन्हें अद्वितीय लालू यादव शैली में दिए गए अपने उग्र भाषणों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लवली ने पूर्वोत्तर दिल्ली से कांग्रेस के टिकट के लिए कड़ी मेहनत की थी लेकिन वह अपने प्रयासों में असफल रहे। जाहिर तौर पर, क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिहारी प्रवासी आबादी के कारण पार्टी ने कुमार पर फैसला किया। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता बिहार के बेगुसराय के रहने वाले हैं।

दरअसल, लड़ाई यूपी प्रवासी बनाम बिहारी प्रवासी में बदल सकती है क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी भी बिहार से हैं। तिवारी लोकप्रिय भोजपुरी फिल्म अभिनेता हैं और एकमात्र मौजूदा भाजपा सांसद हैं जिन्हें चुनाव में दोहराया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कुमार को दिल्ली

संपादकीय

लाचारी बेबसी वेचारगी से जुझते लोगों की मजबूरियां बेहिसाब होती है!

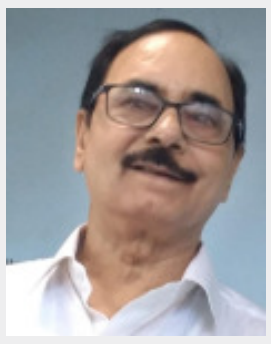

लाचारी, बेबसी और मजबूरी से जिसका पाला पड़ जाता है, उसे अपने हक हकुक से भी बेदखल होना पड़ता है। चाह कर भी सही और सच्चाई उससे दूर हो जाता है, आदमी। वर्तमान काल में यह सब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत में चरितार्थ हो जाता है और सामर्थ्यबान लोग कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी गलत सलत बात को भी सही सिद्ध करने में सफल हो जाते है। बेबसी लाचारी न जाने आदमी को आदमियतों से दूर कर देता है, आदमियत ना जाने किस कोने में जा बैठती है और आदमी से आदमी को न जाने, क्या से क्या करा देती है। आज के आधुनिक युग में मजबूरियों के बस में बंध कर रह गया है, आदमी।इस आधुनिक काल में लोग जिंसों और मिहनत की कीमत नहीं लेते, मजबूरियों की कीमत लगाते हैं। जरूरत के हिसाब से मौके का फायदा उठाते, दाम लगता है आज। जिस चीज का दाम दस रुपये होते हैं, मजबूरी में उसके दाम ऊंचा यानी दस का सौ रुपये हुआ बताया जा सकता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना मजबूर हैं, मजबूरियां इस कदर सितम ढाने लगी है कि लोग अब वेउवहार भूल चुके हैं।पैसे पर हर चीज चल रही है, जान हो या फिर जिंदगी सब कुछ पैसे पर टीक गया है। पैसा के चलते लोग क्या से क्या करने लग गए हैं।ईमानदारी को ताक पर रखकसर सिर्फ पैसा कमाने की चाहत रखने वाले लोग दुनिया में भर गये है। दुनिया पैसे पर ही चलती है, यह तो सभी जानते हैं।यह सब की बात है, आप हो या हम। पर जो कोई ईमानदार होता है, उसे यह सब सालता है, लगता है कि यह सब क्या हो रहा है, यह सब आज के आधुनिक जुग में जो बदलाव आया है, उसी का नतीजा दिखता है, जो नई पीढी आई है, वह बदलाव के साथ चल रही है। बदलाव भी ऐसा कि सब कुछ भुला कर सिर्फ और सिर्फ पैसा ही पैसा कमाना। फिर उस पैसे को जिसी तिस तरह खर्च कर देना, यानी शानो शौकत में अपनी सुख-सुविधाओं में लगा देना। कमाना और खर्च कर सुख से जीने की चाहत रखना। हर तरह की जरूरतें पूरी हो।शानो शौकत बनी रहे, आज के लोगों का खास शगल बन गया है। विशेष कर युवाओं को इसका लत सा लग गया है और इसी को लत को लक्ष्य बना कर लोग जीना चाहते हैं, जी रहे हैं। इसी लक्ष्य के पीछे सभी भाग रहे हैं। लक्ष्य की प्राप्ति में चाहे जो कुछ भी करना पड़े, किसी का भी मन मान मयार्दा खत्म करना पड़े, वह तुरंत खत्म कर देते हैं। दोस्ती रिश्तेदारी समाज, परिवार सब इसी के पीछे लगे हैं, पैसा है तो सब कुछ है, वर्ना कुछ भी नहीं है। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं । लोग पैसे की चाहत में किसी की भी जान लेना आसान बात समझते हैं। जीवन दे नहीं सकते, लेकिन पैसे के लिए जीवन ले सकते हैं। तो बात कर रहा था कि मजबूरियां अगर आपके सामने हैं, तो मजबूर होकर आपको वह सब कुछ करना ही पड़ेगो जो, आपकी मजबूरी का निदान है और यह मजबूरी सिर्फ खत्म हो सकती है, तो वह पैसे से ही खत्म हो सकती है।अब सवाल उठता है कि लोगों की मजबूरियों को जिस कदर भंजाया जा रहा है, वह कितना उचीत है? उसे रोकने वाला कौन है! कोई तो दिखता नहीं? सब्जी खरीदने जाइए वहां भी दस का सौ लेना दुकानदार चाहता है और आपकी मजबूरी है कि खरीदनी ही है, तो फिर खरीदिए! क्योंकि हर कोई आपसे आपके मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए तत्पर रहता है और जब जमात के जमात लोग एक ही मकसद पाल रखे हो, तो फिर आपकी मजबूरी के किसी को क्या लेना देना।आपकी मजबूरी से आप को निजात दिलाने वाला कौन हो सकता है, हर जगह चाहे वह काम करने वाला मजदूर हो, रिक्शा ठेला चलाने बाला, ड्राइवर जो चार चक्का चलाता, सभी का अपना अपना हिसाब हो गया है। काम कम करना है और अधूरा कर पैसे की? मांग यह आदत में सुमार हो गया है। यह पूरी तरह से तो पैसे पर निर्भर हो गया है। लोग कहते हैं की दूध में जितना चीनी डालोगे, उतना ही मिठ होगा। मजबूरियां वेहिसाब हैं, डॉक्टर चिकित्सा किल्नीक, स्कूल शिक्षा का केंद्र यानी, यानी हर जगह, मजबूर अगर आप है, आपकी चाहत है, यही चीज खरीदनी है, यही नाम लिखना है, यही इलाज कराना है, तो फिर अगला जो है, वह आपको अपने हिसाब से चलाएगा हजार का दस हजार भी ले सकता है।अब इस महंगाई के जमाने में, सभी लोग महंगाई का रोना रोते है। सभी कहते हैं कि जमाना बदल गया, सभी मानते हैं कि सब ऊपर वाले का किया कराया है। अपनी जवाबदेही, अपनो का सम्मान, इमानदारी, सब कुछ ताक पर रख दिया गया है।वह जमाना आ गया है, जब लोग अपने अपने हिसाब से व्यवहार भी करने लगे हैं। हर जगह पैसे का बोलबाला हो गया है। हर कोई पैसे बटोरने में लगा है, अगले के पास कितनी मजबूरी है, इसकी कोई गिनती नहीं करता, अपने पैसे गिनने में ही लगा रहता है।आज ईमानदारी, सच्चाई, सज्जनता, सब कुछ भटका सटका चला जा रहा है। मिटता चला जा रहा है। ? मजबूरियों का जाल इस कदर लोगों को अपने में समेट कर चल रहा है कि लगता है, यह जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए ही बना है, पैसे पर ही मजबूरियों का निदान होना है। पैसा हर किसी के लिए जरूरी है, पर पैसे के लिए आदमियता को भूल जाए, यह तो जरूरी नहीं दिखता? आदमीयता, ईमानदारी, सच्चाई, भी कोई चीज है, जिसे मनुष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योकि इस धरा पर अगर आए हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे काम, नेक दिल से करते रहे। जिंदगी को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आपकी नेक नियति बनी रहे। मजबूरियां को भुनाए नही, उसका गलत फायदा उठाने की आदत से बाज भी आइए, वर्ना, कभी न कभी आप भी शिकार बन ही जाएगें और गाएगें हाय मजबूरियों ने हमें मार डाला। समय और परिस्थितियां आदमी से बहुत कुछ करा देती हैं। मजबूरियों में और आदमी लाचार बेबस बनकर बस अपनी मजबूरियों के आगे अपनी खुशियों को निछावर कर देता है। वक्त का मारा हुआ आदमी मजबूरियों से घिरा होता है। वीर से वीर पुरुष, धीर गंभीर होकर भी, मजबूरियों के चलते लाचार हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी विकट स्थिति में लाने वाली मजबूरियां को क्या कहा जाए? क्यो मजबूरियों के बीच जीने को विवश होते हैं, लोग। जीवन में मजबूरियां आदमी को इस कदर परेशान करती है कि जीवन ही निरस हो जाता है। जबकि मजबूरियों को वक्त के हालात के साथ धैर्य पूर्वक सामना करने से, निश्चित रूप से उसे बदला जा सकता है, कामयावियों में। इसलिए मजबूरियों से घबराने की जरूरत नहीं, परिस्थितियों के साथ उससे देखने की जरूरत होती है और बुद्धि ज्ञान से उसे दूर हटाने की कोशिश की जानी चाहिए। जीवन को मजबूरियों के तहत नहीं बिताना चाहिए, बल्कि मजबूरियों को अपना ताकत बना कर जीवन संघर्ष के साथ जीवन को सफल और सार्थक बनाने में व्यक्ति को लगाना होता है। संस्कार और संस्कृति के साथ जीवन को बिताना होता है। परिस्थितियां आदमी को आदमी रहने नहीं देता लेकिन आदमी वह होता है जो हर परिस्थिति को समय के साथ झेलते हुए जीवन नैया को खेवता रहता है। तभी जीवन सार्थक और सफल कहलाता है।

प्रभात वर्मा

कहानी

मर्दानी

"क्या नाम है?" - "दुलारी देवी।" - "पति का नाम?" - "स्वर्गीय किसुन राय? - "वार्ड नंबर ?" - "बारह।" - "कितना खेत दहाया है?" - "दो बिगहा सात कट्ठा सरकार।" - "रसीद कटवाती है?" मुंशी जी ने चश्मे के ऊपर से उसे देखा। सफेद वस्त्र में लिपटी हुई एक दुखियारी अधेड़ स्त्री निरीह भाव से उनके सामने खड़ी थी। उसके गेहुंए रंग काले पड़ गये थे। - "झूठ बोलती है जनानी।" पीछे से कतार में खड़े चानो यादव ने अपना टांग अड़ाया, "इसके पास पाँच-सात कट्ठा जमीन बची है सर। रसीद मांगिये।" पता नहीं, चानो यादव उनसे किस जन्म का खुन्नस निकाल रहा था। विपत्ति की घड़ी में जब अपने भी मुँह फेर लेते हैं, तो चानो से वह क्या आस रखती। आज अंजू के बाप होते तो.......! आँचल से आँखें पोछने लगी दुलारी! "रसीद नहीं है सरकार, लेकिन हमारे पास दो बिगहा सात कट्ठा खेत है?" अंजू के माथे पर हाथ रख दी वह, "डेढ़ बिगहा खेत कोसी के पेट में समा गया सरकार। घर-घरारी सब बह गया.....उसके साथ अंजू के बाप......!" बुक्का पार कर रोने लगी दुलारी। अंजू बोरे को फेंककर माँ को संभालने लगी। दुखों का पहाड़ टूटा था उन पर! लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। कतार में खड़े लोगों की आँखें माँ-बेटी जम गयीं। "नाटक बंद करो यहाँ, जाओ रसीद लेकर आओ। तब मिलेंगे पैसे और अनाज।" सिपाही ने उसे कतार से बाहर कर दिया। "हमारी तो जिंदगी ही उजड़ गयी सरकार.....खेत को कौन पूछता है?" दुलारी अपना दुखरा सुनाने लगी, "कोसी बांध पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं!" मुंशी जी को इतनी फुर्सत कहाँ? उनकी आँखें फिर बही- खाते में धँस गयीं - "चानो यादव..?" -"जी सरकार।" किरतपुर ब्लॉक पर लोगों की जबरदस्त भीड़ लगी थीं। किसान, मजदूर से लेकर जमींदार तक लाईन में खड़े थे।सबको पर बीघा दो हजार रूपए और एक क्विंटल अनाज दिये जा रहे थे। दहनाली का मुआवजा अगस्त-सितंबर के बजाय जनवरी में मिल रहा था, फिर भी सबके चेहरे खिल रहे थे। किसान खुश थे कि गेहूँ और मकई की फसल के लिए खाद और पानी का इंतजाम हो गया। उनके मन में हरे-भरे खेत नाच रहे थे। रब्बी की फसल अच्छी हो गयी तो सब दुःख दूर हो जाएगा। इस बार मौसम ने दगा दिया। मूँग की फसल भी मारी गयी। अप्रैल-मई महीने में धूप के तेज होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त था, पर किसान बेहद खुश थे। मूँग के लिए यही अनुकूल मौसम है। मूँग कचकचा कर फला था। लेकिन मई के अंत में चार दिनों तक आंधी-पानी.... सत्यानाश कर दिया। किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। किन्तु अच्छी बारिश होने से धान की फसल लहलहा उठी, पर डायन कोसी सब बहाकर ले गई! दुलारी की आँखें सावन-भादव के मेघ की भाँति लगातार बरस रही थीं। अंजू माँ को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दो क्विंटल अनाज और चार हजार रुपए पाने की उम्मीद लेकर यहाँ माँ-बेटी सुबह से बैठी थी! मिल जाता तो कुछ दिन का समय कट जाता। उसका धैर्य जवाब दे गया था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा......! 'मुझे माफ कर देना अंजू की माई! बाल-बच्चे का ध्यान रखना.....हिम्मत न हारना......!' अंजू के बाप का एक-एक शब्द उसके कलेजे को बरछी की भाँति बेध रहा था। कोसी के गर्भ में इतना कहकर समा गया था वह। अब किसके सहारे वह धैरज धरे? कौन है उसका सहारा? विपत्ति के समय में पकी मछली भी पानी में तैर जाती है! उस दिन खेत से लौटने पर कितना दुःखी था किसुन! कहने लगा- ' अंजू की माई, लगता है हराही बाध पूरा समा जाएगा कोसी में! अपना दसकठवा खेत तो अब आधा बचा है! दुलारी गंभराये धान को काटकर लौटी थी। उसके माथे पर धान का बोझ किसी प्रियजन की लाश के समान भारी लग रहा था। बड़े मनोयोग से कमठौनी की थी माँ बेटी ने। समय से बारिश होती गयी, जिससे धान पूरी तरह पल गया था। एक-एक जड़ से दर्जनों कोपलें निकल आयी थीं। चारों ओर धान की हरियाली के सिवा दूर-दूर तक कुछ न सूझता था। लेकिन कोसी मैया कुपित थी। सर्वनाश...... -"कसुन भाय, लगता है इस बार कोसी फिर सर्वनाश करेगी?" सरयुग ने दुखी होकर पूछा। वह भी पति-पत्नी अपने खेत के गंभराए धान को काट रहे थे। सरयुग उसका लंगोटिया 'मीत' था। जीवन के कई संदर्भ दोनों के जुड़े हुए थे। घर- गृहस्थी और खेती-पथारी से लेकर पंजाब जाने तक में दोनों साथ रहते थे। -"माता की जो मरजी!" किसुन ने मानो रोकर जवाब दिया। नदी में फिर करीब सात-आठ हाथ का रादा धराम से गिरा। ऊफनता हुआ पानी बीस हाथ ऊपर तक गया और वहाँ से गिर कर फिर धारा में समा गया। उसने अपना कलेजा थाम लिया। हाथ तेजी से चल रहे थे। जब तक वे चार डेग फसल काटते, उससे पहले ही आगे दरारें पड़ जाती थीं। दरारें पड़ती गयीं। धान कटते गये। साथ में कटते और बहते गये उसके सपने! दरारें जमीन में नहीं, उनके कलेजे में पड़ रही थीं। इसी खेत के भरोसे वह पंजाब को तिलांजलि दे आया था। अपने परिवार के साथ आधे पेट खाकर वह खुश था। अंजू की माई कहती थी - परदेस का भरोसा कब तक? अवस्था गिरने पर इसी खेत का आसरा होगा...... खेत का कोसी में समा जाना कोई नयी घटना नहीं थी उनके लिए। हर दस -बारह साल पर जमीन समा जाती है कोशी में! वह अपनी धारा बदलती रहती है। बड़े किसान को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कोना दहाने-भसने से वह गरीब नहीं हो जाता, परंतु छोटे किसान तो बह जाते हैं उसी के साथ! करीब बारह साल पहले भी उसकी जमीन, घर-द्वार.....सब बह गया था कोसी में! तभी से वह पंजाब खटने लगा। वह तीन साल पहले लौटा था पंजाब से। दुलारी ने फोन पर बताया कि अपना पूरा खेत जाग गया है। माता कोशी ने अपनी धारा बदल दी है। लोग अपने-अपने खेत जोत रहे हैं। जल्दी से गाड़ी पकड़ लीजिए। मकई रोपनी का 'तड़क' है। "नेपाल लगातार बरस रहा है किसुन भाय!" सरयुग ने हाथ रोककर कहा, "पछुआ हवा बह रही है। हिमालय का कलेजा पिघल रहा है। सुनते हैं भीम बराज से पानी छोड़ दिया गया है। वह पानी कल तक बजरेगा (उतरेगा) ।जमालपुर के सामने बांध में कटाव लगा है। रात भर सोते नहीं हैं भीतर के लोग। सर्वनाश करेगी कोसी! फिर पंजाब का आसरा........" पंजाब के नाम पर चिढ़ जाता है किसुन! दिन-रात खटते रहो, बाल-बच्चे को त्यागकर! और सारा माल ठीकेदार पीट लेता है। मजदूर एड़ी-चोटी का पसीना एक कर अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता और ठीकेदार-नंबरदार दो साल में कोठा पीट लेता है। उसके सामने चानों यादव का चेहरा नाचने लगा। चानो उसका ठीकेदार था, जो हर साल बीसों मजदूर को अपने खर्चे पर बहला-फुसलाकर ले जाता है और उसके पसीने की कमाई पर हाथ मारता है। वह हर साल दस कट्ठा जमीन खरीदता है। कोठे पर कोठा पीट रहा है। साथ में सूद-ब्याज का कारोबार। दसटकया ब्याज.... सूद का सूद जोड़ता है बेईमान! किसुन पाँच मजदूरों को लेकर खुद जमींदार से बात करके खटने लगा था। उसे लगा था कि वह चानों के महाजाल से उसे मुक्ति मिल गयी है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि ऐसे निरीह कामगारों का श्रम लूटने के लिए सब जाल बिछाए रहते हैं। यह सब उसे तब मालूम हुआ, जब जमीन मालक ने ही उसकी मजदूरी मार ली। विरोध करने पर वह बोला, 'साला भागता है यहाँ से कि नहीं। बिहारी भिखमंगे कहीं के!' तब से पंजाब के नाम पर घीन आती है उसे। उसने पंजाब को आखिर बार सलाम कर लिया था। इतनी मेहनत कोई अपने खेत में करे तो सोना उगलेगी यहाँ की धरती। बिहार की सूरत बदल जाएगी। "खेत बह गया तो बटाई खेती करेंगे। जोड़ी भर बैल है न, क्या दिक्कत है! लेकिन पंजाब.....पंजाब को तीन बार परणाम करते हैं।" उसने सरयुग को बेलाग जवाब दिया। पछुआ हवा बहती गई.... तेज.... और तेज। हिमालय का कलेजा पिघलता गया। नदी हाथियों की झुंड की तरह चिंघारती हुई तांडव करने लगी। पंडित जी ने ठीक ही कहा था। अबकी हाथी पर सवार होकर आएगी कोसी। सत्यानाश करेगी।खेत समाते गये कोसी के गर्भ में। गाँव के पूरबी छोर पर कटनिया लगी है। जगेसर मंडल, धनपत ठाकुर, सजन मलाह सबका घर-द्वार बह गया! बाबा डिहबार भी मंदिर समेत नदी में समा गये। अब कुर्मी टोले में कटाव......भीतर से बाहर तक काँप गया किसुन! बाढ़! बाढ़!! बाढ़!!! बाढ़ आ गयी। धरती चारों तरफ जलमग्न! पानी.... पानी.....पानी......कटाव। कुर्मी टोला नदी में.... कोसी का भयंकर तांडव। आर्तनाद.......त्राहिमाम......... सब भाग रहे हैं! रासन-पानी, बक्सा-पेटी, माल-जाल लेकर....जान है तो जहान है। तरवारा बांध पर पैर रखने की जगह नहीं है। आदमी से लेकर माल-जाल सबका यही एक आसरा है। कई जगह बांध में कटाव जारी है। विभागीय अधिकारी परेशान हैं। ऊपर के अधिकारियों और मंत्रियों की धमकी....'बांध टूटा तो नपेंगे अधिकारी'। एक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ के पसीने छूट रहे हैं। लगातार कैरेटिंग जारी है। मजदूर दिन-रात खट रहे हैं। बबूल का पेड़ काटकर डाल रहे हैं। बोरियों में बालू -ईंट भरकर तार के जाल में डाल रहे हैं। लेकिन सब समाता जा रहा है कोशी के गर्भ में। अपनी गति से बढ़ती जा रही है वह भीषण अट्टहास करती हुई! किसुन नाव मांगने गये थे, जगेसर मलाह से। अभी तक नहीं लौटे। सुबह से दोपहर हो गया। दुलारी और अंजू अनाज को बोरियों में भरकर बैठी थी। मंगल भूसे का अंतिम फलिया भरकर बांध रहा था। सबके भूख-प्यास मर गये थे! दोनों बैल पगहा तोड़ने पर ऊतारू थे। भैंस सारी परिस्थिति से अनजान बनी हुई जुगाली कर रही थी। वह गाभिन थी। अंतिम महीना चल रहा था। इस पर समधी की नजर कब से गड़ी है। अब भैस के साथ ही अंजू की बिदाई होगी। गछे हैं तो देना ही पड़ेगा। अंजू की शादी को तीन साल हो गये। पति दिल्ली रहकर डायरी में गाय दूहता है। बाप का सच्चा सपूत। भैस नहीं तो बिदाई नहीं... किसुन और मंगल नाव से तीन खेप में सबकुछ बांध पर रख आए। अंजू वहीं बैठकर चौकीदारी करने लगी। अब दोनों बैलों तथा भैस को पार उतारना था। वे लोग जब तक लौटे, तब तक भूसा-घर जल समाधि ले चुका था। कटाव अब दालान मे लगा था। वह पहले दोनों बैलों को पार किया, चूँकि बैलों में अधिक घबराहट थी। अब वे भैस को लेने आए थे। नाव छोटी थी इसलिए भारी-भरकम भैस को नाव के साथ तैरकर जाना था। किसुन ने जोर से पगड़ी बांधी और भैस का पूछ पकड़कर धारा के साथ होड़ लगाने लगा। मंगल नाव खे रहा था। दुलारी पतवार चला रही थी। बांध की दूरी एक मील। लगातार कटाव के कारण नदी विकराल होती जा रही थी। उसकी चौड़ाई चौगुनी हो गयी थी। भैस विशालकाय शरीर के बावजूद भी धारा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। पार करना उसके लिए कठिन नहीं था। लेकिन तभी जलकुंभी का एक पहाड़ उसके साथ हो लिया। भैस का दम फूलने लगा। अभी वे बीच नदी में आए थे। नाव भी दिशाहीन हो गयी। "भैस की रस्सी छोड़ दो अंजू की माई।" किसुन चिल्लाया। उसने रस्सी छोड़ दिया। नाव जलकुंभी के घेरे से बाहर हो गयी। लेकिन भैस चारों तरफ से घिर गयी थी। वह उससे मुक्त होने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन नदी की तेज धारा उसे लिए जा रही थी। "चल बेट्टा हम हैं पीठ पर!" किसुन ने लिलकारी दिया। वह एक बार पीछे मुड़कर किसुन को देखी। एक गहन आत्मीयता थी दोनों में। चार साल पहले कितनी छोटी थी वह, जब किसुन उसे ससुराल से लेकर आया था। 'डकहा' रोग के कारण उसकी माँ चल बसी थी। पशुओं के लिए कहर आन पड़ी थी। उसके ससुर ने इसका पगहा किसुन के हाथ में थमा दिया था। मर्जी हो तो पाल लेना, न मर्जी हो तो बेच देना किसी कसाई के हाथ......यहाँ रह गयी तो बचेगी नहीं! दोनों को एक-दूसरे पर अटूट विश्वास था। "नांगर (पूँछ) को जोर से पकड़े रहना अंजू के बाबू।" दुलारी चिल्लायी। भैस पूरी शक्ति लगा रही थी। तभी पानी के परत पर खून की एक परत उभरने लगी। किसुन को समझते देर न लगी कि भैस को ग्राह ने अपने कब्जे में कर लिया है। वह अंतिम बार किसुन को मुड़कर देखी। मानो, अब उनसे बिदाई मांग रही हो। किसुन ने फिर लिलकारी भरने की कोशिश की। लेकिन तब तक भैस जल समाधि ले चुकी थी। उसकी पूँछ एक झटके के साथ हाथ से छूट गयी। दुलारी छाती पीटने लगी। "हमें माफ कर देना अंजू की माई! धैरज रखना..... हिम्मत न हारना!" जलकुंभी के पहाड़ों के बीच से आवाज आयी थी। रात भर सो नहीं पायी दुलारी। चानों ने तो ठीक ही कहा था। झूठ बोलती है जनानी। पाँच-सात कट्ठा खेत है इसके पास। बांध पर किनारे झोपड़ी बनाकर रहती है यह। दाने-दाने को तरस रहे थे वे। दोनों बैलों को खोलकर ले गये चानों यादव। अंजू की शादी में उनसे दस हजार रूपया कर्ज लिया था। दस हजार अब पैंतीस हजार हो चुका था। पंचों ने बैलों का दाम बीस हजार निर्धारित किये। मतलब अब भी उस पर पन्द्रह हजार का बकाया......वह कई बार मंगल को पंजाब ले जाने की कोशिश की, ताकि बाकी का रकम बसूला जा सके। उसने कई बार दुलारी को समझाने की कोशिश की थी। मंगल पंजाब खटने लगेगा तो संकट की घड़ी टल जाएगी। परिवार में खुशहाली लौट आएगी..... अभी पंजाब में धनरोपनी का 'तड़क' है। चानो यादव जब भी मंगल को पंजाब ले जाने की बात करता है। दुलारी कलेजे से साट लेती है बेटे को! अभी तो पन्द्रह साल का हुआ है मंगल। पंजाब की खटनी में कैसे ठठेगा? धनरोपनी और कटनी में कलेजा टूट जाता है! संकट की इस घड़ी में समधी पिछले सप्ताह धमकी दे गये थे। 'भैस मर गयी तो क्या, हमें जमीन बेचकर पचास हजार रुपए दो, भैस का पूरा दाम......नहीं तो गौना नहीं होगा! हम बेटे का बियाह कहीं और कर देंगे। फिर झाल बजाते रहना माँ-बेटी, बांध पर बैठकर।' सूरज उगने तक आधे खेत को कुदाली से कोर चुकी थी दुलारी। अब यही पचकठवा खेत उसकी संपत्ति थी। उसका भरोसा सब पर से उठ चुका था। किसुन का एक-एक शब्द उसकी शक्ति बन गयी। सूरज की प्रथम किरणें उसके पोर-पोर में समा गयी। अब उसके भीतर प्रकाश था....केवल प्रकाश। माँ-बेटी ने खेत मे ही डेरा जमा दिया। कुछ ही दिनों में समूचे खेत में फूट-तरबूज और परबल की फसलें लहराने लगीं। थोक खरीदार खेत से ही माल उठाना शुरू कर दिया। अब उसके पास पैसे का अभाव नहीं रहा। एक दिन मंगल सुबह-सुबह नाचता हुआ घर आया - "माँ अपना पूरा का पूरा खेत जाग गया है। सरयुग काका कह रहे थे कि मकई की जबरदस्त फसल होगी उसमें।" दुलारी का मन खेत को वापस पाकर खिल उठा। वह फिर बैलों को वापस ले आयी चानों का बकाया देकर। अब सुबह से लेकर शाम तक खेत में लगी रहने लगे माँ-बेटी और मंगल। गाँव में हल्ला था कि दुलरिया रात में खुद हल जोतती है...... बीज बोती है। वह जनानी नहीं 'मदार्नी' है।

दस्तक प्रभात
डॉ.उमेश कुमार शर्मा

कविता

जिंदगी ये तेरी खरोचें...

जिंदगी ये तेरी खरोंचें
हैं मुझ पर
या फिर तू मुझे तराशने
की कोशिश में है
जिस मोड़ से गुजरता हूं,
सामने तनी शमशीरें
खंडित कर देना चाहते
हैं हाथ की लकीरें
समझ नहीं आता
क्यों गले पड़ गए हैं
तकदीरें टुकड़ों में कट गए हैं
ओह क्या करें हांफता
कांपता हाशिए में है
जिंदगी ये तेरी खरोंचें...
चलना तो चाहा,
लेकिन आगे कुआं पीछे खाई
अश्रुपूरित, है
नहीं कहीं सुनवाई
कहते, अतीत की
गुस्ताखियों का अभिशाप
हाथ जोड़ विनती,
आखिर कब तक संताप
बहा तो दी है नैया
लेकिन गर्दिश में है
जिंदगी ये तेरी खरोचें...
सोचा था कल
सुहानी भोर होगी
कर दीदार, धमनियां
भाव विभोर होगी
लगता मुंगेरी थे सपने,
हकीकत नहीं बन सके
तकदीर का यही फैसला,
अपने नहीं बन सके
कैसी यह क्रीडा,
अपनों की साजिश में हैं
जिंदगी ये तेरी खरोचें...
पुरवाईयों ने ली है अंगड़ाई,
सपने सुहावने होंगे
धन्यवाद प्रभु, कोई तो
गले लगाने वाले होंगे
भोर हुई, सब कुछ हवा
हवाई हो गया
था तो दीप्त उजाला,
जीवित जमीं तले दब गया
थक गया, छोड़ो,
किनारे बंदिश में हैं
जिंदगी ये तेरी खरोचें...

दस्तक प्रभात/दर्शन सिंह

बात बे बात

क्या हमारे गांव वालों ने पंद्रह-पंद्रह लाख वर्षों पहले गंवा दिये?

मोदी जी वाले पंद्रह लाख की बात नहीं है। दरअसल, कल बनारस में लुप्त हो रहे एक दुर्लभ वन्य जीव पैंगोलिन को पकड़ा गया। वह जिंदा है। एक होटल से कई तस्कर भी गिरफ्त में आये। उसमें पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर व सीतामढ़ी के भाई लोग भी पकड़ में आये। इस एक पैंगोलिन की कीमत पंद्रह लाख बतायी जा रही है। अब हमको इस बात की चिंता क्यों न हो। कुछ ऐसे ही जीव का सामना गांव पर बचपन में अक्सर होता रहा है। जो अखबार में इसका फोटो दिख रहा है, कुछ ऐसा ही दिखता था। तब हम बच्चा पार्टी भी मदन चाचा और उनके दस-बीस जवान साथियों के साथ पीछे लग कर 'शिकार' पर निकल जाया करते थे। कोई बंदूक-भाला नहीं, केवल लाठी-डंडा सबके हाथ में होते थे। अपनी हैसियत के हिसाब से हमलोग भी अपना-शस्त्र लकड़ी-पैना छांट लेते। वीर कुंवर सिंह जैसा साफा सबके सिर पर सजा रहता। गमछे का बना बड़े लोग का बड़ा मुरेठा और हमारे छोटे-छोटे मुरेठी। सब गांव से थोड़ी दूर बहती अपनी छेर नदी के उस पार पहुंचते। वहां तब जंगल-झाड़ ज्यादा होता था। मिट्टी के बड़े-बडे. पहाड़ जैसे टीले फैले हुए थे। याद आता है कि वहीं सबसे ज्यादा बबूल के छोटे-बड़े पेड़ मिलते थे। आये दिन वहां से हमलोग कांटों से बचते बचाते दतुवन तोड़ लाया करते थे। बाबा

बताते थे कि बबूल के दातून से दांत चमकते और बहुत मजबूत होते हैं। हमलोग अपनी टोली बनाकर नदी किनारे मर-मैदान (फ्रेश होने) के बाद उस पार टीले पर चढ़ जाते और हाथ-पांव के छीलने की परवाह किये बिना दतुअन तोड़ने की कम्पटीशन में जूट जाते। तो बता रहे थे कि कभी-कभी वहां शिकार का भी रोमांचक प्रोग्राम बनता। वह दिन और अधिक मजेदार होता । ऐसे शिकार प्रोग्राम के दिन वह चालबाज प्राणी पूरे मुस्तैदी के साथ खोजा जाता था, जिसकी रुपरेखा आज के अखबार वाले फोटो से मिलती है। हम जंगल- झाड़ के बीच टीले पर चारों तरफ घात लगाकर फैल जाते। चाचा लोग कहते थे कि जहां दिख जाये, बता देना, धीरे से इशारा कर देना।घबराने वाली बात नहीं है। वह काटता नहीं। लेकिन, कौन माने उनकी बात कि काटता नहीं। हमलोग अपनी चालाकी दिखाते। मुड़ी हिला देते कि डर नहीं लगेगा। पर डर तो दोनों बातों का लगता था। एक तो काटे जाने का और दूसरा शिकार पार्टी से निकाले जाने का। इसलिए काटे जाने का डर उजागर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर सावधानी पूर्वक अपने साहस का नकली परिचय देते हुए चुपचाप चाचा लोगों के पीछे लगे रहते। इस बीच किसी बिल या खोह से कोई बड़ा खेत खाने वाला चूहा निकलकर भागता, तो बड़ी बहादुरी से हमसब अपना हथियार लिए उसके पीछे हल्ला बोल देते।मदन चाचा डांटते कि तुमलोग बना बनाया काम बिगाड़ दोगे। वह चूहा था। उसके पीछे क्यों शोर मचा रहे हो ? हम बताते, नहीं चाचा वह चूहा नहीं था। और हम फिर शिकार में जुट जाते। आज याद नहीं आता कि ऐसे शिकार में कभी कुछ खास मिला भी या नहीं । वह फोटो वाला प्राणी था या कुछ और चीजें थी। पर, इतना याद है कि वह फोटो वाले जीव के तरह ही होता था। तब कहां पता था कि खोह बिल में छुपकर रहने वाला जीव इतना कीमती भी होगा। वह भी पंद्रह लाख का।बाप रे अफसोस आज गांव जाकर उसे खोज भी नहीं सकते। आज मदन चाचा और उनके कोई साथी भी जवान नहीं रहे। कुछ गुजर गये।कई एकदम बूढ़े हो गये। लेकिन हमारे मदन चाचा का हौसला आज भी जवानों जैसा है और सबसे बड़ी बात कि हम चाहें तब भी ' शिकार ' करने कहां जायेंगे ? सूत भर की नदी रह गयी है। किन्तु किनारे का सारा जंगल झाड़ कब का साफ हो चुका है। वो बड़े टीले गायब हैं। सब सफाचट। सारा समतल कर खेत बना दिया गया। अब दूर दूर तक केवल खेत ही खेत। उस पार अब जंगल झाड़ का कोई बीच में पर्दा नहीं । इस गांव से उस गांव को अब सीधे देखने की सुविधा। बीच में मानव निर्मित बड़ा सन्नाटा। सांय...सांय। जैसे हवायें भी गुजरने से डरती हों। संतोष करना है। जमाना बदल रहा है।

दस्तक प्रभात/ परशुराम शर्मा

https://t.me/AllNewsPaperPaid

रक्षा क्षेत्र में बढ़ेगी धाक

ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल भारत ने फिलीपींस को दे दी। दोनों देशों के बीच 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर में समझौता 2022 में हुआ था। भारतीय वायु सेना के अमेरिकी मूल के सी-17 के ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से फिलीपींस मरीन क्राफ्स को ये हथियार सौंपे। यह ऑर्डर 290 किलोमीटर की रेंज वाली एंटी शिप क्रूज मिसाइल के तट आधारित संस्करण के लिए है। ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल भारत-रूस का संयुक्त उद्यम है। भारत डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशिनोस्ट्रोयेनिया इसके प्रमुख साझेदार हैं। ब्रह्मोस की धाक पूरी दुनिया में है तथा यह पहला अंतरराष्ट्रीय ऑडर है। अंदाजा है कि फिलीपींस इसे अपने तटीय इलाकों में तैनात करेगा। इस मिसाइल पणाली में लॉन्चर, वाहन, लोडर, कमांड और नियंत्रण केंद्र आदि शामिल हैं। भारत के पास लंबी दूरी की कई अन्य मिसाइलें भी हैं। मगर फिलीपींस को दी गई मिसाइलें भिन्न रूप से छोटी बताई जा रही हैं, जो बिल्कुल नई हैं तथा उस खेप का हिस्सा नहीं हैं, जो भारतीय सशस्त्र बल के पास हैं। यह प्रसिद्ध हथियार ऐसे वक्त सौंपा जा रहा है, जब दक्षिण चीन सागर में लगातार झड़पें चालू हैं जिससे दोनों मुल्कों के दरम्यान लगातार तनाव बढ़ रहा है। चूंकि ये मिसाइलें दस सेकेंड के भीतर दुश्मन को निशाना बना सकती हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि फिलीपींस समुद्र में अपनी ताकत बढ़ा कर चीन से आमने-सामने झड़प के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है। हमारे विशेषज्ञ फिलीपींस की सेना को इसकी विशेष ट्रेनिंग भी देंगे जो इस ऑर्डर में लिखित है। इससे न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में हमारी धाक बढ़ेगी, बल्कि हमारी सेना का मनोबल भी ऊंचा हो सकेगा। अपनी इन क्षमताओं के बूते साउथ ईस्ट एशिया में भारत प्रमुख शस्त्र निर्यातक बनने की तैयारी भी कर सकता है, जो वैश्विक रूप से भारत की बदलती छवि को लेकर बेहतरीन भूमिका निभाने वाला साबित हो सकता है। निःसंदेह अपने यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में अपने यहां विशेषज्ञों की धाक जमी हुई है। यदि उन्हें बेहतर मौके मिलते हैं, तो वे देश का नाम रोशन करने के साथ ही चौतरफा अनुभव बटोर सकेंगे और उत्साहजनक ढंग से प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रों में अव्वल आने के मौके नहीं चूकने का बेहतरीन प्रयास करेंगे।

विरासत टैक्स एवं निजी सम्पत्ति सर्वे पर संकट में घिरी कांग्रेस

आरती कुमारी

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जनता के बीच जिस तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा में हैं, उनमें देश विकास से अधिक मुक्त की रेवड़िया बांटने या अतिश्योक्तिपूर्ण सुविधा देने की बातें हैं तो 'विरासत टैक्स' के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई को हड़पने के सुझाव है। ऐसी विरोधीभासी सोच एवं योजनाएं कांग्रेस की अपरिपक्व एवं स्वार्थप्रेरित राजनीति को ही उजागर करती है। इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष एवं राहुल गांधी के विश्वस्त सलाहकार सैम पित्रोदा ने चुनावी समर में अपने ताजा बयान में विरासत टैक्स की वकालत की है। उन्होंने अमेरिका में लागू इस टैक्स की पैरवी करते हुए भारत के लिये उपयोगी बताया। सैम ने अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख सफाई दी है, तो कांग्रेस ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन राजनीति की इन कुचालों एवं ऐसे बयानों में कांग्रेस का इरादा जनता की मेहनत की कमाई की संगठित लूट और वैध लूट ही नजर आता है। सैम पित्रोदा के बयान में कांग्रेस की सोच एवं संकल्प ही नहीं दिखा बल्कि कांग्रेस की भावी योजनाओं की परतें भी खुली है।

भले ही इस बयान ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हो, लेकिन जनता को मूर्ख समझ हर बार हंगामा खड़ा करना कांग्रेस की नीति एवं नियत रही है। सैम ऐसे ही विवादास्पद बयानों से पूर्व में भी चर्चा में रहे हैं। अमेरिका में विरासत टैक्स जैसी अनेक स्थितियां एवं कानून हैं जो भारत में नहीं है क्योंकि हर देश की अपनी स्थितियां होती है। सैम के इस बयान ने इसलिए तूल पकड़ लिया, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोगों की संपत्ति के सर्वे का वादा किया है। इसकी व्याख्या भाजपा पहले से ही इस रूप में कर रही है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का आकलन करके संपन्न-सक्षम लोगों की संपदा का एक हिस्सा लेने का इरादा रखती है। चूंकि सैम पित्रोदा का कथन कुछ इसी ओर संकेत करता दिख रहा था, इसलिए भाजपा ने नए सिरे से उनके बयान को मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तो कहा जब तक आप जीवित रहेंगे, तब तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे, तब आप पर विरासत का बोझ लाद देगी।' कांग्रेस की लूट जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बाद भी कह कर मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह कह दिया कि यदि कांग्रेस वैसा कुछ करने का नहीं सोच रही है, जैसा सैम पित्रोदा कह रहे हैं तो वह अपने घोषणा पत्र से संपत्ति के सर्वेक्षण वाली बात हटाए।' निश्चित ही कांग्रेस की संपत्ति के सर्वेक्षण की बात में गहरे अर्थ, संदेह एवं शंकाएं निहित हैं।

राजननेताओं के बयानों पर राजनीति होना लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन जनता के हितों पर आघात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतन्त्र में सतत् रूप से अमीर-गरीब का विमर्श चलता रहता है, गरीबों के हित की बात करके अधिसंख्य मतदाताओं को लुभाना राजनीतिक चतुराई है, लेकिन जनता को बांटना एवं अलग-अलग खेमों में खड़ा करना, लोकतंत्र को कमजोर करता है। मगर भारत का मतदाता अब इतना सुविज्ञ एवं समझदार हैं कि वे राजनेताओं की मंशा को समझकर उस समय आगे बढ़कर नेतृत्व खुद संभाल लेते हैं जब नेतागण अपना पथ भूल जाते हैं। भारत के चुनावों का इतिहास इसका गवाह रहा है। इसलिए राजनैतिक विमर्श चाहे जितना गर्त में चला जाये मगर मतदाता की सूझबूझ, जागरूकता एवं विवेक कभी मंद नहीं पड़ती।

भले ही सैम पित्रोदा अमेरिका का उदाहरण देकर उस पर भारत में बहस की जरूरत जता रहे थे, लेकिन उन्हें गलत समय ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए था, जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह भारत की परिस्थितियों के लिये सही न हो और जिसके विवाद का विषय बनने की भरी-पूरी संभावनाएं हो। यह तो कांग्रेस ही जाने कि वह संपत्ति के सर्वे के जरिये क्या हासिल करना चाहती है, लेकिन इससे इन्कार नहीं कि देश में आर्थिक असमानता कम करने की आवश्यकता है। इसके बाद भी इस आवश्यकता की पूर्ति न तो वामपंथी सोच वाले तौर-तरीकों से की जा सकती है और न ही उन उपायों से, जो समाज में विभाजन पैदा करें। जो भी निर्धन-वंचित हैं या सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके उत्थान की अतिरिक्त चिंता की जानी चाहिए, लेकिन बिना उनका जाति, मजहब देखे, बिना विभाजन की राजनीति को किये।

सैम पित्रोदा, राजनीति की दुनिया में यह नाम कोई नया नहीं है, कांग्रेस के शासन में तकनीकी एवं आधुनिक विकास के वे पुरोध रहे हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के सलाहकार रह चुके पित्रोदा इस समय राहुल के खास लोगों में से एक हैं। पित्रोदा अपने काम से कम अपने बयानों के चलते ज्यादा चर्चे में रहते हैं। उनके बयान अक्सर कांग्रेस के लिए भी सरदर्द बनते रहे हैं। पित्रोदा के अनेक बयान पहले भी विवाद एवं कांग्रेस के सिरदर्द की वजह बन चुके हैं। साल 2019 में ही उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मध्यमवर्गीय परिवार को रोजगार और अधिक अवसर मिलेंगे। इस बयान ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई थीं और पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा था। पित्रोदा यहीं नहीं रुके, उन्होंने 2019 के ही पुलवामा हमले पर कहा था कि ऐसे हमले तो होते रहते हैं, मुंबई में भी हमला हुआ था। निश्चित ही कांग्रेस के शासन में ऐसे हमले एवं साम्प्रदायिक दंगे होते ही रहते थे। उन्होंने बालाकोट एयरस्ट्राइक ऑपरेशन पर सबूत मांगे थे। सैम पित्रोदा के बयान एवं कांग्रेस के घोषणा पत्र के निजी सम्पत्ति सर्वे की बात में अवश्य ही रिश्ता है, जिसने पूरे देश के सामने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है कि निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर वह इस धन को अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। ऐसी योजना यूपीए सरकार में तय भी हुई थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक और उसमें भी सबसे अधिक मुस्लिमों का है, उस प्रकार से कांग्रेस की यह मुसलमानों को लुभाने एवं उन्हें लाभ पहुंचाने की अघोषित चुनावी घोषणा है, इस तरह की घोषणाएं लोकतंत्र में सुशासन एवं राजनीति मूल्यों को धुंधलाने की कुचेष्टा ही कही जायेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता बादशाह नहीं होता बल्कि साधारण मतदाता बादशाह होता है क्योंकि उसके ही एक वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। मतदाता को जो मूर्ख समझते हैं उनसे बड़ा मूर्ख दूसरा नहीं होता। ऐसे तथाकथित बयानों से भारत में संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र कभी भी प्रभावित नहीं होगा, वह सफल रहा है और रहेगा क्योंकि भारत के लोग अनपढ़ व गरीब हो सकते हैं मगर वे अज्ञानी या मूर्ख नहीं है। उनका व्यावहारिक ज्ञान बहुत मजबूत होता है और वे राजनीतिक दलों के भ्रम में नहीं आने वाले, गुमराह नहीं होने वाले। यह सच है कि जब से भारत में जातिवादी, क्षेत्रवादी, भाषावादी, वर्गवादी व सम्प्रदायवादी राजनीति का बोलबाला हुआ है तभी से राजनीति के विमर्श में गिरावट आनी शुरू हुई है, लेकिन इस गिरावट को संभालने के लिये मतदाता को अधिक परिवक्व एवं समझदार होने की अपेक्षा है।

अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारत के साथ व्यापार शुरू करने को आतुर पाकिस्तान !

अशोक भाटिया

मीडिया समाचारों के अनुसार अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पाकिस्तान लगातार हाथ पैर मार रहा है। अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार में विदेश मंत्री और नवाज शरीफ के समधि इशाक डार ने भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की बातचीत पर जोर दिया है। शहबाज शरीफ के मंत्री का यह बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ फिर से व्यापारिक संबंधों की शुरुआत करने को आतुर है। बीते सालों में ऐसा देखा गया है पाकिस्तान के मंत्री अक्सर भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को शुरू करने के लिए जोर दे चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल में किसी अन्य देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर को रोककर उनसे प्याज और टमाटर पाकिस्तान भेजने की गुहार लगा चुके हैं। गौरतलब है कि डार ने पहली बार पिछले महीने लंदन में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने की संभावना का संकेत दिया था। उनका विचार था कि पाकिस्तान का व्यापारिक समुदाय पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार संबंधों की बहाली चाहता है। उनके बयान की विपक्षी दलों और आलोचकों ने आलोचना की। हालांकि, डार ने गुरुवार को अपनी पिछली टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा कि कई व्यापारियों ने उन्हें बताया कि वे किसी तीसरे देश के माध्यम से भारत से सामान आयात कर रहे थे, जिससे उन्हें अधिक लागत आती थी इसलिए वे दोनों देशों के बीच सीधे व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने के पक्ष में थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने लंदन जाकर यह बयान ऐसे समय में दिया था जबकि भारत में आम चुनाव शुरू होने वाले थे । इसलिए चर्चा के लिए तो इस बयान का महत्व हो सकता है लेकिन वास्तविक महत्व तभी होगा जब भारत में नयी सरकार बन जाने के बाद इस पर बातचीत होगी। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या भारत को फिर से पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ता बहाल करना चाहिए? इस सवाल के जवाब में किसी भी राजनैतिक दल ने अपने मेनिफेस्टो में उल्लेख किया है न किसी जाहिर सभा में इसका जिक्र। ज्ञात हो कि जब अगस्त 2019 में भारत की केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था । ये भारतीय संविधान का एक प्रावधान था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। धारा हटाते हुए सेंटर ने तर्क दिया कि इससे यह राज्य पूरे देश से जुड़ सकेगा। ऐसा हुआ भी। इसी बात पर पाकिस्तान परेशान हो उठा, और बौखलाकर भारत से अपने व्यापारिक रिश्ते निरस्त कर दिए। दूसरी ओर ये बात भी हो रही थी कि ट्रेड सस्पेंशन की बड़ी वजह कुछ और ही थी। असल में उसी साल भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस ले लिया और पाकिस्तानी इंपोर्ट पर टैरिफ 200 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था। भारत ने यह कदम पुलवामा हमले के बाद लिया था, जिसे पाकिस्तानी टैरर गुट जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया था। हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। अटैक के चौबीस घंटों के भीतर ही पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा हटा दिया गया। यहां बता दें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का टैरिफ एंड ट्रेड एग्रीमेंट 1994 कहता है कि सारे सदस्य देश एक-दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा दें, खासकर पड़ोसी देश ताकि फ्री टेड आसान हो सके। हालांकि ये कोई पक्का नियम नहीं। यही वजह है कि रिश्ते खराब होने पर देश सबसे पहले आपस में यही स्टेटस खत्म करते हैं ताकि नाराजगी का आर्थिक असर भी दिखे। भारत और पाकिस्तान साल 1996 से ही एक-दूसरे को मोस्ट-फेवर्ड नेशन मानते आए। इसके बाद भी पाकिस्तान ने लंबी लिस्ट बनाई, जिसमें वो आइटम थे, जो भारत से आयात नहीं किए जा सकते। ये उत्पाद एक-दो नहीं, बल्कि 12 सौ भी ज्यादा थे। उसका कहना था कि वो ये बैन अपने घरेलू उद्योगों को चलाए रखने के लिए लगाए हुए है। हालांकि पहले वो 2 हजार से भी ज्यादा उत्पादों को आयात की मंजूरी दे चुका था। निगेटिव-लिस्टिंग के बाद केवल 138 उत्पाद ही रहे, जो वो भारत से आयात कर रहा था। ध्यान रहे कि पाकिस्तान हमसे कपास, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, मशीनरी और मैकेनिकल डिवाइस जैसी चीजें इंपोर्ट करता था। हम भी पाकिस्तान से कई चीजें आयात करते रहे, जैसे- फल और सूखे मेवे, नमक, सल्फर, पत्थर, कई तरह की धातुएं और चमड़ा आदि। ट्रेड सस्पेंड करने के बाद भी पाकिस्तान हालांकि दवाएं मंगाता रहा क्योंकि उसके तुरंत बाद ही कोविड 19 का दौर आ गया था। भारत ने तब उसकी खासी मदद की थी। बंद होने के बावजूद भारत-पाकिस्तान के बीच लेनदेन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था । मीडिया की एक रिपोर्ट में सरकारी हवाले से कहा गया है कि थोड़ा-बहुत व्यापार वाघा-अटारी बॉर्डर के रास्ते हो रहा था, साथ ही कराची बंदरगाह के जरिए भी लेनदेन चलता रहा। लेकिन ये पहले से बहुत कम, लगभग नहीं जितना हो चुका था। पाकिस्तान हमसे सबसे ज्यादा कॉटन लिया करता था। अब वो इसके लिए ब्राजील और अमेरिका पर निर्भर है। लंबे रास्ते से आने वाले इन उत्पादों पर समय के साथ पैसे भी काफी खर्च हो रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान जिस आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, दूरदराज के देशों से आयात उसपर और भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि उसके विदेश मंत्री ने ट्रेड की वापस बहाली की बात की। हालांकि ये बात उन्होंने सीधे-सीधे नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल मंच पर की। तो फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा। इसके अलावा भारत की मंजूरी भी जरूरी है।दरअसल भारत के लिए पाकिस्तान किसी अन्य देश जैसा ही नहीं है। पाकिस्तान का जन्म भारत को मजहबी हिंसा में झोंककर और लाखों लोगों की कुर्बानी तथा बर्बादी पर हुआ है। उसके साथ न भारत का रिश्ता कभी सहज रहा है और न रह सकता है। इसका कारण सिर्फ यह भर नहीं है कि पाकिस्तान पहले दिन से कश्मीर पर दावा किये बैठा है और उसे आतंकवाद के जरिए हासिल करना चाहता है। बल्कि जब जब भारत पाकिस्तान की ओर आगे बढेगा, उसके उन घावों से खून रिसने लगेगा जो पाकिस्तान ने अपने जन्म से अब तक भारत को दिए हैं।सर सैय्यद अहमद हों या फिर अल्लामा इकबाल या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। किसी न किसी तरह से समय समय इन्होंने यही डर दिखाया था कि अंग्रेजों के जाने के बाद हिन्दू अक्सरियत में मुसलमान दब जाएगा। पाकिस्तान भले ही जिन्ना ने मांगा हो लेकिन अविभाजित पंजाब, सिन्ध से लेकर अविभाजित बंगाल तक मुस्लिमों ने अगर अलग पाकिस्तान का समर्थन किया तो उसके मूल में एक बड़ा कारण हिन्दू बनियों का व्यापार में वर्चस्व होना भी था।आज भी पाकिस्तान में हिन्दुओं की पहचान हिन्दू बनिया के रूप में की जाती है। उनके लिए व्यंग में एक कहावत वहां बहुत प्रचलित है कि हिन्दू वह बनिया है जिसके मुंह में राम और बगल में छूरी रहती है। इसलिए जब 1947 में भारत को काटकर पाकिस्तान बन रहा था तब वहां के मुस्लिम व्यापारियों ने इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा था। फिर वो सिन्ध के कारोबारी रहें हों या पंजाब के कारोबारी। उन्हें लगता था कि जो व्यापारिक संभावना हिन्दू बनिया छोड़कर जा रहा है वो उसे भुना लेंगे और आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएंगे।शुरुआत के दो दशक जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही सोशलिस्ट नीति पर चल रहे थे तब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भारत से अच्छी थी। लेकिन बांग्लादेश के अलग होते ही पाकिस्तान ने जो मजहबी रफ्तार पकड़ी तो उसकी अर्थव्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती चली गयी।

वैसे तो आर्थिक रूप से पाकिस्तान के बर्बाद होने के बहुत से कारण हैं लेकिन सबसे प्रमुख कारण भारत और हिन्दुओं से नफरत ही बनी रही। पाकिस्तान कभी अमेरिका की गोद में बैठा तो कभी चीन के आगे बिछ गया। लेकिन जब जब हिन्दू बनिया से तिजारत (व्यापार) बढाने की बात आई तब तब वहां के मजहबी मुल्लाओं ने बांग दिया कि क्या पाकिस्तान हिन्दुओं से तिजारत करने और अच्छा रिश्ता रखने के लिए बना था? मुल्लाओं का तर्क अकाट्य है। यही कारण है कि जैसे जैसे पाकिस्तान सच्चे इस्लाम के रास्ते पर आगे बढता गया वहां के लोगों के मन में भारत को लेकर नफरत बढती गयी। जिया उल हक के जमाने से आज तक तमाम उतार चढाव के बावजूद वहां की आम अवाम ही इस बात के हक में नहीं रहती है कि भारत के साथ तिजारती रिश्ते बढाये जाएं। उनकी इस नफरत के बावजूद अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ कुछ व्यापारिक रिश्ते रखे हैं तो उसका कारण अंतरराष्ट्रीय बाध्यता और उनकी अपनी आर्थिक मजबूरियां थीं। लेकिन इस दौरान भी पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कश्मीर और पंजाब में ही नहीं मुंबई पर आतंकी हमला जैसा जघन्य कुकर्म पाकिस्तान के हुक्मरानों ने प्लान किया। एक ओर पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करता रहा दूसरी ओर दो दशक तक देशभर में बम विस्फोट के जरिए हजारों लोगों की जान लेता रहा। एक दशक पहले तक टीवी पर बैठकर आईएसआई के चीफ रहे हामिद गुल जैसे हुक्मरान भारत के मुंबई या बंगलौर जैसे शहरों को बर्बाद करने की धमकी देते रहे। परमाणु बम की धमकी तो मानों उनके लिए कंचे गोली खेलने जैसा हो। 2019 में ही सरकार में दोबारा आने के बाद जब मोदी सरकार ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किया तब पाकिस्तान ने एकतरफा अपनी ओर से न केवल भारत से हाई कमिश्नर वापस बुला लिया बल्कि सभी प्रकार के व्यापारिक रिश्ते भी खत्म कर दिये। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि जब तक कश्मीर में अनुच्छेद 370 वापस नहीं लागू कर दिया जाता, भारत से कोई तिजारती रिश्ता कायम नहीं होगा।

गौरतलब है कि देश को अरबों डॉलर के कर्ज के लिए अक्सर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) या सऊदी अरब और चीन जैसे मित्र देशों से संपर्क करना पड़ रहा है। भारत के साथ व्यापार बंद होने से दूर देशों से सामान आयात करने में बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार यूज करना पड़ रहा है, जो पहले से ही काफी कम है। इन वजहों से पाकिस्तान भारत संग व्यापार के लिए छटपटा रहा है। हालांकि, भारत का रुख एकदम साफ है कि जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा, पाकिस्तान संग बातचीत समेत रिश्ते सामान्य नहीं होंगे।

मेष राशिः आज आपका दिन सुखद रहने वाला है। आज आपके लिए कोई जमीन या मकान खरीदने के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त करेंगे। आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आज आपको माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा। आज आपके ऊपर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिन्हें आप पूरा करेंगे। सभी लोग आपके द्वारा किए गए कार्यों से काफी खुश नजर आएंगे।

वृष राशिः आज आपका दिन उत्तम रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी छवि के अनुसार आपको परिणाम मिलेंगे। आज आप किसी से बात करते वक्त संयम रखें। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, तो उसे बढ़ाने के लिए थोडी और मेहनत करने की जरूरत है। आज कोई पड़ोसी आपसे किसी प्रकार की साहयता मांगेगा, जिसे आप असानी से पूरा करेंगे।

मिथुन राशिः आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप अपने कारोबार में किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आप समय-समय पर नया बदलाव करेंगे। इस दौरान आप घर में कोई लग्जरी आइटम खरीदेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको दूसरों से प्रेरणा लेकर काम करने की जरुरत है। आज बोलने से ज्यादा आपको काम पर ध्यान देना चाहिए।

कर्क राशिः आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आप माता-पिता से आप अपने मन की बातों को साझा करेंगे। आपका विनम्र स्वभाव साराहा जाएगा। आपका धन कहां खर्च हो रहा है। इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। आज आपको बेवजह की उलझन लेने से बचना चाहिए। छात्रों को आज किसी प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम हासिल होगा।

सिंह राशिः आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। आप अपने आप को काफी तरोताजा महसूस करेंगे, जिससे आप अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल होंगे। आज मित्रों की सहायता से आपको आय के अवसर मिलेंगे, जिनसे आप लाभ कमा कर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आज का दिन आनंद से भरा रहेगा, आप जिंदगी को पूरी तरह जिएंगे।

कन्या राशिः आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। परिवार का सहयोग मिलेगा और यह सीखेंगे की धन को कैसे बचा कर रखा जाता है, जिससे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। साथ ही आज आपके ऊपर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिन्हें आप पूरा करेंगे। सभी लोग आपके द्वारा किए गए कार्यों से काफी खुश नजर आएंगे।

तुला राशिः आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज उच्च वर्ग के लोगों से आपका संपर्क जुड़ेगा। आज किसी मित्र से कॉल पर बात होगी, पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। संतान पक्ष से सुखद अनुभूति होगी। माता-पिता आज बच्चों का पूरा सहयोग करेंगे। ऑफिस में किसी पर निर्भर होकर काम न करें। अपने लक्ष्य के प्रति डेडीकेशन ही आपको सफल बनायेगा।

वृश्चिक राशिः आज आपका दिन अनुकूल रहने वाला है। आज आप कोई नया कारोबार शुरू करने का मन बना सकते हैं। साथ ही बड़ों की सलाह लेना उचित रहेगा। इस राशि के डांस में रूचि लेने वाले लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचने का जल्द मौका मिलेगा। आज किसी विषय में ज्यादा न सोचें, वरना आपको उलझन होगी।

धनु राशिः आज आप महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहेंगे। आज किसी रिश्तेदार को दिए रुपए आपको वापस मिलेंगे। सोंचे हुए कार्यों में उनका इस्तेमाल करेंगे। मीडिया से जुड़े लोगों को आज अच्छा लाभ मिलेगा। प्राइवेट जॉब के लोगों को आज प्रमोशन से जुडी अच्छी खबर मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में आपसी लगाव बढेगा। आज आपको सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आज थोड़ी मेहनत से किसी बड़े फायदे का योग बन सकता है।

मकर राशिः आज आपका दिन बढिया रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा के छात्र अपनी तैयारी जम कर करें, जल्द अच्छे अंक हासिल होंगे। ऑफिस में फ़ोन का उपयोग कम करें, अन्यथा आपकी छवि ख़राब हो सकती है। बेवजह की भागदौड़ से आपको थकावट महसूस होगी। बच्चों के साथ आज मनोरंजन करके समय बिताएंगे। सरकारी विभाग से जुड़े लोगों का पद बढेगा।

कुंभ राशिः आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। नौकरी में आज आपको सुखद परिवर्तन नजर आएंगे। तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे अंक मिलेंगे, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। आज आपका स्वास्थ्य फिट एंड फाइन रहेगा। आपकी सभी उलझने आज समाप्त होंगी। कपडा व्यापारियों को आज अच्छा धन लाभ होगा। आज आप अपनी माता की मनपसन्द चीज़ लाकर गिफ्ट देंगे। बुजुर्गों का आज दान पुण्य के कार्यों में मन लगेगा।

मीन राशिः आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, आज आपकी पहले से चल रही द्वद्वद्व पूरी होगी। आज फैशन डिजाइनर्स का दिन बेहतर रहेगा। आज कोई ऑनलाइन बड़ा आर्डर आपको मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आपकी पारिवारिक स्थिति पहले से अनुकूल बनेगी। आज बेटे का रिजल्ट आ सकता है, रिजल्ट उनके पक्ष में होगा। आपके शत्रु परास्त्र होंगे। आज किसी कार्य में आपके विरोधी आपकी सलाह मागेंगे।

जीवन में रामत्व

ऋचा सिंह

श्रीराम को सनातन धर्म में विष्णु का अवतार माना गया है । लोग उनको भगवान और आराध्य मान कर पूजार्चन करते हैं । लेकीन जब हम राम के सम्पूर्ण जीवन का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि राम केवल पूजा के विषय नहीं हैं वह अनुकरणीय हैं हर स्थिति काल में जीवन को दिशा प्रदान करने वाले प्रेरणा पुंज हैं । ऐसा इसलिए क्योंकि राम ने स्वयं को एक राजा और भगवान के अवतार के रूप में नहीं अपितु जननायक के रूप में स्थापित किया। हम उनके संपूर्ण जीवन में देखते हैं कि कैसे उन्होंने कठिन स्थितियों में भी मर्यादा के नूतन आयाम स्थापित किए । राजकुल में जन्म लेने के बाद भी राम ने अपना जीवन राजसी वैभव में नहीं बिताया । उनका बाल्यकाल आश्रम में व्यतीत हुआ, गुरुकुल में वह राजकुमारों की भांति नहीं अपितु समान्य बालकों की भांति अपने और आश्रम के सारे कार्य करते थे । जब वह युवा हुए और राज्याभिषेक का समय आया तो उन्हें पिता के वचन के लिए वनगमन करना पड़ा । राम का जीवन मानवीय संबंधों के मार्गदर्शन में प्रेरणा देता आया है जिसके कारण वह लोक चेतना और परम्परा में सदैव जीवंत रहते हैं । जो लोक में व्याप्त है वह कालजयी है, वही सर्वमान्य है ,वही अनुकरणीय है, वही वंदनीय है। लोक परंपरा में भी हम पाते हैं कि जन्मोत्सव ,विवाह , हवन, कीर्तन, मांगलिक अयोजन आदि में महिलाएं जो मंगल गीत गाती हैं उसमें भी राम का नाम और उनका संबंध मूल्य ही समाहित है । ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो लोक के मन में हैं जो जन-जन के हृदय में बसते हैं । देखें तो राम ही त्यौहार हैं ,उल्लास हैं उत्सव हैं ,भक्ती हैं ,शक्ति हैं ,पूजा हैं ,ज्ञान हैं , प्रेरणा हैं और जीवन के प्रकाश स्तम्भ हैं । राम केवल जन-जन की भावना नहीं या सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भगवान राम तो जीवन जीने का तरीका है । फिर चाहे वह संबंध मूल्यों को निभाना हो धर्म के मार्ग पर चलना हो या फिर अपने दिए हुए वचन को पूर्ण करने के साथ कर्तव्य निर्वहन हो । राम सिर्फ कहने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है बल्कि हर मायने में वह एक उत्तम और आदर्श पुरुष है वह जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने वाले प्रकाश हैं । राम के जीवन आदर्शों को अनुकूल स्थिति में अपने आचरण में लाना जीवन को सरल और सहज बनाता है। राम का जीवन आदर्श, नैतिकता और व्यवहार का उच्चतम मापदंड है जो हर स्थिति में प्रासंगिक हैं । गुरु-शिष्य,राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक,पिता-पुत्र ,पति-पत्नी, भाई-भाई, मित्र-मित्र के आदर्शों के साथ धर्म नीति ,राजनीतिक, अर्थनीति के साथ सत्य, त्याग, सेवा, प्रेम, क्षमा, शौर्य, परोपकार, दान आदि मूल्यों का सुंदर, समन्वित आदर्श रूप राम के संपूर्ण जीवन में देखने को मिलता है। राम के जीवन के पुरुषोत्तम होने की विशेषताओं का संदर्भ रामायण में अनेक स्थानों पर देखने को मिलता है जिसका जीवन में अनुकरण करने पर समरसता पूर्ण समन्वित और खुशहाल व्यक्तित्व का निर्माण होता है । राम का जीवन इतना अदभुत और विशाल है कि उनके जीवन के प्रसंगों को बार-बार देखने और सुनने से भी मन नहीं भरता । आज ज्ञान, विज्ञान , तकनीकी ने कितनी भी प्रगति कर ली हो लेकिन जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर पाता है तब वह श्रीराम के जीवन आदर्शों में ही समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। राम तो प्रभु का अवतार थे लेकिन जब उन्होंने भी मानव शरीर में धरती पर जन्म लिया तब उन्हें भी सामाजिक, पारिवारिक, सांसारिक बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन राम ने हर स्थिति में स्थितप्रज्ञ होकर कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उनके जीवन में यह विशेष और अनुकरणीय है । राम का जीवन हर मानव के हृदय में मन मस्तिष्क में इसलिए बसा हुआ है क्योंकि उनकी कथाएं लोक में व्याप्त हैं । हजारों वर्षों से राम कथा का जतन एवं संवर्धन कलाओं के माध्यम से ,गीतों के माध्यम से, मंचन के माध्यम से आम जनमानस के बीच होता रहा है । देखा जाए तो लोक संस्कृति के विभिन्न प्रकारों में रामायण प्रदर्शित होता है जिसमें अपनी भिन्न-भिन्न परंपराएं,अपनी विशिष्ठ वेशभूषा , भाषा के साथ जन जीवन के कई आयाम देखने को मिलते हैं । जिससे जनमानस अपने आप को समृद्ध करता आया है । लोकमंगल की भावना में भी राम के जीवन की अनंत कहानियों द्वारा बच्चों में मूल्यों को रोपित करने की परम्परा चली आ रही हैं। राम के नाम के सहारे अनंत गीतों ,कहानियों, मनोभावों की जनमानस भावाभिव्यक्ति करता आया है। राम केवल लोगों की भावनाओं में समाए हुए देव नहीं है जिनके प्रति सिर्फ आस्था रखकर पूजा किया जाय बल्कि राम सही मायने में उत्तम पुरुष हैं जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं। राम का चरित्र ,आदर्श ,धर्म पालन ,नैतिकता और मानवीय संबंधों के मार्गदर्शन हमें सदैव प्रेरणा प्रदान करता आया है,इसीलिए जनजीवन हर आयाम में हर कलाओं में राम के जीवन को उनके आदर्शों को प्रकट करता रहा है। हम देखें तो राम का जीवन ही ऐसा है जो जनमानस से रिश्ता जोड़कर रखता है। श्रीराम के लिए समाज के सभी वर्ग समान थे, उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं था जैसा हम उनके जीवन में पाते हैं कि निषाद राज , केवट , शबरी माता, जटायु बानर सेना इसके उदाहरण हैं ।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

यूपीएससी : मप्र का बढ़ता ग्राफ

देश की अत्यंत प्रतिष्ठित और कठिन प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी में मप्र से 31 प्रतियोगी का चयन सफलता के बढ़ते ग्राफ की निशानी है। इनमें से भी 7 का चयन आईएएस के लिए हुआ है। इस परीक्षा में देश भर से कुल 1016 प्रतियोगी उत्तीर्ण हुए हैं। मप्र से भोपाल के अयान जैन ऑल इंडिया में 16 वें स्थान पर रहे हैं। मप्र से चयनित अभ्यर्थियों में से अधिकांश मप्र मूल के हैं। सफल अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा भोपाल से 12 अभ्यर्थी हैं। भोपाल के ही तेजस अग्निहोत्री को 27 वीं रैंक मिली है। इसके अलावा छाया सिंह की 63 वीं और ग्वालियर की माय को 84 वीं रैंक प्राप्त हुई है। परीक्षा परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश से सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हुए परीक्षार्थियों के घर पर उत्सव सा माहौल बन गया। लोग उनको बधाई देने पहुंचने लगे। सतना जिले में पदस्थ सब इंस्पेक्टर विजय सिंह कुशवाह की बेटी काजल सिंह ने प्रथम प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर 485वीं रैंक हासिल की है। खास बात यह लोक सेवकों के चयन की इस महत्वपूर्ण परीक्षा में समाज के निम्न मध्यम वर्ग, कमजोर और गरीब तबके के प्रतियोगी भी अपनी मेहनत से सफलता अर्जित कर रहे हैं। पहली बार भिलाला समाज की प्रतियोगी चयनित हुई है। इसका सीधा अर्थ यही है कि यूपीएससी से सिलेक्टेड प्रतिभागियों में सर्वसमावेशिता बढ़ी है। इस पर सम्पन्न वर्ग तथा बड़े शहरों का एकाधिकार नहीं रह गया है। यह सामाजिक समसरता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बुधवार को यूपीएससी के नतीजे घोषित होने के बाद प्रतिभागियों की मेहनत और समर्पण की प्रेरक कहानियां सामने आ रही हैं। यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों में उल्लेखनीय संख्या उनकी है, जो आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की संतानें हैं। इसे हम सीधे तौर पर परिवारवाद तो नहीं कह सकते, क्योंकि यूपीएससी में सिफारिश नहीं चलती । कड़ी मेहनत से ही अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होना होता है। अलबत्ता आला अफसर की संतान होने के नाते उन बच्चों को समय पर सही मार्गदर्शन और परिवार का सपोर्ट जरूर मिल जाता है, जो शायद दूसरे बच्चों को आसानी से नहीं मिल पाता। मसलन भोपाल की छाया सिंह ने 65वीं रैंक पाई है। छाया सिंह आईएएस अधिकारी छोटे सिंह की बेटी है। एक और उल्लेखनीय और दिलचस्पी कामयाबी दो सगे भाइयों का चयन है। भोपाल के दो सगे भाई सचिन गोयल और समीर गोयल का भी यूपीएससी में चयन हुआ है। सचिन गोयल की 209वीं और समीर गोयल की 222वीं रैंक आई है। इंदौर की आराधना चौहान की 251वीं रैंक आई है। उनके पिता वरदीप सिंह चौहान पूर्व अधिकारी हैं, तो मां रेखा गृहिणी। इसके अलावा यूपीएससी में महिलाएं लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। यूपीएससी महिला वर्ग में तेलंगाना की डोनुरू अनन्या रेड्डी महिलाओं में शीर्ष स्थान पर रहीं। अनन्या ने पहले ही प्रयास में यह परीक्षा पास की। यूपीएससी की टॉप टेन लिस्ट में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। महिला वर्ग में तेलंगाना की डोनुरू अनन्या रेड्डी ने टॉप किया। उन्होंने पहले ही प्रयास में ये परीक्षा पास की। उधर यूपी के अनिल प्रकाश मिश्रा के परिवार के चार सदस्यों ने यूपीएससी पास कर नया इतिहास रच दिया है। अनिल मिश्रा ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं। कुछ और सफल प्रत्याशियों के मां बाप छोटी मोटी नौकरी करते हैं या फिर ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऐसे बच्चों सीमित संसाधनों और कमजोर वर्ग के बच्चों की सफलता के पीछे उनकी अथक मेहनत, दृढ़ संकल्प और समर्पण है। निश्चय ही सफल प्रत्याशियों ने कड़े परिश्रम के बाद ही यह कामयाबी पाई है, लेकिन वो सेवा के दौरान अपने मूल्यों पर कितना कायम रहते हैं, यह देखने की बात है।

मतदान अनिवार्य करने के लिए विधेयक

आज मतदान करने वाले नागरिक के भी गिले शिकवे हैं। वह मतदान नहीं करने से कतरा रहा है। नागरिकों के भीतर मतदान से दूरी बना लेना देश हित में नहीं है। ऐसे नागरिक समाज की संख्या शहरी क्षेत्रों में बहुतायत में है। इनकी मतदान से अरुचि के कारण चाहे जो भी हों लेकिन मतदान में देश को ऐसे नागरिक कभी लाभ नहीं पहुंचाते। वे यह सोचते हैं कि सरकार चाहे जिसकी बने हमें क्या फायदा है? ऐसा भी सोचना उनका होता है कि अरे चुनाव में हमारे मतदान से क्या होने वाला है? हमारे वोट को कौन पूछता है? हमारे वोट न डालने से क्या होगा, सरकार जिसकी बननी है, बन ही जाएगी। दरअसल, ऐसे नागरिकों से देश कमजोर होता है। लोकतंत्र कमजोर होता है। अब समय आ गया है कि 'मतदान अनिवार्य विधेयक' लाया जाए। मतदान क्यों नहीं करेंगे आप? यदि देश के नागरिक हैं तो मतदान करना अनिवार्य होना ही चाहिए।

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

देश मतदान से गुजर रहा है। भारत के हर कोने में देश के नेतृत्व के सन्दर्भ में चर्चा है। हमारे देश की एक खुबसूरत बात यह है कि यह देश विविधता से भरा हुआ है। जो नागरिक संविधान में दिए गए मतदान हेतु आयु-सीमा को पार कर चुका है, सबको अपने मत का अधिकार है। यह मताधिकार नागरिक को उसके लिए यह चयन करने का अवसर प्रदान करता है कि वह अपने देश की बागडोर किसे सौंपना चाहता है। वह अपना देश किस तरह, किसके हाथों में सुरक्षित देख रहा है।

आज़ादी के बाद बहुत से चुनाव भारत में संपन्न हुए। सभी चुनाव से चुनाव आयोग और देश के नागरिक कुछ न कुछ सीखते हैं। चुनाव के बाद यह आंकलन करते हैं कि इस चुनाव में जो परिणाम आये हैं, उसमें क्या अच्छाइयाँ थीं और इसमें क्या कमी थी। बौद्धिक वर्ग प्रायः इसका आंकलन करता है। सरकारें बनने के बाद वह यह भी आंकलन करता है कि जिसे हमें चयन किया था उसने देश के लिए क्या किया और देश ने इनके नेतृत्व से क्या तरक्की पायी। यह स्वस्थ लोकतंत्र में ही संभव है। यह एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की अपनी खूबसूरती है कि वह चुनाव कराती है और देश की दिशा दृष्टिकोण तय करके वर्तमान का परिष्कार करती है और इससे ही देश जाना जाता है अपनी भौगोलिक क्षेत्र में। दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के आकलन भी देश की अपनी योजना, दृष्टि और क्रियान्वयन के आधार होते हैं। अंतरराष्ट्रीय महत्व की बहुत सी एजेंसीज हमारे सुशासन का बखान करती हैं और यदि देश में कुछ गलत होता है तो उसकी आलोचना करती हैं।

भारत में 2024 अपने देश के लिए एक नया अध्याय है जब देश में मतदान हो रहे हैं। विभिन्न पार्टियाँ अपने-अपने अनुसार देश को बेहतर बनाने का दावा करके आमजनता को रिझा रही हैं। मतदाता का अपना विवेक ऐसे में बहुत मायने रखता है। मतदाता विचार करके अपने मतदान का प्रयोग करे, यह ज़रूरी है। कहा गया है-बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताय। यह मतदान देश के भविष्य का निर्धारण करता है। यह मतदान देश को निर्णायक गतिशीलता प्रदान कर सकता है। इसलिए मतदान तो सदैव सोच-समझकर ही करने की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब

विभिन्न दल चुनाव में अपने-अपने घोषणा-पत्र के साथ चुनाव में जाते हैं तो उनके पास बहुतेरे ऐसे नारे, दावे, योजनाओं की अम्बार होते हैं, लेकिन वे सब कहीं भुलावे के लिए प्रयोग में तो नहीं लाया जा रहा है, इसे हर मतदाता को ध्यान देना चाहिए। पार्टियाँ चालबाज होती हैं। वे ऐसे-ऐसे तथ्यों को सामने रखती हैं जिससे किसी आम आदमी का कोई सरोकार नहीं होता। पार्टियाँ सोचती हैं जैसे तैसे, किसी भी प्रकार से वे मतदाताओं को अपने पक्ष में कर लें लेकिन यह एक भुलावा होता है। उनकी बातों में, उनके दावों में कोई सचाई नहीं होती। झूठ का व्यापार कोई इनसे सीखे।

नागरिक को खुद मौलिक होना चाहिए। उसकी सोच में मौलिकता होनी चाहिए। यह एक नैतिक नागरिक ही कर सकता है। किसी के बहलावे में आकर घूमता हुआ व्यक्ति अपनी मौलिकता इस कदर खो देता है कि वह खुद की कोई राय नहीं बना पाता। वह सिर्फ पार्टी की मंशा पर काम करता है। उसी के लिए झूठ, फरेब और षड्यंत्र की बलि खुद को चढ़ाता जाता है। यद्यपि एक मौलिक सोच वाला व्यक्ति देश का नागरिक होने के नाते किसी दल या पार्टी को वोट तो करेगा ही, लेकिन उसे वोट किसे करना है और किसे नहीं यह विवेक वह प्रयोग कर लेता है। वह अपने स्व को खोकर कोई मतदान नहीं करता। इसी वजह से कभी-कभी जो हम चुनाव के बाद अप्रत्याशित परिणाम देखते हैं, वे परिणाम आ पाते हैं। देश हित में वास्तव में एक मौलिक सोच वाला नागरिक ही कार्य करता है। वह देश का होता है। मतदान में जब देश होता है तो भी वह देश पहले देखकर मतदान करता है।

देश में मतदान जब होते हैं तो देश बड़ा होता है। मतदान उसकी मजबूती के लिए उसी तरह काम करते हैं जैसे एक स्वस्थ शरीर की कोशिकाएं अपनी मजबूती देकर देह को मजबूती देती हैं। मौलिकता देह के भीतर बहता हुआ रक्त है। रक्त ख़राब होने का अर्थ है कि शरीर ज्यादा दिन तक कम नहीं करेगी। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए जैसे शुद्ध रक्त की अवश्यकता होती है वैसे ही देश के स्वास्थ्य के लिए नैतिक, मौलिक, संवेदनशील नागरिक की आवश्यकता होती है। मतदान होने के बाद प्रायः एक चीख सुनाई देती है कभी उसको स्मरण करें कि वह सकारात्मक ज्यादा होती है कि नकारात्मक। यह सकारात्मकता और नकारात्मकता का जो शोर है उसे हम बाद में क्यों आमंत्रित करें। अच्छा तो यही है कि चुनाव में प्रतिभागिता करने से पूर्व विचार करके देश के लिए जो सकारात्मक है, उसी दिशा में अपना विचार बनाएं और देश के लिए मतदान करें। बाद में जो कोश्ने की आदत बनती जा रही है वह जंक की तरह होते हैं। वे देश के लिए सर्वदा हानिकारक ही होते हैं।

आज मतदान करने वाले नागरिक के भी गिले शिकवे हैं। वह मतदान नहीं करने से कतरा रहा है। नागरिकों के भीतर मतदान से दूरी बना लेना देश हित में नहीं है। ऐसे नागरिक समाज की संख्या शहरी क्षेत्रों में बहुतायत में है। इनकी मतदान से अरुचि के कारण चाहे जो भी हों लेकिन मतदान में देश को ऐसे नागरिक कभी लाभ नहीं पहुंचाते। वे यह सोचते हैं कि सरकार चाहे जिसकी बने हमें क्या फायदा है? ऐसा भी सोचना उनका होता है कि अरे चुनाव में हमारे मतदान से क्या होने वाला है? हमारे वोट को कौन पूछता है? हमारे वोट न डालने से क्या होगा, सरकार जिसकी बननी है, बन ही जाएगी। दरअसल, ऐसे नागरिकों से देश कमजोर होता है। लोकतंत्र कमजोर होता है। अब समय आ गया है कि 'मतदान अनिवार्य विधेयक' लाया जाए। मतदान क्यों नहीं करेंगे आप? यदि देश के नागरिक हैं तो मतदान करना अनिवार्य होना ही चाहिए। ऐसे नागरिकों को जो मतदान नहीं करते उनको चिन्हित करना ही होगा तभी देश में उसकी नागरिकता का मूल्य होगा।

कदाचित यह विधेयक अब तक आ जाना चाहिए था लेकिन हर बार चुनाव का वहिस्कार देश का एक बड़ा तबका कर रहा है, यह ठीक नहीं है। जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, अशक्त हैं जो वे अगर मतदान देने नहीं जा पाते, उनकी तो कोई छुट भी हो लेकिन जो जानबूझकर चुनाव में प्रतिभागिता नहीं कर रहा है, वह तो मतदान के लिए बाध्य किया जाना चाहिए भले ही वह नोटा का प्रयोग करके आ जाए। वह मतदान में प्रतिभागिता करने से यदि जी चुरा रहा है तो उसकी नागरिक होने या कहलाने पर भी सवाल है। ज्यादा पढ़े-लिखे लोग चुनाव से जी चुराते हैं, यह शर्म की बात है।

मतदान में देश जब अपने नागरिकों से अच्छी सरकार की अपेक्षा करता है तभी ऐसे मतदान में अरुचि दिखने वाले नागरिक देश को धोखा दे रहे होते हैं। ऐसे में 'अनिवार्य मतदान विधेयक' की अनिवार्यता यदि सरकार समझती है तो उसे सबके मताधिकार को देश के लिए तैयार करने हेतु यह विधेयक लाना ही चाहिए। श्रेष्ठ देश बनाने की अनिवार्यता यह भी होती है कि श्रेष्ठ नागरिक के नैतिक प्रतिबद्धताएं भी तय हों। केवल अधिकार के लिए लिए नागरिक नहीं होने चाहिए बल्कि कर्तव्य के लिए भी नागरिक तैयार होने चाहिए। मतदान में जब देश हो तो देश के नागरिकों का प्रथम कर्तव्य यही है कि वह मतदान में प्रतिभागिता करे।

अध्यात्म

विनम्रता से हारा अंहकार

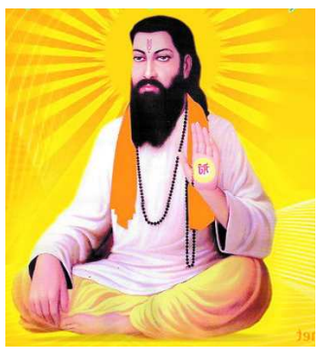

संत रविकुमार त्याग और वैराग्य का जीवन व्यतीत करते थे। वह निरंतर ईश्वर का स्मरण करते और संतो के साथ आध्यात्मिक चर्चाओं में लीं रहते थे। लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर-दूर से आते थे।

किन्तु संत रविकुमार इस लोकप्रियता के अहंकार से कोसो दूर अत्यंत विन्रम रहते थे। संत रविकुमार को आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त थी। एक बार संत रविकुमार से संत वर्मदेव मिलने आए।

संत वर्मदेव के पास पानी के ऊपर चलने की शक्ति थी। संत वर्मदेव को नहीं पता था कि संत रविकुमार के पास आकाश में उड़ने की शक्ति है। अहंकारवश संत वर्मदेव ने संत रविकुमार को नीचा दिखाने की सोची। उन्होंने संत रविकुमार से कहा - क्यों न हम झील के पानी के ऊपर चलते हुए आध्यात्मिक चर्चा करें।

संत रविकुमार उनके अहंकार वश संकेत को समझ गए। संत रविकुमार शांत भाव से बोले - आध्यात्मिक चर्चा अगर हम आज आकाश में भ्रमण करते हुए करें तो कैसा रहेगा ?

संत वर्मदेव समझ गए कि रविकुमार आकाश में उड़ने की शक्ति जानते हैं। संत वर्मदेव निरुत्तर हो गए। वर्मदेव जी, जो काम आप कर सकते हैं वो तो एक छोटी-छोटी से मछली भी कर सकती है और जो काम मैं कर सकता हूँ वो तो एक छोटी-सी मक्खी भी कर सकती है, लेकिन सत्य इस करिश्मेंबाजी से कोसों दूर है।

उसे तो विन्रम होकर खोजना पड़ता है। आपको और हमें जो शक्तियां प्राप्त हैं, वाज जनकल्याण के लिए हैं। इन शक्तियों का अंहकार करना उचित नहीं है।

संत वर्मदेव ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अहंकार को त्यागकर जनकल्याण के लिए निकल पड़े। वस्तुतः मै अथवा द्वैत के भाव का हम या अद्वैत भाव में विसर्जन ही ईश्वर की प्राप्ति का द्वार है।

कम मतदान होने का सच

लोकसभा चुनाव के पहले चरण के 102 स्थानों का लोकसभा चुनाव संपन्न होने के कई तरह के आकलन सामने आ रहे हैं। इस दौर में नौ राज्यों तमिलनाडु ,उत्तराखंड, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,नगालैंड, सिक्किम तथा तीन केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान, लक्षद्वीप और पुडुचेरी का मतदान संपन्न हो चुका है। हिंदी भाषी राज्यों के दृष्टि से देखे तो ऐसे 35 स्थान का चुनाव संपन्न हुआ है जिनमें बिहार के चार,मध्य प्रदेश के 6, राजस्थान के 12, उत्तर प्रदेश के आठ और उत्तराखंड के पांच स्थान शामिल हैं।

दक्षिण के राज्य तमिलनाडु के सभी 39 स्थानों पर मतदान संपन्न हो चुका है। माना जा रहा था कि देश के एक बड़े क्षेत्र में मतदान के बाद इसकी प्रवृत्तियों का आकलन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन मतदान के बाद आम टिप्पणी यही है कि प्रवृत्तियों का आकलन कठिन हुआ है। बहरहाल , इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर कहीं भी किसी तरह की हिंसा की घटना नहीं हुई। यह बताता है कि देश का चुनाव तंत्र बिल्कुल सहज, सामान्य और सुव्यवस्थित अवस्था में काम कर रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि हम कम अवधि और कम चरणों में भी लोकसभा चुनाव को समाप्त कर सकते हैं।

सबसे ज्यादा चर्चा मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर है और कई तरह के आकलन किया जा रहे हैं। हालांकि तथ्य नहीं है कि सभी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा गिरा है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में ज्यादा मतदान हुए तो बिहार और उत्तराखंड में अत्यंत कम। इन दो राज्यों में भी अलग-अलग क्षेत्र को देखें तो कहीं ज्यादा तो कहीं कम मतदान हुआ है। एक बार राज्य , मतदान प्रतिशत को देखें। उत्तर प्रदेश में 2019 के 63.88 के मुकाबले 60.25 प्रतिशत,उत्तराखंड में 61.88 प्रतिशत के मुकाबले 55.89 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 67.08 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 65.80 की जगह 67.56 प्रतिशत, राजस्थान में 63.71 की जगह 57.26 प्रतिशत, बिहार में 53.47 प्रतिशत की जगह 48.88 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 83.7 प्रतिशत की जगह 80.55 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 63.0 प्रतिशत की जगह 61.87 प्रतिशत तमिलनाडु के सभी 39 क्षेत्र में 69.46 प्रतिशत, असम में 78.23 प्रतिशत की जगह ,75.95 प्रतिशत, अरुणाचल में 67 प्रतिशत की जगह 72.74 प्रतिशत, मणिपुर में 78.20 प्रतिशत की जगह 72.117 प्रतिशत, मेघालय में 67.15 प्रतिशत की जगह 74.5 0 प्रतिशत, मिजोरम में 63.02 प्रतिशत की जगह 56.6 0 प्रतिशत, नागालैंड में 83.12 प्रतिशत की जगह 56.91 प्रतिशत, त्रिपुरा में 83.12 प्रतिशत की जगह 81.62 प्रतिशत, सिक्किम में 78.11 प्रतिशत की जगह 80.003 प्रतिशत, पुडुचेरी में 81.19 प्रतिशत की जगह 78.8 0 प्रतिशत, अंडमान निकोबार में 64.85 प्रतिशत की जगह 63.99 प्रतिशत, लक्षद्वीप में 84.96 प्रतिशत की जगह 83.88 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 57.35 प्रतिशत की जगह 68 प्रतिशत मतदान हुआ। तो एक-दो स्थान को छोड़कर ज्यादातर जगहों में मतदान गिरा है। उत्तर प्रदेश में 2019 के मुकाबले लगभग 5.30 प्रतिशत कम मतदान हुआ। सबसे अधिक 83.88 प्रतिशत मतदान लक्षद्वीप सीट पर तो बंगाल के जलपाईगुड़ी में 82.15 प्रतिशत मतदान हुआ। हिंसा के शिकार मणिपुर में मतदान कम नहीं माना जा सकता है। कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में 2019 में औसत मतदान 69.43 प्रतिशत से ज्यादा हुआ था। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह करीब 68.29 प्रतिशत है। यानी करीब 1.14 प्रतिशत कम मतदान हुआ है। तो राष्ट्रीय स्तर पर मतदान में ज्यादा गिरावट नहीं है । 2019 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान हुआ था। तो यह माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में इससे ज्यादा मतदान की संभावना शायद अभी नहीं है।

नागालैंड में इसलिए मतदान प्रतिशत ज्यादा गिरा क्योंकि छह जिलों में ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स फ्रंट (ईएनपीओ) ने अलग राज्य की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। इन छह जिलों के 20 विधानसभा क्षेत्रों में चार लाख से अधिक मतदाता हैं। जब इतनी संख्या में मतदाता मत डालेंगे नहीं तो उसे गिरना ही है। इसे मतदान की प्रवृत्ति नहीं मान सकते। करीब डेढ़ दशक पहले मतदान घटने का अर्थ सत्तारूढ़ घटक की विजय तथा बढ़ने का अर्थ पराजय के रूप में लिया जाता था और प्रायः ऐसा देखा भी गया। किंतु 2010 के बाद प्रवृत्ति बदली है। मतदान बढ़ने के बावजूद सरकारें वापस आई हैं और घटने के बावजूद गई है। इसलिए इसके आधार पर कोई एक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। दूसरे, हर जगह मतदान प्रतिशत ज्यादा गिर भी नहीं है। तीसरे, बंगाल में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्षों के मतदाताओं में एक दूसरे को हराने और जीताने की प्रतिस्पर्धा है।। संदेशखाली से लेकर अन्य मामलों के कारण वहां हिंदुओं के बड़े समूह के अंदर ममता बनर्जी को लेकर आक्रोश है।

सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की है तो जरा क्षेत्र के हिसाब से देखें कि कहां कितना मतदान हुआ। सहारनपुर में पिछली बार 70.87 प्रतिशत हुआ था जबकि इस बार 68.99 प्रतिशत, पीलीभीत में 67.41 की जगह 63.70, मुरादाबाद में 65.46 की जगह 62.05, कैराना में 67.45 की जगह 61.5 , नगीना में 63.66 की जगह असर दशमलव 54, मुजफ्फरनगर में 80.42 की जगह 58.5, बिजनौर में 66.022 की जगह 58.21 और रामपुर में 63.01 की जगह 55.75 प्रतिशत मतदान हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में मतदान प्रतिशत घटना सामान्य स्थिति का परिचायक नहीं है। इस क्षेत्र को जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का विशेषण प्राप्त है। तो यह आकलन करना कठिन है कि जहां मतदान प्रतिशत गिरा वहां किनके मतदाता नहीं आए। पिछले चुनाव में भाजपा के लिए यह चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था तथा बसपा सपा ने उसे गंभीर चुनौती दी थी। भाजपा को केवल तीन स्थान मिले थे जबकि बसपा को तीन और सपा को दो। अगर भाजपा विरोधी उसे हराना चाहते थे तो उन्हें भारी संख्या में निकलना चाहिए। कहा भी जा रहा है कि सपा के कोर मतदाता यानी मुसलमान और यादवों का बड़ा समूह आक्रामक होकर मतदान कर रहा था।। विरोधी भारी संख्या में निकलेंगे तो समर्थक भी इसका ध्यान रखेंगे। हालांकि उम्मीदवारों के चयन, दूसरे दलों से आये लोगों को महत्व मिलने तथा कहीं -कहीं, गठबंधन को लेकर भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष है तथा एक जाति विशेष ने भी विरोधात्मक रूप अख्तियार किया था। बावजूद यह कहना कठिन होगा कि भाजपा समर्थक मतदाता ही ज्यादा संख्या में नहीं निकले। अभी तक की प्रवृत्ति इसका संकेत नहीं देती। समर्थक कार्यकर्ता थोड़ा असंतुष्ट हों तो इसका असर होता है किंतु विरोधी तेजी से हराने के लिए निकले और इसके बावजूद वो प्रतिक्रिया न दें इस पर विश्वास करना कठिन होता है।

अभी तक के चुनाव अभियान में जनता के उदासीनता दिखी है। हालांकि विपक्ष के प्रचार के विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर आम जनता के अंदर कहीं व्यापक आक्रोश या भारी विरोधी रुझान बिल्कुल नहीं दिखा है। कल्याण कार्यक्रमों के लाभार्थी तथा विकास नीति की प्रशंसा करने वाले हर जगह दिखाई देते हैं । श्री रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा से लेकर समान नागरिक संहिता एवं नागरिकता संशोधन कानून आदि पर विपक्ष के रवैये ने भाजपा के समर्थकों और मतदाताओं में प्रतिक्रिया भी पैदा की है। आम प्रतिक्रिया यही है नरेंद्र मोदी को ही होना चाहिए। लोग अगर वोट डालते समय यह विचार करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है तो वो किसका समर्थन करेंगे? कार्यकर्ताओं नेताओं और समर्थकों के एक समूह के थोड़ा असंतोष का कुछ असर हो सकता है। हालांकि जिनके अंदर असंतोष है उनमें भी यह भाव है कि अगर यह सरकार हार गई तो कहा जाएगा कि हिंदुत्व विचारधारा की हार हो गई है। जिस जाति के विद्रोह की चर्चा हो रही है वहां भी लोगों के अंदर भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सहानुभूति का भाव दिखता है। इसलिए यह मानने में भी कठिनाई है कि इन्होंने बिल्कुल एक मस्त आक्रामक होकर भाजपा के विरोध में मतदान किया होगा। ऐसा होने का अर्थ मतदान बढ़ना होना चाहिए। मतदान कम होने को भाजपा विरोधी रचन का संकेत मानना उचित नहीं होगा।

आज का कार्टून

राशिफल

मेष

अपनी कार्यशैली में बदलाव कर सकते हैं। पारिवारिक विवाद हल होने के योग बन रहे हैं। शत्रु आपके सामने मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं।

वृषभ

रिश्तेदारों पर आपको ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिये। पैतृक व्यवसाय में आप काफी ध्यान देने वाले हैं। सेहत को लेकर आप थोड़ा सतर्क रहें।

मिथुन

कार्यक्षेत्र का वातावरण अनुकूल रहेगा। बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखें। मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे। अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकता है।

कर्क

आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पढ़ाई में बच्चों का शानदार प्रदर्शन रहेगा। रोजगार में आप बदलाव कर सकते हैं। विचारों में सकारात्मकता बनाये रखें।

सिंह

आज का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। बुजुर्गों के विचारों का सम्मान करें। गुरु तुल्य लोगों का मार्गदर्शन मिल सकता है। क्रोध और आवेश से बचना चाहिये।

कन्या

नया व्यवसाय शुरू करने का विचार बनायेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जीवनसाथी का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ायेगा।

तुला

आज अपने क्रोध पर नियन्त्रण रखें। पुराने कर्जों को चुकाने का दबाव रहेगा। एकान्त के आपको समय नहीं बिताना चाहिये। सोचे हुये कार्य देरी से पूर्ण होंगे।

वृश्चिक

जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें। घर का माहौल सकारात्मक रखने का प्रयास करें। व्यापार में नकदी की समस्या दूर होगी।

धनु

परिवार में उत्सव का वातावरण रहेगा। आपको किसी विशेष कार्य के लिये सम्मानित किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतरीन रहेगी। आप आज कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे।

मकर

गैरकानूनी कार्यों से आपको बचना चाहिये। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार में उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों के साथ मनोरञ्जन भरा समय व्यतीत करेंगे। मन में विकृत विचार जन्म लेंगे।

कुंभ

व्यक्तिगत समस्याओं को दूसरों से ज्यादा शेयर न करें। सन्तान के करियर को लेकर कुछ चिन्ता रहेगी। ऑनलाइन लेन-देन सावधानी पूर्वक करना चाहिये।

मीन

व्यापार में रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा। जीवनसाथी के व्यवहार से आपका मन प्रसन्न रहेगा। सभी काम योजना बनाकर करें तो आपको लाभ मिलेगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चीनकी कुटिलता

चीन अपनी कुटिलतापूर्ण हरकतोंसे बाज नहीं आ रहा है। एक ओर तो वह एलएसीपर तनाव बढ़ाकर पाकिस्तानअधिकृत कश्मीरमें सड़क निर्माणमें जुटा है, वहीं दूसरी ओर विश्वके देशोंकी गतिविधियोंपर नजर रखनेके लिए अन्तरिक्षमें जासूसी सेटेलाइटोंका जाल बिछा रहा है और समुद्री गतिविधियोंकी निगरानीके लिए जगह-जगह अपने जासूसी पोतोंको तैनात कर विश्वकी चिन्ता बढ़ा रहा है। मालदीवमें चीनी समर्थित मोहम्मद मुइज्जूकी सरकार बनते ही चीनी ऐजेण्डेपर काम शुरू हो गया है। मालदीवमें उच्च तकनीकसे युक्त चीनी समुद्री जहाज जियांग यांग होंग-०३ पुन: वापस लौट आया है। यह वही जहाज है जो पहले भी चीनसे मालदीव पहुंचा था और भारतने हिन्द महासागरमें इसको लेकर एतराज किया था लेकिन मालदीवकी मोहम्मद मोइज्जूकी सरकारने इसे दरकिनार कर दिया। इसपर जासूसी जहाज होनेका आरोप लगता रहा है। पूर्वमें भारतने श्रीलंकापर दबाव डालकर इसी जहाजको कोलम्बो पोर्टपर रुकनेसे मना करा दिया था। मालदीव भारतके पश्चिमी समुद्र तटसे करीब तीन सौ नाटिकल मील दूर है, वहीं लक्षद्वीप समूहके मिनिकाय द्वीपसे महज ७० नाटिकल मीलकी दूरीपर है। हिन्द महासागर क्षेत्रमें वाणिज्यिक समुद्री मार्गोंका केन्द्र होनेकी वजहसे इस जगहका अपना अलग ही सामरिक महत्व है। भौगोलिक रूपसे मालदीवकी स्थिति भारतके लिए और वैश्विक व्यापारके लिए बेहद अहम है। यह हिन्द महासागरके हिस्सेमें है, जहांसे वैश्विक शिपिंग लाइनें गुजरती हैं। इस क्षेत्रमें चीनकी कुटिल निगाहें बराबर बनी हुई हैं। हालांकि हिन्द महासागर क्षेत्रमें मालदीव भारतका अहम सहयोगी रहा लेकिन मालदीवमें चीन समर्थक मुइज्जूकी पार्टीकी जीतके बाद फिरसे बीजिंग और मालदीवकी नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। मुइज्जूके चीन दौरेके २४ घण्टेके अन्दर चीनके इस जहाजकी मालदीवमें तैनाती चिन्ता बढ़ानेवाली है। हालांकि भारत और अमेरिकाने इसका विरोध किया है लेकिन मुइज्जू सरकारने इसका खुलासा नहीं किया है कि जासूसी जहाजके मालदीवमें तैनातीका कारण क्या है। भारत और मालदीवके बीच रिश्तोंमें आयी खटासका चीन भरपूर फायदा उठा रहा है। हालांकि भारतकी नजर लगातार चीनपर बनी हुई है। भारतको सतर्कता बढ़ानेके साथ चीनके दुस्साहसका जवाब देनेके वैश्विक लिए रणनीति बनानी होगी और चीनपर दबाव बनाना होगा।

मतदानमें गिरावट चिन्तनीय

देशके १८वीं लोकसभा चुनावमें मतदानका प्रतिशत अपेक्षासे काफी कम होना स्वस्थ लोकतंत्रके लिए शुभ संकेत नहीं है। दूसरे चरणमें १३ राज्योंकी ८८ सीटोंपर शुक्रवारको ६१ प्रतिशत मतदान हुआ जो मतदानके प्रति मतदाताओंकी उदासीनताको दर्शाता है। पहले चरणमें १९ अप्रैलको २१ राज्योंकी कुल १०२ सीटोंके लिए हुए मतदानमें ६३.२९ प्रतिशत मतदाताओंने अपने मताधिकारका उपयोग किया था। पहले चरणकी अपेक्षा दूसरे चरणमें जहां मतदानका प्रतिशत बढ़ना चाहिए था वहीं इसमें आयी गिरावट अत्यन्त चिन्ताका विषय है। पहले चरणमें मतदाताओंकी उदासीनतापर केन्द्र सरकार और चुनाव आयोगने चिन्ता जतायी थी और मतदाताओंको जागरूक करनेके लिए विभिन्न स्तरोंपर प्रयास भी किये गये। यहांतककी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सर्वोच्च न्यायालयके प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़को भी मतदानके लिए अपील करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी मतदाताओंकी बेरुखी यथावत बनी रही। इसके पीछेके कारणोंकी समीक्षा करनेकी जरूरत है। इस लोकसभा चुनावमें राजनीतिक दलोंके शीर्ष नेताओं और प्रत्याशियोंके हमलावर बिगड़े बोलमें जिस तरह अशोभनीय और अमर्यादित भाषाओंका प्रयोग किया जा रहा है वैसा पूर्वमें कभी नहीं हुआ था। मतदानमें कमीका एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है। दूसरा प्रमुख कारण इण्डिया गठबन्धनके नेताओंकी स्वार्थपरक नीतियां हैं जिसका खामियाजा जनता पहले भी भुगत चुकी है। जब गठबन्धनकी सरकारमें पांच सालमें चार प्रधान मंत्री बने। इस बार तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए पांच प्रधान मंत्रीकी गूंज सुनायी दे रही है। ऐसी स्थितिमें यदि इनकी सरकार बन भी गयी तो वह कितनी स्थिर होगी और देश तथा जनताके हितमें कितना काम करेगी, यह यक्ष प्रश्न मतदाताओंको प्रभावित कर रही है। फिर भी मजबूत लोकतंत्रके लिए हर नागरिकको अपने बुद्धि और विवेकसे अपने मताधिकारका उपयोग करना चाहिए। लोकतंत्रके महापर्वमें यह मतदाताओंकी परीक्षाकी घड़ी है और उम्मीद की जाती है कि शेष पांच चरणोंमें मतदानका प्रतिशत बढ़ेगा।

लोक संवाद

गर्मीके कहरसे प्रभावित चुनाव

महोदय,-राजस्थान जैसे रेगिस्तानी राज्यमें पारा ४५ सैल्सियसतक पहुंच गया है। दूसरे चरणका मतदान ८९ लोकसभा सीटोंके लिए हुआ और मौसम विभागने ईवीएमके कामकाजको प्रभावित करनेके अलावा ३० से अधिक सीटोंपर लूकी स्थितिकी भविष्यवाणी की है, जो भारतके चुनाव आयोगके लिए चिंताजनक हो सकती है। विवाह समारोहोंको संपन्न करनेके लिए अनुकूल तिथियोंमें परम्परा और विश्वासको देखते हुए, मईका महीना २, ४, ८, १०, ११, १५, १६, २०, २१, २२ सहित शुभ दिनों (शुभ मुहर्त) से भरा हुआ है। २७, २९, ३० और १ जून, जिसके बाद पांच महीनेकी अशुभ अवधि नवंबर २०२४ तक बढ़ जायगी। ज्योतिषियोंके अनुसार, गुरु उदय २९ अप्रैलसे शुरू होगा और लोग अप्रैल और मईमें विवाहका आयोजन कर सकते हैं जिसमें मतदानकी दो तारीखें २० मई (पांचवां चरण) और १ जून (मतदानका अंतिम चरण) शामिल हैं। उनका मानना है कि खरमास १४ अप्रैलको समाप्त हो गया है, जिसके बाद १५ दिनोंका अंतराल आता है। उनका तर्क है कि अप्रैल २०२३ बृहस्पतिकी चालके कारण विवाह समारोहोंके लिए एक बुरा समय था। यह एक स्थापित तथ्य है कि संबंधित परिवार एक वर्ष या उससे अधिक पहलेसे शादीकी योजना बनाते हैं। निर्वाचन आयोगके अधिकारियोंके अनुसार इन व्यस्तताओं और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय कार्योंके मद्देनजर सात चरणके मतदानकी तारीखोंको अंतिम रूप दिया गया है, लेकिन कई बार थकान अगले कुछ दिनोंमें मतदान करनेके इरादेपर हावी हो सकती है। विशेषज्ञ इस बातपर एकमत हैं कि २०१४ की मोदी लहर और २०१९ के राष्ट्रवादके बवंडरके विपरीत, पहले चरणके मतदानके दौरान भाजपाके पक्षमें लहर गायब थी, हालांकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीने कोई कसर नहीं छोड़ी। गठबंधन द्वारा निर्धारित ४०० सीटोंके लक्ष्यको हासिल करनेके लिए अभियानकी गतिको बनाये रखनेमें कोई कसर नहीं छोड़ी गयी। ३९ सीटोंवाले तमिलनाडुमें २०१९ में ७२.४ प्रतिशतके मुकाबले ६७.२ प्रतिशत मतदान हुआ और राजस्थानमें भी मतदान ६४ प्रतिशत (२०१९) से घटकर २०२४ में ५७.३ प्रतिशत हो गया। पश्चिम बंगालमें मतदान ७२ प्रतिशत दर्ज किया गया और यहां तीनसे चार प्रतिशतकी गिरावट आयी। भाजपा-प्रभुत्व वाले पूर्वोत्तर राज्योंमें भारी मतदान हुआ, जिनमें मेघालयमें ७४.५ प्रतिशत, मणिपुरमें ६९.२ प्रतिशत, असममें ७२.३ प्रतिशत, अरुणांचल प्रदेशमें ६७.७ प्रतिशत और छोटे राज्य त्रिपुरामें ८०.६ प्रतिशत मतदान हुआ। भाजपाके पास राजस्थान और मध्य प्रदेशमें मतदान प्रतिशतमें गिरावटपर चिंतित होनेका तर्क है, जहां वह मजबूत है और दोनों राज्योंपर शासन कर रही है। अग्निवीर योजनाका सीधा नकारात्मक असर राजस्थानपर पड़नेके साथ ही किसानोंके आन्दोलनका भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञोंका कहना है कि मतदानमें गिरावटकी तुलना करनेपर राजस्थानके गंगानगर, जो कि कृषि आन्दोलनके केंद्रीय केंद्रोंमेंसे एक है और झुंझुनू जैसे स्थानोंमें उल्लेखनीय कमी आयी है, जहां महत्वाकांक्षी युवाओंका एक महत्वपूर्ण हिस्सा अग्निपथ योजनासे मोहभंग व्यक्त कर रहा है। कार्यक्रमके अनुसार ७ मईको ९४ सीटोंके लिए तीसरा चरण, १३ मईको ९६ सीटोंके लिए चौथा तथा ४९ सीटोंके लिए पांचवां चरण २० मईको होगा। २५ मईको ५७ सीटोंपर छठे चरण और १ जूनको ५७ सीटोंपर अंतिम चरणका मतदान होगा। राजनीतिक पर्यवेक्षकोंका कहना है कि २०१४ में मोदी लहर चली क्योंकि मतदाता भ्रष्टाचारमें डूबी यूपीए सरकारसे तंग आ चुके थे इसलिए वे इससे छुटकारा पाना चाहते थे। चुनावोंसे संबंधित एक दिलचस्प घटनाक्रममें भारत सरकारने चुनावोंकी निगरानीके लिए विदेशोंसे २० राजनीतिक दलोंको आमंत्रित किया है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिकाके प्रतिष्ठित नागरिक समाज संस्थानोंको उनके स्वयंके चुनावोंका हवाला देते हुए बाहर रखा गया है, जो छह महीने दूर हैं। आलोचकोंका कहना है कि भारत कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता इसलिए नेपाल, बंगलादेश, वियतनाम, युगांडा, तंजानिया, मॉरीशस आदि मित्र देशोंको आमंत्रित किया गया है। विशेषज्ञोंका कहना है कि टिप्पणीकार और विश्लेषक मतदान प्रतिशतमें गिरावट और बाकी चरणोंमें भी इस गिरावटके जारी रहनेकी संभावनाके विभिन्न कारकोंको बता रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचारमें तेजी आ सकती है जिससे राजनीतिकी गतिशीलता और चुनाव नतीजे बदल भी सकते हैं। -**के.एस. तोमर, वाया ईमेल।**

गम्भीर चुनौती बना महंगा चुनाव

विश्वके सबसे बड़े लोकतंत्र भारतके लोकसभा चुनाव २०२४ अनेक दृष्टियोंसे यादगार एवं ऐतिहासिक होनेके साथ अबतकका विश्वका सबसे खर्चीला चुनाव है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजकी रिपोर्टके अनुसार चुनावी खर्च एक लाख बीस हजार करोड़ रुपयेके खर्चके साथ दुनियाका सबसे महंगा चुनाव होनेकी ओर अग्रसर है।

❑ **ललित गर्ग**

वर्ष २०१९ के लोकसभा चुनावके खर्चकी तुलनामें इस बार दुगुना खर्च होगा। चुनाव प्रक्रिया अत्यधिक महंगी एवं धनके वर्चस्ववाली होनेसे राजनीतिक मूल्योंका विसंगतिपूर्ण एवं लोकतंत्रकी आत्माका हनन होना स्वाभाविक है। चुनाव जनतंत्रकी जीवनी शक्ति है। यह राष्ट्रीय चरित्रका प्रतिबिम्ब होता है। जनतंत्रके स्वस्थ मूल्योंको बनाये रखनेके लिए चुनावकी स्वस्थता, पारदर्शिता, मितव्ययता और उसकी शुद्धि अनिवार्य है। चुनावकी प्रक्रिया गलत होनेपर लोकतंत्रकी जड़े खोखली होती चली जाती हैं। करोड़ों रुपयेका खर्चीला चुनाव, अच्छे लोगोंके लिए जनप्रतिनिधि बननेका रास्ता बन्द करता है और धनबल एवं धंधेबाजोंके लिए रास्ता खोलता है। इन चुनावोंमें अर्थका अनुचित एवं अतिशयोक्तिपूर्ण खर्चका प्रवाह जहां चिन्ताका कारण बन रहा है, वहीं समूची लोकतांत्रिक प्रणालीको दूषित करनेका सबब भी बन रहा है। इस तरहकी बुराई एवं विकृतिको देखकर आंख मूंदना या कानोंमें अंगुलियां डालना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके विरोधमें व्यापक जनचेतनाको जगाना जरूरी है। यह समस्या या विकृति किसी एक देशकी नहीं, बल्कि दुनियाके समूचे लोकतांत्रिक राष्ट्रोंकी समस्या है।

अट्ठारहवीं लोकसभा चुनावमें हर राजनीतिक दल अपने स्वार्थकी बात सोच रहा है तथा येन-केन-प्रकारेण ज्यादासे ज्यादा वोट प्राप्त करनेकी अनैतिक तरकीबें निकाल रहा है। एक-एक प्रत्याशी चुनावका प्रचार-प्रसार करनेमें करोड़ों रुपयोंका व्यय करता है। यह धन उसे पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, राजनीतिक दलों एवं प्रायोजकोंसे मिलता है। चुनाव जीतनेके बाद वे उद्योगपति उनसे अनेक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इसी कारण सरकार उनके अनुचित दबावके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा पाती और अनैतिकता एवं आर्थिक अपराधकी परम्पराको सिंचन मिलता रहता है। यथार्थमें देखा जाय तो जनतंत्र अर्थतंत्र बनकर रह जाता है, जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा, वह उतने ही अधिक वोट खरीद सकेगा। लेकिन इस तरह लोकतंत्रकी आत्माका ही हनन होता है, इस सबसे उन्नत एवं आदर्श शासन प्रणालीपर अनेक प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज रिपोर्टके मुताबिक आम तौरपर चुनाव अभियानके लिए धन अलग-अलग स्रोतोंसे अलग-अलग तरीकोंसे उम्मीदरवारों और राजनीतिक दलोंके पास आता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारोंको चुनाव खर्चके लिए मुख्य रूपसे रियल इस्टेट, खनन, कारपोरेट, उद्योग, व्यापार, ठेकेदार, चिटफण्ड कम्पनियां, ट्रांसपोर्टर, परिवहन ठेकेदार, शिक्षा उद्यमकर्ता, एनआआई, फिल्म, दूरसंचार जैसे प्रमुख स्रोत है। इस साल डिजिटल मीडिया द्वारा प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक दल पेशेवर एजेंसियाकी सेवाएं ले रहे हैं। इनसे सबसे अधिक राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार अभियान, रैली, यात्रा खर्चके साथ-साथ सीधे तौरपर गोपनीय रूपसे मतदाताओंको सीधे नकदी, शराब, उपहारोंका वितरण भी शामिल है। देशमें १९५२ में हुए पहले आम चुनावकी तुलनामें २०२४ में ५०० गुणा अधिक खर्च होनेका अनुमान है। प्रति मतदाता छह पैसेसे बढ़कर आज ५२ रुपये खर्च होनेका अनुमान है। हालांकि रिपोर्टके मुताबिक चुनावमें होनेवाले वास्तविक खर्च और अधिकारिक तौरपर दिखाये गये खर्चेमें काफी अंतर है। रिपोर्टके मुताबिक २०१९ के लोकसभा चुनावमें देशके ३२ राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों द्वारा आधिकारिक तौरपर सिर्फ २,९९४ करोड़ रुपयेका खर्च दिखाया। इनमें दिखाया गया कि राजनीतिक दलोंने ५२९ करोड़ रुपये उम्मीदवारोंको चुनाव लड़नेके लिए दिये थे। रिपोर्टके मुताबिक चुनावमें राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन आयोगमें पेश खर्चका ब्यौरा और वास्तविक खर्चके साथ-साथ उम्मीदवारों द्वारा अपने स्तरपर किये जा रहे खर्चेमें काफी अंतर है। अमेरिकी चुनावपर नजर रखनेवाली एक वेबसाइटके रिपोर्टका हवाला देते हुए, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजके अध्यक्ष एन भास्कर रावने कहा कि यह २०२० के अमेरिकी चुनावोंपर हुए खर्चके लगभग बराबर है, जो १४.४ बिलियन डालर यानी एक लाख २० करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि दूसरे शब्दोंमें कहें तो भारतमें २०२४ में दुनियाका सबसे बड़ा चुनाव अबतकका सबसे महंगा चुनाव साबित होगा। भारतमें होनेवाले चुनावमें हो रहे बेसुमार खर्चकी तपीश समूची दुनियातक पहुंच रही है। समूची दुनियाके तमाम देशोंमें भारतके चुनावको न केवल दम साध कर देखा जा रहा है, बल्कि इन चुनावके खर्चों एवं लगातार महंगे होते चुनावकी चर्चा भी पूरी दुनियामें व्याप्त है। लोकसभा चुनावमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस आदि दलों एवं उनके उम्मीदावारोंने मतदाताओंको प्रभावित करनेके लिए तिजोरियां खोल दी है। यह चुनाव राष्ट्रीय मसलोंके मुकाबले राजनीतिक दलोंके हित सुरक्षित रखनेके वादेपर ज्यादा केंद्रित लग रहा है और टकरावके मुद्दे थोड़े ज्यादा तीखे हैं। लेकिन यदि मुद्दोंसे इतर अभियानोंकी बात करें तो यह खबर ज्यादा ध्यान खींच रही है कि इस बार चुनाव अबतकके इतिहासमें सबसे खर्चीला साबित होने जा रहा है। इस चुनावोंके अत्यधिक खर्चीले होनेका असर व्यापक होगा। चुनावके तवेको गर्म करके अपनी रोटियां सेंकनेकी तैयारीमें प्रत्याशी वह सब कुछ कर रहे हैं, जो लोकतंत्रकी बुनियादको खोखला करता है। काफी लम्बे और जटिल प्रक्रियाके तहत चलनेवाले चुनावमें जनताके बीच समर्थन जुटानेके लिए उम्मीदरवार जितने बड़े पैमानेपर अभियान चलाते हैं, उसमें उन्हें स्थानीय कार्यकर्ताओंसे लेकर सामग्रियों और जनसंपर्कोंतकके मामलेमें कई स्तरोंपर खर्च चुकाने पड़ते हैं। यूं किसी भी देशमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाके तहत होनेवाले चुनावोंमें ऐसा ही होता है, लेकिन भारतमें इसी कसौटीपर खर्चमें कई गुना ज्यादा होना चिन्ताका सबब बनना चाहिए। दुनियाकी आर्थिक बदहाली एवं युद्धकी विभीषिकासे चौपट काम-धंधों एवं जीवन संकटमें लोकसभाके चुनाव कहां कोई आदर्श प्रस्तुत कर पा रहे हैं। इस बातका अंदाजा इसी बातसे लगाया जा सकता है, जो लोग चुनाव जीतनेके लिए इतना अधिक खर्च कर सकते हैं तो वे जीतनेके बाद क्या करेंगे, पहले अपनी जेबको भरेंगे, अर्थव्यवस्थापर आर्थिक दबाव बनायेंगे और मुख्य बात तो यह है कि यह सब पैसा आता कहांसे है। कौन देता है इतने रुपये। धनाढ्य अपनी तिजोरियां तो खोलते ही है, कई कम्पनियां हैं जो इन सभी चुनावी दलों एवं उम्मीदवारोंको पैसे देती है, चंदेके रूपमें। चन्दाके नामपर यदि किसी बड़ी कम्पनीने धन दिया है तो वह सरकारकी नीतियोंमें हेरफेर करवा कर लगाये गये धनसे कई गुणा वसूल लेती है। इसीलिए वर्तमान देशकी राजनीतिमें धनबलका प्रयोग चुनावमें बड़ी चुनौती है। सभी दल पैसेके दमपर चुनाव जीतना चाहते हैं, जनतासे जुड़े मुद्दों एवं समस्याओंके समाधानके नामपर नहीं। कोई भी ईमानदारी और सेवाभावके साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। राजनीतिके खिलाड़ी सत्ताकी दौड़में इतने व्यस्त है कि उनके लिए विकास, जनसेवा, सुरक्षा, महामारियां, युद्ध, आतंकवादकी बात करना व्यर्थ हो गया है। सभी पार्टियां जनताको गुमराह करती नजर आती है। सभी पार्टियां नोटके बदले वोट चाहती है। राजनीति अब एक व्यवसाय बन गयी है। सभी जीवन मूल्य बिखर गये है, धन तथा व्यक्तिगत स्वार्थके लिए सत्ताका अर्जन सर्वोच्च लक्ष्य बन गया है। लोकसभा चुनावकी सबसे बड़ी विडम्बना एवं विसंगति है कि यह चुनाव आर्थिक विषमताकी खाईंको पाटनेकी बजाय बढ़ानेवाले साबित होने जा रहे हैं। आखिर कबतक चुनाव इस तरहकी विसंगतियोंपर सवार होता रहेगा।

वर्तमानमें धनबलका प्रयोग चुनावमें बड़ी चुनौती है। सभी दल पैसेके दमपर चुनाव जीतना चाहते हैं, जनतासे जुड़े मुद्दों एवं समस्याओंके समाधानके नामपर नहीं। सभी पार्टियां जनताको गुमराह करती नजर आती है। राजनीति अब एक व्यवसाय बन गया है। सभी जीवन मूल्य बिखर गये है, धन तथा व्यक्तिगत स्वार्थके लिए सत्ताका अर्जन सर्वोच्च लक्ष्य बन गया है। लोकसभा चुनावकी सबसे बड़ी विडम्बना है कि यह चुनाव आर्थिक विषमताकी खाईंको पाटनेकी बजाय बढ़ानेवाले साबित होने जा रहे हैं। आखिर कबतक चुनाव इस तरहकी विसंगतियोंपर सवार होता रहेगा।

आधुनिक सभ्यतामें सूखा आनन्द रस

मानवीय जीवन मूल्योंपर संकट है। इतिहासके किसी अन्य कालखण्डमें इस तरहका मानवीय संकट नहीं था। समाचार माध्यम भी कब विश्वयुद्धकी आशंकाकी बातें करते हैं। विचार भी अपना प्रभाव खो रहे हैं।

❑ **हृदयनारायण दीक्षित**

विचार ही मनुष्य जातिके वाह्य स्वरूप और आंतरिक उदात्त भावके प्रसारक रहे हैं। विचार भी अपना प्रभाव खो रहे हैं। मानवीय सभ्यता आधुनिक कालका मनुष्य विरोधी प्रेरक तत्व बन गयी है। वातावरणमें निश्चिन्तता नहीं है। संदेह और अनिश्चितताका वातावरण है। मनुष्य जाति भविष्यके भयसे डरी हुई है। धनका प्रभाव और धनका अभाव दोनों ही मारक हैं। मानवताका बड़ा भाग पर्याप्त भोजनसे वंचित है। इस वर्गमें सामान्य चिकित्सा और शिक्षा, आश्रय-घरका अभाव है। आधुनिक सभ्यताके प्रभावमें अभावग्रस्त लोगोंके सामने संकट है। विज्ञानके जानकार प्रकृतिके तमाम रहस्य बता रहे हैं। नि:संदेह वैज्ञानिक शोधोंने चिकित्साके क्षेत्रमें क्रांतिकारी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक शोधोंने पृथ्वी ग्रहके अस्तित्वके समाप्त होनेका खतरा पैदा कर दिया है। युद्धके तमाम आश्चर्यजनक हथियार पृथ्वी और मानव जातिके अस्तित्वके लिए खतरा बन गये हैं। परमाणु हथियार सहित अनेक आश्चर्यजनक अस्त्रोंकी खोजोंसे पृथ्वीके ही अस्तित्वपर खतरा है। पृथ्वी ग्रह संकटमें है और उससे पोषण पानेवाली मानव जाति भी संकट में है। वैज्ञानिकोंने तमाम ग्रहोंकी गतिविधिका पता लगा लिया है। आशंका है कि किसी समय पृथ्वी चन्द्रमाके निकट पहुंच सकती है। सूर्यका ईंधन लाखों वर्षसे खर्च हो रहा है। सूर्यके ठंडा हो जानेसे ही मनुष्य जाति नष्ट हो सकती है। हम इन्हें भविष्यकी आशंकाएं कह सकते हैं। डाक्टर राधाकृष्णनने धर्म और समाजमें धर्मकी आवश्यकता शीर्षकमें कहा है, अधिक सम्भावना इस बातकी है कि मानव जाति स्वयं जान-बूझकर किये गये कार्योंसे, अपनी मूर्खता और स्वार्थके कारण नष्ट हो सकती है। संसार आनन्दके लिए है। हम युद्ध यंत्र जातकी पूर्णत: तक पहुंचनेमें लगायी जा रही ऊर्जाओंके केवल थोड़ेसे हिस्सेका ही इसके लिए प्रयोग करें तो सबको आनन्दमय बनाया जा सकता है।

सम्पूर्ण मानवता विषाद ग्रस्त जान पड़ रही है। आदर्श परम्पराएं, स्वत: प्रेरित अनुशासन और राष्ट्र राज्यों द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था शिथिल हो रही हैं। डार्विनने लिखा है, मनुष्य जीवन सभ्यतामें उन्नति करता जा रहा है। छोटे वर्ग समूह बड़े समुदायोंमें संघटित होते जाते हैं। त्यों-त्यों व्यक्तिको यह बात समझमें आती जाती है कि उसे अपनी सामाजिक सहज प्रवृत्तियों और संवेदनाओंका विस्तार अपने राष्ट्रके लिए कर लेना चाहिए। सभ्यता आखिरकार क्या है। मनुष्यके बौद्धिक विकासका सबसे बड़ा उपकरण संवाद है और संवादकी प्रारंभिक शर्त है प्रेमपूर्ण भाषा और वाणी। वैदिक कालमें संवादकी अनेक संस्थाएं थी। सभा और समितियां विचार-विमर्शका मंच थी। सभामें विचार रखनेवाले सभेय कहे जाते थे। इसीसे शब्द बना है सभासद। सभामें प्रेमपूर्ण ढंगसे अपनी बात रखने वाले व्यक्तिको सभ्य कहा जाता था। किसी समूहका शब्द आचरण और सौन्दर्यबोध सभ्यता है लेकिन प्रेमपूर्ण संवाद घटा है। प्रकृति और मनुष्यके मध्य परस्परावलंबन है। मनुष्य प्रकृतिका भाग है। हमारे और प्रकृतिके मध्य आत्मीयता होनी चाहिए। प्रकृतिकी सभी शक्तियोंके लिए चित्तमें आत्मीय भावके साथ आदर भावकी भी आवश्यकता है। लेकिन प्रकृति और मनुष्यके बीच अंतर्विरोध भी हैं। आंधी, तूफान और ऐसी ही तमाम प्राकृतिक आपदाएं मनुष्यको व्यथा देती हैं और जीवनके लिए खतरा भी बनती हैं। ऐसी घटनाओंको प्राकृतिक मानकर अपना जीवनयापन करनेकी बात सही है। लेकिन अनेक संकट आधुनिक सभ्यताने भी पैदा किये हैं। भूमण्डलीय ताप, भूगर्भ जल स्तरका गिरना, वायु प्रदूषण आदि आपदाएं उपभोक्तावादी आचरणसे पैदा होती हैं। सीबी जुंगने अपनी पुस्तक मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोउलमें लिखा है, आधुनिक सभ्यता और मनुष्य उन्नतिकी चरम सीमापर है। भविष्यमें लोग उससे भी आगे निकल जायंगे। यह बात ठीक है कि वह एक युगव्यापी विकासका अंतिम परिणाम है। लेकिन साथ ही यह मानव जातिकी आशाओंकी दृष्टिसे अधिकतम निराशाजनक भी है। आधुनिक मनुष्यको इसकी जानकारी भी है। उसने देख लिया है कि विज्ञान, शिल्प और संघटन कितने लाभकारी हैं और वे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ईसाई चर्च, मनुष्योंका भाईचारा, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक संघटन और आर्थिक हितोंकी एकता सबके सब खोटे सिद्ध हुए हैं। मनोविज्ञानकी भाषामें कहें तो लगभग प्राणान्तक आघात पहुंचा है। परिणामस्वरुप मनुष्य अनिश्चिततामें जी रहा है। परिदृश्य चिन्ताजनक है। मनुष्यकी वाह्य समृद्धि बढ़ी है। मनुष्य यंत्र हो रहा है। उसकी आत्मा खो गयी है। वह खोई हुई आत्माकी पुन:प्राप्तिका प्रयास नहीं कर रहा है। भारतकी प्राचीन सभ्यतामें तमाम भौतिक अभावोंके बावजूद मनुष्य आनंदित था। राष्ट्रके प्रति उसकी निष्ठा थी। सभी रिश्तोंमें आत्मीयता थी। मनुष्यमें मनुष्येत्तर प्राणियों और सम्पूर्ण जगत्के प्रति भी आत्मभाव था। भारतके मनुष्यकी दृष्टि और जीवनकी गतिविधि सामूहिक थी। सुख दुख सामूहिक थे। पर्व उत्सव सामूहिक उत्सव आनंदका स्रोत थे। परिवार आनन्द मठ था। यत्र तत्र सर्वत्र आनन्द था। आधुनिक सभ्यताके प्रभावमें जीवनका आनन्द रस सूख गया है। आधुनिक सभ्यता द्वारा मनुष्यको नितांत व्यक्तिवादी और मशीन बनाया है। वैदिक सभ्यता और संस्कृतिमें सम्पूर्ण विश्वको परिवार जाना गया है। वसुधैव कुटुम्बकम वैदिक संस्कृतिका लोकप्रिय सूत्र है। विश्वके अणु और परमाणुके प्रति श्रद्धा और आदरभाव रहा है। शांति मानवताकी प्यास है। वैदिक साहित्यमें शांतिको जीवनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया है। भारतीय समाजके चिन्तकों, विद्वानों और वैदिक कालके ऋषियोंने शांतिकी उपासना की है। ऋग्वेदमें विश्व शांतिकी प्रार्थना है। यह भारतवासियोंकी शांतिकी प्यासको सुंदर अभिव्यक्ति देती है। शांति मन्त्रमें कहते हैं, अंतरिक्ष शांत हों। पृथ्वी शांत हों। आकाश शांत हों। वनस्पतियां औषधियां शांत हों। शांति भी शांत हों। यहां केवल मनुष्योंके बीच परस्पर सद्भाव वाली शांतिकी ही बात नहीं है। यहां पृथ्वीसे लेकर आकाशतक शांति स्थापित होनेकी प्रार्थना है। शांति-अशांतिकी अनुपस्थिति नहीं है। शांति मौलिक रूपमें मानव मनकी प्राकृतिक प्यास है। अशांत चित्तसे सृजन संभव नहीं होते। अशांत चित्त विध्वंसक होता है और शांत चित्त सर्जक। विश्व तनावमें है। हिन्दुत्व परिपूर्ण जीवन दृष्टि है। पूरी जीवन दृष्टि आतंरिक आत्मीयताके आधारपर विकसित हुई है। धरती माता है। आकाश पिता है। जल माताएं हैं। जलसे जीवनका उद्भव ऋग्वेदमें उल्लिखित है। जलमाताओंने ही संसारको जन्म दिया। नदियां माताएं हैं। सूर्य संरक्षक हैं। परोपकार और सदाचार उत्कृष्ट जीवन मूल्य हैं। दुख और वैराग्यके स्थानपर आनन्द और प्रवृत्ति हैं। संसार त्याज्य नहीं है। संसार धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र है। जीवन कर्म प्रधान है। जीवनमें पलायनका कोई भाव नहीं। वनस्पतियां भी प्रणामके योग्य हैं। उन्हें देवता कहा गया है। वैदिक सभ्यतामें विचार विविधता है। जीवन और जगत्को समझनेके लिए पूर्व मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बुद्ध और जैन आठ दर्शन हैं। भारतीय दर्शन किसी देवदूतकी घोषणा नहीं है। आधुनिक सभ्यताकी सभी विसंगतियोंके उपचार हिन्दुत्व में हैं।

पुष्टिमार्गके प्रवर्तक

❑ **श्रीकल्प जी महाराज**

भारत अनेकतामें एकता रखनेवाला देश है। यहांपर विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृतियोंके लोग वास करते हैं। यहां तो प्रकृतिमें भी विविधता देखनेको मिलती है। कहीं बहुत तेज गर्मी तो कहीं कड़कड़ाती ठंड, कहीं दूर-दूरतक सुनहरा रेगिस्तान तो कहीं पहाड़ ही पहाड़। इन्हीं भिन्नताओंमें जो एक चीज हमें बांधे रखती है, वह है हमारी भारतीयता और भारतीयोंका अध्यात्मसे बहुत गहरा नाता रहा है। अध्यात्म भी हमारे यहां भिन्न प्रकारका मिलता है, कई प्रकारकी भक्ति मिलती है। कोई ईश्वरके साकार यानी सगुण रूपको मानता है तो कोई निराकार यानी निर्गुण रूपको। जब भी भक्ति या अध्यात्मकी बात होती है तो याद आती है भारतमें भक्तिकी अविरल धाराओंकी जो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, आचार्य निंबार्क और वल्लभाचार्यसे होती हुई अभीतक नये-पुराने रूपोंमें बहती चली आ रही हैं। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखाके वह आधारस्तंभ हैं, जिन्होंने साधनाके लिए पुष्टिमार्गसे परिचित करवाया, जिन्होंने सूरदासको पुष्टिमार्गका जहाज बनाया। पुष्टिमार्गके इस प्रवर्तककी जयंती वैशाखके पावन मासमें मनायी जाती है। माना जाता है कि वैशाख मासकी कृष्ण एकादशीको कृष्णभक्तिके मार्गको दिखानेवाले सूरदासको लीलाधरकी लीलाओंसे परिचित करानेवाले वल्लभाचार्यका जन्म हुआ था। पुष्टिमार्गके प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जीका जन्म विक्रमी संवत १५३५ में दक्षिण भारतके कांकरवाड़ ग्राम, जो कि वर्तमानमें छत्तीसगढ़की राजधानी रायपुरके निकट चंपारण है, में तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जीके घर हुआ। उनकी माताका नाम इल्लमागारू था। उनके जन्मको लेकर एक किंवदंती भी प्रचलित है जिसके अनुसार कहा जाता है कि उनका जन्म माता इल्लमागारूके गर्भसे अष्टमासमें ही हो गया था। उनको मृत जान माता-पिताने छोड़ दिया जिसके पश्चात श्री नाथ जीने स्वयं स्वप्नमें माता इल्लमागारूको दर्शन दिये और कहा कि स्वयं श्री नाथ जी उनके गर्भसे प्रकट हुए हैं। जिस शिशुको आप मृत जान छोड़ आये हैं, वह जीवित है। तत्पश्चात माता-पिता उन्हें वापस ले जाने हेतु उसी स्थानपर पहुंचे तो देखा कि अग्निकुंडके बीच वह अंगूठा चूस रहे हैं और अग्निकुंडके इर्द-गिर्द सात अवगढ़ साधु बैठे हैं। जब उन्होंने साधुओंसे कहा कि शिशु उनका है तो उन्होंने अग्निकुंडसे शिशुको निकालनेमें अपनी असमर्थता प्रकट की। तब उन्होंने श्रीनाथ जीका ध्यान लगाया और अपने शिशुको अग्निकुंडसे निकाला। इसी कारण श्री वल्लभाचार्य जीको अग्नि-अवतार भी माना जाता है और चंपारण पुष्टिमार्गी साधनाका स्थल माना जाता है। श्री वल्लभाचार्य जीके अनुसार ब्रह्म, जगत और जीवकी सत्ताको स्वीकार्य तत्व मानते हैं। वल्लभाचार्य जीने स्वयं तो ग्रंथ लिखे ही हैं, साथ ही सूरदास जैसे कविको लीलाधरकी लीलाओंसे परिचित करवाकर उन्हें भी लीलागानकी प्रेरणा दी जिसके कारण हम श्रीकृष्णकी बाल लीलाओंसे रूबरू होते हैं। उन्होंने अनेक भाष्य, ग्रंथ, नामावलियां, स्तोत्र आदिकी रचना की है। उनकी प्रमुख सोलह रचनाओंको षोडष ग्रंथके नामसे जाना जाता है।

कम होती मतदाताओंकी भागीदारी

❑ **रमा निवास तिवारी**

हम यानी मतदाता लोकतंत्रके प्रहरी हैं। जब प्रहरी ही अपने अधिकारों और कर्तव्योंसे च्युत हो जायेगा तो लोकतंत्र कहांसे मजबूत और खूबसूरत बन पायेगा। दुनियाके सबसे बड़े लोकतंत्रका महापर्व चल रहा है, दो चरणके चुनाव सम्पन्न भी हो चुके हैं लेकिन मतदाताओंने इन दोनों ही चरणोंमें अपने वोटके इस्तेमालके प्रति उदासीनता दिखाई है, यह बात बहुत ही चिन्ताजनक है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबेके मतदाताओंकी भागीदारीका प्रतिशत तो काफी कम दिखा। चुनावमें बढ़-चढ़कर मतदाताओंकी भागीदारी स्वस्थ लोकतंत्रके निर्माणकी प्रथम शर्त है और हम यहीं फेल होते दिखाई दे रहे हैं। चुनावके संपन्न हो चुके दो चरण कोई अच्छे संकेत नहीं देते हैं।

चुनाव एक मौका होता है अपने देशको अच्छे जन-प्रतिनिधियोंके हवाले करनेका, चुनाव कोई महीने दो महीनेके मनोरंजनका मसला नहीं है, बल्कि यह देशके भविष्यकी मुनादी तय करता है। लोकतंत्रके महायज्ञमें सबकी आहुतियां पड़नी चाहिए। जिन मतदाताओंने वोट नहीं दिया, यह मानना चाहिए वे लोकतंत्रके प्रति अपनी बड़ी जिम्मेदारीसे चूक गये, साथ ही आगे बननेवाली किसी भी सरकारकी गलत नीतियोंको कोसनेका अधिकार भी गंवा बैठे। यद्यपि भीषण गर्मीमें चुनाव हो रहे हैं फिर भी केवल एक दिनकी ही तो बात है, सारा काम छोड़कर मतदानके लिए जाना ही चाहिए। हम अपने दूसरे कामोंमें गर्मी सर्दी कुछ नही देखते हैं, फिर मतदानके लिए इतनी-सी चुनौती नहीं स्वीकार कर सकते हैं। सच तो यह है कि हम मतदानको कोई बड़ा और आवश्यक कार्य समझते ही नहीं हैं, हम यह मानकर चलते हैं कि हमारे एक वोटसे क्या होगा, जिसको जीतना होगा वह जीतेगा ही। कोउ नृप होय हमय का हानी। ऐसे ऐसे जुमलोंके तर्क देकर वोट न देनेके अपने निर्णयको सही सिद्ध करने लगते हैं। मतदाताओंकी यही सोच कम मतदानका कारण है। लोकतंत्रमें चुनाव यदि प्रत्याशियोंकी परीक्षा है तो निश्चित तौरपर मतदाता ही वह परीक्षक है जो प्रत्याशियोंको फेल या पास करता है। परीक्षक जितने अधिक होंगे पास फेलके परिणाम भी उतने ही परिपक्व होंगे, नतीजोंके सटीक होनेकी सम्भावना बलवती होगी। मतदाता देशका भाग्यविधाता भी है, एक मतदाताके रूपमें उसे इस बातका भान होना चाहिए। अभी तो शुरुआती दो दौरका मतदान ही हो पाया है, अभी पूरा चुनाव बाकी है, अब भी हम लोकतंत्रके प्रहरियोंको सजग हो जाना चाहिए। ज्यादासे ज्यादा मतदाताओंका सामना करके बननेवाली सरकारोंकी विश्वसनीयता भी अधिक होती है। वे असली जनादेशका प्रतिबिंब होती हैं। उत्तर प्रदेशमें दूसरे दौरके मतदानमें लगभग ५४ फीसदी वोट पड़ा है, जिसका सीधा अर्थ है कि लगभग आधे मतदाताओंने चुनावसे दूरी बनाये रखी। सोचनेवाली बात है कि जब आधे मतदाता वोट ही नहीं दे रहे हैं तो लोकतंत्रकी उभरती हुई सूरत कितनी खूबसूरत होगी। दूसरी ओर विजयी प्रत्याशियोंको असली जनादेशका प्रतिनिधित्व करते हुए कैसे माना जाये। एक मतदाताके रूपमें अंगुलीपर चुनावी स्याहीका अंकन आपको लोकतंत्रमें जिम्मेदार नागरिक होनेका प्रमाण-पत्र देता है। चुनाव आयोगकी बारम्बार अधिक मतदानकी अपीलों, जागरूकता कार्यक्रमोंके बाद भी हम अपनी जिम्मेदारियोंका निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो यह चिंताजनक है। आगेके चरणोंमें लोकतंत्रके इस महापर्वपर हम सभी अपना मतदान करके देशका जिम्मेदार नागरिक होनेका प्रमाण दें। साथ ही केवल मताधिकारको पहचाने ही न, बल्कि उसके प्रति अपने दायित्वोंका निर्वहन भी करें। मेरी यह अपील है आप लोकतंत्रके प्रहरियोंसे कि उठो और चुनावके अगले चरणोंमें अपना मतदान अवश्य करो।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

देशप्राण
स्वतंत्र हिन्दी दैनिक
रविवार
रांची, 28 अप्रैल, 2024

स्त्री धन पर सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला देते हुए कहा है कि स्त्री धन पूरी तरह महिला की संपत्ति होती है, जिस पर पति का कोई हक नहीं होता। हालांकि हिंदू लॉ की यह पोजीशन पहले से स्पष्ट है और इस लिहाज से फैसले को नया नहीं बताया जा सकता, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आज की तारीख में न केवल कानूनी हलकों में बल्कि सामाजिक संदर्भों में भी काफी अहमियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह बात और स्पष्ट हो गई है कि स्त्री धन को पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता। स्त्री धन का मतलब उस धन, संपत्ति, गहने-जेवर या रकम से है, जो शादी के समय लड़की को या लड़के और लड़की को दिया जाता है। आम तौर पर परिवार इसे अपनी संपत्ति के रूप में देखता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यह कहना महत्वपूर्ण है कि अगर किसी संकट के दौरान पति इस धन का इस्तेमाल करता है तो यह उसका नैतिक दायित्व है कि वह धन या उसके बराबर रकम पत्नी को वापस करे। यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब कई अन्य फैसलों की बदौलत और महिलाओं की बढ़ती जागरूकता के कारण भी, समाज में स्त्री-पुरुष संबंधों का सदियों से चला आ रहा समीकरण बदल रहा है। महिलाएं घर से निकल कर हर क्षेत्र में अपना दखल बढ़ा रही हैं। परिवार के अंदर भी पैतृक संपत्ति में अपना जायज हिस्सा मांग रही हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में फैसले लेने की प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सेदारी कर रही हैं। इन सबका एक साइड इफेक्ट यह है कि पुरुषों के एक हिस्से में महिलाओं के अधिकारों को लेकर बेचैनी का अहसास बढ़ा है। कहीं यह उनमें बढ़ते असुरक्षा बोध के रूप में सामने आता है तो कहीं महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने की प्रवृत्ति के रूप में। ऐसे में यह और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज का बड़ा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस रूप में देखता है। चूंकि स्त्री धन और उस पर मालिकाना पारंपरिक तौर पर ही स्त्रियों का माना जाता रहा है, इसलिए समाज में प्रचलित पारंपरिक सोच का एक रिएक्शन यह भी हो सकता है कि इस फैसले का स्वागत करते हुए लड़कियों के अधिकारों को वहीं तक सीमित करने की कोशिश की जाने लगे। कानूनी तौर पर तो लड़कियों के सारे अधिकार सुरक्षित हैं। अदालतें इस मामले में सतर्क भी हैं। लेकिन समाज में इस फैसले की आड़ में प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी सोच हावी न हो, इसे लेकर सावधानी बरतने की खास जरूरत है।

क्यों श्रेष्ठ कॉलेज खोलें गांवों में स्कूल

आरके सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

कभी विचार कीजिए कि किसी स्कूल या कॉलेज को किस आधार पर श्रेष्ठ कहा जाना चाहिए? बेशक, इसका एकमात्र पैमाना यही हो सकता है कि उस शिक्षण संस्थान ने अपने विद्यार्थियों को इस तरह के संस्कार दिए जिसके चलते उन्होंने आगे चलकर बेहतर नागरिक बनकर देश और समाज की सेवा की।

अभी कुछ दिन पहले संघ लोक सेवा परीक्षा (यूपीएससी) की परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए। सारा मीडिया सफल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करता रहा। बीते सालों की तरह से इस बार भी राजधानी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़े हुए बहुत से विद्यार्थियों ने यूपीएससी परीक्षा को क्रैक किया। सेंट स्टीफंस कॉलेज के छात्र रहे अंशुल भट्ट ने मेरिट लिस्ट में 14वें स्थान ग्रहण किया। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक अध्यक्ष शक्तिकांत दास सेंट स्टीफंस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं।

इसका एक पैमाना यह भी हो सकता है कि क्या उसने (शिक्षण संस्थान) ने अपना विस्तार किया ? विस्तार से मतलब है कि क्या उसने अपनी कोई अन्य शाखा भी खोली और वहां का शिक्षण भी श्रेष्ठ और स्तरीय रहा । इस मोर्चे पर दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज का नाम लेना होगा। सेंट स्टीफंस कॉलेज को गांधी जी के परम सहयोगी दीनबंधु सी.एफ.एंड्रूज की संस्था दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी ने स्थापित किया था। एंड्रूज ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी भारत की आजादी के समर्थक थे। उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ाया भी। अब उनके कॉलेज ने अपना विस्तार कर लिया है। इसने कोई अन्य कॉलेज नहीं खोला है।

अब दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी ने दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत की सीमा के राई नामक ग्रामीण क्षेत्र में सेंट स्टीफंस कैम्ब्रिज स्कूल खोला है। यानी कि यह स्कूल शहरों और महानगरों की चमक-दमक से दूर ज्ञान की रोशनी को फैलाएगा। निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षण संस्था का यही लक्ष्य होना चाहिए। भारत के गांवों में जितने बेहतर स्कूल खुले, उतना ही बेहतर होगा। हमारे बड़े-बड़े शहरों में तो अब खूब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, पर जरूरत है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक स्कूल खोलने की है, जिनकी स्तरीय फैकल्टी हो और वहां बाकी तमाम सुविधाएं भी मौजूद हों। यह प्रयास पिछले लगभग 140 वर्षों में 700 से ज्यादा शिक्षण संस्थान देश के कोने-कोने में खोले और सेवा भाव से चलाया। सन 1885 में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित डीएवी(दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल) और कॉलेज समूह इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि समाज में सेवा भावना से चलाया जाने वाला कार्य भी सफल हो सकता है।

अभी कुछ दिन पहले संघ लोक सेवा परीक्षा (यूपीएससी) की परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए। सारा मीडिया सफल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करता रहा। बीते सालों की तरह से इस बार भी राजधानी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़े हुए बहुत से विद्यार्थियों ने यूपीएससी परीक्षा को क्रैक किया। सेंट स्टीफंस कॉलेज के छात्र रहे अंशुल भट्ट ने मेरिट लिस्ट में 14वें स्थान ग्रहण किया। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक अध्यक्ष शक्तिकांत दास सेंट स्टीफंस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी सेंट स्टीफंस कॉलेज से ही पढ़ाई की है। इसने देश के न जाने कितने सितारे निकाले हैं। उनकी गिनती करना असंभव है।

सेंट स्टीफंस कॉलेज के शुरूआती दौर में पढ़ने के लिए मौजूदा हरियाणा राज्य से चौधरी छोटूराम भी आया करते थे। वे आगे चलकर किसानों के मसीहा कहलाए। अब भी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता चौधरी छोटूराम को अपना मसीहा मानती है। संयोग देखिए कि अब उनके प्रदेश में उनके शिक्षण संस्थान ने दस्तक दे दी। जाहिर है, इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा।

अगर आपका कभी दिल्ली के चांदनी चौक में जाना हो तो आपको वहां पर किनारी बाजार को ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वहां से आप कटरा खुशहाल राय में चंद मिनटों में पहुंच सकते हैं। यहां पर पहुंचकर किसी से पूछिए कि सेंट स्टीफंस कॉलेज कहां था? आपको कोई ना कोई बता देगा कि उस सामान्य सी हवेली का रास्ता जहां से 1 फरवरी, 1881 को सेंट स्टीफंस कॉलेज की यात्रा शुरू हुई थी। यह तब कलकत्ता यूनिवर्सिटी का हिस्सा था। सेंट स्टीफंस कॉलेज की दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित पहली इमारत को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यहां से शुरू हुआ सेंट स्टीफंस कॉलेज बुलंदियों को छूने लगेगा। जो सफर 140 साल से भी पहले शुरू हुआ था था, उसका अब विस्तार हो चुका है। सेंट स्टीफंस कैम्ब्रिज खुल चुका है। महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में ब्रदरहुड ऑफ दि एसेंनडेंड क्राइस्ट की स्थापना सन् 1877 में हुई थी। इसका संबंध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है। इसने आगे चलकर अपना नाम दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी रखा। इसने ही राजधानी में सेंट स्टीफंस अस्पताल की भी स्थापना की थी। देश के बंटवारे के बाद सरहद के उस पार से लुटे-पिटे आए लाखों हिन्दू और सिख शरणार्थियों का इस अस्पताल ने श्रेष्ठ इलाज किया था।

एक बात बहुत साफ है कि स्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ होनी बहुत आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि सालों, दशकों से स्थापित शिक्षण संस्थाएं अपना तेजी से विस्तार करें। वे देश के ग्रामीण क्षेत्रों का रुख भी करें। वहां पर स्तरीय और सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवाएं। स्कूल या कॉलेज खोलने का आधार अपनी जेबें भरना नहीं होना चाहिए। जो शिक्षा के नाम पर मोटी कमाई कर रहे हैं, वे सच में मां सरस्वती का अपमान कर रहे हैं। मैं यहां पर महात्मा गांधी के परम शिष्य ब्रज कृष्ण चांदीवाला का उल्लेख करना चाहता हूं। चांदीवाला गांधी जी से पहली बार 1918 में मिले थे। तब गांधी जी दिल्ली आए ही थे। उसके बाद वे गांधी जी के जीवनपर्यंत शिष्य बनकर साथ रहे। उन्होंने गांधी जी के पार्थिव शरीर का 31 जनवरी,1948 की रात को अंतिम स्नान भी करवाया था। ब्रज कृष्ण चांदीवाला ने अपनी मां और समाज सेविका श्रीमती जानकी देवी जी के नाम पर 1959 में राजधानी में जानकी देवी कॉलेज स्थापित किया था। इस कॉलेज ने अब तक लाखों बेटियों को साक्षर बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। यहां इन्द्रप्रस्थ हिन्दू गर्ल्स स्कूल की चर्चा करना समीचीन होगा। राजधानी का यह कन्या विद्यालय 1904 में शुरू हुआ था। यह उत्तर भारत के पहले कन्या विद्यालयों में से एक माना जाता है। कमला नेहरू, प्रख्यात सरोद वादिका शरण रानी बाकलीवाल, कपिला वात्स्यायन वगैरह ने इसी में शिक्षा ग्रहण की थी। इस स्कूल के प्रबंधन ने ही राजधानी में इन्द्रप्रस्थ कॉलेज खोला जिसने हाल ही में अपना 100 साल का सफर पूरा किया है।

यह कैसे हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक रामजस कॉलेज के संस्थापक , शिक्षाविद और दानवीर राय केदारनाथ का उल्लेख रह जाए। उन्होंने अपने पिता लाला रामजस मल के नाम पर रामजस कॉलेज और अनेक स्कूल स्थापित किये। राय केदारनाथ दिल्ली के सेशन जज भी रहे। उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़कर ज्ञान की रोशनी फैलाने में अपना जीवन लगा दिया। कहते हैं कि वे अपने स्कूलों की इमारतों के निर्माण के समय खुद सिर पर ईंटें ढोया करते थे। रामजस कॉलेज और स्कूलों में देशभर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहां दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से भी एक स्कूल चलाया जाता है। यह विश्वविद्यालय कैंपस में ही है। उसने कुछ समय पहले अपनी 75वी वर्षगांठ मनाई। कितना अच्छा हो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से किसी ग्रामीण इलाके में स्कूल चलाया जाये।

टीएन शेषन ने बदली थी भारत के अराजक चुनावों की तस्वीर

योगेंद्र योगी

राजीव ने स्वामी को छेड़ते हुए कहा कि वो दाढ़ी वाला शख्स (चंद्रशेखर) उस दिन को कोसेगा, जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला किया था। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने साठ के दशक में तमिलनाडु में शेख को नजर बंद करवा दिया था। शेषन उस समय मदुरै जिले के कलेक्टर थे। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो शेख द्वारा बाहर भेजे गए हर पत्र को पढ़ें। शेख ने डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पत्र लिखा। शेषन ने बिना डरे पत्र पढ़ लिया। शेख ने घोषणा की कि वो उनके साथ किए जा रहे खराब व्यवहार के विरोध में आमरण अनशन पर जाएंगे। शेषन ने कहा कि सर ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई आपके सामने पानी का एक गिलास भी लेकर न आए। शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव के धर्मराजन त्रिपुरा में हो रहे चुनावों का पर्यवेक्षक का कार्य छोड़ कर थाइलैंड चले गए। इस पर दंडित करते हुए शेषन ने उनकी गोपनीय रिपोर्ट में विपरीत प्रविष्टि करने का फैसला किया। शेषन ने वर्ष 1993 में 17 पेज का आदेश जारी किया कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नही देती, तब तक देश में कोई भी चुनाव नहीं कराया जाएगा। आखिरकार सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। मौजूदा आदर्श आचार संहिता उसी आदेश का परिणाम है। शेषन के आने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एक आज्ञाकारी नौकरशाह होता था जो वही करता था जो उस समय की सरकार चाहती थी।

देश की मौजूदा पीढ़ी को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि भारत की आजादी के बाद की ऊबड-खाबड़ यात्रा में देश ने ऐसे-ऐसे हिचकोले खाए कि लगने लगा था कि लोकतंत्र पटरी से उतर कर अराजकता में बदल जाएगा। इसी यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती थी, देश के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना। आज जिस तरह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराए जा रहे हैं। करीब साढ़े तीन दशक पहले इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। उस दौर में ऐसा कोई भी चुनाव नहीं रहा जो खून-खराबे से भरा नहीं रहा हो। देश में बैलेट पर बुलट भारी था। बंदूक की नोक पर वोटों की पेटियों को लूटना आम बात थी। भारत की चुनावी प्रक्रिया में हर तरह की बुराई थी।

ऐसे में देश को एक ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त मिलता है, जो पूरी चुनाव व्यवस्था को बदलकर रख देता है। बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं को नकेल कस देता है। उस मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम था टीएन शेषन। आज देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल में चुनाव हो पाता है तो इसका श्रेय टीएन शेषन को ही जाता है। देश के दबंग चुनाव आयुक्त के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले टीएन शेषन नौकरशाही में भी सुधार के जनक थे। ईमानदारी और कानून के प्रति अपनी निष्ठा की वजह से वह बहुतों को खटकते भी थे। इस वजह से उनके विरोधी उनको सनकी और तानाशाह तक भी कहते थे। लेकिन वह व्यवस्था में क्रांति लाने वाले इंसान, मेहनती, सक्षम प्रशासक, योग्य नौकरशाह, बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग के नायक थे।

पलक्कड़ (केरल) के निवासी टीएन शेषन ने 1955 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में ट्रेनी के तौर पर अपने करियर की शुरूआत की। शेषन ने अपनी पहली तैनाती में ही तीखे तेवर दिखाते हुए तमिलनाडु के मदुरै जिले के डिंडीगुल में सब कलेक्टर पद पर रहते हुए हरिजन समुदाय के एक व्यक्ति पर फंड के घपले के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया। मंत्री के दबाव के बाद भी आरोपी को नहीं छोड़ा।

चेन्नई में यातायात आयुक्त पद के दौरान एक बार एक ड्राइवर ने शेषन से पूछा कि अगर आप बस के इंजन को नहीं समझते और ये नहीं जानते कि बस को ड्राइव कैसे किया जाता है, तो आप ड्राइवरों की समस्याओं को कैसे समझ पाएंगे। शेषन ने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने न सिर्फ. बस की ड्राइविंग सीखी बल्कि बस वर्कशॉप में भी काफी समय बिताया। एक बार उन्होंने बीच सड़क पर ड्राइवर को रोक कर स्टेयरिंग संभाल लिया और यात्रियों से भरी बस को 80 किलोमीटर तक चलाया। शेषन का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से काफी झगड़ा हो गया, जिसके बाद वे प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली आ गए और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के एक सदस्य के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आग्रह पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव बन गए। सचिव के तौर पर उन्होंने टिहरी बांध और सरदार सरोवर बांध जैसी परियोजनाओं का विरोध किया। भले ही सरकार ने उनको विरोध को दरकिनार कर दिया और परियोजना पर काम को आगे बढ़ाया लेकिन बांध के पर्यावरण पर पड? वाले प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया गया।

इसके साथ ही शेषन ने विभागों में नहीं कहने का रुझान शुरू किया। इस दौरान राजीव गांधी से उनकी नजदीकी बढ़ी। वहां से उनको आंतरिक सुरक्षा का सचिव बनाया गया। करीब 10 महीनों बाद उनको कैबिनेट सचिव बनाया गया। जब राजीव गांधी दिसंबर 1989 में चुनाव हार गए और प्रधानमंत्री नहीं रहे तो टीएन शेषन का ट्रांसफर योजना आयोग में कर दिया गया। शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की दास्तां भी कम दिलचस्प नहीं है। दिसंबर 1990 केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और शेषन के दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के दूत के तौर शेषन पर मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की पेशकश की। शेषन इस प्रस्ताव से बहुत अधिक उत्साहित नहीं हुए थे, क्योंकि पहले ही कैबिनेट सचिव विनोद पांडे ने भी उन्हें ये प्रस्ताव दिया था। शेषन इस प्रस्ताव पर राजीव गांधी से मिले। राजीव गांधी ने शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति दे दी। लेकिन वो इससे बहुत खुश नहीं थे।

राजीव ने स्वामी को छेड़ते हुए कहा कि वो दाढ़ी वाला शख्स (चंद्रशेखर) उस दिन को कोसेगा, जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला किया था। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने साठ के दशक में तमिलनाडु में शेख को नजर बंद करवा दिया था। शेषन उस समय मदुरै जिले के कलेक्टर थे। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो शेख द्वारा बाहर भेजे गए हर पत्र को पढ़ें। शेख ने डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पत्र लिखा। शेषन ने बिना डरे पत्र पढ़ लिया। शेख ने घोषणा की कि वो उनके साथ किए जा रहे खराब व्यवहार के विरोध में आमरण अनशन पर जाएंगे। शेषन ने कहा कि सर ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई आपके सामने पानी का एक गिलास भी लेकर न आए।

शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव के धर्मराजन त्रिपुरा में हो रहे चुनावों का पर्यवेक्षक का कार्य छोड़ कर थाइलैंड चले गए। इस पर दंडित करते हुए शेषन ने उनकी गोपनीय रिपोर्ट में विपरीत प्रविष्टि करने का फैसला किया। शेषन ने वर्ष 1993 में 17 पेज का आदेश जारी किया कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नही देती, तब तक देश में कोई भी चुनाव नहीं कराया जाएगा। आखिरकार सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। मौजूदा आदर्श आचार संहिता उसी आदेश का परिणाम है। शेषन के आने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एक आज्ञाकारी नौकरशाह होता था जो वही करता था जो उस समय की सरकार चाहती थी। ये शेषन का ही बूता था कि उन्होंने चुनाव में पहचान पत्र का इस्तेमाल आवश्यक कर दिया।

शेषन ने साफ कह दिया कि अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं बनाए गए तो 1 जनवरी 1995 के बाद भारत में कोई चुनाव नहीं कराए जाएंगे। शेषन के दौर में ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दिन पंजाब के मंत्रियों के 18 बंदूकधारियों को राज्य की सीमा पार करते हुए धर दबोचा गया। उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा पर तैनात नागालैंड पुलिस ने बिहार के विधायक पप्पू यादव को सीमा नहीं पार करने दी। हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल गुलशेर अहमद को चुनाव आयोग द्वारा सतना का चुनाव स्थगित करने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। गुलशेर अहमद पर आरोप था कि उन्होंने राज्यपाल पद पर रहते हुए अपने पुत्र के पक्ष में सतना चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया था। उसी तरह राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल बलिराम भगत को भी शेषन का कोपभाजन बनना पड़ा था, जब उन्होंने एक बिहारी अफसर को पुलिस का महानिदेशक बनाने की कोशिश की। शेषन ने बिहार में पहली बार चार चरणों में चुनाव करवाया और चारों बार चुनाव की तारीखें बदली गईं। ये बिहार के इतिहास का सबसे लंबा चुनाव था। शेषन ने आचार संहिता के उल्लंघन पर पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं होने दिया, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु इतने नाराज हुए कि उन्होंने उन्हें पागल कुत्ता कह डाला। साल 1992 के शुरू से ही शेषन ने सरकारी अफसरों को उनकी गलतियों के लिए लताड ?ा शुरू कर दिया था। उसमें केंद्र के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल थे। बीते दशकों में टीएन शेषन से ज्यादा नाम शायद ही किसी नौकरशाह ने कमाया हो। वर्ष 1990 के दशक में तो भारत में एक मजाक प्रचलित था कि भारतीय राजनेता सिर्फ. दो चीजों से डरते हैं। एक खुदा और दूसरे टीएन शेषन से।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है गंभीर चुनौती

ललित गर्ग

दुनिया की आर्थिक बदहाली एवं युद्ध की विभीषिका से चौपट काम-धंधों एवं जीवन संकट में लोकसभा के चुनाव कहां कोई आदर्श प्रस्तुत कर पा रहे हैं? इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जो लोग चुनाव जीतने के लिए इतना अधिक खर्च कर सकते हैं तो वे जीतने के बाद क्या करेंगे, पहले अपनी जेब को भरेंगे, अर्थव्यवस्था पर आर्थिक दबाव बनायेंगे। और मुख्य बात तो यह है कि यह सब पैसा आता कहां से है? कौन देता है इतने रुपये? धनाढ्य अपनी तिजोरियां तो खोलते ही है, कई कम्पनियां हैं जो इन सभी चुनावी दलों एवं उम्मीदवारों को पैसे देती है, चंदे के रूप में।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकसभा चुनाव 2024 अनेक दृष्टियों से यादगार, चर्चित, आक्रामक एवं ऐतिहासिक होने के साथ-साथ अब तक का सबसे महंगा एवं दुनिया का सबसे खचीर्ला चुनाव है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार का चुनावी खर्च एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये के खर्च के साथ दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के खर्च की तुलना में इस बार दुगुना खर्च होगा। चुनाव प्रक्रिया अत्यधिक महंगी एवं धन के वर्चस्व वाली होने से राजनीतिक मूल्यों का विसंगतिपूर्ण एवं लोकतंत्र की आत्मा का हनन होना स्वाभाविक है। चुनाव जनतंत्र की जीवनी शक्ति है। यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिम्ब होता है। जनतंत्र के स्वस्थ मूल्यों को बनाए रखने के लिए चुनाव की स्वस्थता, पारदर्शिता, मितव्ययता और उसकी शुद्धि अनिवार्य है। चुनाव की प्रक्रिया गलत होने पर लोकतंत्र की जड़े खोखली होती चली जाती हैं। करोड़ों रुपए का खचीर्ला चुनाव, अच्छे लोगों के लिये जनप्रतिनिधि बनने का रास्ता बन्द करता है और धनबल एवं धंधेबाजों के लिये रास्ता खोलता है। इन चुनावों में अर्थ का अनुचित एवं अतिशयोक्तिपूर्ण खर्च का प्रवाह जहां चिन्ता का कारण बन रहा है, वहीं समूची लोकतांत्रिक प्रणाली को दूषित करने का सबब भी बन रहा है। इस तरह की बुराई एवं विकृति को देखकर आंख मूंदना या कानों में अंगुलियां डालना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके विरोध में व्यापक जनचेतना को जगाना जरूरी है। यह समस्या या विकृति किसी एक देश की नहीं, बल्कि दुनिया के समूचे लोकतांत्रिक राष्ट्रों की समस्या है। 18वीं लोकसभा चुनाव में हर राजनैतिक दल अपने स्वार्थ की बात सोच रहा है तथा येन-केन-प्रकारेण ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने की अनैतिक तरकीबें निकाल रहा है। एक-एक प्रत्याशी चुनाव का प्रचार-प्रसार करने में करोड़ों रुपयों का व्यय करता है। यह धन उसे पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, राजनीतिक दलों एवं प्रायोजकों से मिलता है। चुनाव जीतने के बाद वे उद्योगपति उनसे अनेक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इसी कारण सरकार उनके अनुचित दबाव के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा पाती और अनैतिकता एवं आर्थिक अपराध की परम्परा को सिंचन मिलता रहता है। यथार्थ में देखा जाए तो जनतंत्र अर्थतंत्र बनकर रह जाता है, जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा, वह उतने ही अधिक वोट खरीद सकेगा। लेकिन इस तरह लोकतंत्र की आत्मा का ही हनन होता है, इस सबसे उन्नत एवं आदर्श शासन प्रणाली पर अनेक प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं।

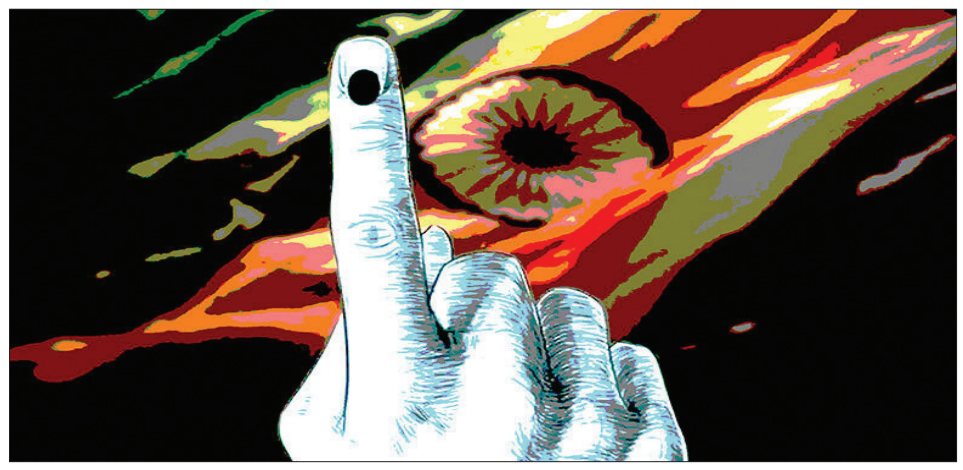

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर चुनाव अभियान के लिए धन अलग-अलग स्त्रोतों से अलग-अलग तरीको से उम्मीदरवारों और राजनीतिक दलों के पास आता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए मुख्य रूप से रियल इस्टेट, खनन, कारपोरेट, उद्योग, व्यापार, ठेकेदार, चिटफण्ड कंपनियां, ट्रांसपोर्टर, परिवहन ठेकेदार, शिक्षा उद्यमकर्ता, एनआआई, फिल्म, दूरसंचार जैसे प्रमुख स्त्रोत है। इस साल डिजिटल मीडिया द्वारा प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक दल पेशेवर एजेंसिया की सेवाएं ले रहे हैं। इनसे सबसे अधिक राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार अभियान, रैली, यात्रा खर्च के साथ-साथ सीधे तौर पर गोपनीय रूप से मतदाताओं को सीधे नकदी, शराब, उपहारों का वितरण भी शामिल है। देश में 1952 में हुए पहले आम चुनाव की तुलना में 2024 में 500 गुणा अधिक खर्च होने का अनुमान है। प्रति मतदाता 6 पैसे से बढ़कर आज 52 रुपये खर्च होने का अनुमान है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में होने वाले वास्तविक खर्च और अधिकारिक तौर पर दिखाए गए खर्चे में काफी अंतर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के 32 राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों द्वारा आधिकारिक तौर पर सिर्फ 2,994 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया। इनमें दिखाया गया कि राजनीतिक दलों ने 529 करोड़ रुपये उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन आयोग में पेश खर्च का ब्यौरा और वास्तविक खर्च के साथ-साथ उम्मीदवारों द्वारा अपने स्तर पर किए जा रहे खर्चे में काफी अंतर है। अमेरिकी चुनाव पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट के रिपोर्ट का हवाला देते हुए, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्यक्ष एन भास्कर राव ने कहा कि यह 2020 के अमेरिकी चुनावों पर हुए खर्च के लगभग बराबर है, जो 14.4 बिलियन डॉलर यानी 1 लाख 20 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव साबित होगा।

भारत में होने वाले चुनाव में हो रहे बेसुमार खर्च की तपीश समूची दुनिया तक पहुंच रही है। समूची दुनिया के तमाम देशों में भारत के चुनाव को न केवल दम साध कर देखा जा रहा है बल्कि इन चुनाव के खर्चों एवं लगातार महंगे होते चुनाव की चर्चा भी पूरी दुनिया में व्याप्त है। लोकसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस आदि दलों एवं उनके उम्मीदावारों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये तिजोरियां खोल दी है। यह चुनाव राष्ट्रीय मसलों के मुकाबले राजनीतिक दलों के हित सुरक्षित रखने के वादे पर ज्यादा केंद्रित लग रहा है और टकराव के मुद्दे थोड़े ज्यादा तीखे हैं। लेकिन अगर मुद्दों से इतर अभियानों की बात करें तो यह खबर ज्यादा ध्यान खींच रही है कि इस बार चुनाव अब तक के इतिहास में सबसे खचीर्ला साबित होने जा रहा है। इस चुनावों के अत्यधिक खचीर्ले होने का असर व्यापक होगा। चुनाव के तवे को गर्म करके अपनी रोटियां सेंकने की तैयारी में प्रत्याशी वह सब कुछ कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करता है। काफी लंबे और जटिल प्रक्रिया के तहत चलने वाले चुनाव में जनता के बीच समर्थन जुटाने के लिए उम्मीदरवार जितने बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हैं, उसमें उन्हें स्थानीय कार्यकताओं से लेकर सामग्रियों और जनसंपर्कों तक के मामले में कई स्तरों पर खर्च चुकाने पड़ते हैं। यों किसी भी देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होने वाले चुनावों में ऐसा ही होता है, लेकिन भारत में इसी कसौटी पर खर्च में कई गुना ज्यादा होना चिन्ता का सबब बनना चाहिए।

दुनिया की आर्थिक बदहाली एवं युद्ध की विभीषिका से चौपट काम-धंधों एवं जीवन संकट में लोकसभा के चुनाव कहां कोई आदर्श प्रस्तुत कर पा रहे हैं? इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जो लोग चुनाव जीतने के लिए इतना अधिक खर्च कर सकते हैं तो वे जीतने के बाद क्या करेंगे, पहले अपनी जेब को भरेंगे, अर्थव्यवस्था पर आर्थिक दबाव बनायेंगे। और मुख्य बात तो यह है कि यह सब पैसा आता कहां से है? कौन देता है इतने रुपये? धनाढ्य अपनी तिजोरियां तो खोलते ही है, कई कम्पनियां हैं जो इन सभी चुनावी दलों एवं उम्मीदवारों को पैसे देती है, चंदे के रूप में। चन्दा के नाम पर यदि किसी बड़ी कम्पनी ने धन दिया है तो वह सरकार की नीतियों में हेरफेर करवा कर लगाये गये धन से कई गुणा वसूल लेती है। इसीलिये वर्तमान देश की राजनीति में धनबल का प्रयोग चुनाव में बड़ी चुनौती है। सभी दल पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों एवं समस्याओं के समाधान के नाम पर नहीं। कोई भी ईमानदारी और सेवाभाव के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। राजनीति के खिलाड़ी सत्ता की दौड़ में इतने व्यस्त है कि उनके लिए विकास, जनसेवा, सुरक्षा, महामारियां, युद्ध, आतंकवाद की बात करना व्यर्थ हो गया है। सभी पार्टियां जनता को गुमराह करती नजर आती है। सभी पार्टियां नोट के बदले वोट चाहती है। राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है। सभी जीवन मूल्य बिखर गए है, धन तथा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता का अर्जन सर्वोच्च लक्ष्य बन गया है। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी विडम्बना एवं विसंगति है कि यह चुनाव आर्थिक विषमता की खाई को पाटने की बजाय बढ़ाने वाले साबित होने जा रहे हैं। आखिर कब तक चुनाव इस तरह की विसंगतियों पर सवार होता रहेगा?

संपादकीय

भाषण पर सवाल जवाब

निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा में दिए भाषण पर भाजपा से जवाब मांगा है। कांग्रेस और वामदलों ने नरेन्द्र मोदी के भाषण को विभाजनकारी और महाहानिकर बताते हुए आयोग से शिकायत की थी। इसी पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने नोटिस दिया है। किसी पदेन प्रधानमंत्री के विरु द्ध आदर्श संहिता उल्लंघन मामले में यह पहली कार्रवाई है। आयोग का अपनी याददाश्त के आधार पर ऐसा दावा है। दूसरी तरफ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विरु द्ध भाजपा की शिकायतों पर जवाब मांगा गया है। ये जवाब 29 अप्रैल तक दिए जाने हैं। इस तरह से आयोग ने निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का एक कठिन पड़ाव पार कर लिया है। उसे इसका श्रेय मिलना चाहिए कि उसने संहिता उल्लंघन पर प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा। यह आरोप भी कमजोर हुआ है कि आयोग विपक्ष और कमजोर दलों के नेता को ही निर्देशित करने में आगे रहता है। पर उसका निर्णायक इम्तिहान दोनों दलों के जवाब पर की जाने वाली कार्रवाई में होगा जो आयोग की शक्ति और क्षेत्र को परिभाषित करने वाला होगा। सार्वजनिक जीवन में गरिमा-मयार्दा और नियम-कायदे का आग्रही तबके ही नहीं, पूरे देश ने देखा-सुना कि बांसवाड़ा में और फिर अलीगढ़ तक में खास समुदाय और धर्म के लोगों के बारे में क्या-क्या न कहा गया। माना कि चुनाव बाद एक प्रधानमंत्री के रूप में आप समुदाय-धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते पर यही भाव चुनावी सभाओं में भी रहना बुरा नहीं होता। यह सामान्य जन अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री को तमाम विभाजनों और दोष-रेखाओं से ऊपर होना चाहिए। तब आयोग को भी रिकार्ड बनाने का मौका नहीं मिलता। चुनाव की घोषणा करते हुए आयोग ने भाषणों में सभ्यता के निर्वाह का अनुरोध दलों से किया था, जिसका पालन किसी ने नहीं किया। विपक्ष में स्थितिजन्य आक्रामकता स्वाभाविक ही होती है। सत्ता अपने व्यवहार से उसको परिमार्जित करती है। खरगे और राहुल सरकार की नीतियों की आलोचना के अधिकार के प्रयोग में सभ्यता भूलते रहे हैं। वे न केवल प्रधानमंत्री को निजी स्तर चोट पहुंचाने वाली भाषा का धड़ल्ले से प्रयोग करते सुने-देखे गए हैं, बल्कि तू-तड़ाक पर भी उतर आए हैं। यह भी रिकार्ड है कि नरेन्द्र मोदी देश के सर्वाधिक आलोच्य प्रधानमंत्री हैं। अगर यही एक परिपक्व लोकतंत्र की भाषा है तो यह वाकई बेहद पीड़ादायक परिदृश्य है।

चिंतन-मनन

रजा का खजाना

फारस के शासक साइरस अपनी प्रजा की भलाई में जुटे रहते थे। लेकिन खुद उनका जीवन सादगी से भरा था। वह रियासत की सारी आमदनी व्यापार, उद्योग और खेतीबाड़ी में लगा देते थे। इस कारण शाही खजाना हल्का रहता था। लेकिन प्रजा खुशहाल थी। एक दिन साइरस के दोस्त और पड़ोसी शासक प्रोशियस उनके यहां आए। उनका मिजाज साइरस से बिल्कुल अलग था। उन्हें प्रजा से ज्यादा अपनी खुशहाली की चिंता रहती थी। उनका खजाना हमेशा भरा रहता था। बातों-बातों में जब प्रोशियस को साइरस के खजाने का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने साइरस से कहा, अगर आप इसी तरह प्रजा के लिए खजाना लुटाते रहोगे तो एक दिन वह एकदम खाली हो जाएगा। आप कंगाल हो जाओगे।

अगर आप भी मेरी तरह खजाना भरने लगें तो आपकी गिनती मेरी तरह सबसे धनी शासकों में होने लगेगी। साइरस मुस्कराए फिर बोले आप दो दिन ठहरिए मैं इस मामले में लोगों का इम्तिहान लेना चाहता हूं। उन्होंने घोषणा करवा दी कि एक बहुत बड़े काम के लिए साइरस को दौलत की निहायत जरूरत है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रजा मदद करेगी। दो दिन पूरा होने से पहले ही शाही महल के बाहर मोहरों, सिक्कों व जेवरों का बड़ा ढेर लग गया। यह देख प्रोशियस हैरत में पड़ गए। साइरस ने कहा, मैंने रियासत का खजाना लोगों की खुशहाली पर खर्च करके एक तरह से उन्हीं को सौंप दिया है। लोग उसमें इजाफा करते रहते हैं। मुझे जब जरूरत होगी वे मुझे लौटा देंगे जबकि तुम्हारा खजाना बांझ है, वह कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा है।

प्रकृति की ताकत के आगे असहाय वैज्ञानिक

सनत जैन

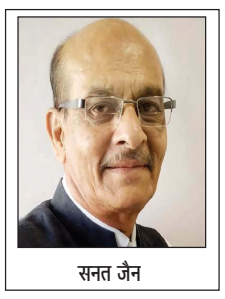

दुनिया में प्रकृति को नजर अंदाज करते हुए, मानवीय विकास को लेकर जो नए-नए शोध और कार्य हुए हैं। उनसे प्रकृति को जिस तरह से खुली चुनौती दी जा रही है। विकास के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए मानव विकास की जो नई संरचना तैयार की जा रही है। वह अपनी उच्चतम सीमा में पहुंच चुकी है। इस कारण अब प्रकृति ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रतिरोध करना शुरू कर दिया है। जिस मानवीय विकास की संरचना को बनाने में कई दशक लगे। प्रकृति ने उसे एक ही झटके में समाप्त कर, यह बता दिया है, कि सीमा रेखा तोड़ोगे तो उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। पांइस में स्थित आईटीआई का भवन जंगल की आग में पूरी तरह जल गया है। जंगल की आग नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। नैनीताल, भीमताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, कमाऊ के जंगल धधक रहे हैं। सेना एवं स्थानीय प्रशासन आग बुझाने में लगी। आग पर काबू पाने में बहुत समय लगा, जिससे जंगल ही बर्बाद हो गया। इसके पहले भी हिमालय की तराई में भू-स्खलन की सैकड़ो घटनाएं हो चुकी हैं। पहाड़ फट रहे हैं। पिछले दो दशकों में हिमालय के पहाड़ों को खोदकर जिस तरह बांध बनाए गए हैं। पावर स्टेशन खड़े किए गए हैं। रोड बनाने के लिए पहाड़ों को काटा गया है। रेल मार्ग के लिए पहाड़ों को एक-दूसरे से जुदा कर दिया गया है। इन सब कृत्यों से शांत पहाड़ों में ऐसा कंपन शुरू कर दिया गया, जिसके कारण हिमालय अब अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, मानवीय विकास की कल्पनाओं और संरचनाओं को एक ही झटके में धूल-धूसरित कर रहा है।

हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल ही शिमला, उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन की बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई। यहां का मौसम भी बड़ी तेजी के साथ बदलने लगा। अप्रैल के महीने में जून जैसी गर्मी पहाड़ों में पड़ रही है। हिमालय के ग्लेशियर पिघलने लगे। भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ रहा है। जो मानवीय एवं प्रकृतिजन्य जीवन के लिए सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्कर के लिए पहाड़ों और प्राकृतिक संरचनाओं को खोखला किया गया। इसका विरोध समय-समय पर वैज्ञानिकों, साधु संतों और (शंकराचार्यों) ने भी किया था। भारत सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थल भी अब सुरक्षित नहीं हैं। अयोध्या मैं रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों शंकराचार्यों ने कहा, जब तक मंदिर के शिखर का निर्माण नहीं होता है ऐसी अवस्था में भगवान प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। सरकार ने अहंकार के चलते, सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरुओं (शंकराचार्यों) की बात भी नहीं मानी। जबकि उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा था यदि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो प्रकृति-जन्य आपदा आना निश्चित है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चारों शंकराचार्य में से कोई भी शंकराचार्य शामिल नहीं हुआ। अब जिस तरह की प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही हैं। उसके बाद यही कहा जा सकता है, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किए जाने पर प्रकृति अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है। उसे ही प्राकृतिक आपदा कहा जाता है।

यहां केवल भारत की बात नहीं हो रही है। पूरी दुनिया के देशों में जिस तरह से प्रकृति को चुनौती देते हुए मानवीय विकास और मानवीय अहंकार के चलते जिस तरह से विकास और आग्नेयू शास्त्रों के माध्यम से राज करने का जो प्रयास हो रहा है, उसके कारण दुनिया के देश विनाश के रास्ते पर चल पड़े हैं। अब इसे प्राकृतिक आपदा कहें, या ईश्वर का प्रकोप कहें। इसमें सभी एक राय नहीं हो सकते हैं। विकास की इस दौड़ में मानव जाति अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति अथवा ईश्वर को चुनौती देने का काम कर रही है। यही कारण है, कि दुनिया के सारे देशों में अब प्राकृतिक आपदाएं बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। विकसित राष्ट्र भी अब इससे अछूते नहीं रहे। अमेरिका, यूरोपीय देश, रूस, चीन जैसी महाशक्तियों को भी प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ रही है। अरब के देशों में बाढ़ आ रही है, जहां रेत का समंदर है वहां बारिश का सैलाब बता रहा है कहीं कुछ तो गलत हुआ है। लगातार भूकंप के झटके दुनियां को सचेत कर रहे हैं, सुप्त ज्वालामुखी अब मुंह खोलने को तैयार नजर आने लगे हैं। ये प्राकृतिक आपदाओं से विकास इन्फास्ट्रक्कर नष्ट हो रहा है। वैसे भी मानवीय शक्ति जब-जब भगवान बनने की कोशिश करती है, तब-तब ईश्वर का (प्रकृति) प्रकोप इसी तरह से सामने आता है। इस खतरे की घंटी से सभी को सावधान होने की जरूरत है। भौतिक संसाधन और कृत्रिम विकास अल्पकालीन होते हैं, इन्हें दीर्घकालीन नहीं बनाया जा सकता है। इस तथ्य को सभी को समझना जरूरी है।

घोषणा पत्र की क्या जरुरत

संजय गोस्वामी

आज कल चुनाव में घोषणा पत्र पर एक दूसरे पर वार पे वार किये जा रहें है इसकी जरुरत ही नहीं क्योंकि दोनों का काम जनता ने देख लिया है वो ना तो घोषणा पत्र का पन्ना पढ़ कर वोट करने वाली है ना ही घोटाला पर किसी के लिए वो घोटाला लगेगा किसी के लिए सोची समझी नीति और कोई कुछ भी ना लें और नोटा पर वोट कर दें इसलिए चुनाव में लोगों की दिलचस्पी नहीं दिखा जो पहले थी अब इसपर नए सिरे से सोचेने की जरुरत है वोट मेरा अधिकार है जिसे देना जरुरी है दरअसल हर 10साल के बाद एंटीइनकॉवेंसी यानि सत्ता पक्ष में कुछ लोगों का विरोध तो होता ही है अब इतनी बड़ी जनसंख्या है 140करोड़ लोगों का देश जब मजदूर को खुश करेंगे तो उद्योगपति को नुकसान होगा और जब मजदूर काम करके भी नहीं खा सकेगा तो ऐ भी उद्योगपति को खुश रखना जैसे होगा,बस सेवा ही एक ऐसा हैजो एक जीवन का हिस्सा है किसी खेल में कोई हारता है कोई जीतता है लेकिन अपशब्द का प्रयोग किसी भी पार्टी के लिए घातक साबित होगी इसमें शांत रहकर लोगों की सेवा करना चाहिए जो जनता के दिल में जगह बनाएगी जो असली प्रेम होगा सेवा करना इंसान को सत्ता या उससे बाहर भी रहकर कर सकते हैं सत्ता में होंगे तो विरोधी आपका टांग खीचेंगे और जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो पावर नहीं होगा जीससे आप काम कर सकें लेकिन अनेकों उदाहरण है जो सत्ता से अलग रहकर भी लोगो की सेवा की और उसी आधार पर भगवान राम हो गए जो सबके पूज्य है सेवा के लिए पहली शर्त प्रेम हैं, अर्थात जिसके दिल में प्रेम हैं, वही सेवा कर सकता है। टॉल्स्टॉय ने कहा है, 'प्रेम स्वर्ग का रास्ता है।' बुद्ध का कथन है, 'प्रेम इंसानियत का एक फूल है और है और प्रेम उसका मधु।' रामकृष्ण परंमहंस ने कहा है, 'प्रेम संसार की ज्योति है।' विक्टर ह्यूगों का कहना है, 'जीवन एक फल है और प्रेम उसका मधु।' रामकृष्ण परंमहंस ने कहा है, 'प्रेम अमरता का समुदंर है।' कबीर का कथन है, 'जिस घर में प्रेम नहीं, उसे मरघट समझ–बिना प्राण के साँस लेने वाली लुहार की धौंकनी।'

ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।। उपरोक्त पंक्ति के रचियता कबीरदास हैं। इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाह रहें है कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुँच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। अलग–अलग शब्दों में सभी महापुरूषों ने प्रेम का बखान किया है। वास्तव में प्रम मानव-जाति की बुनियाद है। प्रेम ऐसा चुम्बक है, जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। जिसके हृदय में प्रेम है, उसके लिए सब अपने हैं। भारतीय संस्कृति में तो सारी पृथ्वी को एक कटुम्ब माना गया है–'वसुधैव कुटुम्बकम्।'

जो सबकों प्रेम करता है, उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं हो सकता। वह दूसरे के दिल में ऊँची भावना पैदा कर देता है। यदि गुस्सा होकर सूरज धूप और रोशनी न दे, धरती अन्न न दे, हवा प्राण न दे, तो सोचिए, हम लोगों की क्या हालत होगी! और प्रेम

इस तर्क मे बड़ी भूल है। ईश्वर ने सारे इंसानो को एक-सा बनाया है। आदमी आदमी मे कोई अन्तर नही रक्खा। अन्तर तो स्वयं आदमी ने पैदा किया है। एक आदमी दिमाग से काम करता है, दूसरा शरीर से। पहले को हम बड़ा मानते है और उसे अधिक पैसा देते है, दूसरे को किसान-मजूर कहकर छोटा मानते है। और उसकी कम कीमत लगाते है। लेकिन यह न्याय नही है। जो दिमाग काम करता है, उसे भी खाने को अन्न चाहिए और अन्न बिना शरीर की मेहनत के नही मिल सकता। शरीर से काम करे वाले को दिमागी काम करने वाले का सहारा चाहिए। इस तरह दोनों एक-दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरे का काम नही चल सकता।

पर आज का समाज उन्हें एक-दूसरे का पूरक या साथी मानता कहाँ है? बुद्धि से काम करने वाला शरीर की मेहनत को छोटा और ओछा मानता है और उससे बचता है। वह मानता है कि मजूर से मेहनत लेने का उसे अधिकार है ईश्वर सच्चिदानन्द है, असीम शक्ति का भंडार है। ईश्वर हमारे लिए एक अनन्त एवं अक्षय शक्तिस्त्रोत है। यदि आपका आत्मविश्वास विलुप्त हो चुका है, आप प्रभु भक्ति के द्वारा उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भावपूर्ण प्रार्थना करना एक विचित्र संबल देता है। धर्मों के नाम पर परस्पर घृणा का प्रचार करनेवाले तथा युद्ध भड़कानेवाले धर्म के तत्व एवं उद्देश्य को नहीं समझते हैं। संत किसी एक धर्म के खूंटे से नहीं बँधते हैं और सत्य का सत्कार करते हैं, वह चाहे जहाँ भी प्राप्त हो। एक सच्चा मानव मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा, मस्जिद को समान रुप से पवित्र मानता है तथा उसे अनेक मार्गों (धर्मों) के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अपनी व्यक्तिगत अनुभूति के आधार पर ईश्वरतत्व को पहचानना तथा अपने स्वभाव के अनुसार उसके साथ एक व्यक्तिगत नाता स्थापित करना ईश्वर-प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है।अतः घोषणा पत्र पर ध्यान ना देकर काम पर ध्यान देना चाहिए चंद्रयान 3की सफलता ने तो भारत में इतिहास बना दिया अगर घोषणा पत्र पर ध्यान देते तो कुछ नहीं होता एक होकर लगन से काम किया कल किसने देखा है उसकी भविष्यवाणी आज हम नहीं कर सकते है हाँ ऐ जरुर कर सकते है संकट में एक दूसरे के काम आजायेगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रधान संपादक : राघवेंद्र, पटना कार्यालय : रामनगरी आशियाना रोड, पटना/रांची कार्यालय: 201 मानस भवन,कांके रोड, रांची। संपर्क : 7488117482...

राष्ट्रीय सहारा
पटना • रविवार • 28 अप्रैल • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन
किसी विज्ञान को समझने के लिए उसका इतिहास जानना आवश्यक है।
-ऑगस्ट कॉम्टे

भाषण पर सवाल जवाब

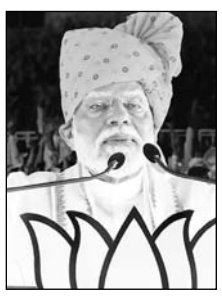

निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा में दिए भाषण पर भाजपा से जवाब मांगा है। कांग्रेस और वामदलों ने नरेन्द्र मोदी के भाषण को विभाजनकारी और महाहानिकर बताते हुए आयोग से शिकायत की थी। इसी पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने नोटिस दिया है। किसी पदेन प्रधानमंत्री के विरुद्ध आदर्श संहिता उल्लंघन मामले में यह पहली कार्रवाई है। आयोग का अपनी याददाश्त के आधार पर ऐसा दावा है। दूसरी तरफ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध भाजपा की शिकायतों पर जवाब मांगा गया है। ये जवाब 29 अप्रैल तक दिए जाने हैं। इस तरह से आयोग ने निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का एक कठिन पड़ाव पार कर लिया है। उसे इसका श्रेय मिलना चाहिए कि उसने संहिता उल्लंघन पर प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा। यह आरोप भी कमजोर हुआ है कि आयोग विपक्ष और कमजोर दलों के नेता को ही निर्देशित करने में आगे रहता है। पर उसका निर्णायक इम्तिहान दोनों दलों के जवाब पर की जाने वाली कार्रवाई में होगा जो आयोग की शक्ति और क्षेत्र को परिभाषित करने वाला होगा। सार्वजनिक जीवन में गरिमा-मर्यादा और नियम-कायदे का आग्रही तबके ही नहीं, पूरे देश ने देखा-सुना कि बांसवाड़ा में और फिर अलीगढ़ तक में खास समुदाय और धर्म के लोगों के बारे में क्या-क्या न कहा गया। माना कि चुनाव बाद एक प्रधानमंत्री के रूप में आप समुदाय-धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते पर यही भाव चुनावी सभाओं में भी रहना बुरा नहीं होता। यह सामान्य जन अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री को तमाम विभाजनों और दोष-रेखाओं से ऊपर होना चाहिए। तब आयोग को भी रिकार्ड बनाने का मौका नहीं मिलता। चुनाव की घोषणा करते हुए आयोग ने भाषणों में सभ्यता के निर्वाह का अनुरोध दलों से किया था, जिसका पालन किसी ने नहीं किया। विपक्ष में स्थितिजन्य आक्रामकता स्वाभाविक ही होती है। सत्ता अपने व्यवहार से उसको परिमार्जित करती है। खरगे और राहुल सरकार की नीतियों की आलोचना के अधिकार के प्रयोग में सभ्यता भूलते रहे हैं। वे न केवल प्रधानमंत्री को निजी स्तर चोट पहुंचाने वाली भाषा का धड़ल्ले से प्रयोग करते सुने-देखे गए हैं, बल्कि तू-तड़ाक पर भी उतर आए हैं। यह भी रिकार्ड है कि नरेन्द्र मोदी देश के सर्वाधिक आलोच्य प्रधानमंत्री हैं। अगर यही एक परिपक्व लोकतंत्र की भाषा है तो यह वाकई बेहद पीड़ादायक परिदृश्य है।

सुविधाजनक संचार

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट अब व्हाट्सऐप संदेशों द्वारा जानकारी साझा करेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी के पिच्छत्तरवें वर्ष में यह छोटी सी योजना की शुरुआत की है। व्हाट्सऐप के रोजाना की जिंदगी में शामिल होने और इसके शक्तिशाली संचार सुविधा होने की बात भी उन्होंने की। इस पहल के अंतर्गत एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तथा शीर्ष अदालत के समक्ष निजी तौर पेश होने वाले वादियों को मुकदमा ऑनलाइन दाखिल करने, वाद सूची, आदेशों तथा निर्णयों के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे क्रांतिकारी कदम बताते हुए इसकी सराहना की। प्रधान न्यायाधीश ने व्हाट्सऐप नम्बर साझा करते हुए स्पष्ट किया कि इस पर कॉल या संदेश प्राप्त नहीं होंगे। निःसंदेह यह सबसे बड़ी अदालत को पेपरलेस बनाने की तरफ उठा बड़ा कदम है। तकनीक संबंधी सुविधाओं को जितनी जल्दी हो सके रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेना उचित होता है। प्रधान न्यायाधीश निरंतर अदालती काम को लेकर ऐसी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट जजों में सबसे ज्यादा फैसले लिखने का रुतबा प्राप्त है। छह वर्ष के भीतर 513 फैसले लिख चुके हैं। न्याय व्यवस्था को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए समय-समय पर उन्होंने बड़े कदम उठाए हैं। विभिन्न फैसलों को उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में अनुदित करवाने की व्यवस्था करके तथा हिन्दी, तमिल, उड़िया और गुजराती में फैसलों का अनुवाद करने के लिए समिति का गठन भी किया। देश में 48 करोड़ से अधिक व्हाट्सऐप प्रयोगकर्ता हैं, जो 2025 तक 80 करोड़ तक पहुंचने का अंदाजा है। हालांकि व्हाट्सऐप मेटा टेक्नॉलाजी कंपनी की सुविधा है, जिसके सीईओ मार्क जकरबर्ग हैं। किसी भारतीय संचार संस्थान को इस जरूरत को समझते हुए आगे कदम बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सरकार, देश के अन्य बड़े संस्थान और गोपनीय दस्तावेज के लिए देसी तकनीक का प्रयोग किया जाना उचित है। तकनीक के मामले में हम दूसरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यह बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके तकनीक का इस्तेमाल सुविधाओं के लिए करना वक्त की मांग है, इसके बिना काम नहीं चल सकता।

कटाक्ष/ कबीरदास

सूरत मॉडल पे ही जा!

भई मोदी जी की ये बात हमारी समझ में तो नहीं आई। बताइए, कामयाब सूरत मॉडल आने के बाद भी, बहनों और माताओं के मंगलसूत्र में ही अटके हुए हैं। नहीं, हम यह नहीं कह रहे हैं कि उन्हें इसका ख्याल करके इस चक्कर से बचना चाहिए था कि सारी वफादारी के बावजूद बेचारे चुनाव आयोग को कोई नोटिस-वोटिस न देना पड़ जाए। इसका ख्याल करके तो हर्गिज नहीं कि देश तो देश, दुनिया भर में कैसा डंका बजेगा। वह सब नहीं। पर जब सूरत मॉडल खोज लिया है, फिर उसी पर ध्यान लगाते, मंगलसूत्र के लिए माथाफोड़ी करने की क्या जरूरत थी। बताइए, सूरत मॉडल को कामयाब होते सबने देखा है कि नहीं। एकदम अचूक।

सिंदूर कर लो, हिन्दू-मुस्लिम कर लो, गारंटी कर लो, 2047 वाला विकास कर लो, सब में आखिरकार पब्लिक बीच में आती ही आती है। और पब्लिक को गोदी मीडिया के बल पर चाहे कितना सिखा-पढ़ा लो, चाहे अपने उद्धारकर्ता होने का उसे कितना ही भरोसा दिला लो, चाहे उसका माथा कितना ही घुमा लो, गर्म करा लो, उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। कब गर्व-वर्व सब भूल कर, पब्लिक अपने पेट की आवाज सुनने लग जाए, कह नहीं सकते। देखा नहीं कैसे सब कुछ करने-कराने के बाद भी, कैसे नासपीटी ने पहले चरण की वोटिंग से नागपुर वालों का ही दम फुला दिया। फिर जब सूरत से एकदम अचूक मॉडल हाथ आ गया है, पब्लिक-वब्लिक के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही क्या है? और सच पूछिए तो सूरत मॉडल सिर्फ अचूक ही नहीं है, बहुत ही सस्ता और टिकाऊ भी है। खरीद-वरीद के जीतने से तो सस्ता और टिकाऊ है ही, पब्लिक को बहला-फुसला कर बटन दबवाने के मुकाबले भी, काफी सस्ता और टिकाऊ है।

मुकेश दलाल की बिना चुनाव की सांसदी, चुनाव वाली सांसदी से तो बहुत सस्ती पड़ी ही होगी। और कामयाबी की गारंटी ऊपर से। हम तो कहते हैं कि मोदी की असली गारंटी तो यही है। बिना चुनाव के जीत की गारंटी। बॉन्ड का पैसा, पुलिस, ईडी, सीबीआई सलामत रहें, विरोधी उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिलेगा। जो फिर भी ना माने, शौक से जेल से चुनाव लड़ सकता है। तब हिचक क्या है; हिम्मत करके एक बार देश भर में सूरत मॉडल आजमाएं, और बेशक, पांच सौ पार का झंडा फहराएं।

भारत विरोध पर मुहर

मालदीव

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

हिन्द महासागर में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए बीजिंग और नई दिल्ली, दोनों मालदीव को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखने के लिए कृतसंकल्पित रहे हैं। इसका असर मालदीव की घरेलू राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित इस द्वीपीय देश में मुइज्जू के राजनीतिक उभार से भारत की समस्याएं बढ़ रही हैं। दरअसल, मुइज्जू भारत की मालदीव में उपस्थिति को अनियंत्रित बता कर देश की सत्ता के शीर्ष पर आए हैं, और भारत विरोध की नीति के सहारे देश की संसद में पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब मुइज्जू ने जिस प्रकार देश की संसद में भी बंपर बहुमत हासिल किया है, उससे लगता है कि उनके भारत विरोध और चीन परस्त नीतियों को जनता ने पसंद किया है। ऐसे में यह विचार लाजिमी है कि आखिर, मालदीव की जनता भारत जैसे विश्वसनीय मित्र के खिलाफ जाकर चीन की कुटिल कर्जनीति में क्यों उलझना चाहती है, और इसके दूरगामी परिणाम भारत के लिए कितने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जनसंख्या की लिहाज से बहुत छोटे इस इस्लाम बाहुल्य देश में पिछले कुछ वर्षों में परंपरावाद को उभारने की कोशिशें राजनीतिक फायदा देने वाली साबित हुई हैं।

खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाने वाले मालदीव के हजारों नागरिकों की कथित धार्मिक अभिव्यक्ति को मुइज्जू ने वोट में बदलने में कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने भारत से ऐतिहासिक जुड़ाव को नजरअंदाज कर बदलती परिस्थितियों में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब की ओर रुख किया। फिलिस्तीन जैसे भावनात्मक मुद्दे को धार्मिक आधार पर उठाया तथा इस्लामिक आदर्शवाद पर आधारित नये मालदीव की परिकल्पना को राजनीतिक आधार पर जनता के सामने रखा। मुइज्जू ने संसद में संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत हासिल कर लिया है। अर्थ यह कि वे राजनीतिक संस्थागत दृष्टिकोण से, सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं खासकर न्यायपालिका की शक्तियां भी प्रभावित हो सकती हैं। मालदीव में राजनीतिक उथल-पुथल का इतिहास रहा है। भारत समर्थक राजनीतिक दलों पर अंकुश लगाने के लिए मुइज्जू प्रमुख नेताओं को जेल में डाल सकते हैं।

मुइज्जू ने सत्ता में आने के बाद चीन से मजबूत रिश्तों को तरजीह दी। वे अब तक नई दिल्ली नहीं आए हैं, बीजिंग की राजकीय यात्रा पर जाकर निवेश के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। चीन के साथ गैर-घातक हथियारों को मुफ्त में देने के साथ-साथ मालदीव के सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करने के लिए एक सैन्य सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और अमेरिका ने पहले मालदीव की सेना को प्रशिक्षित किया था। भारत मालदीव को हिन्द महासागर क्षेत्र में प्रमुख समुद्री भागीदार के रूप में मान्यता देता है।

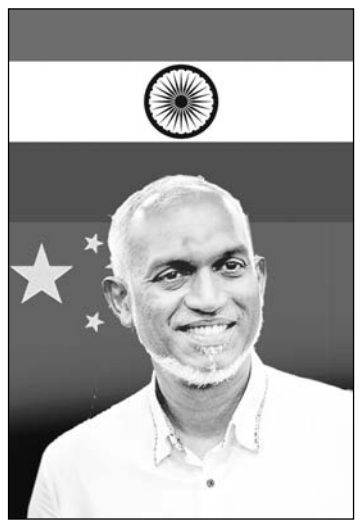

यह द्वीपीय राष्ट्र भौगोलिक दृष्टि से भारत और कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों पर नजर रखता है। भारत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि मालदीव व्यापार, पर्यटन और शिपिंग के लिए रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है। मालदीव रणनीतिक रूप से लक्षद्वीप द्वीप समूह से केवल सात सौ किलोमीटर और भारत की मुख्य भूमि से बारह सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मालदीव में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत से इसकी निकटता को देखते हुए महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं को जन्म देता है। हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन ने तेजी से सैन्य आधुनिकीकरण किया है, इससे भारत की सामरिक और आर्थिक क्षमताओं के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं।

हिन्द महासागर में बीजिंग के बढ़ते प्रभाव और उसकी महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल में मुइज्जू की दिलचस्पी कम नहीं है। 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर मोहम्मद मुइज्जू के चुने जाने के बाद से क्षेत्र में देश के रिश्ते बदल गए हैं। मालदीव ने चीन के साथ रक्षा समझौतों और बुनियादी ढांचे के सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन के समुद्री अनुसंधान जहाज जियांग यांग होंग को मालदीव के बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति देने से चीन का प्रभाव और भी पुष्ट होता है। जनवरी में जब मुइज्जू ने चीन का दौरा किया था, इसके चौबीस घंटे के बाद चीन के इस जहाज ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी।

संभवतः मुइज्जू इसके जरिए भारत को यह संदेश भी दे देना चाहते थे कि वे चीन से रिश्तों को लेकर कोई समझौतावादी रुख नहीं अपनाएंगे। बारह सौ द्वीपों की श्रृंखला से बने मालदीव के अधिकांश द्वीप निर्जन हैं। मालदीव लंबे समय से भारत के प्रभाव क्षेत्र में रहा है। वहां अपनी मौजूदगी बनाए रखने से दिल्ली को हिन्द महासागर के एक प्रमुख हिस्से पर नजर रखने की क्षमता मिलती है।

मुइज्जू को देश में चीन के हितों के समर्थक के रूप में देखा जाता है। भारत और चीन, दोनों रणनीतिक रूप से स्थित द्वीपों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो व्यस्त पूर्व पश्चिम शिपिंग लेन में फैले हुए हैं। चीन, अपनी तेजी से बढ़ती नौसेना के साथ, रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान तक पहुंच तथा भारत को रोकना चाहता है। दिल्ली और बीजिंग, दोनों ने मालदीव को बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान के रूप में करोड़ों डॉलर दिए हैं। मुइज्जू अब चीन पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं, और यह भारत के लिए चुनौतीपूर्ण बन रहा है।

भारत को हिन्द महासागर के अहम साझेदार मालदीव के साथ राजनीतिक गतिरोध को दूर करने की कोशिशें करते रहना होगा। आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता देनी होगी। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे प्रमुख सुरक्षा भागीदारों के साथ भी रक्षा सहयोग को मजबूत करना होगा जिससे चीन को इस क्षेत्र में निर्णायक रणनीतिक बढ़त लेने से रोका जा सके। चीन मालदीव जैसे छोटे से देश की भारत पर सैन्य निर्भरता कम करने के लिए उसकी सैन्य क्षमताओं का विकास कर रहा है, इससे मालदीव की सेना मजबूत होगी और इसके राजनीतिक दुरुपयोग की आशंकाएं भी बढ़ सकती हैं। मुइज्जू चीन के उस सामरिक चक्रव्यूह को रचने में मददगार बन रहे हैं, जिसके अनुसार चीन मालदीव में नौसैनिक अड्डा बना कर समुद्री सीमा पर भारत को रणनीतिक रूप से घेर ले जिससे हिमालय की सीमा पर भारत पर सैन्य दबाव बढ़ सके।

भारत को हिन्द महासागर के अहम साझेदार मालदीव के साथ राजनीतिक गतिरोध को दूर करने की कोशिशें करते रहना होगा। आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता देनी होगी। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे प्रमुख सुरक्षा भागीदारों के साथ भी रक्षा सहयोग को मजबूत करना होगा जिससे चीन को इस क्षेत्र में निर्णायक रणनीतिक बढ़त लेने से रोका जा सके

मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में 8.1 फीसद की वृद्धि

- **देश के मीडिया और मनोरंजन (एमएंडई) क्षेत्र में 2023 में 8.1 फीसद की वृद्धि हुई और यह 2.32 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया**
- **उद्योग मंडल फिक्की और ईवाई की एक संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक, इसके 2024 में 2.53 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने और 2026 तक तीन लाख करोड़ रुपये को पार करने की संभावना है**

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

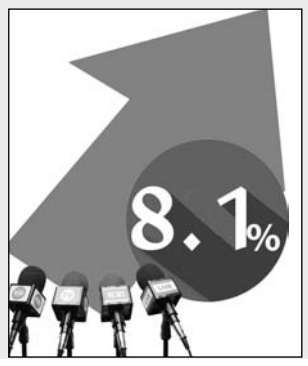

हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं। पर समाज व राजनीति के बारे में हमारे कुछ विचार जरूर हैं। आज सुबह एक विचार आपके सामने रख रहा हूं: ऐसे लोगों/दलों को हरगिज वोट मत दीजिये जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। ऐसे लोग धर्म के 'धंधेबाज' होते हैं, ये देश और समाज का भला नहीं करते! जय हिंद!

उर्मिलेश, पत्रकार
@UrmileshJ

हथियारों की होड़ चिंताजनक

मुद्दा | ललित गर्ग

शांति के तमाम उपायों के बीच दुनिया भर में सैन्य खर्च, शस्त्रीकरण एवं घातक हथियारों की होड़ खतरे की घंटी हैं। शस्त्रीकरण के भयावह दुष्परिणामों से समूचा विश्व भयाक्रांत है। हर पल आणविक हथियारों के प्रयोग को लेकर दुनिया डर के साये में जी रही है। इसीलिए आज अयुद्ध, निशस्त्रीकरण एवं शांति की आवाज चारों ओर से उठ रही हैं। शक्ति संतुलन के लिए शस्त्र-निर्माण एवं शस्त्र संग्रह की बात से किसी भी परिस्थिति में सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि इससे अपव्यय तो होता ही है, साथ ही गलत हथियारों के हाथों में पड़कर दुरुपयोग की आशंकाएं बढ़ जाती हैं।

ताजा घटनाक्रम को देखें तो एक ओर रूस और यूक्रेन आमने-सामने हैं, दूसरी तरफ इस्राइल और ईरान के बीच तल्खी भी चरम पर है। चीन और ताइवान के बीच भी रह-रह कर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे माहौल में सवाल स्वाभाविक है कि क्या सचमुच दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हुए घातक हथियारों की प्रयोगभूमि बन रही है? सवाल और भी हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हथियारों पर ताजा रिपोर्ट ऐसे ही सवाल खड़े कर रही है। दुनिया सीधे-सीधे दो खेमों में बंट गई है। स्टॉकहोम की रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले ही नहीं, डराने वाले भी हैं। शांति के तमाम उपायों के बीच दुनिया भर में सैन्य खर्च का बढ़ना एवं नये-नये हथियारों का बाजार गरम होना, चिंताजनक है। रिपोर्ट में खास बात यह है कि दुनिया में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत चौथे नंबर पर बरकरार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। भारत ने बीते पांच साल में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोप का हथियार आयात 2014-18 की तुलना में 2019-23 में लगभग दोगुना बढ़ा है, जिसके पीछे रूस-यूक्रेन युद्ध बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा हथियार एशियाई देशों ने खरीदे। इस लिस्ट में रूस-यूक्रेन युद्ध ने देश के रक्षा निर्यात को काफी प्रभावित किया है। इस कारण पहली बार रूस हथियार निर्यात में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है तो अमेरिका पहले और फ्रांस दूसरे नम्बर पर हैं। पिछले 25 सालों में पहली बार अमेरिका एशिया और ओशिनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा।

अमेरिका की हथियारों की होड़ एवं तकनीकीकरण की दौड़ पूरी मानव जाति को ऐसे कोने में धकेल रही है, जहां से लौटना मुश्किल हो गया है। अब तो दुनिया के साथ-साथ अमेरिका स्वयं ही हथियारों एवं हिंसक मानसिकता का शिकार है। अमेरिका ने दुनिया पर आधिपत्य स्थापित करने एवं अपने शस्त्र कारोबार को पनपाने के लिए जिस अपसंस्कृति को दुनिया में फैलाया है, उससे पूरी मानवता पीड़ित है। अमेरिका ने नई विश्व व्यवस्था (न्यू वर्ल्ड ऑर्डर) की बात की है, खुलेपन की बात की है। लगता है कि 'विश्व मानव' का दम घुट रहा है, और घुटन से बाहर आना चाहता है। विडंबना देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली और सुरक्षित देश है, लेकिन उसके नागरिक सबसे अधिक असुरक्षित और भयभीत नागरिक हैं। वहां की जेलों में आज जितने कैदी हैं, दुनिया के किसी देश में नहीं हैं। कई वाकये हो चुके हैं कि किसी रेस्तरां, होटल या फिर जमावड़े पर अचानक किसी सिरफिरे ने गोलीबारी शुरू कर दी और बड़ी तादाद में लोगों को मार डाला। 2014 में अमेरिका में हत्या के दर्ज सवा चौदह हजार मामलों में अड़सठ फीसद मामलों में बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था।

दरअसल, मनुष्य के भयभीत मन को युद्ध एवं हथियारों की विभीषिका से मुक्ति दिलाना जरूरी है। युद्धरत देशों में शांति स्थापित कर, युद्ध-विराम करके विश्व को निर्भय बनाना चाहिए। निश्चय ही यह किसी एक या दूसरे देश की जीत नहीं, बल्कि समूची मानव-जाति की जीत होगी। यथार्थ यह है कि अंधकार प्रकाश की ओर चलता है, पर अंधापन मृत्यु-विनाश की ओर। रूस ने अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य का अहसास गलत समय पर गलत उद्देश्य के लिए कराया है। युद्ध से तबाही रूस-यूक्रेन की नहीं, बल्कि समूची दुनिया की तबाही होगी, क्योंकि रूस परमाणु विस्फोट करने को विवश होगा जो दुनिया की बड़ी चिंता का सबब है। बड़े शक्तिसंपन्न देशों को युद्ध विराम के प्रयास करने चाहिए। लेकिन प्रश्न है कि जो देश हथियारों के निर्माता हैं, वे क्यों चाहेंगे कि युद्ध विराम हो। जब तक शक्तिसंपन्न देशों की शस्त्रों के निर्माण एवं निर्यात की भूख शांत नहीं होती तब तक युद्ध की आशंकाएं मैदान में, समुद्र में, आकाश में तैरती रहेंगी।

अध्यात्म | संत राजिन्दर

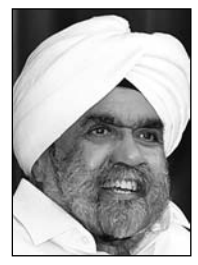

हम अपना जीवन भौतिक और बौद्धिक लक्ष्यों को पाने में लगा देते हैं, पर हम अध्यात्म से अनजान ही रहते हैं। जब भौतिक मृत्यु की उफनती लहरें हमारे ऊपर आ जाती हैं, तो हम में कोई आध्यात्मिक क्षमता नहीं होती कि हम अपने जीवन के अंत में से आसानी से निकल सकें। जब हमें खबर मिलती है कि हमें एक जानलेवा बीमारी है, या अचानक हमें अपनी मृत्यु दिखाई देती है, तो हम भयभीत हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। हमने अपना समय जीवन और मृत्यु का सच्चा अर्थ समझने में नहीं लगाया होता है, और हम अपने अंत से डर जाते हैं। जिन व्यक्तियों ने ध्यान-अभ्यास के द्वारा आध्यात्मिक धारा में तैरना सीखने में अपना जीवन गुजारा है, उन्हें कोई डर नहीं होता। वे अपने अंत का शांति और निडरता से सामना करते हैं। कैसे? वे इसी जीवन में परलोक के जीवन की शान देख चुके होते हैं। वे देहाभास से ऊपर उठने की कला सीख चुके होते हैं, और स्वयं परलोक के क्षेत्रों को देख चुके होते हैं। जब उनका भौतिक अंत आता है, तो उन्हें किस बात का डर होगा? जब उनके शरीर की भौतिक नाव डूबने वाली होगी तो उन्हें परलोक में तैरना आता होगा। अधिकतर इंसान भौतिक मृत्यु की सच्चाई की तब तक उपेक्षा करते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। वे समझते हैं कि बौद्धिक ज्ञान, धन-संपत्ति, नाम और सत्ता अर्जित करना ही अधिक महत्त्वपूर्ण है, पर जब मृत्यु पास आती है तो उन्हें अनुभव होता है कि बौद्धिक ज्ञान और सांसारिक जायदाद किसी काम की नहीं हैं। उस अवसर पर वे पछताते हैं कि उन्होंने आत्मा, परमात्मा और परलोक की जानकारी पाने में अधिक समय क्यों नहीं व्यतीत किया। जो व्यक्ति छोटी उम्र में अध्यात्म की शिक्षा पा लेते हैं, वे भाग्यशाली हैं। वे प्रति दिन कुछ समय अपने आध्यात्मिक अभ्यास में लगा सकते हैं ताकि इसी जीवन में देहाभास से ऊपर उठने की कला में माहिर हो सकें। तैरने के जैसे, इसका अभ्यास करना पड़ता है। दैनिक ध्यान-अभ्यास से हमारी आध्यात्मिक कुशलता तो विकसित होगी ही जिससे हम वहां पर पहुंच सकें, जहां पर हम अंतर के रूहानी मंडलों का अनुभव पा जाएं।

रीडर्स मेल

सोच-समझ कर वोट करें

चुनाव के इस असंतुलित वातावरण में चारों ओर नई सरकार के चुने जाने का उत्साह दिखाई देता है। एक पक्ष को अनजाने में या फिर उसकी प्रासंगिकता का क्षीण हो जाने के कारण कोई देख नहीं रहा। इस चुनाव से कहीं महत्त्वपूर्ण है जीवन के अनेक पड़ावों में से सही या गलत का चुनाव, सुख को प्राप्त करने की चाहत में अनचाहे दुखों का चुनाव, जीवन के हर पड़ाव पर स्वयं की अस्मिता को व्यक्त करने का चुनाव और उससे भी महत्त्वपूर्ण है अपने अस्तित्व का चुनाव। यह सुनकर आपको शायद अटपटा लग रहा होगा लेकिन आधुनिक युग में हम अपने अस्तित्व का चुनाव स्वयं नहीं करते हैं। कभी स्थिति के चलते तो कभी आर्थिक रूप से कमजोर होना हमसे उस भविष्य का चुनाव करवा देता है, जो हम नहीं करना चाहते। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि लोकतंत्र में किसका चुनाव किया जाए। किसको चुना जाए। ऐसा चुनाव कैसे किया जाए। सोचना जरूरी है।

प्रिया कुशवाह, ई मेल से

नियमों की अनुपालना जरूरी

पराली जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद पराली जलाई जा रही है, हिमालय की चोटियों से लगा कर सागर की तलहटी तक प्लास्टिक, पोलिथिन और ई-वेस्ट कचरे से भर चुकी हैं, और जैव-विविधता तथा पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, नदियों में कूड़ा-करकट फेंक कर उन्हें गंदा किया जा रहा है, तापमान बढ़ने से हिमाच्छादित ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ गई है जिससे कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। अमानक पोलिथिन पर बेन के बावजूद इसका उत्पादन, विक्रय और उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे संभव होगा, इस पर रोकथाम के लिए सख्त नियमों की दरकार है। सिर्फ सख्त नियमन ही नहीं, उनकी अनुपालना भी जरूरी है।

संजय सिंह, गया

क्यों लगे विरासत कर?

हाल ही में सैम पित्रोदा के संपत्ति में 55 परसेंट सरकार द्वारा ले लिए जाने के कानून का समर्थन करने की बाबत सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे इसी प्रकार के मामले में बहस जारी है। सरकार को तरह-तरह के टैक्स लगाकर, जीएसटी में बड़ी भारी आमदनी प्राप्त हो रही है। पेट्रोलियम पदार्थों पर, शराब पर शत-प्रतिशत से अधिक टैक्स वसूलने के बाद भी सरकारों की नजर जनता के धन पर लगी रहती है। सभी तरह के टैक्स चुका कर कठोर परिश्रम से एकत्र किए गए धन पर फिर से कुंडली मारने की मंशा स्वीकार करने योग्य नहीं है, और ऐसी स्थिति में तो और भी जब सरकारी संसाधनों को वोट कबाड़ने के लिए कर्ज लेकर दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है। महिलाओं को, किसानों को अरबों रुपये नकद दिए जा रहे हैं। अस्सी करोड़ लोगों को अगले पांच साल तक मुफ्त अनाज बांटने की घोषणा हो चुकी है। दिन-रात एक कर के सभी प्रकार के करों का भुगतान करने के बाद भी हर कार्य के लिए रिश्वत देकर अपने परिवार का पेट पालने के बाद संतानों के भविष्य के लिए संग्रहित किए जाने वाले धन को भी छीनने की मंशा निंदनीय है, और इसका देश भर में जोरदार विरोध होगा।

सुभाष बुडावन वाला, ई मेल से
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 18, अंक 6285 — आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07 — *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

टीएन शेषन ने बदली थी भारत के अराजक चुनावों की तस्वीर

ऐसे में देश को एक ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त मिलता है, जो पूरी चुनाव व्यवस्था को बदलकर रख देता है। बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं को नकेल कस देता है। उस मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है टीएन शेषन। आज अगर देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल में चुनाव हो पाता है तो इसका श्रेय टीएन शेषन को जाता है।

देश की मौजूदा पीढ़ी को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि भारत की आजादी के बाद की ऊबड़-खाबड़ यात्रा में देश के ऐसे-ऐसे हिचकोले खाए कि लगने लगा था कि लोकतंत्र पटरी से उतर कर अराजकता में बदल जाएगा। इसी यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती थी, देश के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना। आज जिस तरह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराए जा रहे हैं। करीब साढ़े तीन दशक पहले इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। उस दौर में ऐसा कोई भी चुनाव नहीं रहा जो खून-खराबे से भरा नहीं रहा हो। देश में बैलट पर बुलट भारी था। बंदूक की नोक पर वोटों की पेटियों को लूटना आम बात थी। भारत की चुनावी प्रक्रिया में हर तरह की बुराई थी। ऐसे में देश को एक ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त मिलता है, जो पूरी चुनाव व्यवस्था को बदलकर रख देता है। बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं को नकेल कस देता है। उस मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है टीएन शेषन। आज अगर देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल में चुनाव हो पाता है तो इसका श्रेय टीएन शेषन को जाता है। देश के दबंग चुनाव आयुक्त के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले टीएन शेषन नौकरशाही में भी सुधार के जनक थे। ईमानदारी और कानून के प्रति अपनी निष्ठा की वजह से वह बहुतों को खटकते भी थे। इस वजह से उनके विरोधी उनको सनकी और तानाशाह तक भी कहते थे। लेकिन वह व्यवस्था में क्रांति लाने वाले इंसान, मेहनती, सक्षम प्रशासक, योग्य नौकरशाह, बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग के नायक थे। पलक्कड़ (केरल) के निवासी टीएन शेषन ने 1955 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में ट्रेनी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। शेषन ने अपनी पहली तैनाती में ही तीखे तेवर दिखाते हुए तमिलनाडु के मदुरई जिले के डिंडीगुल में सब कलेक्टर पद पर रहते हुए हरिजन समुदाय के एक व्यक्ति पर फंड के घपले का आरोप में गिरफ्तार करवा दिया। मंत्री के दबाव के बाद भी आरोपी को नहीं छोड़ा। चेन्नई में यातायात आयुक्त पद के दौरान एक बार एक ड्राइवर ने शेषन से पूछा कि अगर आप बस के इंजन को नहीं समझते और ये नहीं जानते कि बस को कैसे चलाया जाता है, तो आप ड्राइवरों की समस्याओं को कैसे समझ पाएंगे। शेषन ने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने न सिर्फ.बस की ड्राइविंग सीखी बल्कि बस वर्कशॉप में भी काफी समय बिताया। एक बार उन्होंने बीच सड़क पर ड्राइवर को रोक कर स्टेयरिंग संभाल लिया और यात्रियों से भरी बस को 80 किलोमीटर तक चलाया। शेषन का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से काफी झगड़ा हो गया, जिसके बाद वे प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली आ गए और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के एक सदस्य के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आग्रह पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव बन गए। सचिव के तौर पर उन्होंने टिहरी बांध और सरदार सरोवर बांध जैसी परियोजनाओं का विरोध किया। भले ही सरकार ने उनके विरोध को दरकिनार कर दिया और परियोजना पर काम को आगे बढ़ाया लेकिन बांध के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया गया।

इसके साथ ही देश भर में शेषन ने विभागों में नहीं कहने का रुझान शुरू किया। इस दौरान राजीव गांधी से उनकी नजदीकी बढ़ी। वहां से उनको आंतरिक सुरक्षा का सचिव बनाया गया। करीब 10 महीनों बाद उनको कैबिनेट सचिव बनाया गया। जब राजीव गांधी दिसंबर 1989 में चुनाव हार गए और प्रधानमंत्री नहीं रहे तो टीएन शेषन का ट्रांसफर योजना आयोग में कर दिया गया। शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की दास्तां भी कम दिलचस्प नहीं है। दिसंबर 1990 केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और शेषन के दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के दूत के तौर शेषन पर मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की पेशकश की। शेषन इस प्रस्ताव से बहुत अधिक उत्साहित नहीं हुए थे, क्योंकि पहले ही कैबिनेट सचिव विनोद पांडे ने भी उन्हें ये प्रस्ताव दिया था। शेषन इस प्रस्ताव पर राजीव गांधी से मिले। राजीव गांधी ने शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति दे दी। लेकिन वो इससे बहुत खुश नहीं थे। उन्होंने उन्हें छेड़ते हुए कहा कि वो दाढ़ी वाला शख्स (चंद्रशेखर) उस दिन को कोसेगा, जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला किया था। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने साठ के दशक में तमिलनाडु में शेख को नज?बंद करवा दिया था। शेषन उस समय मदुरै जिले के कलेक्टर थे। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो शेख बाहर भेजे हुए पत्र को पढ़ें। शेख ने डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पत्र लिखा। शेषन ने बिना डरे पत्र पढ़ लिया। शेख ने घोषणा की कि वो उनके साथ किए जा रहे ख?ब व्यवहार के विरोध में आमरण अनशन पर जाएंगे। शेषन ने कहा कि सर ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई आपके सामने पानी का एक गिलास भी ले कर न आए। शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव के धर्मराजन त्रिपुरा में हो रहे चुनावों का पर्यवेक्षक का कार्य छोड़ कर थाईलैंड चले गए। इस पर दंडित करते हुए शेषन ने उनकी गोपनीय रिपोर्ट में विपरीत प्रवृष्टि करने का फैसला किया। शेषन ने वर्ष 1993 में 17 पेज का आदेश जारी किया कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देती, तब तक देश में कोई भी चुनाव नहीं कराया जाएगा। आखिरकार सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। मौजूदा आदर्श आचार संहिता उसी आदेश का परिणाम है। शेषन के आने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एक आज्ञाकारी नौकरशाह होता था जो वही करता था जो उस समय की सरकार चाहती थी। ये शेषन का ही बूता था कि उन्होंने चुनाव में पहचान पत्र का इस्तेमाल आवश्यक कर दिया। शेषन ने साफ कह दिया कि अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं बनाए, तब 1 जनवरी 1995 के बाद भारत में कोई चुनाव नहीं कराए जाएंगे। शेषन के दौर में ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दिन पंजाब के मंत्रियों के 18 बंदूकधारियों को राज्य की सीमा पार करते हुए धर दबोचा गया। उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा पर तैनात नागालैंड पुलिस ने बिहार के विधायक पप्पू यादव को सीमा नहीं पार करने दी। हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल गुलशेर अहमद को चुनाव आयोग द्वारा सतना का चुनाव स्थगित करने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। गुलशेर अहमद पर चुनाव आयोग के राज्यपाल पद पर रहते हुए अपने पुत्र के पक्ष में सतना चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया था। उसी तरह राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल बलिराम भगत को भी शेषन का कोपभाजन बनना पड़ा था, जब उन्होंने एक बिहारी अफसर को पुलिस का महानिदेशक बनाने की कोशिश की। शेषन ने बिहार में पहली बार चार चरणों में चुनाव करवाया और चारों बार चुनाव की तारीखें बदली गईं। ये बिहार के इतिहास का सबसे लंबा चुनाव था। शेषन ने आचार संहिता के उल्लंघन पर पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं होने दिया, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु इतने नाराज हुए कि उन्होंने उन्हें पागल कुत्ता कह डाला। साल 1992 के शुरू से ही शेषन ने सरकारी अफसरों को उनकी गलतियों के लिए लताड ?ा शुरू कर दिया था। उसमें केंद्र के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल थे। बीते दशकों में टीएन शेषन से ज्यादा नाम शायद ही किसी नौकरशाह ने कमाया हो। वर्ष 1990 के दशक में तो भारत में एक मजाक प्रचलित था कि भारतीय राजनेता सिर्फ.दो चीजों से डरते हैं। एक खुदा और दूसरे टीएन शेषन से। - योगेन्द्र योगी

अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारत के साथ व्यापार शुरू करने को आतुर पाकिस्तान !

अशोक भाटिया

मीडिया समाचारों के अनुसार अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पाकिस्तान लगातार हाथ पैर मार रहा है। अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार में विदेश मंत्री और नवाज शरीफ के समधि इशाक डार ने भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की बातचीत पर जोर दिया है। शहबाज शरीफ के मंत्री का यह बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ फिर से व्यापारिक संबंधों की शुरुआत करने को आतुर है। बीते सालों में ऐसा देखा गया है पाकिस्तान के मंत्री अक्सर भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को शुरू करने के लिए जोर दे चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने किसी अन्य देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर को रोककर उनसे प्याज और टमाटर पाकिस्तान भेजने की गुहार लगा चुके हैं। गौरतलब है कि डार ने पहली बार पिछले महीने लंदन में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने की संभावना का संकेत दिया था। उनका विचार था कि पाकिस्तान का व्यापारिक समुदाय पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार संबंधों की बहाली चाहता है। उनके बयान की विपक्षी दलों और आलोचकों ने आलोचना की। हालांकि, डार ने गुरुवार को अपनी पिछली टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा कि कई व्यापारियों ने उन्हें बताया कि वे किसी तीसरे देश के माध्यम से भारत से सामान आयात कर रहे थे, जिससे उन्हें अधिक लागत आती थी इसलिए वे दोनों देशों के बीच सीधे व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने के पक्ष में थे।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने लंदन जाकर यह बयान ऐसे समय में दिया था जबकि भारत में आम चुनाव शुरू होने वाले थे। इसलिए चर्चा के लिए तो इस बयान का महत्व हो सकता है लेकिन वास्तविक महत्व तभी होगा जब भारत में नयी सरकार बन जाने के बाद इस पर बातचीत होगी। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या भारत को फिर से पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ता बहाल करना चाहिए? इस सवाल के जवाब में किसी भी राजनैतिक दल ने अपने मेनिफेस्टो में उल्लेख किया है न किसी जाहिर सभा में इसका जिक्र।

ज्ञात हो कि जब अगस्त 2019 में भारत की केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था। ये भारतीय संविधान का एक प्रावधान था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। धारा हटाते हुए सेंटर ने तर्क दिया कि इससे यह राज्य पूरे देश से जुड़ सकेगा। ऐसा हुआ भी। इसी बात पर पाकिस्तान परेशान हो उठा, और बौखलाकर भारत से अपने व्यापारिक रिश्ते निरस्त कर दिए।

दूसरी ओर ये बात भी हो रही थी कि ट्रेड सस्पेंशन की बड़ी वजह कुछ और ही थी। असल में उसी साल भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस ले लिया और पाकिस्तानी इंपोर्ट पर टैरिफ 200 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था। भारत ने यह कदम पुलवामा हमले के बाद लिया था, जिसे पाकिस्तानी टैरर गुट जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया था। हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। अटैक के चौबीस घंटों के भीतर ही पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा हटा दिया गया।

यहां बता दें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का टैरिफ एंड ट्रेड एग्रीमेंट 1994 कहता है कि सारे सदस्य देश एक-दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा दें, खासकर पड़ोसी देश ताकि फ्री ट्रेड आसान हो सके। हालांकि ये कोई पक्का नियम नहीं। यही वजह है कि रिश्ते खराब होने पर देश सबसे पहले आपस में यही स्टेटस खत्म करते हैं ताकि नाराजगी का आर्थिक असर भी दिखे। भारत और पाकिस्तान साल 1996 से ही एक-दूसरे को मोस्ट-फेवर्ड नेशन मानते आए। इसके बाद भी पाकिस्तान ने लंबी लिस्ट बनाई, जिसमें वो आइटम थे, जो भारत से आयात नहीं किए जा सकते। ये उत्पाद एक-दो नहीं, बल्कि 12 सौ भी ज्यादा थे। उसका कहना था कि वो ये बैन अपने घरेलू उद्योगों को चलाए रखने के लिए लगाए हुए है। हालांकि पहले वो 2 हजार से भी ज्यादा उत्पादों को आयात की मंजूरी दे चुका था। निगेटिव-लिस्टिंग के बाद केवल 138 उत्पाद ही रहे, जो वो भारत से आयात कर रहा था।

ध्यान रहे कि पाकिस्तान हमसे कपास, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, मशीनरी और मैकेनिकल डिवाइस जैसी चीजें इंपोर्ट करता था। हम भी पाकिस्तान से कई चीजें आयात करते रहे, जैसे- फल और सूखे मेवे, नमक, सल्फर, पत्थर, कई तरह की धातुएं और चमड़ा आदि। ट्रेड सस्पेंड करने के बाद भी पाकिस्तान हालांकि दवाएं मंगाता रहा क्योंकि उसके तुरंत बाद ही कोविड 19 का दौर आ गया था। भारत ने तब उसकी खासी मदद की थी। बंद होने के बावजूद भारत-पाकिस्तान के बीच लेनदेन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मीडिया की एक रिपोर्ट में सरकारी हवाले से कहा गया है कि थोड़ा-बहुत व्यापार वाघा-अटारी बॉर्डर के रास्ते हो रहा था, साथ ही कराची बंदरगाह के जरिए भी लेनदेन चलता रहा। लेकिन ये पहले से बहुत कम, लगभग नहीं जितना हो चुका था।

पाकिस्तान हमसे सबसे ज्यादा कॉटन लिया करता था। अब वो इसके लिए ब्राजील और अमेरिका पर निर्भर है। लंबे रास्ते से आने वाले इन उत्पादों पर समय के साथ पैसे भी काफी खर्च हो रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान जिस आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, दूरदराज के देशों से आयात उसपर और भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि उसके विदेश मंत्री ने ट्रेड की वापस बहाली की बात की। हालांकि ये बात उन्होंने सीधे-सीधे नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल मंच पर की। तो फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा। इसके अलावा भारत की मंजूरी भी जरूरी है। दरअसल भारत के लिए पाकिस्तान किसी अन्य देश जैसा ही नहीं है। पाकिस्तान का जन्म भारत को मजहबी हिंसा में झोंककर और लाखों लोगों की कुर्बानी तथा बर्बादी पर हुआ है। इसके साथ न भारत का रिश्ता कभी सहज रहा है और न रह सकता है। इसका कारण सिर्फ यह भर नहीं है कि पाकिस्तान पहले दिन से कश्मीर पर दावा किये बैठा है और उसे आतंकवाद के जरिए हासिल करना चाहता है। बल्कि जब जब भारत पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ेगा, तबके उन घावों से खून रिसने लगेगा जो पाकिस्तान ने अपने जन्म से अब तक भारत को दिए हैं। सर सैय्यद अहमद हों या फिर अल्लामा इकबाल या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। किसी न किसी तरह से समय समय इन्होंने यही डर दिखाया था कि अंग्रेजों के जाने के बाद हिन्दू अक्सरियत में मुसलमान दब जाएगा। पाकिस्तान भले ही जिन्ना ने मांगा हो लेकिन अविभाजित पंजाब, सिन्ध से लेकर अविभाजित बंगाल तक मुस्लिमों ने अगर अलग पाकिस्तान का समर्थन किया तो उसके मूल में एक बड़ा कारण हिन्दू बनियों का व्यापार में वर्चस्व होना भी था। आज भी पाकिस्तान में हिन्दुओं की पहचान हिन्दू बनिया के रूप में की जाती है। उनके लिए व्यंग में एक कहावत वहां बहुत प्रचलित है कि हिन्दू वह बनिया है जिसके मुंह में राम और बगल में छूरी रहती है। इसलिए जब 1947 में भारत को काटकर पाकिस्तान बन रहा था तब वहां के मुस्लिम व्यापारियों ने इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा था। फिर वो सिन्ध के कारोबारी रहें हों या पंजाब के कारोबारी। उन्हें लगता था कि जो व्यापारिक संभावना हिन्दू बनिया छोड़कर जा रहा है वो उसे भुना लेंगे और आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएंगे।शुरुआत के दो दशक जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही सोशलिस्ट नीति पर चल रहे थे तब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भारत से अच्छी थी। लेकिन बांग्लादेश के अलग होते ही पाकिस्तान ने जो मजहबी रफ्तार पकड़ी तो उसकी अर्थव्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती चली गयी। वैसे तो आर्थिक रूप से पाकिस्तान के बर्बाद होने के बहुत से कारण हैं लेकिन सबसे प्रमुख कारण भारत और हिन्दुओं से नफरत ही बनी रही। पाकिस्तान कभी अमेरिका की गोद में बैठा तो कभी चीन के आगे बिछ गया। लेकिन जब जब हिन्दू बनिया से तिजारत (व्यापार) बढाने की बात आई तब तब वहां के मजहबी मुल्लाओं ने बांग दिया कि क्या पाकिस्तान हिन्दुओं से तिजारत करने और अच्छा रिश्ता रखने के लिए बना था?

मुल्लाओं का तर्क अकाट्य है। यही कारण है कि जैसे जैसे पाकिस्तान सच्चे इस्लाम के रास्ते पर आगे बढता गया वहां के लोगों के मन में भारत को लेकर नफरत बढती गयी। जिया उल हक के जमाने से आज तक तमाम उतार चढाव के बावजूद वहां की आम अवाम ही इस बात के हक में नहीं रहती है कि भारत के साथ तिजारती रिश्ते बढाये जाएं। उनकी इस नफरत के बावजूद अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ कुछ व्यापारिक रिश्ते रखे हैं तो उसका कारण अंतरराष्ट्रीय बाध्यता और उनकी अपनी आर्थिक मजबूरियां थीं।

लेकिन इस दौरान भी पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कश्मीर और पंजाब में ही नहीं मुंबई पर आतंकी हमला जैसा जघन्य कुकर्म पाकिस्तान के हुक्मरानों ने प्लान किया। एक ओर पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करता रहा दूसरी ओर दो दशक तक देशभर में बम विस्फोट के जरिए हजारों लोगों की जान लेता रहा। एक दशक पहले तक टीवी पर बैठकर आईएसआई के चीफ रह हामिद गुल जैसे हुक्मरान भारत के मुंबई या बंगलौर जैसे शहरों को बर्बाद करने की धमकी देते रहे। परमाणु बम की धमकी तो मानों उनके लिए कंचे गोली खेलने जैसा हो।

2019 में ही सरकार में दोबारा आने के बाद जब मोदी सरकार ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किया तब पाकिस्तान ने एकतरफा अपनी ओर से न केवल भारत से हाई कमिश्नर वापस बुला लिया बल्कि सभी प्रकार के व्यापारिक रिश्ते भी खत्म कर दिये। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि जब तक कश्मीर में अनुच्छेद 370 वापस नहीं लागू कर दिया जाता, भारत से कोई तिजारती रिश्ता कायम नहीं होगा।

गौरतलब है कि देश को अरबों डॉलर के कर्ज के लिए अक्सर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) या सऊदी अरब और चीन जैसे मित्र देशों से संपर्क करना पड़ रहा है। भारत के साथ व्यापार बंद होने से दूर देशों से सामान आयात करने में बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार यूज करना पड़ रहा है, जो पहले से ही काफी कम है। इन वजहों से पाकिस्तान भारत संग व्यापार के लिए छटपटा रहा है। हालांकि, भारत का रुख एकदम साफ है कि जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगी, पाकिस्तान संग बातचीत समेत रिश्ते सामान्य नहीं होंगे।

नशे और पैसे से प्रभावित होते चुनावी नतीजे

संजीव ठाकुर

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले आम चुनाव से लेकर अध्यतन चुनाव में पैसे तथा नशे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है' वैश्विक स्तर पर भी भी इस महत्वपूर्ण कारक का प्रभाव रहा है। आम चुनाव में लोकसभा,विधानसभा के चुनाव से लेकर स्थानीय चुनाव तक सक्षम चुनाव के उम्मीदवार पैसे और नशे की खेप से मतदाता के बड़े गरीब तपके के मतदाताओं को प्रभावित करते आए हैं। मतदान के ठीक 1 दिन पहले रात्रि में मजदूरों की झुग्गी झोपड़ीयों में बकरा तथा शराब की पार्टियों तथा रूपयों के साथ अन्य आवश्यक सामग्रियों के वितरण द्वारा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। शराब तथा पैसों की लगातार आपूर्ति और वितरण मतदाताओं को प्रभावित करने का मापदंड बनता चला आया है। शराब एवं अन्य नशा देश के नौजवानों को मानसिक शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर करता रहा है तथा चुनाव के समय इस पर प्रभावी नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है इस पर एक राष्ट्रीय कानून तथा संविधान बनाने की बड़ी और प्रभावी आवश्यकता है। आईए एक विश्लेषण में देखते हैं कि नशा किस तरह देश के आर्थिक तथा मानसिक विकास को क्षति पहुंचाता आया है।

देश मे हर तरह के एक सूखे और अन्य नशे से न सिर्फ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संरचना कमजोर होती है, बल्कि परिवार, समाज और देश के आर्थिक तंत्र पर बड़ी चोट लगती है। वैश्विक स्तर पर यह माना जाता है कि विश्व का हर चौथा युवा नशे की गिरफ्त में है और उसकी सांसे नशे के नियंत्रण में ही हैं। भारत युवा शक्ति का देश है और भारत को नशे की गिरफ्त से बचाकर एक ऊजार्वान युवा शक्ति का बड़ा केंद्र बनाना ही हमारी सार्थकता होगी। विश्वव्यापी नशे की व्यापकता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को एक प्रस्ताव पारित कर हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया था। ये एक तरफ लोगों को नशे के प्रति चेतना फैलाता है ।वहीं दूसरी तरफ नशे की गिरफ्त में आए लोगों के उपचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाता है।

मादक पदार्थों की नशे की लत आज के युवाओं में तेजी से फैल रही है। कई बार फैशन की खातिर दोस्तों के कहने पर लिए गए यह मादक पदार्थ अक्सर युवाओं के लिए जानलेवा साबित होते हैं। युवा तो युवा बच्चे भी फेविकोल,तरल इरेजर, पेट्रोल की गंध और स्वाद के प्रति आकर्षित होते हैं, और कई बार कम उम्र के बच्चे आयोडेक्स, वोलीनी जैसी दवाओं को सूघकर नशे का आनंद लेते हैं। कुछ मामलों में आयोडेक्स को ब्रेड में लगाकर खाने का नशा भी बच्चों में देखा गया है। और मजाक मजाक में जिज्ञासा बस कोरेक्स, कोडन, अल्प्राजोलम, कैनेबिस जैसी दवाओं को पीकर नशे में झूमते हैं। यह नशीली दवाएं कब बच्चों को तथा गरीब युवाओं को अपने घेरे में ले लेती है पता ही नहीं चलता। तंबाकू, सिगरेट, गांजा, कोकीन, चरस, स्मैक, भांग जैसी नशीली वस्तुओं का आज युवा वर्ग लगातार सेवन कर अपनी जिंदगी से खेलने में लगा हुआ है। पहले इन लोगों को मादक पदार्थों की मुफ्त में लग लगाकर सबको इसका आदी बनाया जाता है,और फिर ऐसी नशे की लत में युवा तथा बच्चे चोरी, डकैती,पॉकेट मारी, घर के पैसे, रुपए, जेवरात चुराने की हरकतें करने लगते हैं,जो न सिर्फ कानूनी अपराध है बल्कि समाज की बहुत बड़ी विसंगति भी है। कई बार बच्चे घर के ही बड़े सदस्यों को देखकर यह नशा करने लगते हैं कि जब बड़े कर रहे हैं तो उन्हें भी यह करने में कोई बुराई नजर नहीं आती है। और फिर इनके द्वारा शुरू होता है असामाजिक कार्यों का सिलसिला धीरे-धीरे युवा नशे की लत में अपराध जगत की ओर बढ़ने लगता है। चिकित्सकीय आधार पर देखा जाए तो हीरोइन चरस कोकीन गांजा जैसे मादक पदार्थों के नशे की गिरफ्त में आकर अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, एवं पागल तथा सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, नशे की लत शरीर को सुस्त कर म्रत्यु की ओर ले जाती है। और नशे की लत में मानसिक संतुलन खोकर व्यक्ति बड़े-बड़े अपराध तक कर बैठता है।, नशे की लत का मामला न सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा होकर बल्कि अपराध जगत से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जीवन अनमोल है और इस अनमोल जीवन को नशे की लत में नष्ट कर समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाने के साथ-साथ मादक पदार्थों से मुकाबले के लिए विभिन्न देशों द्वारा उठाए गए कदमों तथा इसके मार्ग में उत्पन्न चुनौतियों तथा निवारण का सही सही उपचार भी बताता है। वैसे इतने घातक तथा खतरनाक नशे की लत को केवल 26 जून को नशा निरोधक दिवस बना कर इतिश्री नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि इसके विरुद्ध हर देश को एक व्यापक जन अभियान भी चलाना चाहिए। 26 जून का दिन मादक पदार्थों से मुकाबले का प्रतीक बन गया है ।और इस दिवस पर मादक पदार्थों के उत्पादन तस्करी तथा सेवन के दुष्परिणामों से बचने के उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा भी की जानी चाहिए।

भारत दक्षिण एशियाई देशों के मध्य हीरोइन का बड़ा उपभोक्ता देश बनते जा रहा है। भारत के कई भूभाग पर अफीम की खेती भी की जाती है। पारंपरिक तौर पर किस के बीच पोस्तों से सब्जी बनाकर खाई जाती थी, किंतु कालांतर में इसका उपयोग एक मादक पदार्थ के रूप में आरंभ हुआ जिसने एक बहुत बड़ा खतरनाक रूप ले लिया। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 12 से 60 साल की उम्र के लोगों में नशे की लत लगभग 1.6% देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जिस अफीम की हीरोइन में तब्दील नहीं किया जाता उसका दो तिहाई हिस्सा 5 बड़े देशों में इस्तेमाल होता है इसमे

ईरान 42%, अफगानिस्तान पाकिस्तान 7%,भारत खुद 6% तथा रूस में इसका 5% उपयोग होता है। भारत में 2008 में 17 मि,टन हीरोइन की खबत होती थी,और वर्तमान में भारत में अफीम की खपत 65 से 70 मी,टन प्रति वर्ष होने लगी है। यह विश्व में इस्तेमाल होने वाली अफीम का 6% है। भारत में ही अफीम की 1500 से लेकर 2000 हेक्टेयर में अफीम की अवैध खेती होती है। यह तथ्य वास्तव में देश के लिए और देश के युवा तथा बच्चों के लिए अत्यंत खतरनाक है। इस पर शासन प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रख इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भारत में शराब सेवन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है साथ ही मध्य पान के कारण 1500 से दो हजार भारतीय आज शराब के नशे में प्रतिवर्ष मरने भी लगे हैं। आज की स्थिति में हर 20 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति शराबखोर है। पुरुष तो पुरुष महिलाएं भी आज की स्थिति में मध्य पान की ओर आकर्षित हो रही हैं। विशेषकर उच्च तथा मध्यम वर्गीय परिवारों में महिलाएं शराब का सेवन करने लगी है ।इसमें से कुछ महिलाएं खुलेआम कुछ छुप-छुपकर इसका सेवन करती हैं। महानगरों में बड़े शहरों की कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों तथा हॉस्टल में महिलाओं का शराब का सेवन तेजी से बढ़ते जा रहा है।

एक सर्वे के अनुसार करीब 20 से 25% महिलाएं शराब खोरी की गिरफ्त में आ चुकी हैं। यूरोपियन देशों में महिलाओं की नशाखोरी की आदत का प्रतिशत 60% से ऊपर है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बैठकों सेमिनार तथा मीटिंग में शराब का सेवन एकदम आम बात बन गई है।

यह एक फैशन की तरह महिलाओं के मध्य फैल कर उन्हें नशे की लत में डुबोने लगा है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के अनुसार नशा मनुष्य के जीवन के लिए जहर जैसा है, नशे की लत में वैवाहिक जीवन भी टूटने के कगार पर आ जाता है ।मनुष्य के शरीर का लीवर, किडनी तथा अन्य अंग खराब होकर मृत्यु की ओर ले जाने को तत्पर रहते हैं। नशे से दूर रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर भारत में भी अनेक उपाय किए जा रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र तथा नशे के पदार्थों पर चेतावनी आदि लिखने का काम किया जा रहा है। नशा आज युवाओं को पथभ्रष्ट चरित्रहीन और अपराधी बनाने के पीछे एक बड़ा घातक कारण है। नशे की प्रवृत्ति से बचाने के लिए मनुष्य को नशे से हर हाल में दूर रखना होगा अन्यथा आने वाली पीढ़ी राष्ट्रीय चरित्र राष्ट्रीय सम्मान तथा राष्ट्रीय शक्ति को भूलती जाएगी और नशे की लत में युवा अपने कर्तव्य से परे हो जाएगा। जोकि एक बहुत खतरनाक स्थिति होगी।

उंगलियां होती है त्रिकाल सूचक

-आत्माराम यादव पीव वरिष्ठ पत्रकार

जीवन को परम आनंद प्रदान करने वाली हमारी ये उंगलियां ही है जिनपर मुद्रा विज्ञान ओर नृत्य साधना का सारा परिणाम निर्भर करता है । मुद्रा विज्ञान में कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, महामुद्रा ओर समय मुद्रा ये चारो मुद्रा जीवन के नित्य कर्म ओर योग साधना का श्रेष्ठ मार्ग है जिससे उंगलियों की विभिन्न आकृतियों की बनने वाली मुद्राओं के द्वारा हम अपने मोक्ष का मार्ग चुनते है, पर आधुनिक समय में हम अपने पुरुषार्थ को विस्मृत कर ऋषि महर्षियों द्वारा प्रदान किए योग, ज्ञान, मोक्ष आदि की उत्कृष्ट उँगलियो कि मुद्रा साधना भूल चुके है, किन्तु आज भी प्रमुख मंदिरों, गुरुकुल, मठ-मठाधीशों के आश्रम में अंग मुद्रा की यह साधना जारी है जिसमें सभी उंगलियों को उसके मूल मुद्राओं के साथ पूजा पाठ, आरती, शयन आरती, प्रभु का जागरण, यज्ञ आहुति आदि का विधान प्रचलित है पर दुनिया भर के हम लोग अपनी संस्कृति ओर संस्कारों से दूर अपनी इन उंगलियों को जो हमारे जीवन की त्रिकालज्ञ सूचक है किन्तु आर मनुष्य अपने मूल कर्तव्य ओर दायित्व से विमुख रह कर उँगलियों का ज्ञान को विस्मृत कर अपने नैतिक आचरण ओर व्यवहार से कोसों दूर जा पहुचा है।

उँगलियों के जीवन की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधा नृत्य, गायन एवं वादन है जिसमें नृत्यकार, गायक ओर विभिन्न वाड यंत्रों के वादक गण अपनी उँगलियो के प्रयोग में जरा सी चूक कर दे तो न तो नृत्य पूर्ण हो सकेगा न गायकी के भाव ही समझ आ सकेंगे ओर न ही वाद्ययन्त्रों के सुरों की लय मेल खा सकेगी, परिणाम बेसुरा, रागहीन लय हीन न होने से बेरंग बेस्वाद होगा ओर सभी के द्वारा निंदनीय होगा। अतएव इन सभी का परिणाम सुखद आए ओर सभी के मन को छूने के साथ हृदय की गहराइयों तक पहुंचे इसलिए जहां नृत्यकार अपने चेहरे पर सम्पूर्ण भाव प्रकट कर अपने नृत्य को पूर्णता प्रदान करता है, वही गायक नृत्य की लय में पूर्ण सुर देता है ओर वादक इन सुर ओर ताल की अखंड लय बनाए रखता है अगर इन तीनों की साधना में ये उंगलिया जरा भी चूक कर दे तो नृत्य की सारी भाव भंगिमाए, सुर के सारे भाव ओर वाद्ययंत्र के सुर,लय ओर ताल सभी अर्थहीन हो जाएंगे।

उँगलियो के साथ शरीर के अंगों की विभिन्न मुद्रा बनाना ओर योग साधना करना, शरीर को दीघार्यु व आरोग्य प्रदान करने की पहली कुंजी है। योग प्राणायाम आदि की ये मुद्रा क्या है, प्रश्न उठेगा, जबाब सीधा है मुद्रा यानि आनंद की प्राप्ति। मुद्रा से आनंद की प्राप्ति के मार्ग में जो योगिक क्रियाओ को शरीर के अंग निष्पादित करते है उससे शरीर की समस्त नाड़ियों के महाजाल में शीतोष्ण ओर ऊष्मीय ऊर्जा का संचालन शरीर के रसो को शोषित कर बिंदुरुप में एकत्र ऊर्जा को उध्वोर्मुखी करता है तब इन उँगलियो की अनेक विधि से बनने वाली ये मुद्राए समस्त योगो के द्वारा अष्ट महासिद्धियों की प्राप्ति का भी मार्ग होती है जिससे ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ आनंदमय जीवन प्राप्त होता है।

भारतीय ज्योतिष का प्रमुख अंग है, सामुद्रिक शास्त्र, जिसके द्वारा व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों की संरचना के आधार पर फलकथन ज्ञात करने का प्रचलन है। सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा नारद आदि महर्षियों ने मनुष्यों के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक की सभी बातों को जान लिया करते थे जिसे आज भी जाना जा सकता है पर इस ज्ञान के विलोप होने की स्थिति के रहते आधे अधूरे जाननेवाले सर्वज्ञानी बनकर ठगी करने में अग्रणी हो गए है इसलिए लोगों का इनपर से विश्वास उठता जा रहा है। इससे हटकर अब बात उंगलियो कि की जा रही है। हाथ के मूल भाग में हर मनुष्य की प्रत्येक उंगली पर से दो लाइनें निकलने के पश्चात सभी उंगली तीन-तीन पर्व में विभक्त है जिन्हे सामान्य गणना करते समय एक उंगली में विभक्त तीन पर्व को शामिल कर इन पांचों उँगलियो के सभी पर्व को 15 तक योग किया जाता है। इन पांचों उँगलियों के परस्पर संबंधो उनकी आकृति, विकृति, विभिन्न प्रकार के प्रतीक, चिन्ह, लाईने, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना अथवा अलग-अलग रहना आदि सभी बातों के माध्यम से जीवन के उतार चढ़ाव का अर्थशास्त्र परिलक्षित होता है। हरेक उंगली के ये तीन पर्व ज्योतिष की दृष्टि में महत्वपूर्ण है जिनमे कनिष्ठिका उंगली में- तुला (गुप्तविचार), वृशिक, धनु (धैर्य), अनामिका उंगली में- कर्क (प्रवास), सिंह, कन्या, मध्यमा उंगली में मकर (व्यवहार), कुम्भ (धनप्रभाव),मीन (आत्मज्ञान), तर्जनी उंगली में मेष (मनःस्थिति), वृषभ (स्थैर्य), मिथुन (एश्वर्य) तथा अंगूठा में महत्वाकांक्षा झइक्छाशक्ति ओर तर्कशक्ति सहित सभी बारह राशियो का प्रतिनिधित्व कर व्यक्ति के गुणविशेष को प्रकट करती उनके भूत भविष्य ओर वर्तमान का दृश्य का सूचक होती है।

हमारी ये उंगलिया शरीर के अलग-2 अंगों से जुडी होती है ओर शरीर में होने वाली बीमारिया ओर विभिन्न अंगों में होने वाले दर्द का केन्द्रबिन्दु भी यही उँगलियो के जोड़ होते है बिना किसी दवा का प्रयोग किए शारी के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द पीड़ा को इन हाथ की उँगलियों को रगड़ने, विशेष पाइंट दबाने से पल में दर्द से मुक्ति मिल सकती है किन्तु हम दर्द के साथ चिंता, डर ओर चिड़्चिड़ेपन को मिटाने वाले कष्टो से छुटकारा के लिए इस घर के वैध के उपायों को भूल गए है, कारण आज हमारे पास न तो नाना नानी, दादा दादी के अनुभव लेने के लिए उनके पास बैठने का समय है ओर उनकी सलाह को एक दकियानूसी सोच समझ उसपर काम करने को मानसिक पिछड़ापन समझने से हम उनपर अमल करना पसंद नही करते है। इन बातों के अलावा अपनी बात को लंबायमान न कर एक ज्योतिषी विचार के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि ज्योतिषी ज्ञान के अनुसार उँगलियों के परिवार के साथ संगठित रहने से आपके जीवन के किस पड़ाव में धनसंपत्ति के अभाव अथवा धनागमन होगा की खबर मिलती है। इन पांचों उँगलियो अंगूठा, मध्यमा, कनिष्ठा, तर्जनी ओर अनामिका उंगली को आपस में सटाने के बाद बीच में उन्हे कई आकृतियो में कम- ज्यादा दूरी में रख परावर्तित कर प्रत्येक उंगली के मूल से छोर तक गैप आपके जीवन में धनवान होने से गरीबी ओर पैसों की तंगी ओर परेशानी का संकेत होते है। प्रत्येक उंगली के पर्व में छोटे बड़े, लंबे-मोटे,चपटे बेढौल, समान, असमान पर्व होने पर व्यक्ति के जन्म भर की आवक जावक, तंगहाली, गरीबी, सहित सभी कलाओं का चित्रण उसके कलाकार, संगीतज्ञ, धनवान, राजनीतिज्ञ, उच्च पदासीन, सफलता असफलता आदि का स्पष्टतया इन पर्वों में देखे जा सकते है। जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथों कि हथेली ओर उँगलियों में भूत, भविष्य ओर वर्तमान सहित तीनों कालों का सम्पूर्ण ज्ञान लिए होता है, सच में उंगलिया करने वाला नई बल्कि उंगलिया को बाचने वाला , उँगलियो कि भाषा को पढ़ने वाला मिल जाए तो हर जातक कि उगलिया त्रिकालसूचक द्रष्टा होती है,जो स्वंय कुछ व्यक्त तो नहीं करती पर जो उन्हे पढ़ ले तो एक खुली किताब के तरह सब कुछ उजागर कर देती है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कांग्रेस के समय किसान आत्महत्या और भ्रष्टाचारी ऐश करता थाः सीएम

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/हाथरस

गरीब, किसान, महिलाएं, युवा सपा-बसपा व कांग्रेस के एजेंडे में नहीं थे। यह केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे। यह जाति, समाज को बांटने का पाप करते थे। उनके समय में गरीब भूखमरी का शिकार होता था और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। किसान आत्महत्या करता था और भ्रष्टाचारी ऐश करता था। माफिया सरपरस्त बनकर सत्ता का संचालन करते थे, लेकिन आज बिना किसी भेदभाव के देश व प्रदेश में कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश में साढ़े छह लाख युवाओं को नौकरी दी गई। अब पात्रता के आधार पर ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ चुनाव में एक तरफ भाजपा व एनडीए है तो दूसरी तरफ कांग्रेस-सपा व इंडी गठबंधन है।

उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं। उन्होंने शनिवार को क्रीड़ा स्थल सिकंदराराऊ में हाथरस लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनूप प्रधान %वाल्मीकि% के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि इस धरती ने अनेक महापुरुषों, साहित्यकारों और काका हाथरसी जैसे कवि को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिकोण से दो चरणों की 191 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। रुझान बताते हैं कि हाथरस के हींग की खुशबू और फिर एक बार मोदी सरकार का स्वर पूरे देश में गूंज रहा है।

सीएम ने कहा कि उत्साहित जनता मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना चाहती है। दस वर्ष में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। नक्सलवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है। विकास के अनेक कार्य हुए हैं। एक ओर भाजपा ने विकास योजनाएं दीं तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने 65 वर्ष तक देश, सपा को चार बार व बसपा को तीन बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला। इन सबको मिलाकर जितना कार्य इन लोगों ने देश-प्रदेश में नहीं किया। उससे अधिक कार्य पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 वर्ष में देश व सात वर्ष में उत्तर प्रदेश में हुआ है। सीएम ने कहा कि सपा-कांग्रेस के समय गरीब भूखों मरता था। स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरते थे। पहले दिल्ली से चला पैसा कांग्रेस, सपा-बसपा के दलाल हजम कर जाते थे। आज सीधे गरीब के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार होली-दीवाली में फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करा रही है।

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने 1947 में देश को बांटा, अब घोषणा पत्र में कह रही है कि हम संपत्ति सर्वे कराएंगे, फिर बाप-दादा की कमाई पर विरासत टैक्स लगाएंगे। इस टैक्स का मतलब चार कमरे के मकान में यह कहेंगे कि दो कमरे में रहो, दो कमरे सपा-कांग्रेस के अधिकार में चला जाएगा। पसीने से मकान बनाया आपने और डकैती करने यह लोग आएंगे। ऐसा करने की कतई छूट नहीं देना है। इन लोगों ने पहले देश को बांटा, अब संपत्ति को बांटने की साजिश कर रहे हैं। जब हम माफिया पर कार्रवाई करते हैं तो यह उसके घर में जाकर फातिहा पढ़ते हैं।

सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि पर्सनल कानून यानी तीन तलाक की कुप्रथा को लागू करेंगे। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के तालीबानीकरण करने की साजिश का हिस्सा है। अल्पसंख्यक को मर्जी के अनुसार खानपान यानी गोकशी की छूट देंगे। हिंदू के लिए इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। कांग्रेस देश को दंगों की आग में झोकना चाहती है और अपने स्वार्थ के लिए भारत के विभाजन की आधार रखना चाहती है। हिंदुस्तान इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। रामकृष्ण की धरती पर गोकशी नहीं होगी। कसाइयों को गौमाता की हत्या की छूट नहीं देने देंगे। कांग्रेस, सपा-बसपा के हिडन एजेंडे को पहचानकर समय रहते जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। यह लोग देश की संप्रभुता-अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

सीएम ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार थी तो अनूसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के लिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की। बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर के नेतृत्व में देश के संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था तो कहा गया कि धर्म के नाम पर कभी आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर

काशी, अयोध्या के बाद अब मथुराःयोगी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/फिरोजाबाद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए कहा है कि राम और कृष्ण की धरती पर ये लोग गोकशी की छूट देना चाहते हैं। फिरोजाबाद लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने यहां जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या के बाद अब वे मथुरा की ओर बढ़ चले हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि %डिस्कवरी ऑफ इंडिया% वाले लोगों को लगता है कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, वहीं कांग्रेस राज में उनके चट्टे-बट्टे गरीबों का राशन भी डकार जाते थे। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की ओर बढ़ चले हैं। उन्होंने सपा को टार्गेट करते हुए कहा कि क्या उन लोगों ने कभी ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए कभी कुछ किया है। उन्हें यादवों में भी केवल अपने परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाया है। इन लोगों ने अपने परिवार के बाहर कुछ सोचा ही नहीं और परिवारवाद के नाम पर जाति को बदनाम करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सहानुभूति गरीबों के साथ न होकर माफिया के साथ है। माफिया के लिए ये लोग फातिहा पढ़ते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी और माफिया गठजोड़ पर सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि सपा पोषित माफिया विधायक कृष्णानंद राय, कई पुलिसकर्मी, कई भाजपा नेता के साथ ही सपा के विधायक राजू पाल और अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या करते हैं, मगर समाजवादी पार्टी को कोई सहानुभूति नहीं, इनकी सहानुभूति केवल माफिया के साथ रहती है। जब माफिया अपनी मौत मर रहा है और अपने कृत्यों की सजा पा रहा है, तो ये लोग फातिहा पढ़ने उसके घर जा रहे हैं। जनता को इन्हें पांच साल और फातिहा पढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग बेकार में चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि देश में सरकार बनाने के लिए 273 सीटें चाहिए और ये केवल 63 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सपा और कांग्रेस अखाड़े में आने से पहले ही युद्ध हार चुके हैं। अब ये पलायन का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सीएम योगी ने पिछली सरकारों के दौरान प्रदेश में हुए आतंकी बम धमकों को याद करते हुए कहा कि जिन आर्तंकियों ने अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में संकट मोचन मंदिर, विभिन्न न्यायालयों और रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था, सपा सरकार ने उन मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। तब न्यायपालिका ने इन्हें लताड़ते हुए यहां तक पूछा था कि आज आप लोग आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल इन्हें पद्म पुरस्कार भी दोगे क्या?

ईवीएम पर सवाल उठाने वाले कभी बैलेट लूटा करते थे

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईवीएम पर सवाल उठाने पर कांग्रेस ओर इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये वही लोग हैं जो बैलेट लूटने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पुख्ता हार को देख कांग्रेस के लोग ईवीएम पर दोषारोपण कर रहे हैं। सीएम योगी शनिवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने गोमांस मुद्दे पर भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने पूछा कि वो अपने घोषणापत्र में लिख रहे हैं अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खान-पान का अधिकारी दिया जाएगा। आखिर अल्पसंख्यकों का ऐसा कौन सा खान-पान है जो शेष समुदाय से अलग है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर इंडी गठबंधन के अन्य सहयोगियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने ईवीएम मुद्दे पर कहा है कि इंडी गठबंधन जब भी हार रहा होता है, तो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर डालने का प्रयास करता है। 2014 से लगातार हम सब इस बात को सुन रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से पूछा कि गत वर्ष हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में क्या बैलेट पेपर से सरकार बनी थी, 2004 में यूपीए की सरकार और 2018 में राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तथा दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार क्या बैलेट पेपर से बनी थी? मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग ईवीएम को नकार रहे हैं ये वही हैं जो बैलेट बॉक्स लूटने का काम करते थे। अगर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सुचिता को सुनिश्चित किया है तो ये लोग अपना गुस्सा ईवीएम पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दो चरणों के चुनाव के रुझान ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। देश ने तय कर लिया है कि अबकी बार 400 पार का जनादेश एनडीए को देने जा रही है। जब एनडीए भाजपा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है तो खीझ मिटाने के लिए इंडी गठबंधन के लोग ईवीएम को निशाना बना रहे हैं।

सपा को 80 प्रतिशत बूथों पर बस्ता लगाने के लिए लोग नहीं मिल रहेःभूपेन्द्र चौधरी

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शनिवार को फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्हें प्रदेश के 80 प्रतिशत बूथों पर बस्ता लगाने के लिए लोग तक नहीं मिल रहे, वो सरकार बनाने का दावा करते फिर रहे हैं। सपा प्रमुख और उनके समर्थक सिर्फ सोशल मीडिया पर ही हवा बना रहे हैं, जमीन पर उनके समर्थक नदारद हैं।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, 2014 के बाद हर बार भाजपा ने सपा का सफाया किया है और इस बार भी समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होना तय है और फिर एक बार मोदी सरकार और वो भी 400 पार आना तय है। प्रदेश की सभी सीटों पर जनता भाजपा को जिता रही है। मोदी जी के गरीब कल्याण, युवा कल्याण, किसान कल्याण और महिला कल्याण के लिए किए गये कार्यों से भाजपा ने जो जनविश्वास अर्जित किया है, उसी के फलस्वरूप ईवीएम कमलमय होने जा रही है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि बिना आंकड़े और सबूत के हवा बड़ी बनाई जा रही है, लेकिन विपक्ष को हाथ कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि पब्लिक उन्हें 'जीरो' यानी शून्य सीटें ही दे रही है। वो जो कुछ भी अपनी रैलियों में बोल रहे हैं, वो अपने मन को बहलाने के लिए अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए बोल रहे हैं। बाकी हकीकत जनता जानती है, क्योंकि आएगें तो मोदी ही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अभी से हार की तैयारी कर ली है और हार के बाद ईवीएम को दोषी ठहराए जाने की पूरी स्क्रिप्ट बन चुकी है। मेरठ में इनके लोगों ने ईवीएम खराब का रोना शुरू कर दिया है और 4 जून को इनके द्वारा 400 सीटों की ईवीएम खराब घोषित कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का नाम ही सपा, वो हर दफा सफा होगी, इसकी गारंटी है। उन्होंने जनता को सावधान करते हुए कहा कि ये सनातन का अपमान करने वाले लोग हैं, जो किसी भी सूरत में सत्ता सुख वापस पाना चाहते हैं। ये फिर देश और यूपी को पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं, लेकिन जनता ऐसे परिवारवादी लोगों को सबक सिखाने को तैयार है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अखिलेश के बयानों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो नकल माफिया को पालते हैं, सेंटर बुक करके नकल कराते हैं, आज उन्हें पेपर लीक की चिंता हो रही है। कहा कि, दंगे, सांप्रदायिक हिंसा और खराब लॉ एंड ऑर्डर जिनकी पहचान थी, आज वो पुलिस की सक्रियता देखकर भौचक हो गए हैं। वो पश्चिम की लहर की बात कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि पश्चिम से लेकर पूरब तक एक ही हवा है और वो मोदी की हवा है। वो तो कन्नौज और मैनपुरी की सीट भी हार रहे हैं।

भाजपा सरकार ने हर वर्ग के साथ धोखा कियाःअखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के साथ धोखा किया है। भाजपा जनता के अधिकार छीन रही है। संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। यह लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह लोकसभा चुनाव संविधान, लोकतंत्र और किसानों, नौजवानों के अधिकार को बचाने का चुनाव है। भाजपा बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को खत्म करना चाहती है। इस सरकार में किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव ने आज शनिवार को कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र जनपद कानपुर देहात और बेला जनपद औरैया तथा उमर्दा जनपद कन्नौज में अपनो संग मेल-मुलाकात के कार्यक्रम में कई जनसमूहों के साथ संवाद किया। श्री अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय रथ से रोड-शो किया। जगह-जगह उपस्थित जनता को सम्बोधित किया। रोड-शो में भारी जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान जनता जनार्दन ने करतल ध्वनि से अपने नेता अखिलेश यादव का अभिवादन किया और उन्हें रिकार्ड मतों से जिताने का भरोसा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जो गारन्टी दे रहे हैं वह गारन्टी नहीं घंटी है। उनकी सभी गारन्टी जुमला निकली है। भाजपा ने नौजवानों का भविष्य खतरे में डाल दिया है। भाजपा सरकार ने फौज की पक्की नौकरी को 4 साल की कर दी, आगे पुलिस की नौकरी भी 3 साल की हो जाए तो आश्चर्य नहीं। जो संविधान बदलने निकले हैं, उन्हें बदलने का मौका है।

यादव ने कहा कि भाजपा बहुत पीछे चली गई है। भाजपा का सत्ता से जाना तय है। जनता संविधान बचाने के लिए वोट दे रही है। यह लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेता तानाशाह हो गए हैं। लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का षडयंत्र करते है। भाजपा के लोगों ने भ्रष्टाचार के रिकार्ड तोड़ दिए हैं। इनके भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ गयी है। भाजपा ने चंदे के नाम पर जो हजार-हजार करोड़, सौ-सौ करोड़ रूपये की वसूली की, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। जिन लोगों ने भाजपा को चंदा दिया। उन्होंने अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा कर महंगाई बढ़ाई और मुनाफा कमाया। महंगाई से जनता पिस गयी। हर वर्ग परेशान हुआ।

अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं सब भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा ने भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को अपने गोदाम में रख लिया है। सब भ्रष्टाचारी, अपराधी भाजपा के साथ हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण से ही भाजपा का पश्रा साफ हो गया है। पश्चिम से जो हवा चली है वह भाजपा का सफाया करती जा रही है। इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। बीजेपी में घबराहट है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठी पार्टी है। भाजपा नेताओं की हर बात झूठी निकली है। दस साल में झूठ और लूट भाजपा की पहचान बन गयी। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। किसानों को उनकी फसलों का लागत मूल्य भी नहीं मिला। गेंहू की खरीद नहीं हो रही है। किसान संकट में है। भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों के 15 लाख करोड़ रूपये का कर्ज माफ कर दिया है लेकिन किसानों को उनकी फसलों के लिए एमएसपी की गारन्टी नहीं दी। यादव ने कहा कि भाजपा ने किसानों को अपमानित किया। समाजवादी इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी। किसानों को सुविधाएं देगी। फसलों की एमएसपी की गारन्टी देगी। यादव ने कहा कि भाजपा ने किसानों की तरह नौजवानों को भी धोखा दिया। नौजवानों के लिए हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। भाजपा जब से सरकार में आयी है हर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो रहे है। भाजपा सरकार में प्रतियोगी परीक्षाओं के दस पेपर लीक हुए। लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया।

भाजपा में आज कई राजनीतिक दलों के नेता होंगे शामिल

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में कल रविवार 28 अप्रैल को सुबह 9.30 बजे बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। भाजपा प्रवक्ता हिमांशु दुबे के मुताबिक प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के समक्ष सपा, बसपा व कांग्रेस के प्रमुख नेता भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भाजपा में ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बखूबी कार्यकरते हुए अबतक बड़ी संख्या में कई बड़े नेता व उनके समर्थकों को शामिल करा चुके हैं।

छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोप में वाहन चालक गिरफ्तार

शाहजहांपुर। जिले में एक छात्रा के साथ स्कूल वाहन चालक ने कथित रूप से अश्लील हरकत की। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।पुलिस ने बताया कि बालिका कक्षा एक में पढ़ती है और चालक उसे स्कूल ले जा रहा था।पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अशोक कुमार मीणा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि शहर के एक निजी स्कूल की छात्रा को शुक्रवार को वाहन चालक स्कूल ले जा रहा था और इसी दौरान उसने कथित तौर पर उससे अश्लील हरकत की।

गृहमंत्री अमित शाह आज कासगंज मैनपुरी, इटावा और कानपुर में

लखनऊ। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी रविवार 28 अप्रैल को कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर के प्रवास पर रहेंगे। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी दोपहर 12:15 बजे बारह पत्थर मैदान, कासगंज में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करेंगें तथा दोपहर 01:50 बजे डी.पी.एस. पब्लिक स्कूल मैदान, किशनी, मैंनपुरी में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करेगे। इसके पश्चात् दोपहर 3:20 बजे नुमाइश ग्राउण्ड, इटावा में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करेंगें और सायं 05 बजे विजय इंटरकाटिनेंटल, तिलकनगर, कानपुर में आयोजित संगठनात्मक बैठक में मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी जी रविवार 28 अप्रैल को कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर के प्रवास पर रहेंगे।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ दोपहर 12:15 बजे बारह पत्थर मैदान, कासगंज में आयोजित जनसभा तथा दोपहर 01:50 बजे डी.पी.एस. पब्लिक स्कूल मैदान, किशनी, मैंनपुरी में आयोजित जनसभा में सम्मिलित रहेंगे। इसके पश्चात् दोपहर 3:20 बजे नुमाइश ग्राउण्ड, इटावा में आयोजित जनसभा और सायं 05 बजे विजय इंटरकाटिनेंटल, तिलकनगर, कानपुर में आयोजित संगठनात्मक बैठक में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ उपस्थित रहेंगे। प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह जी रविवार 28 अप्रैल को कानपुर के प्रवास पर रहेगें। प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के साथ सायं 05 बजे विजय इंटर काटिनेंटल, तिलकनगर, कानपुर में आयोजित संगठनात्मक बैठक में सम्मिलित रहेंगे ।

योगी आज बरेली, बदायूं व एटा में करेंगे जनसभा

लखनऊ। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ रविवार, 28 अप्रैल को बरेली, बदायूं व एटा के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:05 बजे सुभाष इंटर कॉलेज का ग्राउंड, आंवला, बरेली में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे तथा दोपहर 01:30 बजे रंजना हास्पिटल के सामने मैदान, मुजरिया तिराहा, बिल्सी, बदायूं में जनसभा को सम्बोधित करेंगें। इसके पश्चात दोपहर 03:05 बजे एमजीएम इंटर कॉलेज, जलेसर, एटा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार 28 अप्रैल को बांदा तथा फतेहपुर के प्रवास पर रहेगें। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोपहर 12 बजे आदर्श इण्टर कालेज बिसंडा, बांदा, में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे। इसके पश्चात दोपहर 01:30 बजे नवीन रिसार्ट, अभय प्रताप डिग्री कालेज के पीछे, बिन्दकी, फतेहपुर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक रविवार 28 अप्रैल को कौशाम्बी के प्रवास पर रहेगें। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दोपहर 01 बजे हीरालाल गेस्ट हाउस पश्चिम सरीरा, मंझनपुर, कौशाम्बी में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे तथा दोपहर 03 बजे भाजपा विधानसभा कार्यालय के पीछे, सिराथू, कौशाम्बी में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रविवार 28 अप्रैल को अयोध्या व गोण्डा के प्रवास पर रहेगें। स्वतंत्र देव सिंह सुबह 11 बजे श्रीराम सिंह मेमोरियल एजूकेशन एकेडमी उत्तर माध्यमिक विद्यालय, अयोध्या में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा दोपहर 02 बजे गांधी विद्यालय, नवाबगंज इण्टर कॉलेज, मनकापुर, गोण्डा में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे। प्रदेश सहप्रभारी संजय भाटिया रविवार, 28 अप्रैल को वाराणसी के प्रवास पर रहेगें। संजय भाटिया सुबह 10 बजे क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में आयोजित संगठनात्मक बैठक में मार्गदर्शन करेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु रविवार 28 अप्रैल को प्रतापगढ़ के प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु सुबह 10 बजे लक्ष्मी गेस्ट हाउस डेरवा नगर पंचायत से पहले, बाबागंज, प्रतापगढ़ तथा दोपहर 02 बजे सनराइज गेस्ट हाउस, मानीकरपुर, कुण्डा बाजार, प्रतापगढ़ में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश यादव रविवार 28 अप्रैल को गाजीपुर के प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश यादव दोपहर 12 बजे जिला भाजपा कार्यालय, गाजीपुर में आयोजित सोशल मीडिया वालेंटियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ0 योगेन्द्र उपाध्याय रविवार 28 अप्रैल को फिरोजाबाद के प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. योगेन्द्र उपाध्याय सुबह 10 बजे किंडर्स कार्नर स्कूल, फिरोजाबाद में प्रबंधक-प्रधानाचार्य बैठक को संबोधित करेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. अरूण सक्सेना रविवार 28 अप्रैल को बदायूं के प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. अरूण सक्सेना सायं 04 बजे बदायूं जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित चिकित्सक बैठक को संबोधित करेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी रविवार 28 अप्रैल को मैनपुरी के प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी दोपहर 12 बजे आर्य समाज मंदिर स्टेशन रोड, मैनपुर में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक रविवार 28 अप्रैल को सम्भल के प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक सम्भल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरूण रविवार 28 अप्रैल को हाथरस व बरेली के प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरूण सुबह 10 बजे हाथरस में जनसम्पर्क करेंगे।

आप भी तो गोदी मीडिया बोल बोल कर विपक्षी पार्टियों का एजेंडा ही चला रहे हो, आप तो गोदी मीडिया ऐसे बोल रहे हो जैसे 2014 से पहले पूरा मीडिया दूध का धुला था ! आप और रघुराम राजन जैसे उच्च शिक्षित और प्रतिभाशाली लोग भी जब 2014 के बाद भारत के लिए केवल नकारात्मकता की ही बातें करते है तो पक्का भरोसा हो जाता है कि प्रतिभाशाली लोग तो भारत में 2014 से पहले भी बहुत लोग थे पर पुरस्कार देकर केवल उन्हें ही आगे बढ़ाया गया जो सत्ता के प्रति नतमस्तक थे ! — सतीश राय, टिप्पणीकार@SatishRaionline

सार्थक बदलाव

भारत डोगरा

युवाओं का भरपूर योगदान कैसे मिले

भारत उन देशों में है जहां जनसंख्या के आयु वर्गीकरण के आधार पर युवा शक्ति का प्रगति में अधिक योगदान अपेक्षित है। इन संभावनाओं को भरपूर प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि युवाओं को इस प्रगति के अनुकूल अपनी क्षमता विकसित करने के पर्याप्त अवसर मिलें। इसके लिए शिक्षा और कौशल विकास के बेहतर अवसर तो जरूरी हैं ही, पर इसके साथ युवा सोच को ऐसी दिशा देना भी जरूरी है जो सामाजिक आर्थिक प्रगति के अनुकूल हो।

यह इस समय और भी जरूरी हो जाता है जब युवाओं के सामने तरह-तरह के अनिश्चय की स्थितियां उपस्थित हैं। एक ओर बेरोजगारी की समस्या है और योग्यता तथा अपेक्षा के अनुकूल रोजगार न मिल पाने की समस्या है। दूसरी ओर, कुछ अन्य स्तर पर भी अनिश्चय और भटकाव है। आखिर, ऐसी क्या बात है कि पंजाब-हरियाणा जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध क्षेत्रों में भी अनेक खाते-पीते परिवारों के युवक भी किसी तरह विदेश जाने से ही अपनी उम्मीदें जोड़ कर बैठ गए हैं। 'डंकी' मार्ग के अनेक खतरों को उठाना मंजूर है, इसके लिए परिवार को कर्जग्रस्त होना मंजूर है, पर विदेश जाना एक जिद बन गई है जबकि आसपास के परिवेश से जुड़कर एक बेहतर जीवन तलाशने का विकल्प स्वीकार्य नहीं है। इस तरह की स्थितियों से लगता है कि एक ओर शिक्षा और रोजगार की स्थिति से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो दूसरी ओर कुछ अन्य तरह का भटकाव और अनिश्चय भी है। इस कारण अनेक तनाव भी बढ़ सकते हैं और नशे जैसी तबाही की ओर झुकाव बढ़ सकता है। इन समस्याओं के बीच समाधान की एक बड़ी राह यह है कि कुछ बुनियादी मूल्यों और प्रतिबद्धताओं को युवाओं में प्रतिष्ठित किया जाए और उनकी सोच को इसके अनुकूल बताया जाए। यह सच है कि अधिकांश युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका की सोच प्रमुख है, पर आगे चुनौती यह है कि इसके साथ एक बेहतर समाज बने और युवाओं को इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका में कैसे जोड़ा जा सकता है।

युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि छात्र जीवन से ही वे इस बारे में अधिक सोचें कि उनकी प्रतिभाएं अधिक विकसित किस क्षेत्र में हो सकती हैं और किस तरह आसपास के समाज से जुड़ सकती हैं। इस तरह उनकी रचनात्मकता कहीं बेहतर ढंग से उभर सकेगी और समाज की भलाई से भी जुड़ सकेगी। इस पर अनेक युवा कहेंगे कि इस तरह की नौकरी न मिले (जिसमें अपनी रचनात्मक प्रतिभा और समाज की बेहतरी का मिलन हो) तो क्या करें। केवल नौकरी ही सब कुछ नहीं है, स्वरोजगार की भी अनेक संभावनाएं हैं, मित्रों-साथियों के साथ मिल कर भी कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं। जरूरत इस बात की है कि इस बारे में खूब सोच-विचार करें, जांच पड़ताल करें, अध्ययन करें और मित्रों, साथियों, अनुभवी व्यक्तियों, अभिभावकों से विमर्श करें कि अपनी प्रतिभा, क्षमता और सामाजिक भलाई के मिलन के आधार पर कैसे आगे बढ़ा जाए। यदि डाक्टर बनना है तो निर्धन लोगों की सेवा में अधिक जुड़ा जाए, यदि अध्यापक बनना है तो शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाएं, यदि पंचायत सदस्य बनना है तो पूरे गांव की भलाई से जुड़ा जाए, यदि किसान बनना है तो पर्यावरण की रक्षा वाली खेती की जाए। यह प्रक्रिया अपने आप इतनी रचनात्मक है कि इसमें गुजरते हुए ही युवाओं की क्षमता और समझ बहुत बढ़ती है और वे बेहतर इंसान भी बनने लगते हैं। इस सोच और विमर्श से गुजरते हुए ही युवाओं की अपने वर्तमान और भावी जीवन के बारे में कुछ ऐसे संकल्प बना लेने चाहिए जो उन्हें बेहतर जीवन और समाज की राह पर चलने में बहुत मदद करेंगे। पहली बात तो यह है कि सभी तरह के नशे से दूर रहने का संकल्प कर लिया जाए। अपने स्तर पर तो यह कर ही लिया जाए और हो सके तो नजदीकी मित्रों और साथियों को साथ लेकर भी यह संकल्प कर लिया जाए। शराब ड्रग्स, सिगरेट-बीड़ी, गुटका आदि सभी तरह के नशों को जीवन भर के लिए त्याग देना चाहिए। खान-पान, आचार, व्यवहार सभी में बेहतर स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के बिना कोई भी बड़ा संकल्प प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयां आती रहती हैं। सुरक्षा का, किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना से बचाव का अपने और परिवार के स्तर पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए जरूरी सावधानियां अपनानी चाहिए।

जब युवाओं के सामने तरह-तरह के अनिश्चय की स्थितियां उपस्थित हैं। एक ओर बेरोजगारी की समस्या है और योग्यता तथा अपेक्षा के अनुकूल रोजगार न मिल पाने की समस्या है। दूसरी ओर, कुछ अन्य स्तर पर भी अनिश्चय और भटकाव है। आखिर, ऐसी क्या बात है कि पंजाब-हरियाणा जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध क्षेत्रों में भी अनेक खाते-पीते परिवारों के युवक भी किसी तरह विदेश जाने से ही अपनी उम्मीदें जोड़ कर बैठ गए हैं। 'डंकी' मार्ग के अनेक खतरों को उठाना मंजूर है, इसके लिए परिवार को कर्जग्रस्त होना मंजूर है, पर विदेश जाना एक जिद बन गई है जबकि आसपास के परिवेश से जुड़कर एक बेहतर जीवन तलाशने का विकल्प स्वीकार्य नहीं है। इस तरह की स्थितियों से लगता है कि एक ओर शिक्षा और रोजगार की स्थिति से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो दूसरी ओर कुछ अन्य तरह का भटकाव और अनिश्चय भी है

युवाओं को अपने परिवार की भलाई से भरपूर जुड़ना चाहिए। आगे उनका विवाह होता है, तो अपने नये परिवार के प्रति पूरी निष्ठा जीवन भर रखनी चाहिए। युवाओं के लिए यह विशेष तौर पर जरूरी है कि महिलाओं का पूरा सम्मान करें और अपनी पत्नी (या किसी भी अन्य महिला के प्रति) कभी भी हिंसा या अत्याचार न करें। अच्छे पारिवारिक जीवन से एक बुनियाद तैयार होती है तो जीवन-पथ पर सदा सहायक होती है। अपने मित्रों, सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, विश्वास और आपसी सहयोग के संबंध बनाए रखना भी लगभग इतना ही जरूरी है। तरह-तरह की फिजूलखर्ची से बचना चाहिए, केवल भेड़-चाल में आ कर अनाप-शनाप खर्च नहीं करना चाहिए और अपनी तथा परिवार की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के साथ कुछ बचत करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ईमानदारी और न्याय के लिए प्रतिबद्धता जीवन में आरंभ से बना लेनी चाहिए और किसी भी अपराध और जुए जैसी बुराइयों के नजदीक भी नहीं जाना चाहिए।

सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया में यह समझ बना लेना बहुत जरूरी है कि इनका सही उपयोग क्या है और अनुचित उपयोग क्या है। अनुचित उपयोग से यथासंभव दूर रहना चाहिए। अपने भीतर की हिंसक प्रवृत्तियों को, क्रोध और हिंसा को प्रयास कर दूर करना चाहिए तथा अमन-शांति तथा अहिंसा की राह पर जीवन भर चलना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, रंग आदि के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव से दूर रहना चाहिए और सभी इंसानों की समानता, सभी धर्मों के सम्मान में गहरा विश्वास रखना चाहिए। न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, पर इसके लिए आपसी एकता से अपने को मजबूत भी बना लेना चाहिए।

ये कुछ ऐसे जीवन-मूल्य हैं जिन्हें अपना लिया जाए, या जिन्हें अपनाने का निरंतरता से प्रयास किया जाए, तो एक ऐसे जीवन की बुनियाद तैयार हो जाती है, जिससे अपनी प्रतिभाओं और रचनात्मकता को समाज की भलाई से अधिकतम जोड़ा जा सकेगा। कल्पना कीजिए, यदि बढ़ती संख्या में युवक-युवतियां, छात्र-छात्राएं अपने भावी जीवन के बारे में इस तरह सोचने लगें तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। युवा ही हमारे समाज की सबसे बड़ी संपत्ति है, देश और समाज का भविष्य उनके ही हाथों में है। अतः आज के तरह-तरह के भ्रम और भटकाव के बीच उनके लिए जीवन की सही विद्या प्राप्त करना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और इस महत्त्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी की हमें कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

जनता की आवाज और मीडिया

मीडिया

सुधीश पचौरी

कहने की जरूरत नहीं कि 'आएगा तो मोदी ही' लोगों की जुबान पर बैठ गया है। इसके बरक्स विपक्ष के किसी नेता के लिए ऐसा कोई वाक्य नहीं सुनाई देता। ध्यान से देखें तो मालूम होता है कि 'दस' में 'छह' मोदी मोदी करते हैं बाकी चार विपक्ष की बात करते दिखते हैं। इो देख कई विपक्षी आरोप लगाते हैं कि चैनल भाजपा की ओर झुके हुए हैं

चैनलों की खबरें और चरचाएं अब बोर करने लगी हैं। हर रोज वही चेहरे, वही बातें, वहीं तर्क, वही नारे, प्रति-नारे और वही वायदे, वही विज्ञापन, वही हेट-स्पीच, वही गाली-गलौज। एक कहता है कि अबकी बार 'चार सौ पार' तो दूसरा कहता है कि एक भाजपा को डेढ़ सौ मिल जाएं तो बहुत...। बहसों में 'जिच' दिखती है। खबरों व चरचाओं में वही आरोप-प्रत्यारोप कि वो नंगे तो ये सुपर नंगे तब कोई नंगों का वोट क्यों दे? कई लोग मानते हैं कि मतदान कम होने का एक बड़ा कारण दलों की यही 'तू तू मैं मैं' है।

'कम मतदान' भी चैनलों की चरचाओं का प्रिय विषय रहा है और इतना प्रिय विषय रहा है कि एक दिन बाद जब चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के आंकड़े जारी किए कि 2019 के मुकाबले 2024 के पहले चरण का मतदान कुल '00.11' प्रतिशत ही कम हुआ है तो भी इस नये तथ्य पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मतदान उतना कम नहीं हुआ जितना वोट की शाम बताया जा रहा था। कई लोग मतदान के कम होने को मोदी के जादू के खत्म होने से जोड़कर देखते रहे ताकि वे विपक्ष की हिम्मत बढ़ा सकें जबकि कई बताते रहे कि भाजपा के वोटर तो कमिटेड होते हैं, वे निकल कर आए हैं, कम मतदान से भाजपा को खतरा नहीं है।

आम लोगों की नजर में अगर मतदान कम हुआ तो उसका एक कारण तो तेज गरमी है। दूसरा, चुनाव को दो महीने में फैला देना है। तीसरा कारण शायद भाजपा का 'बड़बोलापन' है और मोदी पर जरूरत से अधिक निर्भरता है...कुछ मानते हैं कि यह चुनाव राममन्दिर के उद्घाटन के वक्त ही 'पीक' कर गया और अब 'कांग्रेस आपकी संपत्ति छीन कर मुसलमानों को दे देगी' वाली 'ध्रुवीकरण की राजनीति' के अलावा ऐसा कोई इमोशनल मुद्दा नहीं है, जो लोगों को वोट डालने के लिए उकसाए...। मतदान कम हो या अधिक, मीडिया में हर चुनाव एक इमोशनल कहानी की तरह आता है। हर चुनाव कई एक कहानी का चुनाव होता है और लोग उसी कहानी को पसंद करते हैं जो अधिकांश जनता के लिए आनंदकारी हो। जो कहानी सुखांत होती है वही जीता करती है। जनता दुखांत कहानी को पसंद नहीं करती। मोदी की कहानी अब भी सुखांत दिखती है जबकि विपक्ष की दुखांत।

इस कहानी को देखना हो तो कई चैनलों के रिपोर्टरों को शहर-कस्बों में घूम-घूम कर चुनाव कवरेज करते देखें। वे आम वोटरों से पूछते हैं कि आप किस मुद्दे पर वोट देंगे/देंगी या आप किस नेता को पसंद करते/करती हैं तो बहुत से छूटते ही कहते हैं कि 'मोदी'... यों, कई विपक्ष का नाम भी लेते हैं। ये रिपोर्टर अचानक पूछने लगते हैं कि आप किसे पसंद करते हैं मोदी को या राहुल को, तो लोग पहले मुस्कुराते हैं; यह उनका पहली बार कैमरे पर आने का तरीका है। फिर कुछ देर इधर-उधर करके रहस्य सा बुनते हैं...जब रिपोर्टर फिर से पूछता है कि बताइए आप किसे चाहते हैं तो कई कहने लगते हैं कि 'आएगा तो मोदी ही' और फिर मुस्कुराने लगते हैं जैसे कोई रहस्य खोल दिया हो...।

कहने की जरूरत नहीं कि 'आएगा तो मोदी ही' लोगों की जुबान पर बैठ गया है। इसके बरक्स विपक्ष के किसी नेता के लिए ऐसा कोई वाक्य नहीं सुनाई देता। ध्यान से देखें तो मालूम होता है कि 'दस' में 'छह' मोदी मोदी करते हैं बाकी चार विपक्ष की बात करते दिखते हैं। इसे देख कई विपक्षी आरोप लगाते हैं कि चैनल भाजपा की ओर झुके हुए हैं जबकि सचाई यह है कि लोग मोदी सरकार से नाराज हैं...। चरचाओं में कई विशेषज्ञ कहते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है तो कई कहते हैं कि ये मुद्दे तो हैं लेकिन नाराजी नहीं है। ऐसा नहीं कि मीडिया ने विपक्ष के खिलाफ कोई पोजीशन ले रखी है, बल्कि सच यह है कि मीडिया भी इन दिनों फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है, और कई तो रिपोर्टिंग से लेकर बहसों तक में 'बेलेंसिग एक्ट' करते दिखते हैं कि कल को कहीं 'इंडी गठबंध' आ गया तो उनका क्या होगा?

कई इसे मीडिया पर दबाव की तरह देखते हैं लेकिन मीडिया जानता है कि उसका हित न इस गठबंध का भौंपू बनने में है न उस गठबंध का भौंपू बनने में है बल्कि जनता का भौंपू बनने में है। यों समकालीन ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते कुछ चाहते हैं कि मीडिया मोदी का विपक्षी बन जाए, तो कुछ चाहते हैं कि वह विपक्ष को निपटाने काम आए लेकिन मीडिया बेहतर जानता है कि उसका असली हित अपनी 'दर्शक/श्रोता' जनता की आवाज बनने में है।

इसीलिए इन दिनों वह सत्ता और विपक्ष, दोनों के प्रति एक क्रिटिकल दूरी बना कर चलता दिखता है।

धर्म आधारित आरक्षण की राजनीति

मुद्दा

प्रमोद भार्गव

वंचित समुदाय, चाहे अल्पसंख्यक हों अथवा गरीब सवर्ण, को बेहतरी के उचित अवसर देना लाजिमी है क्योंकि बदहाली की सूरत अल्पसंख्यक अथवा जातिवादी चश्मे से नहीं सुधारी जा सकती? खाद्य की उपलब्धता से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी ठेस मानवीय सरोकार हैं, उनको हासिल करना मौजूदा दौर में पूंजी और शिक्षा से ही संभव है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धर्म के आधार पर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी करने के संविधान विरोधी प्रयासों पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस से सवाल किया है, 'क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि वे संविधान में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को कम करके इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे?' 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी तो उसने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में एससी/एसटी आरक्षण को कम कर इस कोटे में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास किया था। यह कांग्रेस का 'पायलट प्रोजेक्ट' था, जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004-2010 के बीच कांग्रेस ने चार बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वे अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए। मोदी ने अब फिर से आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में लोगों का धन छीन कर अपने 'खास' लोगों को बांटने की साजिश रची है। यह अत्यंत तल्ख टिप्पणी राजस्थान के टोंक जिले में एक चुनावी जनसभा में की।

प्रधानमंत्री की टिप्पणी संपूर्ण सत्य है। एक समय कांग्रेस सरकार की अल्पसंख्यक बनाम मुस्लिमों को पिछड़ों, दलित और आदिवासियों के संविधान में निर्धारित कोटा के अंतर्गत 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने की मंशा रही थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दायर अपील को खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश चाहती थी। इस मंशा के विपरीत कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट करने को कहा था कि वह बताए कि उसने किस आधार पर अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया? कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह तो कोटे में उपकोटा आरक्षित करने का सिलसिला चलता रहेगा। दरअसल, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने धर्म के आधार पर' आरक्षण का लाभ संविधान के विरुद्ध बताया था।

वर्तमान में दिसम्बर, 2011 के बाद से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसद आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन केंद्र सरकार ने ओबीसी के कोटे में खास तौर से मुस्लिमों को लुभाने के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कर दिया था। इसे कानूनी रूप देते हुए 'अल्पसंख्यकों से संबंधित' और 'अल्पसंख्यकों के लिए' जैसे वाक्यों का जो प्रयोग किया गया वह असंगत है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इस फैसले का व्यापक असर होना तय था क्योंकि यह प्रावधान आईआईटी जैसे केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भी लागू हो गया था।

वंचित समुदाय, चाहे अल्पसंख्यक हों अथवा गरीब सवर्ण, को बेहतरी के उचित अवसर देना लाजिमी है क्योंकि बदहाली की सूरत अल्पसंख्यक अथवा जातिवादी चश्मे से नहीं सुधारी जा सकती? खाद्य की उपलब्धता से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी ठोस मानवीय सरोकार हैं, उनको हासिल करना मौजूदा दौर में पूंजी और शिक्षा से ही संभव है। ऐसे में आरक्षण के सरोकारों के जो वास्तविक हकदार हैं, वे अपरिहार्य योग्यता के दायरे में न आ पाने के कारण उपेक्षित ही रहेंगे। अलबत्ता, आरक्षण का सारा लाभ वे बटोर ले जाएंगे जो आर्थिक रूप से पहले से ही सक्षम हैं, और जिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों से पढ़े हैं। इसलिए इस संदर्भ में मुसलमानों और भाषायी अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की वकालत करने वाली रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट के भी कोई बुनियादी मायने नहीं रह गए थे? यह रिपोर्ट भी मुसलमानों को संवैधानिक प्रावधानों में आरक्षण जैसे विकल्प खोलने के लिए तैयार कराई गई थी।

वर्तमान समय में मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध ही अल्पसंख्यक दायरे में आते हैं जबकि जैन, बहाई और कुछ दूसरे धर्म-समुदाय भी अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करना चाहते हैं लेकिन जैन समुदाय केंद्र द्वारा अधिसूचित सूची में नहीं है। इन्हीं वजहों से आतंकवाद के चलते अपनी ही पुश्तैनी जमीन से बेदखल कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। दरअसल, 'अल्पसंख्यक श्रेणी' का अधिकार पा लेने के क्या राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक निहितार्थ हैं, इन्हें समझना मुश्किल है।

सामूहिक जिम्मेदारी से ही बनेगी बात

पर्यावरण

देवेन्द्रराज सुथार

भारत को पहली बार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) 2022 रैंकिंग में सबसे खराब पांच देशों में शामिल किया गया है। 180 देशों में भारत की सबसे निचली रैंकिंग ने देश की पर्यावरण नीतियों और पहलों की प्रभावकारिता पर बहस छेड़ दी है। हालांकि सरकार ने इस रैंकिंग के लिए दोषपूर्ण पद्धतियों को जिम्मेदार ठहराया है। निर्विवाद है कि भारत को पर्यावरणीय प्रबंधन में वायु और पानी की गुणवत्ता एवं पारिस्थितिकी तंत्र जैसे क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

उल्लेखनीय है कि ईपीआई जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर देशों को रैंक करता है। यह वायु गुणवत्ता, पेयजल और स्वच्छता जैसी 11 श्रेणियों में 40 प्रदर्शन संकेतकों को मापता है। भारत में 2014 में लॉन्च किए गए एसबीएम ने लाखों शौचालयों और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के निर्माण सहित बुनियादी ढांचे के विकास में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। मगर तमाम प्रयासों के बावजूद देश के कई हिस्सों खासकर ग्रामीण इलाकों में अनुचित अपशिष्ट निपटान और खुले में शौच की आदतें अभी भी कायम हैं। एसबीएम के तहत बुनियादी ढांचे के विकास प्रयासों की प्रभावशीलता अक्सर जमीनी स्तर पर अपर्याप्त संसाधन आवंटन और उपयोग से बाधित होती है। हालांकि सरकार ने मिशन के लिए महत्त्वपूर्ण धनराशि आवंटित की है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि इन संसाधनों को प्रभावी ढंग से वहां तैनात किया जाए जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, एक लगातार चुनौती बनी हुई है। उचित निगरानी और फीडबैक तंत्र की कमी भी इन मुद्दों को और बढ़ा देती है।

इन चुनौतियों से पार पाने के लिए सामुदायिक सहभागिता और पर्यावरणीय पहलों में भागीदारी पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। स्थानीय समुदायों और संगठनों को अपने संबंधित क्षेत्रों में स्वच्छता प्रयासों का स्वामित्व लेने के लिए सशक्त होना चाहिए जिससे पर्यावरण प्रबंधन के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिले। पर्यावरणीय गिरावट के मूल कारणों का निस्तारण करने वाले स्थायी समाधानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें न केवल बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है, बल्कि टिकाऊ उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देने, प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रयास भी शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ कृषि और हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश भी महत्त्वपूर्ण है।

स्वच्छता के प्रति गहरी जड़ें जमा चुके सांस्कृतिक दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलना आवश्यक है। इसलिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें न केवल सरकारी हस्तक्षेप, बल्कि समुदायों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग भी शामिल हो। स्वच्छ भारत मिशन की दीर्घकालिक सफलता के लिए निरंतर निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्र के साथ-साथ स्वच्छता के मुद्दों के मूल कारणों को संबोधित करने वाले स्थायी समाधान आवश्यक हैं। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहल ने प्रगति की ठोस नींव रखी है, लेकिन पर्यावरण की गुणवत्ता में सार्थक और टिकाऊ सुधार हासिल करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है।

कोई नया विकल्प उभरना चाहिए

बतंगड़ बेतुक

विभांशु दिव्याल

झल्लन बोला, 'ददाजू, हमारे मोदी जी हडकंप मचा दिये हैं, चुनावी माहौल में आग लगा दिये हैं, हम समझ नहीं पा रहे है कि भला किये हैं या बुरा किये हैं।' हमने कहा, 'कौन सी नयी बात है। मोदी जी तो हड़कंप मचाते ही रहते हैं, लोगों के दिलों में देशभक्ति की आग लगाते ही रहते हैं, उनकी नजर में जो देशद्रोही हैं उनको बैठे-ठाले सुलगाते रहते हैं, किसी को पुचकारते हैं किसी को दुत्कारते हैं, किसी को हड़काते हैं किसी को भड़काते हैं। आजकल चुनाव चल रहे हैं सो अपनी हर सभा में चार सौ पार की बात उठा रहे हैं और अपने विरोधियों के बीच हड़कंप मचा रहे हैं। जिसे बुरा लगे लगता रहे, जिसे रोना है रोता रहे। अब इसे तू बुरा मान ले या भला मान ले, तू चाहे इसे जैसे जान ले, पहचान ले।'

झल्लन बोला, 'ददाजू, वैसे तो हम मोदी जी के कहे-किये को जान भी लेते हैं, पहचान भी लेते हैं और कभी-भी तो मान भी लेते हैं। पर जब मोदी जी गुलेल में कंकड़ की जगह एटम बम रखके चलाते हैं तो हमारे औसान फना हो जाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो लोगों की संपत्ति बंटवाएगी, माताओं-बहनों के मंगलसूत्र बिकवाएगी और इससे जो लाभ कमाएगी वो घुसपैठियों में बंटवाएगी। अब मोदी जी की यही बात हमें जच नहीं रही है और सच कहे ददाजू, बिल्कुल पच नहीं रही है और उधर देखिए, मुसलमानों के तानाशाह ओवैसी ने घुसपैठियों का मतलब भारतवासी मुसलमान निकाल लिया, जलती आग में अपनी तरफ से मुसलमानी पेट्रोल डाल दिया।' हमने कहा, 'झल्लन, चाहे मोदी जी हों या कोई और, चुनाव के दौर में नेताओं के भाषण, भाषण नहीं बेलगाम घोड़े हो जाते हैं जो चुनाव प्रचार के मैदान में छुट्टा छोड़े जाते हैं। कोई कहता कुछ और है पर अर्थ कुछ और खोज लिया जाता है और सुनने वालों के दिमागों पर थोप दिया जाता है। अब देख, कांग्रेस कह रही है कि अगली बार जैसे ही मोदी सत्ता संभालेगा तो दलितों-पिछड़ों का सारा धन छीनकर अपने अमीर दोस्तों को थमा देगा। उधर भाजपा कह रही है कि खुदा न खास्ता असंभव को संभव बनाते हुए राहुल बबुआ सत्ता पा जाएगा तो पिछड़ों-अतिपिछड़ों का सारा आरक्षण मुसलमानों के पास चला जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि न भाजपा वह कर पाएगी जो कांग्रेस कह रही है और न कांग्रेस वह कर पाएगी जो भाजपा कह रही है, मगर दोनों की अपनी-अपनी ढपली है जो अपनों-अपनों को बहलाने-फुसलाने को बज रही है।'

झल्लन बोला, 'पर ददाजू हम तो मंगलसूत्र को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मां-बहनों का मंगलसूत्र बच जाये, भले हमारा वोट मोदी जी को चला जाये।' हमने कहा, 'वैसे हमारी कोई औकात नहीं पर इतनी गारंटी तो तुझे हम भी दिये देते हैं कि तेरे घर की किसी देवी का मंगलसूत्र कहीं नहीं जाएगा, जिसके पास है उसी के पास रहा आएगा।' झल्लन बोला, 'आपकी बात सुनकर थोड़ी राहत मिली ददाजू, वरना हम तो घबरा गये थे कि अपनी होने वाली बीवी का मंगलसूत्र भी नहीं बचा पाएंगे तो कैसे किसी को मुंह दिखा पाएंगे। पर ददाजू, एक बात तो आप भी मानेंगे कि हमारे मोदी जी कभी-कभी ज्यादा बोल जाते हैं, बेवजह चुनावी दूध में हिंदू-मुसलमान की खटाई डाल जाते हैं।' हमने कहा, 'झल्लन, आजकल हिंदू-मुसलमान की खटाई कौन नहीं डाल रहा है, किस पार्टी का कौन सा नेता ऐसा है जो विरोधियों के प्रति नफरत नहीं उछाल रहा है, कोई हिंदुओं को भड़का रहा है तो कोई मुसलमानों को भड़का रहा है, हर कोई अपनी-अपनी जाति-जमातों को भड़काकर ही चुनावी माल कमा रहा है। जो नफरत भड़काता है वह हिट हो जाता है और जो प्यार-मोहब्बत की बात करता है वह कहीं का नहीं रहता, घर में बैठे-बैठे ही पिट जाता है। जो सिर्फ मोदी को ही दोषी ठहराते हैं वे खुद अपने गिरेबान में नहीं झांकते, अपनी जबान और करतूतों को नहीं आंकते। ताली एक हाथ से नहीं सभी हाथों से बजायी जा रही है, आग एक तरफ से नहीं चारों तरफ से लगायी जा रही है।'

झल्लन बोला, 'पर ददाजू हम तो मंगलसूत्र को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मां-बहनों का मंगलसूत्र बच जाये, भले हमारा वोट मोदी जी को चला जाये।' हमने कहा, 'वैसे हमारी कोई औकात नहीं पर इतनी गारंटी तो तुझे हम भी दिये देते हैं कि तेरे घर की किसी देवी का मंगलसूत्र कहीं नहीं जाएगा, जिसके पास है उसी के पास रहा आएगा।' झल्लन बोला, 'आपकी बात सुनकर थोड़ी राहत मिली ददाजू, वरना हम तो घबरा गये थे कि अपनी होने वाली बीवी का मंगलसूत्र भी नहीं बचा पाएंगे तो कैसे किसी को मुंह दिखा पाएंगे। पर ददाजू, एक बात तो आप भी मानेंगे कि हमारे मोदी जी कभी-कभी ज्यादा बोल जाते हैं, बेवजह चुनावी दूध में हिंदू-मुसलमान की खटाई डाल जाते हैं।' हमने कहा, 'झल्लन, आजकल हिंदू-मुसलमान की खटाई कौन नहीं डाल रहा है, किस पार्टी का कौन सा नेता ऐसा है जो विरोधियों के प्रति नफरत नहीं उछाल रहा है, कोई हिंदुओं को भड़का रहा है तो कोई मुसलमानों को भड़का रहा है, हर कोई अपनी-अपनी जाति-जमातों...

झल्लन बोला, 'चलो आपकी बात का संज्ञान लेते हैं, जो कह रहे हो वो मान लेते हैं। राहुल बबुआ कह रहा है कि मोदी फिर आ गया तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो संविधान भी नहीं बचेगा। सो जो भी लोकतंत्र और संविधान बचाना चाहे, वो अपना वोट लेकर उनके हाथ में आ जाये।' हमने कहा, 'झल्लन, दरअसल न संविधान खतरे में है न लोकतंत्र खतरे में है, वस्तुतः फिर से सत्ता पर काबिज होने की इन सबकी उम्मीद खतरे में है। ये सबके सब बौखला गये हैं, दिमाग से खोखला गये हैं। कुतर्क रच रहे है, असंगत बात कह रहे हैं। सब हड़कंप मचाना चाहते हैं, किसी तरह सत्ता में आना चाहते हैं।' झल्लन बोला, 'ददाजू, ऐसे तो पूरे मुल्क का माहौल खराब हो जाएगा, जो अच्छा है वो भी बुरा हो जाएगा। हमें तो लगता है ददाजू, अब आपको ही मैदान में आना चाहिए और अपने मुल्क को बचाना चाहिए।' हमने कहा, 'हम तो क्या बचाएंगे, पर हमें लगता है कोई नया विकल्प जरूर उभरना चाहिए, किसी नयी ताकत को मैदान में उतरना चाहिए।'

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-33, अंक 256 आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

'शुद्ध' शाकाहारी में कुपोषण के कारण इतना अहं होता है कि आप उनकी मानसिक व्याधि और ग्रंथियों को लेकर ट्वीट नहीं करते हैं, तो वे उपेक्षित, अकेले, दयनीय, अवांछित, अलग-थलग, नाजायज महसूस करते हैं।
—देवदत्त पटनायक, धर्म मर्मज्ञ@devduttmyth

उपलब्धि

प्रह्लाद सबनानी

धार्मिक पर्यटन से होंगे एक पंथ दो काज

हाल ही के समय में भारत के नागरिकों में 'स्व' का भाव विकसित होने के चलते देश में धार्मिक पर्यटन बहुत तेज गति से बढ़ा है। अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम के भव्य मन्दिर में श्रीराम लला के विग्रहों की प्राण-प्रतिष्ठा के पश्चात प्रत्येक दिन औसतन दो लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह तो केवल अयोध्या की कहानी है। इसके साथ ही तिरुपति बालाजी, काशी विश्वनाथ मन्दिर, उज्जैन में महाकाल लोक, जम्मू स्थित वैष्णो देवी मन्दिर, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं यमनोत्री जैसे कई मन्दिरों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। भारत में धार्मिक पर्यटन में आई जबरदस्त तेजी की बदौलत रोजगार के लाखों नये अवसर सृजित हो रहे हैं, जो देश के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक हो रहे हैं।

जेफरीज नामक एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज कंपनी ने बताया है कि अयोध्या में निर्मित प्रभु श्रीराम के मन्दिर से भारत की आर्थिक संपन्नता बढ़ने जा रही है। 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में संपन्न प्रभु श्रीराम मन्दिर में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के बाद स्थानीय कारोबारी अपना उज्ज्वल भविष्य देख रहे हैं। अयोध्या धार्मिक पर्यटन का हब बनाने जा रहा है तथा अब अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जेफरीज के अनुसार अयोध्या में प्रति वर्ष 5 करोड़ से अधिक पर्यटक आ सकते हैं। अभी अयोध्या में केवल 17 बड़े होटल हैं। इनमें कुल मिलाकर 590 कमरे उपलब्ध हैं, लेकिन अब 73 नये होटलों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 40 होटलों का निर्माण कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। अभी तक नये एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, टाउनशिप और रोड कनेक्टिविटी में सुधार जैसे कामों पर 85,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस निवेश का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर दिखाई देने जा रहा है। शीघ्र ही अयोध्या वैश्विक स्तर पर धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। इससे होटल, एयरलाइन, हॉस्पिटिलिटी, ट्रैवल, सीमेंट जैसे क्षेत्रों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। भारत के विभिन्न शहरों से 1000 के आसपास नई रेल अयोध्या के लिए चलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे देश से 23 जनवरी, 2024 के बाद से प्रति दिन भारी संख्या में धार्मिक पर्यटक अयोध्या पहुंच रहे हैं। हर्ष का विषय है कि पहले दिन ही पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रभु श्रीराम के दर्शन किए हैं।

विश्व के कई अन्य देश भी धार्मिक पर्यटन के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्थाएं सफलतापूर्वक मजबूत कर रहे हैं। सऊदी अरब धार्मिक पर्यटन से प्रति वर्ष 22,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर अर्जित करता है। सऊदी अरब इस आय को आगे आने वाले समय में 35,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक ले जाना चाहता है। मक्का में प्रति वर्ष 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं, जबकि मक्का में गैर-मुस्लिम के पहुंचने पर पाबंदी है। इसी प्रकार, वेटिकन सिटी में प्रति वर्ष 90 लाख लोग पहुंचते हैं। इस धार्मिक पर्यटन से अकेले वेटेकन सिटी को प्रति वर्ष लगभग 32 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आय होती है, और अकेले मक्का शहर को 12,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आमदनी होती है। अयोध्या में तो किसी भी धर्म, मत, पंथ मानने वाले नागरिकों पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। अतः अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 से 10 करोड़ तक प्रति वर्ष जा सकती है। फिर अकेले अयोध्या नगर को होने वाली आय का अनुमान तो सहज रूप से लगाया जा सकता है। अभी अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अयोध्या में रुकते नहीं थे प्रातः अयोध्या पहुंच कर प्रभु श्रीराम के दर्शन कर शाम तक वापस चले जाते थे परंतु अब अयोध्या को इतना आकर्षक रूप से विकसित किया गया है कि श्रद्धालु 3-4 दिन रुकने का प्रयास करेंगे। एक अनुमान के अनुसार, प्रत्येक पर्यटक लगभग 6 लोगों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है। इस संख्या के हिसाब से तो लाखों नये रोजगार के अवसर अयोध्या में उत्पन्न होने जा रहे हैं। अयोध्या के आसपास विकास का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। यह कहना भी अतिश्योक्ति नहीं होगा कि अब अयोध्या के रूप में वेटिकन एवं मक्का का जवाब भारत में खड़ा होने जा रहा है।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भी धरातल पर बहुत कार्य संपन्न किया है। अब इसके अंतर्गत एक रामायण सर्किट रूट को भी विकसित किया जा रहा है। इस रूट पर विशेष रेलगाड़ियां भी चलाए जाने की योजना बनाई गई है। यह विशेष रेलगाड़ी 18 दिनों में 8000 किलो मीटर की यात्रा संपन्न करेगी, इस विशेष रेलगाड़ी के इस रेलमार्ग पर 18 स्टॉप होंगे। यह विशेष रेलमार्ग प्रभु श्रीराम से जुड़े ऐतिहासिक नगरों अयोध्या, चित्रकूट एवं छतीसगढ़ को जोड़ेगा। अयोध्या में नवनिर्मित प्रभु श्रीराम मंदिर वैश्विक पटल पर इस रूट को भी रखेगा। केंद्र सरकार द्वारा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार किए जा रहे प्रयासों का परिणाम भी अब दिखाई देने लगा है। देश में धार्मिक पर्यटन में हो रही भारी वृद्धि के चलते भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में भी तेजी दिखाई देने लगी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ने भारत सहित विश्व के समस्त आर्थिक विश्लेशकों को चौंका दिया है। इस दौरान, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई है जबकि प्रथम तिमाही के दौरान वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही के दौरान 7.6 प्रतिशत की रही थी। ■

विश्व के कई अन्य देश भी धार्मिक पर्यटन के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्थाएं सफलतापूर्वक मजबूत कर रहे हैं। सऊदी अरब धार्मिक पर्यटन से प्रति वर्ष 22,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर अर्जित करता है। सऊदी अरब इस आय को आगे आने वाले समय में 35,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक ले जाना चाहता है। मक्का में प्रति वर्ष 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं, जबकि मक्का में गैर-मुस्लिम के पहुंचने पर पाबंदी है। इसी प्रकार, वेटिकन सिटी में प्रति वर्ष 90 लाख लोग पहुंचते हैं

संजीव चतुर्वेदी

बिहार योग : स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए मौन क्रांति

वैसे तो पूरे भारत में योग की शिक्षाओं की परंपरा शताब्दियों से रही है, लेकिन यह आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी। भारतीय समाज में योग की शिक्षा गुरु-शिष्य परंपरा के तहत दी जाती थी, या कहें कि सनातन संस्कृति में शिक्षा गुरुकुल में ही दी जाती थी। लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी के बाद योग का प्रचार-प्रसार ज्यादा होने लगा। 18वीं शताब्दी के अंत में साधु, संन्यासी, योगियों का यूरोप और अमेरिका के लोगों से ज्यादा परिचय होने लगा। स्वामी विवेकानंद के शिकागो सम्मलेन के भाषण के बाद तो बहुत तेजी से पश्चिमी देश योग के प्रति आकर्षित हुए। फिर 19वीं शताब्दी में तो बहुत सारे साधु-संन्यासी, योगी, गुरु, योग आचार्य और सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए विश्व भ्रमण पर जाने लगे। योग बहुत तेजी से फैलने लगा। फिर भी 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों तक योग आम लोगों से दूर ही था।

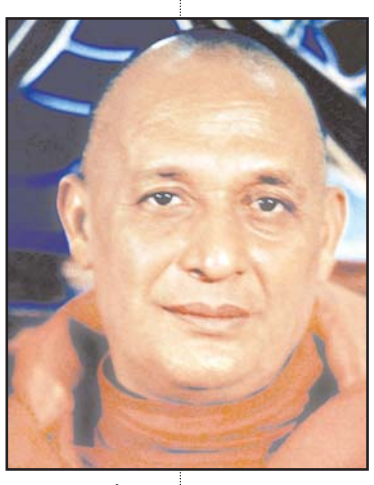

बिहार योग का बीजारोपण-स्वामी शिवानंद सरस्वती का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वो डॉक्टर थे। बाद में वो डॉक्टरी का अपना पेशा छोड़ कर अध्यात्म की खोज में ऋषिकेश आ गए। वहां उन्होंने दिव्या लाइफ सोसायटी की स्थापना की। वहां जब उन्होंने देखा की बहुत सारे साधु-संत या अन्य लोग विभिन्न बिमारियों से ग्रसित हैं, और इलाज करवाने में सक्षम नहीं हैं, तब वो अपनी संस्था के माध्यम से सभी की मदद करने लगे। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। कई किताब लिखीं। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि समाज में जाओ और योग द्वारा लोगों की सेवा करो। 1963 में मुंगेर में बिहार योग विद्यालय की स्थापना की गई।

गुरु साक्षात परम ब्रह्मा-स्वामी सत्यानंदा जी अपने गुरु के आदेश को पूरा करने में लग गए। देश-विदेश भ्रमण के दौरान सत्संग में मिले दान से डॉक्टर तथा लैब किराये पर लेकर योग के अभ्यासों पर रिसर्च करते थे तथा उसके परिणामों द्वारा योग के महत्त्व तथा विशेषताओं को आम लोगों के सामने रखते थे ताकि वे विश्वास के साथ योग के अभ्यासों द्वारा स्वास्थ्य लाभ कर सकें। उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन करके योग के अभ्यासों को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया। हरेक अभ्यास के गुण-दोष को परख कर सामान्य भाषा में लोगों के सामने रखा। स्वामी जी ने स्वलिखित सैकड़ों किताबों और प्रशिक्षित योग शिक्षकों के माध्यम से योग को सर्वसुलभ बनाया।

समग्र योग और मानक की स्थापना-प्राचीन काल से ही भारत में योग की परंपरा रही है। बहुत सारे गुरु या शिक्षक व्यक्तिगत रूप से या किसी संस्था के माध्यम से योग की शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन ज्यादार एक परंपरा या रास्ते को चुनकर सिखाते थे या अभी भी सिखा रहे हैं, जैसे कोई कर्मयोग तो कोई भक्ति योग, कोई क्रिया योग तो कोई तंत्र योग, कोई सिर्फ आसन तो कोई प्राणायाम या सिर्फ ध्यान सिखा रहे हैं लेकिन स्वामी सत्यानंदा जी ने महसूस किया कि योग के विभिन्न माध्यम को एकीकृत करके लोगों के सामने लाना पड़ेगा ताकि यह सभी के लिए फायदेमंद हो। स्वामी जी ने योग में एक मानक की स्थापना की। अपने अनुभवों से पाया कि व्यक्तिगत रूप से लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए उनकी जरूरत भी एक दूसरे से अलग होती हैं। कोई एक अभ्यास या परंपरा या व्यवस्था सभी के लिए फायदेमंद या उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने योग के विभिन्न आयामों को मिला कर एक मानक तैयार किया जो आज बिहार योग या सत्यानंद योग के रूप में प्रचलित है।

बिहार योग का महत्त्वपूर्ण योगदान-सभी ने अपनी-अपनी तरह से सनातन धर्म और योग के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दिया है खासकर सोशल मीडिया के दौर में विज्ञापनबाजी द्वारा योग का प्रसार तेजी से हुआ। योग आज अरबों डॉलर का व्यवसाय बन चुका है। लेकिन बिहार योग आज भी मीडिया और विज्ञापनबाजी से दूर रह कर अपना काम कर रहा है। स्वामी सत्यानंदा जी के आदेशानुसार आज भी उनके परम शिष्य और बिहार योग के परमाचार्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी, जिन्हें 2017 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, आज भी योग को बेच नहीं रहे हैं, बल्कि योग शिक्षा को दानस्वरूप समाज को दे रहे हैं। आज आप लगभग सभी योग से जुड़े संस्थानों में बिहार योग द्वारा प्रकाशित किताबों की जरूर देखेंगे। बिहार योग मौन क्रांति की तरह 50 वर्षों से अपना काम कर रहा है, जो ऋषिकेश से शुरू हुआ था।

स्वामी सत्यानंदा जी के कुछ प्रमुख योगदान-

पवनमुक्तासन समूह का विकास-मेरे विचार से इस समूह के विकास से बुजुर्गों, शारीरिक रूप से कमजोर, मरीजों, चोटग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुलभ हो गया। हठ योगियों को देख कर लोग डर जाते थे लेकिन पवनमुक्तासन ने ज्यादा लोगों को योग के प्रति आकर्षित किया।

योगाभ्यासों का समूहीकरण-स्वामी जी ने योगाभ्यासों खासकर आसनों और प्राणायामों का समूहीकरण और सूचिबद्ध करके उनके लाभ-हानि को विस्तार से समझाया और लिपिबद्ध किया। विस्तारपूर्वक उल्लेख किया कि अभ्यासों को कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है तथा इसके परिणाम क्या होंगे आदि।

षट्क्रियाओं का सरलीकरण-षट्क्रियाओ का अभ्यास आम लोगों के लिए निषेध था, लेकिन स्वामी जी ने इसको सरल बनाया और उसको विस्तारपूर्वक लिपिबद्ध किया। खासकर लघु शंखप्रक्षालना, कपालभाति और त्राटक के अभ्यास को आम लोगों तक पहुंचाया।

मुद्रा और बंध का उपयोग-मुद्रा और बंध को उच्च अभ्यास माना जाता था और कुछ मुद्राओं का प्रयोग ध्यान के लिए किया जाता था लेकिन स्वामी जी ने इसको आसन और प्राणायाम के साथ एकीकृत करके उसके फायदे को विस्तारपूर्वक समझाया।

योग निद्रा-स्वामी सत्यानंदा जी ने इस अभ्यास का प्रयोग खुद अपने परम शिष्य स्वामी निरंजनानंद जी पर किया और फिर आम लोगों को उपलब्ध कराया। आज विश्व में योग निद्रा काफी प्रचलित है। शारीरिक-मानसिक शांति, मरीजों के पुनर्वास, बच्चों को बौद्धिक तथा मानसिक शिक्षा देने तथा पुरानी बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

तंत्र आधारित ध्यान का अभ्यास-तंत्र की शक्तिशाली शिक्षा गुप्त रूप से दी जाती थी और लोगों में तंत्र के बारे में गलतफहमियां थीं। उन्होंने उन अभ्यासों को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया। आज लोग अंतरमौन, अजपा जप , धारणा ध्यान, त्राटक आदि का अभ्यास आसानी से कर रहे हैं। पहले यह उन्हें उपलब्ध नहीं था।

उच्च अभ्यास और उसके तकनीक का एकीकरण-स्वामी जी ने विभिन्न योग परंपराओं के अभ्यास की तकनीकों का एकीकरण किया ताकि लोग उन तकनीकों का उपयोग करके लाभ उठा पाएं। प्राचीन ग्रंथों में दी गईं तकनीकों के संदर्भ में भ्रम की स्थिति थी, जिसको स्वामी जी ने सुलभ बनाया। मंत्रों को योग कक्षा में सम्मलित करके योग अभ्यासों को मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी सटीक बनाया।

सजगता और शिथिलता के साथ अभ्यास-स्वामी जी ने किसी अभ्यास को किस दृष्टिकोण या रवैया से करना है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया। पहले सिर्फ अभ्यास को करने पर ध्यान दिया जाता था लेकिन स्वामी जी ने अभ्यास को कैसे करना है, उस पर भी ध्यान दिया ताकि अभ्यास सिर्फ शारीरिक बनकर न रह जाए।

योग शिक्षकों की गुणवत्ता-स्वामी सत्यानंदा जी ने योग शिक्षकों की गुणवत्ता पर बहुत ध्यान दिया। खुद ही शिक्षकों को प्रशिक्षित करते थे ताकि योग शिक्षक योग विज्ञान को गुणवत्ता और बिना किसी नकारात्मक छवि के साथ समूचे विश्व में पहुंचाया जा सके। आज बिहार योग भरोसेमंद योग संस्था के रूप में देश-विदेश में प्रचलित है। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के सन्निध्य में यह पूरे विश्व में अपना प्रकाश फैला रहा है। बिहार योग ने कभी हर शहर या देश में अपनी शाखा बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान दिया। बिहार योग ने कभी योग को बिजनेस नहीं बनाया, बल्कि प्रसाद के रूप में घर-घर पहुंचाने की कोशिश है। स्वामी निरंजन जी आज अपने परम गुरु स्वामी शिवानंद जी और गुरु स्वामी सत्यानंद जी के सपनों को साकार करके समाज को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में मौन रूप से लगे हुए हैं। यह एक मौन क्रांति ही है जो मानवता के लिए अमृत के समान है। ■

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मोबाइलमय जीवन

विष है मोबाइल, अमृत है मोबाइल
मर गई संवेदना, जीवित है मोबाइल

भोजनालय में मोबाइल, शौचालय में मोबाइल
लड़खड़ाने लगी भक्ति, देवालय में मोबाइल
मन में मोबाइल, मनन में मोबाइल

मुरझाने लगी जिंदगी, जीवन में मोबाइल

बचपन में मोबाइल, यौवन में मोबाइल
धूमिल हुई रोशनी, नयन में मोबाइल

जन्म में मोबाइल है, मरण में मोबाइल
हम हैं पाताली, गगन में मोबाइल

रोजी है मोबाइल, सेज है मोबाइल
हम हैं अधीन, अंग्रेज है मोबाइल

■ सुनील चौरसिया 'सावन'

राग रंग | आलोक पराड़कर

ऐसा ही गुरु भावे

अब प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन-साजन मिश्र की गाई रचना है-'साधो, ऐसा ही गुरु भावे, राग रंग का भर-भर प्याला पीवे और पिलावे, नाद छिपा तन में लय मन में, कोई पता ना पावे, चांद सूरज सा लोचन गुरु का, देखे और दिखावे, साधो, ऐसा ही गुरु भावे...'। वे इसे विभिन्न संगीत महफिलों में गाते रहे हैं। वास्तव में यह फिल्म 'सुर संगम' का गीत है, जिसमें पंडित राजन-साजन मिश्र के गाए गीत आज भी खूब सुने जाते हैं। गुरु वंदना का यह गीत मिश्र बंधु के साथ पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल ने गाया है। हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत गुरु-शिष्य परंपरा में आगे बढ़ा है। संगीत के संस्थानों की स्थापना और महाविद्यालयों-विश्वविद्यालयों में इसकी शिक्षा के बावजूद आज भी शास्त्रीय संगीत में गुरु -शिष्य परंपरा का विशिष्ट महत्त्व है। संगीत के विद्यार्थी अपने गुरुओं के साथ रहकर, उनके साथ अधिक से अधिक समय बिता कर संगीत की शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं।

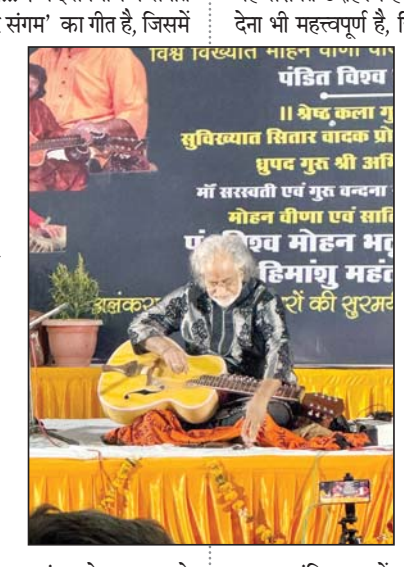

पंडित राजन-साजन मिश्र के शिष्य हैं ग्वालियर के पंडित उमेश कंपूवाले। माधव संगीत महाविद्यालय सहित विभिन्न संगीत विद्यालयों में अध्यापन कर चुके 66 वर्षीय कंपूवाले ने करीब दो दशक तक मिश्र बंधु से शिक्षा ग्रहण की है। शास्त्रीय संगीत में गुरु-शिष्य परंपरा की भावना का निर्वाह वे बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। इस परंपरा के महत्त्व को समझाने के लिए वे जहां गुरु-शिष्य परंपरा संगीत संस्थान की स्थापना कर काफी संख्या में विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं, जो बड़े ही आदर के साथ गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं वहीं अपने गुरु पंडित राजन मिश्र के कोरोना काल में 25 अप्रैल, 2021 को दिवंगत होने के बाद कंपूवाले पुण्यतिथि पर हर साल ग्वालियर में स्मृति समारोह का आयोजन करते हैं, और गुरु की स्मृति में सम्मान भी प्रदान करते हैं। इस वर्ष ग्वालियर के महाराज बाड़ा स्थित टाउनहाल में 25 अप्रैल को आयोजित समारोह में प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक पंडित विश्वमोहन भट्ट को पंडित राजन मिश्र स्मृति अलंकरण प्रदान किया गया।

सम्मान प्रदान करने से पहले जब कंपूवाले वाले ने मंच पर ही पंडित विश्वमोहन भट्ट के पांव पखारे तो वे भावुक हो उठे। भट्ट जी ने कहा कि सम्मान तो कई जगह मिले लेकिन यह सम्मान और उसको प्रदान करने का तरीका सबसे विशिष्ट है। उन्होंने कहा कि जब गुरु रूप में किसी कलाकार के चरण धोए जाते हैं, तो वास्तव में कलाकार के भीतर बसी उस शक्ति और ज्ञान के प्रति आदर व्यक्त किया जा रहा होता है, जो उसे कलाकार बनाती है, कलाकार तो एक निमित्त मात्र है। भट्ट जी ने कहा कि गुरु-शिष्य परंपरा का यह सशक्त उदाहरण है। शिष्यों को संगीत की शिक्षा देने के साथ ही संस्कार देना भी महत्त्वपूर्ण है, जिसका उदाहरण यहां देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सम्मानों-पुरस्कारों में औपचारिकता दिखती है लेकिन इस सम्मान में औपचारिकता कहीं खो गई है, अपनापन और कला के प्रति इज्जत दिखाई दिख रही है। उन्होंने कहा कि अपने गुरु पंडित राजन मिश्र के प्रति ऐसी सोच, ऐसी श्रद्धा और ऐसा आदर अभिभूत करने वाला है।

समारोह में ग्वालियर घराने के मूर्धन्य संगीत साधक पंडित केशवराव राजहंस कंपूवाले जन्मशताब्दी संगीत उत्सव के अंतर्गत राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के कुलगुरु एवं प्रमुख सितार वादक प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर तथा प्रमुख ध्रुपद गुरु पंडित अभिजीत सुखदाणे को श्रेष्ठ कला गुरु सम्मान प्रदान किया गया।

समारोह में संगीत प्रस्तुतियां भी हुईं। पंडित विश्वमोहन भट्ट ने पुत्र सलिल भट्ट के साथ स्वरचित राग 'विश्वरंजनी' सुनाया जो 'मधुवंती' और 'शिवरंजनी' जैसे मधुर रागों से मिलकर बना था। हालांकि वाद्य में इलेक्ट्रिक प्रयोगों के बीच कई बार प्रस्तुति की मधुरता प्रभावित होती हुई भी दिखी। बाद में पिता-पुत्र राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी बजाया। तबले पर हिमांशु महंत ने संगत की। समारोह में पंडित उमेश कंपूवाले ने अपने शिष्य-शिष्याओं के साथ सरस्वती वंदना एवं पंडित राजन-साजन मिश्र की गाई गुरु वंदना-'ऐसा ही गुरु भावे...' सुनाया जिसमें आरोह कंपूवाले, अक्षत मिश्र, हर्ष भाटिया, अनुनय शर्मा, रश्मि सासोड़े, निकिता जोशी, सत्यम पाठक, गौरी पंडित, सोनिया अग्रवाल, महेश राजपूत, प्रीति, कपिल शर्मा, प्रेम सिंह, चैती कंपूवाले, अनिल वर्मा, हमीर कंपूवाले और दीपिका गोयल ने भाग लिया। समारोह में पंडित राजन मिश्र के साथ कई संगीत समारोहों में संगत कर चुके वरिष्ठ हारमोनियम वादक एवं गायक पंडित धर्मनाथ मिश्र, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया सहित कई प्रमुख लोग शामिल थे। प्रभावपूर्ण संचालन अशोक आनंद का रहा। ■

कैनवस | जय त्रिपाठी

विकास का अचरज

सृजन के विभिन्न रूप कला के प्रत्येक माध्यमों में होते हैं। कलाकार के कुछ रचने से भी अधिक आवश्यक है, उनके द्वारा तत्वों का एक नया संयोजन प्रयोग में लाया जाना। दृश्य कलाकार प्रायः हो चुकी घटनाओं के साथ वर्तमान को लेकर जितना संवेदनशील होता है, उतना ही आने वाले समय को लेकर आशान्वित रहता है। कला भावनात्मकता के साथ कलाकार की आत्म-अभिव्यक्ति भी है। जरूरी नहीं कि यह किसी की निजी भावना हो। किसी राष्ट्र की संस्कृति या संपूर्ण मानवता की भावना भी उसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति की प्रेरणा हो सकती है। जो सिर्फ भावनाओं तक ही सीमित नहीं रह कर कलाकार के विचारों को भी व्यक्त करती है। परंतु कलात्मक सृजन का विशिष्ट अभिव्यक्तिवादी दृष्टिकोण भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक रचना में मनोरम दृश्य उत्पाद है, जो कला सौष्ठव के निर्वाह से बनता है। अतः कलाकार के भावनात्मक जीवन में कला अपने उसी रूप और अर्थ में जुड़ी होती है। नई दिल्ली के डी 49, डिफेंस कालोनी स्थित कला दीर्घा में 'इट मेक्स मी वंडर' शीर्षक से प्रदर्शित एकल चित्रों की प्रदर्शनी में चित्रकार कुमार विकास सक्सेना की कला कृतियों के चित्रण में इन्हीं वैचारिकी का दिग्दर्शन मिलता है।

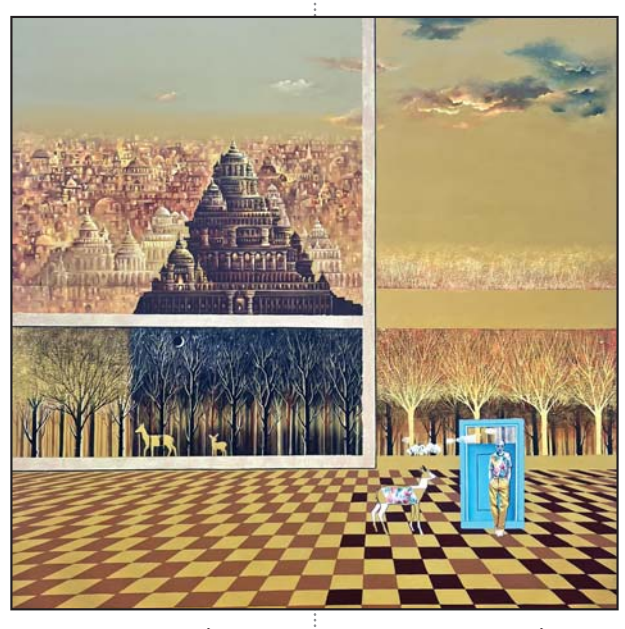

भारतीय संस्कृति के बहाने विकास समसामयिक विषय को अपनी कृति में तल्लीनता से गढ़ते हैं। फिर वे अन्य प्रेक्षकों के बीच ही इनको निहारने-परखने का आनंद लेते हैं। सृजन का एकांत संग-साथ में उत्सव बन कर खिलता है। विकास अपने कला-विषयों को जीवन के खुरदरे परिवेश से चुनते हैं। फिर अति-यथार्थवादी शैली में कैनवस पर एक्रलिक रंगों में रंगते हैं। उत्तराखंड के कुमांऊ विश्वविद्यालय से कला शिक्षा प्राप्त करने वाले कलाकार कुमार विकास का कला कौशल 'इट मेक्स मी वंडर' में स्पष्ट दिखाई देता है। यह शीर्षक के अनुरूप ही प्रेक्षकों को चकित करता है। आकर्षक कला कृतियों को रचते कुमार विकास कई तरह से प्रयोग करते हैं, जो उनकी तकनीकी क्षमता को दर्शाते हैं। समकालीन कलाकार के रचे गए चित्रों में मंदिरों-देवालयों के साथ-साथ मानव, पक्षी, जानवर, जंगल आदि उन प्रतीकों के रूप में प्रतिबिंबित हुए हैं, जो इस आधुनिक दुनिया को एक संदेश देते हैं। वे रचनात्मक दृष्टि से इस पर जितना विचार करते हैं, तकनीकी रूप से भी उतना ही समृद्ध दिखते हैं।

कुमार विकास की कृतियों में शहरीकरण की नाना परेशानियां एवं पहाड़ों के प्रति आमजन की पीड़ा दिखती है। हरे-भरे पेड़ों से घिरे अपने गांव के जीवंत परिदृश्य को बचपन से देखते आए कलाकार की यह पीड़ा, उनकी कला कृतियों में रंगों आदि से हुए प्रयोग में परिलक्षित होती है। शहर और गांव के बीच की संस्कृति का असंगत होना कलाकार को विचलित करता है। उन्होंने इसे बहुत सहजता तथा रचनात्मक परिपक्वता के साथ कला में रखा है। अतः कुमार विकास सक्सेना की प्रत्येक नई रचना, कलाकार की संवेदनशील उपस्थिति दर्ज कराने के साथ वैचारिक दृष्टि से भी बड़ी होती जाती है। जो विचारों और पद्धतियों से कृतियों को अधिक सशक्त और समृद्ध बनाती है। यह कलाकार अपनी सृजनात्मक शक्ति से रचना में कुछ नया करने का प्रयत्न भी करता है, जो उनके व्यक्तित्व की गतिमयता को दर्शाता है। वे सहजता से अपने इन नवीन चित्रों की श्रृंखला में मुख्यतः एक्रलिक रंगों में प्रयोग करते हैं। उनका मुख्य विषय हमारे आस-पास तेजी से बदलता परिदृश्य है।

कुमार विकास के चित्रों की एकल प्रदर्शनी न केवल सौंदर्य संबंधी आकांक्षाओं को कला रूप में सामने लाती हैं, बल्कि अपने परिवेश के प्रति उनकी सहज चिंता को दर्शाती हैं। प्रत्येक कृति एक क्षेत्र के सौंदर्य, संस्कृति, वनस्पति, वन्य जीवन, प्राकृतिक संरचना और अविश्वसनीय रूप से गायब हो रही लोक-संवेदनशीलता को प्रतिबिंबित करती है। इंपावरमैंट संस्था द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी को डी 49,डिफेंस कालोनी,नई दिल्ली में 2 मई तक देखा जा सकता है। ■

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

भारत-जर्मन संबंध

पिछले कुछ दशकों में भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक और सामरिक दोनों तरह के संबंधों में काफी मजबूती आई है। जर्मनी द्विपक्षीय एवं वैश्विक दोनों संदर्भों में भारत के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। 2014 में सत्ता सम्भालने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 के दौरान जर्मनी का दौरा किया था। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में 3 बार जर्मनी की यात्रा की थी। 2006 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। जर्मनी आतंकवाद की खिलाफत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और अन्य कई मुद्दों पर भारत के समान विचार रखता है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते जर्मनी से संबंधों में कुछ समय के लिए ठहराव आता रहा है। हथियारों के मामले में रूस पर निर्भरता कम करने के लिए भी जर्मनी भारत पर दबाव डालता रहा है लेकिन भारत अपने हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। भारत की विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र है। जर्मनी ने एक बार फिर भारत से रक्षा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीति में बदलाव किया है और उसने भारत को छोटे हथियारों और उनके स्पेयर पार्ट्स बेचने पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया है।

जर्मन सरकार ने एमपी-5 सब मशीनगन के लिए पुर्जे और सहायक उपकरण खरीदने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस यूरोपीय देश ने पहले छोटे हथियारों के साथ-साथ उनके पुर्जों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। जर्मनी ने इन प्रतिबंधों को भारत के अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा हथियारों के संभावित उपयोग और मानवाधिकार मुद्दों पर अपनी चिंताओं से जोड़ा था। 15 साल पहले एनएसजी ने जर्मन कम्पनी हैकलर एंड कोच द्वारा निर्मित एमपी-5 खरीदे थे। अब जर्मनी ने हथियारों की बिक्री के लिए भारत को अपवाद बताया है। यह जर्मन नीति में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अब तक गैर-नाटो देशों को छोटे हथियारों की बिक्री के बारे में सख्त नियम थे "नीति में बदलाव से भारतीय सशस्त्र बलों, साथ ही अर्धसैनिक बलों और पुलिस को जर्मन मूल की राइफलें, पिस्तौलें, उनके स्पेयर पार्ट्स और सहायक उपकरण खरीदने की अनुमति मिल जाएगी।" जर्मनी हथियारों की बिक्री और उन्नत सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन से लेकर इंडो-पैसिफिक में सैन्य अंतर-संचालनीयता तक के क्षेत्रों में भारत के साथ संबंध बढ़ाने का इच्छुक है, जहां चीन आक्रामक कदम उठा रहा है।

> भारत की विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र है। जर्मनी ने एक बार फिर भारत से रक्षा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीति में बदलाव किया है और उसने भारत को छोटे हथियारों और उनके स्पेयर पार्ट्स बेचने पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया है। जर्मन सरकार ने एमपी-5 सब मशीनगन के लिए पुर्जे और सहायक उपकरण खरीदने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस यूरोपीय देश ने पहले छोटे हथियारों के साथ-साथ उनके पुर्जों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ था।

जर्मनी अब नाटो के अलावा भी अपने डिफैंस रिलेशन मजबूत करना चाहता है। भारत और जर्मनी की सेनाएं इसी वर्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करने वाली हैं। जर्मनी के रुख में बदलाव दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे की चिंता के बाद हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग भी एक बड़ी वजह है। चीन के विस्तारवादी रवैये से यूरोपीय देशों की परेशानी और बढ़ गई है। हिन्द महासागर में वह अन्तर्राष्ट्रीय नियम तोड़ रहा है। भारत इस क्षेत्र में बड़ी ताकत है। भारत चाहता है कि प्रशांत में बेरोकटोक ट्रैवल के लिए जरूरी है कि समान विचारधारा वाले देश ताकतवर रहें।

हिंद महासागर में इस वक्त जर्मनी के 32 एयरक्राफ्ट तैनात हैं। इनमें से 8 यूरोफाइटर और 12 टॉर्नेडो जेट्स हैं। इसके अलावा एयरबस 300 भी यहां मौजूद है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए एयरबस 400 एम भी है। 15 फ्रेंच और स्पैनिश एयरक्राफ्ट भी हिंद महासागर में तैनात हैं। ये सभी अगस्त में होने वाले तरंग शक्ति (पहला चरण) अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इसके बाद भारत- जर्मनी की नेवी अक्तूबर में गोवा में एक्सरसाइज करेंगी।

इंडियन नेवी 6 एडवांस्ड स्टील्थ इलैक्ट्रिक सबमरीन हासिल करना चाहती है। करीब 42 हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजैक्ट में जर्मनी अपनी रुचि दिखा रहा है। इस वर्ष की शुरूआत में जर्मनी ने भारत को 6 अत्याधुनिक किलर पनडुब्बी खरीदने की पेशकश की थी। यह पनडुब्बियां एआईपी से लैस हैं। हिन्द महासागर में चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत लम्बे समय से यह डील करना चाहता है। अपनी पनडुब्बियां बेचने के लिए स्पेन की कम्पनी नेवंतिया ने भी भारत को पेशकश की थी। जर्मनी ने पनडुब्बियों के उपकरणों को लेकर अपने लाइसैंस नियमों में भी ढील दी है। भारत इस समय अमेरिका और फ्रांस से लगातार सहयोग के क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। भारत ऐसा जर्मनी के साथ भी कर सकता है। दोनों देश अन्तरिक्ष, कौशल विकास वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान, कृषि तकनीक और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। भारत अब वैश्विक शक्ति है और इसे कोई नजरंदाज नहीं कर सकता।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

प्रकृति से खिलवाड़...

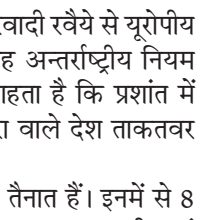

भगवान ने एक खूबसूरत जहान बनाया,
इंसान ने आते ही दुनिया में अपनी जरूरत का सामान बनाया,
अपनी सहूलियत के लिए दुपहिया, चार पहिया वाहन बनाया,
पर लालसाओं का दायरा इस हद तक बढ़ा, कि कर प्रकृति से
खिलवाड़ देश की राजधानी को कूड़ेदान बनाया...!!

-गीता पाढा

कर्नाटक में क्यों बम-बम है कांग्रेस

नई दिल्ली, (एनटीआई): कर्नाटक में जब से जेडीएस ने भाजपा से हाथ मिलाया है, वहां के मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो गए हैं। नहीं तो अब से पहले यहां मुसलमानों के वोट कांग्रेस और जेडीएस के बीच बंटते रहे थे। सूत्रों की मानें तो दानिश अली प्रकरण के बाद ही प्रदेश के मुसलमानों की नाराज़गी जेडीएस से बढ़ी है। दानिश अली जिन्हें जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा का बहुत करीबी माना जाता था उन्हें 2019 में बसपा का टिकट दिलवाने में देवेगौड़ा की महती भूमिका रही थी। देवेगौड़ा ने स्वयं मायावती से बात की थी। लेकिन जब संसद में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली पर उनकी कौम को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी की तो दानिश के बचाव में देवेगौड़ा का कोई भी बयान सामने नहीं आया। जिससे कर्नाटक के मुसलमान देवेगौड़ा से खासे कुपित हुए। जेडीएस के कोर वोट बैंक वोक्कालिग्गा पर भी कांग्रेस ने धावा बोल दिया है। राज्य के कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार देवेगौड़ा के ही सजातीय वोक्कालिग्गा हैं, डीके वोक्कालिग्गा समुदाय के लिए खासे मुखर रहते हैं। इस वजह से भी इन चुनावों में वोक्कालिग्गा वोटों में बंटवारा मुमकिन हो पाया है।

वरुण गांधी ने रायबरेली को क्यों कहा ना

मिर्च मसाला
त्रिदीब रमण
gossipguru.in

'आसमां के सबसे ऊंचे घर में रहता है तू,
और रब से तेरा चेहरा मिलता है हुबहु,
पर तू दुआएं किसी की कुबूल क्यों नहीं करता,
तू खुदा सा है मगर कभी खुदा हो नहीं सकता'

सूरज के सातवें घोड़े 'पंक्ति' पर सवार भाजपा के देदीप्यमान शीर्ष नेतृत्व को यूपी के सियासी गर्दो गुबार में बुझती आस्थाओं के नए मिथक ढूंढने पड़े। पार्टी हाईकमान ने डंके की चोट पर जिस वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से काट दिया था, राय बरेली से उन्हें मैदान में उतरने के लिए उनकी चिरौरी करनी पड़ी। भाजपा से जुड़े विश्वस्त सूत्र खुलासा करते हैं कि अपनी बीमारी के बाद घर में आराम फरमा रहे वरुण गांधी को पहला फोन भाजपाध्यक्ष जेपी नड्डा का आया। जिसमें इस युवा गांधी से कहा गया वे राय बरेली से भाजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस लें पर वरुण ने इस संदेशवाहक को टका सा जवाब देकर उन्हें निरूत्तर कर दिया। फिर वरुण के पास दो ओर बड़े नेताओं के फोन आये। पटकथा वही थी, संवाद भी वही पुराना था, पर फिर भी जब वरुण नहीं माने। सूत्रों की माने तो उन्हें समझाया गया कि 'मौजूदा परिस्थितियों से उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, वे अपने भविष्य की डोर भाजपा के हाथों में सौंप कर निश्चिंत हो जाएं।'

वरुण ने विनयपूर्वक अनुनय को ठुकराते हुए कहा-चूंकि रायबरेली से उनकी बड़ी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाली हैं सो वे अपनी बहन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि प्रियंका से उनके बेहद आत्मीय रिश्ते हैं। भाजपा को इस बात का कहीं पहले इल्म हो गया था कि गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर अपना दावा बरकरार रखने वाला है। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका वाड्रा चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं जिससे कि यूपी में एक चुनावी माहौल बनाया जा सके। अमेठी से पहले से ही स्मृति ईरानी का नाम तय था सो, रायबरेली के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश शुरू हो गई। रायबरेली में भाजपा नेतृत्व ने संभावित नामों को लेकर एक जमीनी सर्वेक्षण कराया ये 5 नाम थे वरुण गांधी, उमा भारती, विनय कटियार, ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे। पर इन तमाम सर्वेक्षणों में वरुण गांधी का नाम ही राय बरेली में सर्वमान्यता की कसौटी पर सबसे प्रमुखता से उभर कर सामने आया। सो, भाजपा ने तय किया कि वरुण को मनाने में ही समझदारी है।

क्यों रद्द हो गया मस्क का भारत दौरा

टेस्ला प्रमुख एलन मस्क की दो दिवसीय भारत यात्रा का सत्ता पक्ष को बेकरारी से इंतजार था। अपनी इस प्रस्तावित भारत यात्रा में मस्क पहले दिन यानी रविवार को पीएम मोदी से मिलने वाले थे और इसके अगले दिन नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में एक बड़े इवेंट का आयोजन था। इस कार्यक्रम में मस्क को 'स्पेस सेक्टर' से जुड़ी कंपनियों से मिलना था और भारत के लिए 20-30 बिलियन डॉलर के निवेश का रोड मैप भी प्रस्तुत करना था। कहते हैं मस्क की इस भारत यात्रा को टलवाने में उनके बायोग्राफर वाल्टर इसाकसन की एक महती भूमिका रही। इसाकसन एक मशहूर पत्रकार और बायोग्राफर हैं जो 'सीएनएन' और 'टाइम' मैगजीन जैसे शीर्ष मीडिया संस्थानों में बड़े ओहदों पर कार्यरत रह चुके हैं। उनकी मस्क से गहरी छनती है और गाहे-बगाहे विभिन्न मुद्दों पर वे मस्क को अपनी सलाह से भी नवाज़ते रहे हैं।

सूत्र बताते हैं कि इसाकसन ने मस्क से कहा कि भारत में इस वक्त चुनाव का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। सो इस वक्त उनका मोदी से मिलना ठीक नहीं होगा। कहते हैं मस्क ने आनन-फानन में इसके बाद अपनी भारत यात्रा कैंसिल कर दी। इसके बाद पीएमओ हरकत में आया। जब इनका मस्क से सीधा संपर्क नहीं हो पाया तो फिर पीएमओ ने मस्क के गुजराती दोस्त नीरव टोलिया से संपर्क साधा जो 'नेक्सट डोर' ऐप्प के संस्थापक और पूर्व सीईओ हैं। कहते हैं इसके बाद नीरव ने मस्क से बात की और उनसे आग्रह किया कि आप फोन पर ही सही कम से कम एक बार पीएम से बात तो कर लें। इस पहल के बाद ही मस्क का 'एक्स हेंडल' पर उनका पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने इस वक्त भारत न आने की अपनी वजह बताई।

महाराष्ट्र की चिंता में भाजपा

भाजपा इन दिनों महाराष्ट्र को लेकर गंभीर चिंता में है। पार्टी की चिंता महाराष्ट्र के भाजपा उम्मीदवारों को लेकर नहीं है अपितु भाजपा के गठबंधन साथियों खास कर एकनाथ शिंदे और अजित पवार के उम्मीदवारों को लेकर है। सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा के जमीनी सर्वेक्षण बताते हैं कि वहां मैदान में भाजपा उम्मीदवारों की स्थिति ठीक-ठाक है, लेकिन जहां गठबंधन धर्म के चलते अजित पवार या शिंदे की पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है उनमें से ज्यादातर उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों से पीछे चल रहे हैं। कई सर्वेक्षणों में तो यह भी दावा हुआ है कि इस दफे महाराष्ट्र में अजित पवार की पार्टी का खाता खुलना भी मुश्किल होगा।

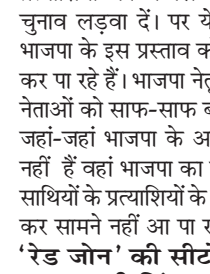

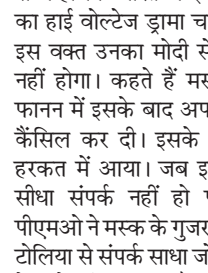

बहुचर्चित बारामती संसदीय सीट जहां से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में हैं, उन्हें शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सूले से कड़ी चुनौती मिल रही है और बारामती में एडवांटेज सुप्रिया बताया जा रहा है। इसके बाद ही भाजपा नेतृत्व ने अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों नेताओं से कहा कि वे अपने कुछ प्रत्याशियों को कमल के निशान पर चुनाव लड़वा दें। पर ये दोनों ही नेता भाजपा के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा नेतृत्व ने इन दोनों नेताओं को साफ-साफ बता दिया है कि जहां-जहां भाजपा के अपने उम्मीदवार नहीं हैं वहां भाजपा का कैडर गठबंधन साथियों के प्रत्याशियों के समर्थन में खुल कर सामने नहीं आ पा रहा है।

'रेड जोन' की सीटों को लेकर भाजपा की चिंता

'400 पार' का नारा भाजपा के गले की हड्डी बन गया है। संघ परिवार और भाजपा की असली चिंता यूपी को लेकर है। भाजपा ने अपनी जीत की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए पूरे यूपी को तीन जोन में बांटा है। पहला जोन 'यलो' यानी पीला है, इस जोन के अंतर्गत वैसी सीटें रखी गई हैं जहां भाजपा सहजता से जीत दर्ज करा रही है।

दूसरा जोन 'ग्रीन' यानी हरा है जहां भाजपा को प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों से कड़ी टक्कर मिल रही है। तीसरा जोन हैं 'रेड' यानी लाल। जहां भाजपा फिलहाल मुकाबले में किंचित पिछड़ती दिख रही है। 'रेड जोन' की कुछ प्रमुख सीटें हैं- मैनपुरी, मुरादाबाद, कन्नौज, बदायुं, मुज्जफरनगर, संभल, पीलीभीत, रामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी, मछलीशहर, कौशांबी और बाराबंकी।

...और अंत में

2024 लोकसभा चुनाव के पहले व दूसरे चरण की कम वोटिंग को लेकर भले ही भाजपा की संभावनाओं को कम करके आंका जा रहा हो लेकिन सच तो यह भी है कि 'इंडिया एलायंस' भी इसका बहुत बड़ा लाभार्थी नहीं दिख रहा अपेक्षाकृत मुस्लिम बहुल इलाकों में भी इस दफे वोटिंग का प्रतिशत कम रहा। यूपी की विरोधी पार्टियों का आरोप है कि हज़ारों की संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं, खास कर कैराना, मुजफ्फरगनर, रामपुर और मुरादाबाद जैसी संसदीय सीटों पर यह शिकायत बेहद आम रही।

विरासत टैक्स पर जोरदार सियासत

खरी-खरी बात
-वीरेन्द्र कपूर

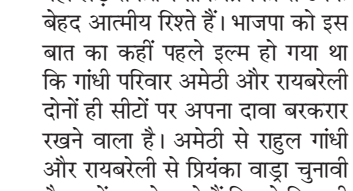

इस बार का लोकसभा चुनाव किस कदर नीरस और उबाऊ हो रहा था, इसका अंदाजा पहले दो चरणों के कम मतदान प्रतिशत से लगा। लेकिन जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुराने मित्र और उनके बेटे राहुल के गुरु सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया, चुनावी माहौल अचानक से जीवंत हो उठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे जोशो खरोश के साथ कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वह दूसरों को बांटने के लिए भारतीयों की संपत्ति और धन को जब्त करना चाहती है।

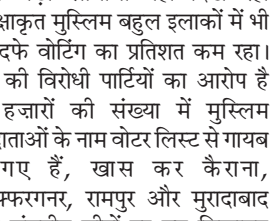

मोदी के हमले की तेजी से कांग्रेस पार्टी हैरान रह गई। उन्होंने पार्टी का मजाक उड़ाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस भारतीयों की जेब काटना चाहती थी 'जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी'। संदर्भ पित्रोदा द्वारा विरासत कर लागू करने के विचार का था, जिसके तहत किसी के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर कर लगाया जाता है।

आइए सुनते हैं खुद पित्रोदा से। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन ने कहा, धन एकत्रित करने में कुछ भी गलत नहीं है लेकिन किस हद तक? अमेरिका में विरासत कर लगता है... फर्ज कीजिए कि किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति है तो मरने के बाद वह अपने बच्चों को केवल 45 प्रतिशत ही हस्तांतरित कर सकता है, सरकार 55 प्रतिशत हड़प लेती है... सिद्धांत यह है कि जीवित रहते हुए आपने 100 मिलियन डॉलर कमाए तो उसकी आधी मरने के बाद जनता के लिए छोड़ना होगा। सब अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ सकते। यह जायज है। भारत में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पूरे 100 मिलियन डॉलर उसके बच्चों को मिलते हैं। जनता को कुछ नहीं मिलता। ये ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर भारतीयों को बहस और चर्चा करनी होगी। निस्संदेह, कांग्रेस के घोषणापत्र में 'नीतियों में उपयुक्त बदलावों के माध्यम से धन और आय की बढ़ती असमानता' को रोकने के लिए कदम उठाने का संकेत दिया गया था, जो विरासत कर के डर को उचित ठहरा सकता है। पित्रोदा और राहुल दोनों ने इस तथ्य की सराहना नहीं की कि भारत में विरासत या संपत्ति कर था, जिसे 1985 में राजीव गांधी सरकार ने ही समाप्त किया था।

> कांग्रेस के घोषणापत्र में 'नीतियों में उपयुक्त बदलावों के माध्यम से धन और आय की बढ़ती असमानता' को रोकने के लिए कदम उठाने का संकेत दिया गया था, जो विरासत कर के डर को उचित ठहरा सकता है। पित्रोदा और राहुल दोनों ने इस तथ्य की सराहना नहीं की कि भारत में विरासत या संपत्ति कर था, जिसे 1985 में राजीव गांधी सरकार ने ही समाप्त किया था।

मोदी ने विरासत कर के उन्मूलन के समय की अटकलों का जिक्र किया कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि राजीव गांधी खुद इंदिरा गांधी से विरासत में मिली जमीन और अन्य संपत्तियों पर भारी शुल्क का भुगतान करने से बच सकें। जब संपत्ति कर और विरासत कर सहित उच्च कराधान या तो सरकार के राजस्व को बढ़ाने या आय असमानताओं को दूर करने में विफल रहा और जब लाइसेंस-कोटा-परमिट राज गरीबी दूर करने में विफल रहा तभी हमें यू-टर्न लेने और बाजार सुधार लाने के लिए बाध्य होना पड़ा। तात्कालिक कारण विदेशी मुद्रा संकट था जिसने भारत को बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास आरक्षित सोना गिरवी रखने के लिए मजबूर किया।

आर्थिक उदारीकरण ने देश को तेज विकास के रास्ते पर ला दिया, हर साल गरीबी से बाहर निकलने वाले गरीबों की संख्या बढ़ रही थी क्योंकि अर्थव्यवस्था सालाना 7-8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। इस बीच, अगर राहुल मानते हैं कि विरासत कर लेने और संपत्ति के पुनर्वितरण से वह गरीबों के वोट जीत सकते हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। गरीब भोले-भाले नहीं होते। वे 'गरीबी हटाओ' और 'समाजवाद' के वादे से निराश हैं, उनके पिता और दादाओं ने आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में इन नारों में अपना विश्वास केवल इसलिए रखा था ताकि उनका मोहभंग हो सके। समाजवाद के उत्कर्ष काल में अमीर और अमीर हो गये तथा गरीब और अधिक गरीब हो गये।

2024 में, गरीब भी एक खुली बाजार अर्थव्यवस्था में अच्छे जीवन की आकांक्षा रखते हैं जो उन सभी को समान अवसर प्रदान करता है जो इसका फायदा उठा सकते हैं। उदारीकृत अर्थव्यवस्था के तहत, उनकी बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, आवास, पीने का पानी, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों की शिक्षा आदि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से पूरी हो रही हैं। समाजवाद ने उन कल्याणकारी उपहारों का एक चौथाई भी पेश नहीं किया जो एक खुली बाजार अर्थव्यवस्था ने सरकारों को करने में सक्षम बनाया है।

सर गंगा राम जैसे अस्पतालों की जरूरत

श्रीमती किरण चोपड़ा
डायरेक्टर- पंजाब केसरी द हिन्द समाचार लि.
चेयरपर्सन- वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब
मुख्य संरक्षिका- चौपाल
सदस्य- राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल, एकल
संरक्षिका- भारतीय लोक विकास परिषद
ब्रांड एंबेसडर- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
f/kiranchopra01
kiranchopra@punjabkesari.com
kiranchopradesk@gmail.com

इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन एक कठिन डगर है लेकिन मेरा मानना है कि जिंदगी जीने के लिए एप्रोच मजबूत होनी चाहिए। जीवन है तो कठिनाईयां हैं और चुनौतियां भी हैं। ऐसे में हमें खुद को ऊर्जावान और शक्तिशाली बनाये रखना होता है। इन्हीं के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होता है। इसके लिए हमें प्रेरणा की जरूरत होती है। मैं कभी भी अपने पंजाब केसरी के पाठकों से दूर नहीं रहती और दूर रहना भी नहीं चाहूंगी। क्योंकि हमारे लाखों पाठक मेरी प्रेरणा हैं और मुझे ऊर्जावान बनाए रखने की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरी लेखनी को यही पाठक गति प्रदान करते हैं। पिछले दिनों मुझे लगभग 5 सप्ताह तक पाठकों से दूर रहना पड़ा और पाठकों के लिए मैं अपना नियमित कॉलम भी नहीं लिख पाई। क्योंकि इस मौसम में मुझे मार्च के महीने में कोविड हो गया जो आजकल बहुत कम सुनाई देता है। उसके बाद खराब गले के साथ वायरल से इतनी तबियत खराब हुई कि पूछो मत। इसके बाद मुझे जीवन माला अस्पताल में इलाज करवाना पड़ा, जहां डा. विनय सब्बरवाल, डा. माला का बहुत ही सहयोग मिला। अच्छी बात है कि सारा परिवार ही निपुण डाक्टरों का है। सबसे बड़ी बात डा. ग्लोसी ने बीमारी का कारण डायग्नोज किया। जन्म से लेकर अब तक मैं ऐसे बीमार कभी नहीं हुई, जितना इन दो महीनों में। फिर छोटी सी सर्जरी जिससे कई डाक्टरों से वास्ता पड़ा और विशेषकर गंगा राम हास्पिटल जिसे प्रसिद्ध डा. डी.एस. राणा जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, की मैनेजमेंट सिस्टम ने इसे बैस्ट हास्पिटल बना दिया है। फिर इसके प्रधान डा. अजय स्वरूप, डा. सुधीर कल्हन, डा. साहनी, डा. मेहता सबके नाम में नहीं लिख सकती, क्योंकि हर फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। यहां तक कि एनेथिसिया देने वाली टीम की हैड श्रीमती सूद। आधी बीमारी तो इन डाक्टरों के अनुभव और व्यवहार देखकर ही दूर हो जाती है। सभी अपने फील्ड में माहिर हैं। खासकर डा. सुधीर कल्हन जो देश में बैस्ट डाक्टर माने जाते हैं। जिससे भी पूछा बड़ा-छोटा या कोई वीआईपी से तो सबने उनकी तारीफों के पुल बांधे और सर्जरी के बाद प्रमाणित भी हो गया कि वैसा डाक्टर सच में कोई नहीं।

जिस दुनिया ने चार साल पहले से शुरू हुए कोरोना का दंश झेला हो, लोगों ने अस्पतालों में उपचार काराया हो, लाखों लोगों ने अपनों को गंवा दिया और सब कुछ अस्पतालों में और छोटी-मोटी डिस्पेंसरियों में हुआ लेकिन उपचार जारी है। आदर्श उपचार अगर अस्पतालों में मिल जाये तो जीवन सुरक्षित है। भारत की हैल्थ सर्विसेज दुनिया के बेहतरीन हैल्थ सिस्टम में से एक है। यद्यपि सरकारी हैल्थ सिस्टम भी बेहतरीन है जिसके दम पर लाखों-करोड़ों लोग बीमारी से निजात पाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। गंगाराम अस्पताल के बारे में मेरा मानना है कि यहां के डाक्टर, यहां की चिकित्सा व्यवस्था, यहां की सिस्टर अर्थात नर्सेस और अन्य कर्मचारी, रिशेप्शन से लेकर डाक्टरों के बीच एक सेतु की तरह काम करने वाली टीम सब एक से बढ़कर एक है। ये सब लोग आपको एक विश्वास दिलाते हैं कि आप सर गंगाराम अस्पताल में आ गए हैं तो आप सुरिक्षत हैं। अस्पताल की दुनिया एक अलग ही दुनिया है। कई लोग अपने-अपने दर्द का जिक्र करते हैं और सब के सब यहां की व्यवस्था तथा हैल्थ सुविधाओं के चलते ठीक होकर ही आते हैं। भारत के और दुनिया के अस्पतालों में सरगंगाराम अस्पताल की हैल्थ सफलता लगभग शत-प्रतिशत है। इस दृष्टिकोण से मैं व्यक्तिगत रूप से अस्पताल अधिकारियों, डाक्टरों और सभी कर्मचारियों का दिल की गहराईयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। सरगंगाराम अस्पताल के स्टाफ की ऐसी अप्रोच सचमुच पूरी दुनिया के हैल्थ सिस्टम के लिए मैं समझती हूं कि एक बड़ा उदाहरण है। यहां तक कि किसी भी ऑपरेशन के बाद जो डाइटीशियन टीम है वह भी मरीज के पास खुद जाकर उसकी पसंद का खाना पूछते हैं और फिर डाक्टर को इस बात की जानकारी दी जाती है कि उनके भोजन की डाक्टरों द्वारा दी जा रही दवाई से अनुकूलता होनी चाहिए।

सभी जानकारियों के मुताबिक मुझे पता चला है कि सरगंगाराम अस्पताल में जितने भी ऑपरेशन थियेटर हैं वे सब अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों से परिपूर्ण हैं। डाक्टरों के पास मरीजों की लंबी लाइने हैं लेकिन मरीजों के परिजनों को अच्छे ढंग से सांत्वना दी जाती है तब उसके बाद जहां तक संभव हो उनको बेड और रूम दिलाकर व्यवस्था की जाती है। जहां मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो वहां व्यवस्था कई बार जवाब दे जाती है लेकिन सरगंगाराम अस्पताल का कुशल संचालन मरीजों और उनके परिजनों को एक बड़ी राहत देता है।

आज के जमाने में दुनिया जितनी एडवांस हो रही है सिस्टम उतने ही बदल रहे हैं। पूरे देश और दुनिया में लेटेस्ट टैक्नीक आ गयी है। हालांकि ट्रीटमेंट महंगे हैं लेकिन जिंदगी की जंग में सब कुछ करना ही पड़ता है। यद्यपि जीवन में बहुत मुश्किलों को झेला है, पर फिर भी लेखक होने के नाते पाठकों से अपनेपन का रिश्ता, कार्य के प्रति समर्पण बना ही रहता है इसीलिए अपने शुभचिंतकों को बताना चाहती हूं कि जितने भारत के डाक्टर और इलाज बैस्ट है वो विदेशों में भी नहीं। मुझे अश्विनी जी के साथ 6 महीने विदेशों और विदेश के डाक्टरों का अनुभव भी है। अभी कि उस समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का बहुत साथ था। सारी इंडिया एम्बैसी साथ थी। वहां के डाक्टर और सिस्टम से प्रभावित थी परन्तु जो इंडियन डाक्टरों में है वो बात कहीं और नहीं।

भारत में भी बहुत उच्च कोटि के अस्पताल हैं परन्तु जो बात सर गंगा राम अस्पताल में है वो कहीं और नहीं। एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे किसी भी इमरजैंसी का सामना करना पड़े। आगे ईश्वर की इच्छा। सबसे बड़ी बात है कि आम जरूरतमंद लोगों के लिए ओपीडी है, जो सुबह से लाइन लग जाती है। बहुत कम रुपयों में सब को हर फील्ड के स्पेशल डाक्टर देखते हैं। वाक्य सर गंगा राम अस्पताल पूरी सुविधाओं से भरपूर आम और खास लोगों के लिए परफैक्ट है। 30 साल पहले मैंने अपने जुड़वा बेटों को इसी अस्पताल में जन्म दिया था, तब भी अच्छा था। अब तो इसका कोई जवाब नहीं।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

बिहारी राजनीति की पहेली

बिहार के लोग यकीनन सियासी तौर पर संवेदनशील हैं, मगर जातियों को लेकर उनके आग्रह, दुराग्रह की हद छूते नजर आते हैं। ऐसे में, 2014 और 2019 की भांति एनडीए अपना जादू बरकरार रख पाएगा या फिर से मुखर हो चले जातीय समीकरण कोई नया गुल खिलाएंगे?...हर बिहारी के मानस में इस वक्त यही सवाल गूंज रहा है।

स्कैन करें
आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

आजकल

शशि शेखर

ये पंक्तियां बिहार से, क्योंकि हिन्दुस्तान की सियासी बारीकियां समझनी हैं, तो यहां आना ही होगा। बिहार के राजनीतिक थियेटर में इतना उतार-चढ़ाव है कि पता नहीं चलता, कब कौन किरदार कहां से प्रकट हो, कब नेपथ्य में चला जाएगा।

यहां के नेता वायदों और दावों के मामले में उत्साही और सामाजिक परिवर्तन के अगुवा मालूम पड़ते हैं, लेकिन वक्त आने पर वे सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। कमाल यह कि इससे उनके 'वोटबैंक' पर कोई खास असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि महागठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार को वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनाने में संकोच नहीं किया था। इस पुनर्जन्म पाए गठबंधन ने 2020 का चुनाव साथ लड़ा और जीता, लेकिन नीतीश कुमार 24 महीने में ही एक बार फिर लालू यादव के साथ चले गए।

यह 'स्वाभाविक साझीदारी' से मुक्त होकर 'पुराने परिवार' में वापसी जैसा कोई करतब था।

सब जानते थे कि इस वापसी की भी वापसी होनी है। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ 'घुटन' महसूस कर चुके नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले फिर भाजपा के साथ सरकार बनाने को राजी हो गए। इन दिनों वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का हिस्सा हैं और कहते हैं- 'अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे।' उनके पुराने गठबंधन के साझीदार, यानी राष्ट्रीय जनता दल के लोग जवाब में वीडियो जारी करते हैं, जिसमें दूसरे गठबंधन के लिए भी वह लगभग ऐसा ही कहते दिखाए जाते हैं।

भाजपा और राजद भी नीतीश कुमार के साथ सुर बदलते रहे हैं। वे जब उनके साथ होते हैं, तो उनकी सी बोलते हैं और जब 'पाला बदल' आकार ले लेता है, तो उनके बयान पुनः पुरानी खाल ओढ़ लेते हैं। बिहार इस मामले में अकेला ऐसा राज्य है, जहां पिछले दस सालों में मुख्यमंत्री ने चार बार अपने साझीदारों की अदला-बदली की। सवाल उठता है कि भाजपा और राजद पुराने अनुभवों से सबक लिए बिना उनसे जब-तब हाथ क्यों मिला लेते हैं? जवाब आसान है। बिहार के लगभग 7.64 करोड़ वोटरों में आठ से दस फीसदी ऐसे लोग हैं, जो उनका साथ हर हाल में पसंद करते हैं।

ऐसा क्यों है? उत्तर के लिए पीछे लौटना होगा।

सन् 2005 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई क्रांतिकारी काम किए थे। जिस बिहार में महिलाएं शाम को घर से बाहर निकलने में झिझकती थीं, वहां उन्होंने शहर से गांव तक की लड़कियों को सरकार की ओर से साइकिलें मुहैया कराई थीं। इससे पढ़ाई-लिखाई के लिए लड़कियों ने बाहर निकलना शुरू किया, जिससे समाज के निचले तबके में बदलाव की शुरुआत हुई। पिछले दो दशकों में ऐसी हजारों बालिकाएं आगे आईं, जिन्होंने पढ़-लिखकर नौकरियां हासिल कीं या अपना रोजगार स्थापित किया। जो इन सबसे वंचित रहीं, वे भी साक्षरता की पूंजी लेकर ससुराल गईं। बताने की जरूरत नहीं कि हमारे देश की लड़कियां एक नहीं, दो घरों को संवारती हैं।

यही नहीं, वर्ष 2016 में शराबबंदी के जरिये उन्होंने गांव की गरीब महिलाओं का दिल हमेशा के लिए जीत लिया। हालांकि, इस प्रयोग की आलोचना भी होती है। इसके बाद यहां जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। इससे मदिरा की तस्करी को भी बढ़ावा मिला और सरकार को राजस्व की भयंकर हानि हुई। यह कानून इतनी कठोरता से बनाया गया था कि लोग उसे 'दानवी' बताने लगे। विरोध पनपता देखकर इसकी धाराओं में कुछ ढील दी गई, पर अभी भी वे कछुए के कवच की भांति कठोर हैं।

घर-घर बिजली और हर घर नल-जल जैसी योजनाएं मूलतः नीतीश कुमार के दिमाग की उपज थीं। बिहार की कानून-व्यवस्था और सड़कों के सुधार में भी उनका अनूठा योगदान रहा है। उनके विपक्षी दावा करते हैं कि पिछली बार के पाला बदल ने उनकी छवि को सांघातिक चोट पहुंचाई है। उनके कुछ बयानों पर पिछले दिनों जमकर बवंडर भी हुआ। मौजूदा चुनाव उनके प्रति मतदाता के रुख-रवैये का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने जा रहा है।

यहां तेजस्वी यादव का उल्लेख करना जरूरी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वह महागठबंधन के अगुवा थे। उनके भगीरथ प्रयासों से बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरा था। यह बात अलग है कि पिछले दिनों उनके पांच विधायकों ने पाला बदल लिया। न जाने क्यों, राजद ने इसकी कोई आधिकारिक शिकायत विधानसभा अध्यक्ष के यहां दर्ज नहीं कराई और वे सत्ता पक्ष के साथ बैठने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी 85 विधायकों के साथ सदन में सर्वाधिक संख्या रखती है।

बताने की जरूरत नहीं कि भाजपा सोच-समझकर सियासी दांव खेलती है। उसे मालूम है कि कब किसको दोस्त बनाना है और किसको मंझधार में छोड़ देना है। पासवान परिवार इसका जीवंत उदाहरण है। 2020 के चुनाव से ऐन पहले रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्र चिराग पासवान और अनुज पशुपति कुमार पारस में विरासत की लड़ाई थी। पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया गया और वह छह में से पांच सांसदों को तोड़कर सत्ता-सुख के भागीदार हुए थे। नतीजतन, खुद को 'मोदी का हनुमान' बताने वाले चिराग निस्संग रह गए थे। मौजूदा चुनावों से पहले भगवा दल ने एक बार फिर उन्हें वरीयता दी और अब पारस अकेले हैं। कमाल यह कि इसके बावजूद न चिराग ने कभी एनडीए से नाता तोड़ा था, न पारस ऐसा कर रहे हैं।

एनडीए से भीतर-बाहर होने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। वह समय के साथ पाला बदलते रहे हैं, जिसका उन्हें भरपूर लाभ मिला है। कभी नीतीश कुमार के अनुयायी रह चुके मांझी अब एनडीए के साथ हैं। वह गया से उम्मीदवार भी हैं। देखना होगा कि मतदाता उनके बार-बार पाला बदल को कैसे लेते हैं? इस बार उन्हें साथ लेने वाले एनडीए का उनकी जाति के मतों से कितना फायदा होता है?

भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी समझदारी से प्रदेश के जातिगत समीकरणों को साधा है। इसके बावजूद उसके सारे उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे वैतरणी पार होने का मनसूबा बांधे हुए हैं। मोदी यहां भी सर्वाधिक आकर्षक नेता हैं, पर एनडीए को इंडिया ब्लॉक से कड़ी चुनौती मिल रही है। पहले चरण में जिन चार सीटों पर मतदान हुआ, वहां हिंदी पट्टी के अन्य प्रदेशों की भांति मत प्रतिशत लगभग पांच फीसदी कम रहा। इसने एनडीए को और सजग कर दिया है।

बिहार के लोग यकीनन सियासी तौर पर संवेदनशील हैं, मगर जातियों को लेकर उनके आग्रह, दुराग्रह की हद छूते नजर आते हैं। ऐसे में, 2014 और 2019 की भांति एनडीए अपना जादू बरकरार रख पाएगा या फिर से मुखर हो चले जातीय समीकरण कोई नया गुल खिलाएंगे? ऊपर से देखने पर चाणक्य और चंद्रगुप्त की इस धरती पर उदासीन सन्नाटा पसरा दिखता है, मगर हर बिहारी के मानस में इस वक्त यही सवाल गूंज रहा है।

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

जीना इसी का नाम है

प्रदीप सेठी
चिकित्सक

दुख अगर सबको मांजता है, तो इस डॉक्टर सा मांजे

जीवन में एक मोड़ ऐसा भी आया, जब सारी कोशिशों के बावजूद चीजें मुश्किल होने लगीं और बात उनकी झोंपड़ी से निकलकर गांव के चबूतरे पर आ गई। तब गांव के कुछ समर्थ लोगों ने बड़प्पन दिखाया और वजीफे के तौर पर उन्होंने प्रदीप की मदद करनी शुरू कर दी।

आजादी के साढ़े सात दशक में हिन्दुस्तान ने कितनी तरक्की की है, इसे देखना है, तो गांवों में जाइए और किसी स्मृति-समृद्ध बुजुर्ग के पास बैठिए, तब आपको सन् 1947 से 2024 तक का देश का सफर साफ-साफ दिखाई पड़ेगा। हिन्दुस्तान महानगरों और शहरों में ही नहीं, अपने साढ़े छह लाख से अधिक गांवों में भी खूब आबाद हुआ है। मगर इन गांवों की एक टीस पुरानी है। महानगरों और बड़े शहरों ने उनकी अनगिनत संतानों को अपने मोहपाश में यूं फांसा कि वे अपनी माटी का कर्ज उतारना भी भूल गईं। मगर प्रदीप सेठी ने जिस तरह से अपनी माटी का कर्ज अदा किया है, उनका गांव पुश्त-दर-पुश्त इसके लिए उन पर नाज करेगा!

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गांव है बेरुनपदी। करीब 44 साल पहले इसी गांव के एक बेहद गरीब परिवार में प्रदीप पैदा हुए थे। तब ओडिशा देश के अति-पिछड़े राज्यों में शामिल था। जाहिर है, बेरुनपदी भी सड़क-बिजली-अस्पताल-साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर था। प्रदीप के परिवार की माली हालत ऐसी थी कि कई बार उन्हें फाकाकशी से गुजरना पड़ा। एक जोड़े कपड़े में कई-कई हफ्ते निकालने पड़ते। मगर यह नियति अकेले उन्हीं के परिवार की नहीं थी। ऐसे में, सभी अभावग्रस्त परिवार एक-दूसरे को सब्र और उम्मीद की डोर थमाते रहते। राहत की बात बस इतनी थी कि 1955 से गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल की सुविधा थी और प्रदीप के पिता ने घनघोर गरीबी के बावजूद बेटे को कभी पढ़ने-लिखने से नहीं रोका। अलबत्ता, उन्हें कई बार स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती, क्योंकि मजदूर पिता कभी गाय चराने, तो कभी खेतों से घास छील लाने की जिम्मेदारी सौंप जाते थे। इन सब व्यवधानों के बावजूद प्रदीप की पढ़ने में रुचि गहराती गई थी।

करीब बारह साल की उम्र में वह जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने गए, वह अंग्रेजी-हिंदी माध्यम का स्कूल था। इससे पहले तो वह सिर्फ उड़िया सुनते-बोलते आए थे। पहली बार यहां उनका हिंदी और अंग्रेजी से परिचय हुआ। शुरू-शुरू में वह कुछ हिचके, थोड़े झेंपे; लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की चाह ने उनका रास्ता आसान कर दिया। बहुत जल्द ही शिक्षकों की नजरों में प्रदीप की मेधा आ गई। उन्होंने उन्हें भरपूर प्रोत्साहन दिया। फिर क्या था, छात्र की लगन और शिक्षकों के सहयोग ने एक गरीब बच्चे के दिन बदल दिए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदीप बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए।

दसवीं के बाद से ही उनके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा पलने लगी थी, मगर मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके परिवार के लिए आसान न था। प्रदीप ने अपनी पढ़ाई-लिखाई से पिता को गौरव के कई पल दिए थे। इसलिए जो भी थोड़ी सी जमीन उनके पास थी, बेटे की मेडिकल फीस जुटाने के लिए उन्होंने उसे दांव पर लगा दिया। परिवार के इस त्याग से प्रदीप मर्माहत तो थे, पर अपने भविष्य को लेकर वह आशान्वित भी कम न थे। वह परिवार की तकलीफ और संघर्ष में बराबर शरीक रहे। उनके पास जो भी खाली वक्त होता, वह उसमें किसी न किसी किस्म की दैनिक मजदूरी करते।

एक ऐसा मोड़ भी आया, जब सारी कोशिशों के बावजूद चीजें मुश्किल होने लगीं और बात उनकी झोंपड़ी से निकलकर गांव के चबूतरे पर आ गई। तब गांव के कुछ समर्थ लोगों ने बड़प्पन दिखाया और वजीफे के तौर पर उन्होंने प्रदीप की लगातार मदद की। प्रदीप को हर महीने एक तय राशि मिलने लगी थी, जिससे वह अपनी किताबें खरीदते और हॉस्टल मेस की फीस चुकाते। अब लक्ष्य सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री थी। वह जी-जान से जुट गए। साल 2004 में एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद उन्हें मास्टर्स कोर्स के लिए देश के प्रतिष्ठित 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' में दाखिला मिल गया, जहां से उन्होंने 'हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी' के गुर सीखे। जाहिर है, यह ऐसा चिकित्सा क्षेत्र है, जो अकादमिक शोध या अपने सौंदर्य को लेकर सजग दौलतमंदों से ज्यादा जुड़ा है। लिहाजा, प्रदीप के पास प्रस्तावों और मरीजों की कोई कमी नहीं रही। पैसे तो खैर आने ही थे। उनके पास दुबई में क्लिनिक खोलने तक का बेहद रोचक प्रस्ताव आया, मगर उसी समय उन्हें आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद जी की यह पंक्ति याद आ गई- 'हर मनुष्य के जीवन का एक बड़ा मकसद होता है।'

नौजवान प्रदीप के जीवन का मकसद सिर्फ दौलत कमाना नहीं था। वह अपनी जड़ों की ओर मुड़े। कैंसरग्रस्त पिता की दिली तमन्ना थी कि गांव में उनका एक घर होना चाहिए। प्रदीप ने घर की तामीर कराई, मगर उसके बनने के चंद महीनों बाद ही वह इस दुनिया से कूच कर गए। उनके जाने के बाद प्रदीप ने साल 2016 में उस घर को एक कोचिंग सेंटर में तब्दील कर दिया, ताकि गांव व आस-पास के बच्चे वहां आकर गणित और अंग्रेजी सीख सकें। इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षित शिक्षक रखे गए थे।

सैकड़ों बच्चों की जिंदगी में इस एक कोचिंग सेंटर से आई तब्दीली देख डॉ प्रदीप को गहरा सुकून मिला। अब उन्होंने गांव में एक ऐसा स्कूल खोलने का फैसला किया, जो गरीब बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा निःशुल्क दे सके। उन्होंने गांव की उसी जमीन पर स्कूल बनाने की शुरुआत की, जहां कभी दैनिक मजदूरी की थी। गांव वालों ने अपने सपूत का बढ़-चढ़कर साथ दिया। कई लोगों ने स्कूल के लिए अपनी-अपनी जमीनें दान में दीं। करीब दस एकड़ में पिछले साल अप्रैल में उत्कल गौरव इंटरनेशनल स्कूल वजूद में आ गया। फिलहाल इसमें 450 बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर इसकी क्षमता 2,500 बच्चों को 12वीं तक उच्च-स्तरीय शिक्षा देने की है।

डॉ प्रदीप ने गांव की उसी जमीन पर स्कूल बनाने की शुरुआत की, जहां कभी दिहाड़ी मजदूरी की थी। गांव वालों ने अपने सपूत का बढ़-चढ़कर साथ दिया। करीब दस एकड़ में पिछले साल उत्कल गौरव इंटरनेशनल स्कूल वजूद में आ गया। फिलहाल इसमें 450 बच्चे पढ़ रहे हैं।

डॉ प्रदीप सेठी आगे अन्य इलाकों में भी स्कूल खोलेंगे, मगर बेरुनपदी का कर्ज उन्होंने अदा कर दिया!

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा

मृणालिनी साराभाई
प्रसिद्ध नर्तकी

यह बच्ची बड़ी होकर जरूर कुछ बनेगी

पिता अपने कर्म से कोई मिसाल कायम करें, तो बेटियां उस मिसाल को मशाल मानकर आगे बढ़ती हैं। पिता वही हैं, जो बेटियों के पंख और परवाज को विस्तार दें। ऐसी बेटियां खुशनसीब होती हैं, जिन्हें पिता द्वारा दिखाए गए आकाश में शानदार उड़ान का मौका मिलता है।

बेटियों के लिए पिता इस संसार सागर में प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं। किसी भी दिशा में चली जाएं बेटियां, पिता को बार-बार खोजती-निहारती रहती हैं कि न जाने कब पिता अपनी आंखों से कोई बात बोल दें, उनके मुखड़े पर कोई उम्मीद तैरने लगे, चुपचाप। बहुत थोड़ा बोलेंगे पिता और बहुत कुछ मन में रख लेंगे। बेटियों के लिए न जाने क्या-क्या अच्छा सोचते रहेंगे पिता और बेटियां भी कोशिश में लगी रहेंगी कि पिता को पूरा जान लें। पिता अगर अपने कर्म से कोई मिसाल कायम करें, तो बेटियां भी उस मिसाल को मशाल मानकर आगे बढ़ती हैं। वस्तुतः पिता वही हैं, जो अपनी बेटियों के पंख और परवाज को विस्तार दें और ऐसी बेटियां भी खुशनसीब होती हैं, जिन्हें पिता द्वारा दिखाए गए आकाश में शानदार उड़ान का मौका मिलता है।

वह बेटी भी बड़ी खुशनसीब थी। बैरिस्टर पिता सुब्बाराम स्वामीनाथन अपनी बेटी के अस्तित्व की धुरी थे। उनकी मुस्कराहट, स्नेह से सराबोर चमकती आंखें। पिता ने एक दिन गर्व से कहा कि 'यह बच्ची बड़ी होकर कुछ बनेगी' और यह बात गहरे असर कर गई। पिता किसी से डरते नहीं थे, बेटी पर भी असर पड़ा। पिता कभी हिम्मत नहीं हारते थे, तो बेटी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिता ने बार-बार कहा, तो बेटी भी बार-बार दोहराने लगी कि मुझे नर्तकी बनना है। जब दूसरे ज्यादातर बच्चे खिलौनों और चॉकलेट के बारे में सोचते थे, तब वह नर्तकी बनने के बारे में सोचती रहती थी। उसने सबको बता दिया, मैं नर्तकी बनूंगी। नृत्य ही मेरी सांस है, मेरा जुनून है।

पिता तभी कुछ अनमने-से लगते थे, जब वह बेटी वाद्य यंत्र पियानो के अभ्यास से मुंह चुराती थी। बेटी को वह वाद्य यंत्र पसंद नहीं था। वह ठहरी चंचल, किसी एक जगह स्थिर बैठना मुश्किल था। उसे गति और गतिशीलता से गहरा प्रेम था। पिता के सान्निध्य में बेटी साहसी और नवाचारी भी खूब हुई। एक बार मंच पर लकड़ी का घोड़ा दौड़ाना था, बेटी ने ऐसी तेजी से दौड़ाया कि घोड़ा टूट गया, पर वह न रुकी। घोड़ा जब टूटा, तो दूसरे लोग यह मान रहे थे कि नाटिका बिगड़ गई, पर उस बेटी ने नाटिका को रुकने नहीं दिया, सामान्य गति में नाटिका को आगे बढ़ा दिया, अपना किरदार ठीक से निभा दिया।

पिता ने कुछ कर गुजरने का जुनून ऐसा पैदा कर दिया था कि वह बेटी जब पढ़ाई करने स्विटजरलैंड गई, तो वहां भी विदेशी नृत्य सीखती रही। वह थोड़े समय के लिए अमेरिका में 'अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स' में भी पढ़ी, पर दिल हिन्दुस्तान खींच लाया। बहुत मुश्किल था फैसला, सब अलग-अलग तरह के नर्तक थे। सब अपनी-अपनी कला में माहिर, पर शांति निकेतन में उस बेटी ने देखा कि कोई छात्र एक साथ कई तरह की कलाएं सीख रहा है। एक साथ अनेक प्रकार के नृत्य सीखना भी मुमकिन है। उस छात्रा की दृढ़ता देख प्रसन्न गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर भी दिशा देने में नहीं चूके। गुरुदेव ने भी इस एहसास को मजबूत किया कि मृणालिनी, तुम्हें नृत्य करने से कोई रोक नहीं सकता। गुरुदेव ने उन्हें अपने नाटक *चांडालिका* में मुख्य भूमिका दी और उनसे अपने हिस्से की कोरियोग्राफी स्वयं करने को कहा; मृणालिनी ने पहली बार टैगोर के नृत्य नाटकों में भरतनाट्यम की शुरुआत की, जिससे उन्हें पहली बार बहुत सराहना मिली। वह सराहना से बहुत खुश हुईं, उन्हें ऐसा लगा, मानो उनकी आत्मा को किसी ने नृत्य के संसार में पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया, अब वह जिधर चाहें, उड़ सकती हैं।

सीखने की तमन्ना इस कदर प्रबल हुई कि किसी महान गुरु ने भरतनाट्यम सिखाया, तो किसी ने कथकली में पारंगत किया, तो किसी ने मोहिनीअट्टम में सिद्ध बना दिया। गुरु उन्हें सिखाकर धन्य-धन्य हो जाते थे। वह अगर उन्नीस भी सीखती थीं, तो उसे इक्कीस बनाकर पेश कर देती थीं।

देश की आजादी के बाद साल 1949 में उन्होंने अहमदाबाद में अपना नृत्य विद्यालय खोल लिया। नृत्य ने ही उन्हें सब कुछ दिया। नृत्य ने ही जीवनसाथी महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई तक पहुंचाया। वह मृणालिनी स्वामीनाथन से मृणालिनी साराभाई हो गईं। विक्रम साराभाई जब आजाद भारत में आधुनिक विज्ञान की नींव रख रहे थे, तब मृणालिनी साराभाई भारतीय नृत्य संस्कृति की नींव गढ़ रही थीं। नृत्य में उनकी सृजनशीलता और नवाचार को पूरी दुनिया में पहचान मिली। दुनिया हर वर्ष 29 अप्रैल को नृत्य दिवस मनाती है और तब मृणालिनी साराभाई (1918-2016) को भी जरूर याद किया जाता है।

अपने पापा की इस बेहद कामयाब प्रिय परी को 97 साल लंबा जीवन मिला और वह अपने पिता को अक्सर याद करती थीं, 'पिता ही मेरी पूरी जिंदगी थे।'

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

साक्षात्कार एक आइडिया

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

कविता, कहानी, उपन्यास व साहित्य क्या है?

साहित्य एक आइडिया है।

साहित्य का हेतु क्या है? वह किसके लिए है, उसका उद्देश्य क्या है?

हेतु-वेतु, उद्देश्य-फुद्देश्य सब आइडिया है।

अच्छा, कविता क्या है? शुक्ल जी ने इस शीर्षक से एक लंबा निबंध ही लिख डाला है, जिसको सब मानते हैं।

शुक्ल जी खुद ही एक आइडिया हैं। उनके विचार भी आइडिया हैं।

अरे सर जी! हिंदी के सबसे बड़े आलोचक को आप आइडिया कह रहे हैं, कैसे साहित्यकार हैं आप? शर्म नहीं आती आपको?

साथी! शर्म भी तो एक आइडिया ही है। वह आती है, और चली जाती है।

हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वमान्य है?

शुक्ल जी का यह इतिहास एक 'ब्राह्मनिकल नैरेटिव' है। एक युवा आलोचक ने बताया भी है कि उनकी आलोचना ब्राह्मणवादी है।

आप जातिवादी हो रहे हैं?

अरे भाई, जाति भी एक आइडिया ही है और जाति-गणना भी तो होने वाली है।

लेकिन शुक्ल जी को 'ब्राह्मणवादी' बताने वाला भी तो एक विशेष जाति का है, तो क्या उसे जाति का वादी न कहेंगे?

जातिवादी होना भी एक आइडिया है।

कल कोई कहे कि शुक्ल जी हिंदूवादी थे तो?

तो क्या? धर्म भी एक आइडिया है, इसलिए हिंदू भी आइडिया है।

तब हिंदू-मुसलमान क्यों होता रहता है?

क्योंकि ये दोनों ही 'आइडियाज' हैं और यह 'आइडियाज' के क्लेश और क्लैश का युग है। क्लेश भी एक आइडिया है और क्लैश भी एक आइडिया है।

साहित्य तो राजनीति के आगे जलने वाली मशाल है। साहित्यकार आत्मा का शिल्पी है। कवि प्रजापति है। अपनी सृष्टि का सृजनकर्ता है। ये सब बातें क्या गलत हैं?

गलत या सही होना भी एक आइडिया है। तुम भी एक आइडिया हो, मैं भी एक आइडिया हूं और यह बातचीत भी एक आइडिया है।

और यह दुनिया, यह समाज?

यह सकल चराचर एक आइडिया है।

तब हमारी यह बातचीत, यह साक्षात्कार, यह रिकॉर्डिंग, इसका यू-ट्यूब पर जाना, लोगों का देखना, पसंद करना, यह सब क्या है?

यह सब भी एक आइडिया है, एक विचार है।

और यह जो आदमी का दुख-दर्द है, भूख-प्यास है, गरीबी-अमीरी है, शोषण-उत्पीड़न है, युद्ध-बमबारी है, दंगा-हिंसा है, खून-खराबा है, ये बातें भी क्या महज आइडिया हैं?

हे तात! ज्ञानगुरु बेनेडिक्ट एंडरसन की कृपा है, जिन्होंने सबसे पहले समझाया कि 'नेशन' और कुछ नहीं, सिर्फ एक आइडिया है और एंडरसन का यह आइडिया इतना हिट हुआ कि सब कहने लगे कि राष्ट्र भी एक आइडिया है।

फिर अपने एक नेताजी के समर्थकों ने कह दिया कि उनके नेताजी भी एक आइडिया हैं, तो मैंने सोचा, अगर साहित्य में इस आइडियाबाजी को ठेल दूं, तो कैसा रहे? साहित्य का साहित्य भी रहे और उसका तत्व भी निकल जाए। साहित्य का सारा बोझ उतर जाए। वह एकदम हल्का-सहज हो जाए। इसलिए हे तात! यह बात समझ कि एंडरसन खुद एक पोस्ट मॉडर्न ज्ञानी हैं। उनकी भाषा उत्तर-आधुनिक भाषा की लीला है। यही तो अपनी 'पोस्ट मॉडर्निटी' का जादू है कि सब कुछ एक आइडिया है।

यहां दर्द भी एक आइडिया है और दवा भी आइडिया है, यानी सब कुछ माया है। इसलिए 'हेट' भी एक आइडिया है और 'लव' भी एक आइडिया है। गाली भी आइडिया है, ताली भी आइडिया है। इन दिनों आइडिया से आइडिया भिड़ रहा है। इसलिए बेटे! ज्यादा चूं-चपड़ न कर। तू भी अपना आइडिया बन जा और फ्रायडिया बन जा, क्योंकि आइडिया रूपी आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता!

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

संकल्प का धनी व्यक्ति ही समृद्धि का पात्र बनता है

मिलावटी उत्पाद

इस पर आश्चर्य नहीं कि हांगकांग और सिंगापुर में भारत की दो कंपनियों के मसालों में कथित तौर पर कैंसरकारक तत्व मिलने और उन पर पाबंदी लगाए जाने के बाद अमेरिका भी इन कंपनियों के मसालों की जांच में जुट गया है। आने वाले दिनों में ऐसी ही खबरें अन्य देशों से भी आ सकती हैं। अंदेशा इसका भी है कि मसालों के साथ भारतीय कंपनियों के अन्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। जैसे-जैसे भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी यह कहना कठिन है कि हांगकांग और सिंगापुर की ओर से एमडीएच एवं एवरेस्ट के मसालों को लेकर जो शिकायत की गई, वह कितनी सही है, लेकिन अच्छा यह होगा कि वे सभी भारतीय कंपनियां चेत जाएं, जो अपने उत्पाद निर्यात करती हैं। उनकी गुणवत्ता की गहन परख होने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा अथवा ईर्ष्यावश भी उन्हें कठघरे में खड़ा किया जा सकता है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि हांगकांग और सिंगापुर की ओर से कदम उठाए जाने के बाद भारतीय मसाला बोर्ड के साथ भारत सरकार भी सक्रिय हुई, क्योंकि यह तो पहले ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि जो मसाले निर्यात हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता सही है या नहीं?

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि एफएसएसएआइ यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकारण अपना काम सही तरह नहीं कर पा रहा है। यह हाल में तब इंगित हुआ था, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले के उत्पाद सेरेलेक के बारे में यह सामने आया था कि उसमें चीनी की मात्रा कहीं अधिक है। क्या यह विचित्र नहीं कि एफएसएसएआइ की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि पूरे देश में मसालों की गुणवत्ता की जांच होगी? आखिर यह काम पहले क्यों नहीं हुआ? उचित यह होगा कि यह जांच मसालों तक ही सीमित न रहे, क्योंकि देश में बिकने वाले न जाने कितने खाद्य एवं पेय पदार्थ ऐसे हैं, जिनकी गुणवत्ता को लेकर संदेह होता रहता है और शिकायतें भी आती रहती हैं। खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता से जानबूझकर समझौता करने के साथ उनमें अखाद्य एवं हानिकारक सामग्री की मिलावट बहुत आम है। इसका बड़ा कारण उनकी गुणवत्ता की जांच सही तरीके से न होना है। यह समस्या दवाओं के मामले में भी है। दवाओं के सैंपल केवल जांच में फेल ही नहीं होते रहते, बल्कि सरकारी अस्पतालों तक में दोयम दर्जे की और कभी-कभी तो नकली दवाएं खपाने के समाचार आते रहते हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले भारत से निर्यात होने वाली खांसी की दवाओं में विषाक्त पदार्थ की मिलावट के मामले सामने आए थे। ऐसे मामले भारत की साख को कमजोर करने के साथ ही देश के फार्मा उद्योग को भी क्षति पहुंचाते हैं।

बिजली की मार

उत्तराखंड में बिजली की दरों में हुई लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि से करीब 27 लाख उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक विद्युत टैरिफ पर मुहर लगा दी है। बिजली की नई दरें बीती एक अप्रैल से लागू होंगी। हालांकि, आयोग ने विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को पुनर्निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा है कि सभी श्रेणियों में क्रास सब्सिडी को कम किया जा सके। खासकर बीपीएल श्रेणी के 4.5 लाख उपभोक्ताओं और स्नो बाउंड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत मूल्य एवं स्थिर प्रभार में कोई वृद्धि नहीं की गई है। लेकिन आम उपभोक्ता को बढ़ी हुई दरों की मार झेलनी पड़ेगी। वैसे नई टैरिफ के अनुसार यदि उपभोक्ता सौ यूनिट तक ही बिजली खर्च करता है तो उसे 25 पैसे के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान करना होगा। जबकि 200 यूनिट तक यह खर्च 30 पैसे और 200 यूनिट से ऊपर 40 पैसे प्रति यूनिट वसूला जाएगा। ऊर्जा निगम का तर्क है कि बाहर से महंगी बिजली खरीद, ट्रांसमिशन लाइनों का खर्चा, हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली खरीदने, सब स्टेशनों की मेंटेनेंस आदि कारणों से उसे विद्युत दरों में वृद्धि करनी पड़ी। लेकिन व्यवहार में इस वृद्धि के लिए भी ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली ही ज्यादा जिम्मेदार है। निगम चाहता तो अपनी रीति-नीति में सुधार लाकर उपभोक्ताओं को राहत दे सकता था। यह किसी से छिपा नहीं है कि प्रदेश में किस तरह बिजली का दुरुपयोग हो रहा है। लाइन लास, बिजली चोरी जैसे कारणों की अनदेखी के पीछे आखिर क्या वजह है। क्यों नहीं बिजली की चोरी रोकने को सख्ती बरती जाती। ऊंची पहुंच वाले ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं, जिनकी ओर निगम का लाखों रुपये बकाया है। इनसे वसूली को निगम ने क्या कदम उठाए। इस ओर भी ध्यान दिया जाता तो उपभोक्ता को महंगी बिजली की मार से काफी हद तक बचाया जा सकता था।

वामपंथी विचारों में जकड़ी कांग्रेस

संजय गुप्त

कांग्रेस पिछले दस वर्षों से जिस एजेंडे पर चल रही है, वह उद्यमशीलता के साथ-साथ कारोबारियों यानी धन का सृजन करने वालों के विरोध में ही अधिक है

अवधेश राजपूत

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने यह कहकर खासी हलचल मचा दी कि यदि अमेरिका में किसी धनी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके बच्चों को उसकी संपत्ति का 45 प्रतिशत हिस्सा ही हस्तांतरित होता है। शेष संपत्ति सरकार के पास चली जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमें इस पर बहस करनी चाहिए। एक तरह से वह भारत में विरासत टैक्स की पैरवी करते दिखे। जब उनकी इस बात पर हंगामा खड़ा हो गया तो खुद उन्होंने सफाई दी और असहज कांग्रेस ने उनके बयान को उनका निजी विचार करार दिया। चूंकि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार भी माने जाते हैं, इसलिए इस मुद्दे पर अभी तक बहस जारी है और कांग्रेस सफाई दे रही है। सैम पित्रोदा ने विवाद पैदा करने वाले बयान से वामपंथी सोच को ही उजागर किया। उनका बयान आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर कांग्रेस पर हमला बोला कि उसका वही करने का इरादा है, जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं। उन्होंने उनके इस बयान को कांग्रेस के घोषणा पत्र से भी जोड़ दिया, क्योंकि उसमें कहा गया है कि सभी की संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा। वैसे कांग्रेस का घोषणा पत्र यह तो नहीं कहता कि संपत्ति का सर्वे कराकर उसका पुनर्वितरण किया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी अपने एक भाषण में इसकी ओर संकेत कर चुके हैं। इसी कारण गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि कांग्रेस ऐसा इरादा नहीं रखती तो अपने घोषणा पत्र में संपत्ति का सर्वे कराने वाली बात हटाए। अब राहुल संपत्ति के पुनर्वितरण से इन्कार कर रहे हैं, लेकिन सैम पित्रोदा के बयान पर कुछ नहीं कह रहे हैं।

विरासत टैक्स वह कर है, जो अमेरिका के छह प्रांतों में लागू है। इसके अलावा कुछ और देशों में भी प्रभावी है। एक समय संपत्ति शुल्क नाम से विरासत टैक्स भारत में भी था, लेकिन 1985 में राजीव गांधी सरकार ने उसे यह कहकर खत्म कर दिया था कि जिस उद्देश्य से उसे लाया गया था, वह पूरा नहीं हुआ। वास्तव में इससे राजस्व की प्राप्ति तो बहुत कम हो रही थी, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोगों का उत्पीड़न हो रहा था। संपत्ति शुल्क संग्रह की हिस्सेदारी मामूली थी। चूंकि इस टैक्स के आकलन की प्रक्रिया जटिल थी और उसमें मुकदमेबाजी भी होती थी, इसलिए उसकी वसूली सरकार को खासी महंगी पड़ती थी। विरासत टैक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने नया मोर्चा खोलते हुए राजीव गांधी को भी लपेट लिया और यह आरोप लगाया कि उन्होंने इंदिरा गांधी की संपत्ति पाने के लिए इस टैक्स को खत्म किया था। प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में यह भी कह रहे हैं कि लोगों की जमीन-जायदाद और यहां तक कि महिलाओं के स्त्रीधन एवं उनके मंगलसूत्र पर भी कांग्रेस की नजर है। वह उन्हें छीनकर अपने पसंदीदा वोट बैंक को देने का इरादा रखती है।

कांग्रेस की सरकारों ने आजादी के बाद धन का सृजन करने वालों पर जो कर लगाए, वे एक समय लगभग 90 प्रतिशत हो गए थे। इसके पीछे पूंजीवाद को बुरा समझने वाला चिंतन था। कांग्रेस में यह चिंतन नेहरू जी के समाजवादी सोच से आया। लगता है कांग्रेस में आज भी यह सोच है कि वेल्थ क्रिएटर्स पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने चाहिए और सरकार को ही सब कुछ करना चाहिए। यह सोच कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी झलकती है। यह सोच देश को पिछली सदी के आठवें-नौवें दशक में ले जाने वाली है, जब विकास दर महज ढाई-तीन प्रतिशत हुआ करती थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब कांग्रेस पर गांधी परिवार का वर्चस्व नहीं था, तभी उसने प्रधानमंत्री नरसिंह राव के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों की नींव रखी, पर कांग्रेस ने उन्हें भुला दिया। कांग्रेस पिछले दस वर्षों से जिस एजेंडे पर चल रही है, वह उद्यमशीलता के साथ-साथ कारोबारियों यानी धन का सृजन करने वालों के विरोध में ही अधिक है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाते ही रहते हैं कि वह केवल अदाणी-अंबानी और अपने कुछ अन्य मित्र कारोबारियों के लिए ही काम कर रहे हैं। कांग्रेस खेती-किसानी का कायाकल्प करने के लिए लाए गए तीन कृषि कानूनों का भी मुखर विरोध कर चुकी है। हालांकि तमाम कृषि विशेषज्ञ इन कानूनों को सही बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों के साथ पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी यूपी के किसान संगठनों के विरोध के चलते मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े। भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ भी यह माहौल बनाया गया था कि सरकार किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। इसी कारण उसे भी वापस लेना पड़ा था। ध्यान रहे कि भूमि अधिग्रहण में विलंब के चलते कई परियोजनाएं अटकती रहती हैं।

राहुल गांधी सरकारी नौकरियों पर खूब जोर दे रहे हैं, जबकि उन पर सरकारों का व्यय पहले से ही काफी अधिक है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया है। हालांकि भारत जैसे बड़े देश में इतनी नौकरियां भी नाकाफी हैं, लेकिन इस वादे के जरिये कांग्रेस यही संदेश देना चाहती है कि वह सरकारी नौकरियों पर जोर देगी। आज आवश्यकता इसकी अधिक है कि निजी क्षेत्र और खासकर मैन्यूफैक्चरिंग एवं सर्विस सेक्टर के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऐसी नीतियां बनाई जाएं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें। राहुल गांधी यह दावा कर रहे हैं कि उनकी और मोदी की गारंटी में फर्क है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले आम चुनाव में जनता ने उनकी गारंटी पर भरोसा नहीं किया था। कांग्रेस के चुनावी वादों और खासकर सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का वामपंथी सोच फिर से उजागर हुआ है। कांग्रेस यह भूल रही है कि आज विश्व में वामपंथी सोच की जगह नहीं है। राहुल गांधी एक अर्से से उद्योगपतियों को खलनायक बनाने पर तुले हैं। वह इससे अनजान बने हैं कि देश आज जो उन्नति कर रहा है, उसमें कारोबारियों की भी एक बड़ी भूमिका है। आवश्यकता तो उन्हें प्रतियोगी, खुला वातावरण देने और उनके लिए ऐसा माहौल बनाने की है, जिसका लाभ उठाकर वे विश्वपटल पर अपनी धाक जमाने के लिए प्रेरित हो सकें। जब ऐसा होगा, तभी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आम जनता को लाभ मिलेगा।

response@jagran.com

अपने बलबूते चुनाव लड़ने की तैयारी

हास्य-व्यंग्य

आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव में मैं भी एक टिकटार्थी था, लेकिन चुनाव समिति ने दूसरे आवेदक को चुनाव चिह्न आवंटित कर उसे प्रत्याशी बना दिया। इस तरह मुझ जैसे एक सर्वगुण संपन्न, समर्पित और निष्ठावान उम्मीदवार की 'उम्मीदों' पर 'वार' हुआ है। चुनाव क्षेत्र में मेरी प्रतिष्ठा की मारक मिसाइलें पार्टी की परमाणु क्षमता के आगे पटाखों जैसी फुस्स हो चुकी हैं। आप भी जानते ही हैं कि न आप इजरायल हैं और न ही मैं ईरान हूं। फिर भी वर्तमान परिस्थितियां हमें वैसी समरभूमि की ओर ही धकेल रही हैं। आखिरकार चुनाव भी तो युद्ध जैसा ही होता है। इसीलिए हम इसे लोकतंत्र का संग्राम कहते हैं।

मान्यवर, न आप चुनाव लड़ रहे हैं और न ही आपने मुझे लड़ने दिया। खैर, आपकी तो जमानत भी नहीं बचती। मैं अपनी तो बचा ही सकता था! आपने मेरा टिकट काटा। अब आपका आने वाला वक्त चैन से नहीं कटेगा। मुझे भी कमतर मत आंकिएगा। मुझे तो पहले दिन से ही आप पर संदेह था। फिर भी, मैंने आपके आश्वासन पर विश्वास किया, मगर आपने मेरी जगह अपने खासमखास को टिकट पकड़ा दिया। सर्वविदित है कि वह आपका चमचा है। उसे तो चमचा कहना भी इस सात्विक शब्द का घनघोर अपमान है! वह तो पिट्ठू है, एक नंबर का पिछलग्गू। चमचों का भी एक स्टैंडर्ड होता है। उनको यह तो पता होता है कि कहां पर कमर झुकानी है और कहां घुटने टेकने हैं। आपके इस फैसले से लोकतंत्र का सिर शर्म से झुक गया। शीश मेरा भी झुका हुआ है, लेकिन वह चुनाव के समय अपने क्षेत्र की जनता के प्रति मेरा कृत्रिम और अवसरजन्य विनम्र झुकाव है।

सूर्यकुमार पांडेय

जिसने मेरा टिकट काटा, उसका आने वाला वक्त चैन से नहीं कटेगा, क्योंकि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा

श्रीमन, मैं अभी तक यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिरकार मेरा टिकट कटा तो क्यों कटा? क्या मेरी दावेदारी इतनी नरम थी! मेरी दावेदारी खरबूज और उनकी पत्थर! जो आप लोगों के काटे न कटी। इस बार पार्टी ने एक पत्थर को पूजा है। देखिएगा, मैं भी ईंट से ईंट बजा दूंगा। मेरी तो छवि भी खराब नहीं। छवि तो उसकी खराब होती है, जिसकी हो। मैं आपके ही आश्वासन पर आपकी पार्टी में शामिल हुआ था। घर में आए मेहमान के साथ ऐसी बदसुलूकी भारतीय परंपरा के खिलाफ है। होना यह चाहिए था कि घर वाले बाद में खाते, पहले मेहमानों के आगे छकने के लिए थालियां परोस दी जातीं। यहां उलटा किया गया। जिस दल को अपनी पंरपरा से प्यार न हो, मैं उसे ठुकराता हूं।

महोदय, मुझ जैसे सुयोग्य, समर्थ और दमदार इंसान को टिकट न मिलने से इस देश की राजनीति कलुषित हुई है। पार्टी का विधान कलंकित हुआ है और मेरी निजी निष्ठाओं को आघात पहुंचा है, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य की कोख में है। इस घोषित सूची से मुझे और मेरे क्षेत्र की जनता को गहरा सदमा लगा है। वैसे मैं दूसरे दल से भी खड़ा हो सकता था। इसकी मुझे आदत भी है, लेकिन इस बार मामला जरा टेढ़ा फंस गया है। सीबीआइ ने विवश कर रखा है और ईडी ने पाई-पाई का 'नीडी' कर दिया है। आप तो सियासत के उस्ताद हैं। आपके सामने ज्ञान बघारना राजनीति के पंडित को चुनावी वर्णमाला का ककहरा पढ़ाने के समान होगा। फिर भी मैं आज खुद को विवश पा रहा हूं। अपने से बड़ों की इज्जत तो कभी भी की जा सकती है। चुनाव के समय अपने से छोटे की इज्जत करना ही धर्म है, अन्यथा खुद की इज्जत भी उतर सकती है। मनुष्य का लचीलापन ही उसे अवसर प्रदान करता है। जो उस अवसर का लाभ उठा लेता है, वह सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ता, सीधा लिफ्ट से टाप फ्लोर पर पहुंच जाता है। अपने यहां विनम्रता को सद्गुण कहा गया है। मैं भी कठोर नहीं हूं। मैं अबकी अपने बूते पर खड़ा हो रहा हूं। फिर जब आपको सरकार बनाने में पूर्ण बहुमत के लिए एक सदस्य की कमी पड़ेगी, मैं ही सबसे पहले याद आऊंगा। यह और बात है कि आज जिसे आप दस रुपये का तुड़ा-मुड़ा नोट समझ रहे हैं, तब उसकी वैल्यू करोड़ों में होगी।

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

तथ्य-कथ्य

पिछले लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों की महिला प्रत्याशियों का प्रदर्शन

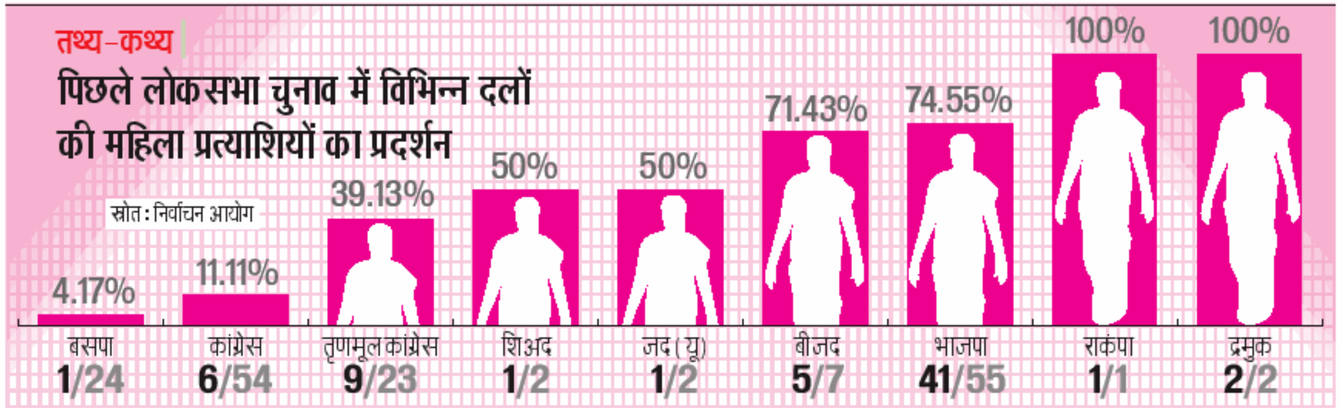

स्रोत : निर्वाचन आयोग

ऊर्जा

अहंकार

अहंकार एक ऐसा नकारात्मक भाव है जो बड़े से बड़े गुणवान व्यक्ति को भी पतन की राह पर मोड़ देता है। अहंकार भी नाना प्रकार का होता है। किसी को ज्ञान का अहंकार होता है, जो वास्तव में अज्ञान ही होता है। किसी को बल या अपनी शक्ति का अहंकार होता है। हालांकि वर्तमान में धन-संपदा और भौतिकता के प्रदर्शन का अहंकार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। विशेषकर अचानक से धनी बने लोगों का व्यवहार उनके दंभ को उजागर कर देता है। जब व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है तो वह यही सोचने लगता है कि उसके पास सब कुछ है। वह दूसरों को अपने से हीन समझने लगता है। अगर उस व्यक्ति ने अनैतिक कार्यों से धन अर्जन किया हो तो उसके अहंकारी होने की आशंका और प्रबल हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश निश्चित होता है। महर्षि दयानंद ने यथार्थ ही कहा कि अहंकारी मनुष्य का पतन निश्चित है और जिसमें अहंकार भर जाता है वह दूसरों के बारे में शायद ही कोई अच्छी बात कहे। अगर कोई धन के प्रति अहंकार करता है तो उसके बुरे दिनों में कोई भी उसकी सहायता करने से संकोच करता है।

अहंकार का एक और रूप होता है, जिसे यूनानी भाषा में ह्रिब्रिस कहते हैं। यूनानी विद्वान विलियम बार्कले के अनुसार ह्रिब्रिस से आशय ऐसे अहंकार से है, जिसमें क्रूरता भरी हुई हो। यह अहंकार का ऐसा स्वरूप है, जिसमें लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उनकी भावनाओं का दमन करते हैं। ऐसे सोच के लोगों में क्रूरता आ ही जाती है। स्मरण रहे कि धन या बल से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु सम्मान और चरित्र नहीं। महात्मा गांधी ने भी इस संबंध में कहा है कि 'ऐसा मानिए कि जो हम करते हैं, वह दूसरे भी कर सकते हैं। यदि हम ऐसा न मानें तो अहंकारी ठहराए जाएंगे।' इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा है, जहां शूरवीरों को भी अहंकार का मूल्य चुकना पड़ा।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

जलवायु परिवर्तन से खरबों की क्षति

मुकुल व्यास

जलवायु परिवर्तन के कारण विज्ञानियों ने वैश्विक आर्थिकी को भारी नुकसान होने की आशंका व्यक्त की है

भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भले ही हम आज से कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन में भारी कटौती कर दें, तब भी जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक वैश्विक आर्थिकी को आय में 19 प्रतिशत की कटौती झेलनी पड़ेगी। आय में यह क्षति ग्लोबल वार्मिंग को दो डिग्री तक सीमित करने के लिए आवश्यक खर्च से छह गुना अधिक होगी। जर्मनी के पाट्सडैम इंस्टीट्यूट फार क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च (पीआइके) के विज्ञानियों ने भविष्य में आर्थिक विकास पर बदलती जलवायु परिस्थितियों के प्रभावों का आकलन किया है। पीआइके के एक विज्ञानी का कहना है कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप सहित अधिकांश क्षेत्रों में आय में कटौती का अनुमान लगाया गया है। इनमें दक्षिण एशिया और अफ्रीका सबसे अधिक प्रभावित होंगे। कृषि उपज, श्रम उत्पादकता और बुनियादी पर इसका अधिक दुष्प्रभाव परिलक्षित हो सकता है।

कुल मिलाकर, वैश्विक वार्षिक क्षति 380 खरब डालर होने का अनुमान है। वर्ष 2050 में यह 190-590 खरब डालर के बीच हो सकती है। यह क्षति मुख्य रूप से बढ़ते तापमान के साथ-साथ वर्षा और तापमान की परिवर्तनशीलता में बदलाव के कारण भी होगी। तूफान या जंगल की आग की घटनाओं जैसी मौसम की अन्य चरम स्थितियों के मद्देनजर क्षति के आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं।

अर्थव्यवस्था में यह नुकसान पिछले उत्सर्जन का परिणाम है। यदि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचना चाहते हैं तो हमें अधिक प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता होगी। हमें उत्सर्जन में भारी कटौती करनी होगी। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो आर्थिक नुकसान सदी के उत्तरार्ध में और भी बड़ा हो जाएगा, जो 2100 तक वैश्विक औसत पर 60 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पिछले 40 वर्षों में दुनिया भर में 1,600 से अधिक क्षेत्रों में आर्थिक विकास पर जलवायु प्रभावों के नवीनतम निष्कर्षों को शामिल किया और अगले 26 वर्षों पर ध्यान केंद्रित किया। विज्ञानियों ने अपने माडल को अत्याधुनिक जलवायु अनुकरण माडल (सीएमआइपी-6) के साथ जोड़ा। उन्होंने यह भी आकलन किया कि अतीत में जलवायु प्रभावों ने अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित किया है। हर जगह नुकसान हो रहा है, लेकिन उष्णकटिबंधीय देशों को सबसे अधिक नुकसान होगा, क्योंकि वे पहले से ही गर्म हैं। इसलिए भविष्य में तापमान में वृद्धि सबसे अधिक हानिकारक होगी। विडंबना यह भी है कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार देशों को ज्यादा नुकसान होगा। इन देशों के पास इसके प्रभावों के अनुकूल ढलने के लिए सबसे कम संसाधन हैं।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

चुनावी उत्सुकता

शुरुआती दो चरण के मतदान के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के अपने-अपने दावे हैं। दोनों खेमे अपनी बढ़त तो दूसरे के कमजोर पिच पर होने के दावे कर रहे हैं। दोनों चरणों में वोटिंग प्रतिशत में आई गिरावट ने भी विश्लेषकों के लिए मतदाताओं के मिजाज की गहराई भांपने की सिरदर्दी बढ़ा दी है। वहीं, देश की नौकरशाही से जुड़े कुछ लोग चुनाव की जमीनी नब्ज टटोलने में अचानक रुचि लेने लगे हैं। नौकरशाही में जगी इस दिलचस्पी को वैसे तो सतर्कता के दायरे में ही रखा गया है, मगर ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए सियासी रूप से कुछ जागरूक लोग राज्यों के चुनावी दौरे कर रहे अपने जानकार पत्रकारों-राजनीतिक विश्लेषकों से अनौपचारिक चर्चा के बहाने थाह लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे।

निगाहें नई कैबिनेट पर

अभी लगभग सभी केंद्रीय मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। अधिकतर मंत्री स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं या फिर पार्टी की तरफ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद मंत्रालय से उनका वास्ता छूट गया है। वैसे भी, इन मंत्रियों को पता है कि चुनाव के बाद उन्हें पुराना मंत्रालय मिलता है या मंत्रिमंडल से ही उनकी छुट्टी हो जाएगी, इसका वह आकलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मंत्रालय का मोह छोड़ दिया है।

इस बीच, एक ऐसे भी मंत्री हैं, जो चुनावी पारा चढ़ने के इस मौसम में भी मंत्रालय में बैठ रहे हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं। देर रात तक वह मंत्रालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और नई सरकार के गठन के बाद होने वाले फैसले की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास तीन-तीन मंत्रालयों का भार है और हाल ही में उन्हें फिर से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया है। तभी उनके विभाग के अधिकारी दबी जुबान में यह कहने से नहीं हिचकते कि मंत्री जी यहां बैठकर अगली कैबिनेट में आने का चुनाव लड़ रहे हैं।

राजरंग

गेहूं और वोट

लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत में कमी के बीच सत्तापक्ष के सियासी खेमे में चर्चा है कि हेमा मालिनी को 'पारिश्रमिक' देने में वोटरों ने इस बार कंजूसी कर दी। चिलचिलाती धूप में कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनकर खेतों में गेहूं की फसल काटना भी काम नहीं आया। इसी अंदाज में पिछले चुनाव में भी उन्होंने गेहूं की फसल काटी थी। तब उन्हें अच्छी 'मजदूरी' यानी राजनीतिक आशीर्वाद मिला था। 60.48 प्रतिशत वोटर बूथों तक पहुंचे थे। जो आए उनमें से भी करीब 60 प्रतिशत ने हेमा को पसंद किया था। ड्रीमगर्ल को इस बार भी पुराने फंडे से उम्मीद थी। इसीलिए तपती गर्मी में भी किसानों के साथ गेहूं काटने के लिए खेतों में उतर गईं, मगर वोटरों को इस बार हेमा का रोल पसंद नहीं आया। वोट का आंकड़ा 50 प्रतिशत भी पार नहीं कर पाया। देश में दूसरे चरण की 88 सीटों पर सबसे कम मतदान मथुरा में ही हुआ। ऐसे में विपक्षी खेमा तंज कस रहा कि स्वप्न सुंदरी अब कोई दूसरा रोल करें। दर्शक उनसे अलग-अलग भूमिका की अपेक्षा करते हैं, लेकिन हेमा सिर्फ गेहूं की फसल काटते हुए ही पोज देती हैं। एक रोचक टिप्पणी आई कि वोट प्रतिशत बढ़ाना है तो अगली बार किसी अन्य फसल काटने का पोज देने की तैयारी कर लेनी चाहिए।

साहब हुए गायब

चुनाव तो वैसे भी सियासी चर्चाओं का स्वर्णिम काल होता है, मगर दक्षिण भारत की एक सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि वहां एक राष्ट्रीय गठबंधन के साथी दो प्रमुख दलों के उम्मीदवार आमने-सामने हैं। इसमें एक प्रमुख विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता के खिलाफ अबकी बार मैदान में उतरी एक महिला उम्मीदवार की भी चर्चा कम नहीं है। महिला उम्मीदवार जिस पार्टी से चुनाव मैदान में उतरी हैं, उनके पति उस पार्टी के प्रमुख पद पर हैं। ऐसे में लोग मानकर चलते हैं कि पत्नी के चुनाव में नेता जी तो जरूर दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी बेटी तो प्रचार में जी-जान से जुटी रहीं, मगर नेता जी के नदारद होने की कानाफूसी ने धीरे-धीरे जोर पकड़ लिया। सभी पूछते रहे कि मैडम चुनाव चरम पर आ गया, मगर साहब कहां गायब हो गए?

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संकल्प का धनी व्यक्ति ही समृद्धि का पात्र बनता है

मिलावटी उत्पाद

इस पर आश्चर्य नहीं कि हांगकांग और सिंगापुर में भारत की दो कंपनियों के मसालों में कथित तौर पर कैंसरकारक तत्व मिलने और उन पर पाबंदी लगाए जाने के बाद अमेरिका भी इन कंपनियों के मसालों की जांच में जुट गया है। आने वाले दिनों में ऐसी ही खबरें अन्य देशों से भी आ सकती हैं। अंदेशा इसका भी है कि मसालों के साथ भारतीय कंपनियों के अन्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। जैसे-जैसे भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी यह कहना कठिन है कि हांगकांग और सिंगापुर की ओर से एमडीएच एवं एवरेस्ट के मसालों को लेकर जो शिकायत की गई, वह कितनी सही है, लेकिन अच्छा यह होगा कि वे सभी भारतीय कंपनियां चेत जाएं, जो अपने उत्पाद निर्यात करती हैं। उनकी गुणवत्ता की गहन परख होने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा अथवा ईर्ष्यावश भी उन्हें कठघरे में खड़ा किया जा सकता है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि हांगकांग और सिंगापुर की ओर से कदम उठाए जाने के बाद भारतीय मसाला बोर्ड के साथ भारत सरकार भी सक्रिय हुई, क्योंकि यह तो पहले ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि जो मसाले निर्यात हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता सही है या नहीं? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि एफएसएसएआइ यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकारण अपना काम सही तरह नहीं कर पा रहा है। यह हाल में तब इंगित हुआ था, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले के उत्पाद सेरेलेक के बारे में यह सामने आया था कि उसमें चीनी की मात्रा कहीं अधिक है। क्या यह विचित्र नहीं कि एफएसएसएआइ की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि पूरे देश में मसालों की गुणवत्ता की जांच होगी? आखिर यह काम पहले क्यों नहीं हुआ? उचित यह होगा कि यह जांच मसालों तक ही सीमित न रहे, क्योंकि देश में बिकने वाले न जाने कितने खाद्य एवं पेय पदार्थ ऐसे हैं, जिनकी गुणवत्ता को लेकर संदेह होता रहता है और शिकायतें भी आती रहती हैं। खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता से जानबूझकर समझौता करने के साथ उनमें अखाद्य एवं हानिकारक सामग्री की मिलावट बहुत आम है। इसका बड़ा कारण उनकी गुणवत्ता की जांच सही तरीके से न होना है। यह समस्या दवाओं के मामले में भी है। दवाओं के सैंपल केवल जांच में फेल ही नहीं होते रहते, बल्कि सरकारी अस्पतालों तक में दोयम दर्जे की और कभी-कभी तो नकली दवाएं खपाने के समाचार आते रहते हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले भारत से निर्यात होने वाली खांसी की दवाओं में विषाक्त पदार्थ की मिलावट के मामले सामने आए थे। ऐसे मामले भारत की साख को कमजोर करने के साथ ही देश के फार्मा उद्योग को भी क्षति पहुंचाते हैं।

आग का बढ़ता खतरा

आग से जान-माल के नुकसान की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो, जब अगलगी की घटना में भारी क्षति नहीं हो रही हो। यह चिंता का विषय है, जिस पर तुरंत पहल करते हुए इसकी रोकथाम के उपाय करने होंगे। दो दिन पहले गुरुवार को पटना स्थित दो होटलों में भयानक आग से सात लोगों की मौत हो गई। अगले ही दिन मसौढ़ी में आग से तबाही मची। बरात में आतिशबाजी के कारण आग लगने से मधुबनी में छह लोग जान से हाथ धो बैठे। शनिवार को रोहतास में आग से एक महिला व तीन बच्चियों की मौत हो गई। चूल्हे से निकली चिंगारी से फूस के घर में आग लग गई और चारों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ये घटनाएं नहीं हों, इसका उपाय ढूंढ़ना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसंख्य घटनाएं फूस के घरों में हो रही हैं, जहां उसे जलाने के लिए एक चिंगारी काफी है। इसके प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना होगा कि गर्मी के मौसम में चूल्हा जलाते समय ध्यान रखें। कई घटनाएं व्यवस्था की अनदेखी के कारण भी हो रही हैं। सुरक्षा मानक का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई से ही इस तरह के हादसे रोके जा सकते हैं। शहरों में तंग गलियों में होटलों का संचालन किया जा रहा है, जहां आग से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पटना के जिस होटल में आग लगी, उसमें बाहर निकलने का कोई वैकल्पिक रास्ता तक नहीं था। ऐसे दर्जनों होटल और लाज का संचालन किया जा रहा है, जहां आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं पहुंच सकती। यह जांच का विषय है कि वे कैसे संचालित किए जा रहे हैं और इसकी अनुमति कैसे मिल गई।

सार्वजनिक स्थलों और भवनों में आग से बचाव को सुरक्षा तंत्र का नितांत अभाव है। इसे लेकर अभियान चलाया जाना चाहिए, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईवीएम पर बेवजह सवाल उठाने वाले शांत होंगे?

आज का सवाल
क्या विश्व कप टीम के लिए शशांक सिंह के नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए?

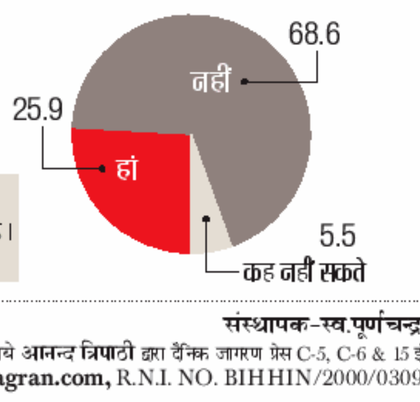

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

वामपंथी विचारों में जकड़ी कांग्रेस

संजय गुप्त

कांग्रेस पिछले दस वर्षों से जिस एजेंडे पर चल रही है, वह उद्यमशीलता के साथ-साथ कारोबारियों यानी धन का सृजन करने वालों के विरोध में ही अधिक है

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने यह कहकर खासी हलचल मचा दी कि यदि अमेरिका में किसी धनी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके बच्चों को उसकी संपत्ति का 45 प्रतिशत हिस्सा ही हस्तांतरित होता है। शेष संपत्ति सरकार के पास चली जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमें इस पर बहस करनी चाहिए। एक तरह से वह भारत में विरासत टैक्स की पैरवी करते दिखे। जब उनकी इस बात पर हंगामा खड़ा हो गया तो खुद उन्होंने सफाई दी और असहज कांग्रेस ने उनके बयान को उनका निजी विचार करार दिया। चूंकि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार भी माने जाते हैं, इसलिए इस मुद्दे पर अभी तक बहस जारी है और कांग्रेस सफाई दे रही है। सैम पित्रोदा ने विवाद पैदा करने वाले बयान से वामपंथी सोच को ही उजागर किया। उनका बयान आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर कांग्रेस पर हमला बोला कि उसका वही करने का इरादा है, जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं। उन्होंने उनके इस बयान को कांग्रेस के घोषणा पत्र से भी जोड़ दिया, क्योंकि उसमें कहा गया है कि सभी की संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा। वैसे कांग्रेस का घोषणा पत्र यह तो नहीं कहता कि संपत्ति का सर्वे कराकर उसका पुनर्वितरण किया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी अपने एक भाषण में इसकी ओर संकेत कर चुके हैं। इसी कारण गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि कांग्रेस ऐसा इरादा नहीं रखती तो अपने घोषणा पत्र में संपत्ति का सर्वे कराने वाली बात हटाए। अब राहुल संपत्ति के पुनर्वितरण से इन्कार कर रहे हैं, लेकिन सैम पित्रोदा के बयान पर कुछ नहीं कह रहे हैं।

विरासत टैक्स वह कर है, जो अमेरिका के छह प्रांतों में लागू है। इसके अलावा कुछ और देशों में भी प्रभावी है। एक समय संपत्ति शुल्क नाम से विरासत टैक्स भारत में भी था, लेकिन 1985 में राजीव गांधी सरकार ने उसे यह कहकर खत्म कर दिया था कि जिस उद्देश्य से उसे लाया गया था, वह पूरा नहीं हुआ। वास्तव में इससे राजस्व की प्राप्ति तो बहुत कम हो रही थी, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोगों का उत्पीड़न हो रहा था। संपत्ति शुल्क संग्रह की हिस्सेदारी मामूली थी। चूंकि इस टैक्स के आकलन की प्रक्रिया जटिल थी और उसमें मुकदमेबाजी भी होती थी, इसलिए उसकी वसूली सरकार को खासी महंगी पड़ती थी। विरासत टैक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने नया मोर्चा खोलते हुए राजीव गांधी को भी लपेट लिया और यह आरोप लगाया कि उन्होंने इंदिरा गांधी की संपत्ति पाने के लिए इस टैक्स को खत्म किया था। प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में यह भी कह रहे हैं कि लोगों की जमीन-जायदाद और यहां तक कि महिलाओं के स्त्रीधन एवं उनके मंगलसूत्र पर भी कांग्रेस की नजर है। वह उन्हें छीनकर अपने पसंदीदा वोट बैंक को देने का इरादा रखती है।

अवधेश राजपूत

कांग्रेस की सरकारों ने आजादी के बाद धन का सृजन करने वालों पर जो कर लगाए, वे एक समय लगभग 90 प्रतिशत हो गए थे। इसके पीछे पूंजीवाद को बुरा समझने वाला चिंतन था। कांग्रेस में यह चिंतन नेहरू जी के समाजवादी सोच से आया। लगता है कांग्रेस में आज भी यह सोच है कि वेल्थ क्रिएटर्स पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने चाहिए और सरकार को ही सब कुछ करना चाहिए। यह सोच कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी झलकती है। यह सोच देश को पिछली सदी के आठवें-नौवें दशक में ले जाने वाली है, जब विकास दर महज ढाई-तीन प्रतिशत हुआ करती थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब कांग्रेस पर गांधी परिवार का वर्चस्व नहीं था, तभी उसने प्रधानमंत्री नरसिंह राव के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों की नींव रखी, पर कांग्रेस ने उन्हें भुला दिया। कांग्रेस पिछले दस वर्षों से जिस एजेंडे पर चल रही है, वह उद्यमशीलता के साथ-साथ कारोबारियों यानी धन का सृजन करने वालों के विरोध में ही अधिक है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाते ही रहते हैं कि वह केवल अदाणी-अंबानी और अपने कुछ अन्य मित्र कारोबारियों के लिए ही काम कर रहे हैं। कांग्रेस खेती-किसानी का कायाकल्प करने के लिए लाए गए तीन कृषि कानूनों का भी मुखर विरोध कर चुकी है। हालांकि तमाम कृषि विशेषज्ञ इन कानूनों को सही बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों के साथ पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी यूपी के किसान संगठनों के विरोध के चलते मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े। भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ भी यह माहौल बनाया गया था कि सरकार किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। इसी कारण उसे भी वापस लेना पड़ा था। ध्यान रहे कि भूमि अधिग्रहण में विलंब के चलते कई परियोजनाएं अटकती रहती हैं।

राहुल गांधी सरकारी नौकरियों पर खूब जोर दे रहे हैं, जबकि उन पर सरकारों का व्यय पहले से ही काफी अधिक है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया है। हालांकि भारत जैसे बड़े देश में इतनी नौकरियां भी नाकाफी हैं, लेकिन इस वादे के जरिये कांग्रेस यही संदेश देना चाहती है कि वह सरकारी नौकरियों पर जोर देगी। आज आवश्यकता इसकी अधिक है कि निजी क्षेत्र और खासकर मैन्यूफैक्चरिंग एवं सर्विस सेक्टर के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऐसी नीतियां बनाई जाएं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें। राहुल गांधी यह दावा कर रहे हैं कि उनकी और मोदी की गारंटी में फर्क है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले आम चुनाव में जनता ने उनकी गारंटी पर भरोसा नहीं किया था। कांग्रेस के चुनावी वादों और खासकर सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का वामपंथी सोच फिर से उजागर हुआ है। कांग्रेस यह भूल रही है कि आज विश्व में वामपंथी सोच की जगह नहीं है। राहुल गांधी एक अर्से से उद्योगपतियों को खलनायक बनाने पर तुले हैं। वह इससे अनजान बने हैं कि देश आज जो उन्नति कर रहा है, उसमें कारोबारियों की भी एक बड़ी भूमिका है। आवश्यकता तो उन्हें प्रतियोगी, खुला वातावरण देने और उनके लिए ऐसा माहौल बनाने की है, जिसका लाभ उठाकर वे विश्वपटल पर अपनी धाक जमाने के लिए प्रेरित हो सकें। जब ऐसा होगा, तभी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आम जनता को लाभ मिलेगा।

response@jagran.com

अपने बलबूते चुनाव लड़ने की तैयारी

हास्य-व्यंग्य

सूर्यकुमार पांडेय

जिसने मेरा टिकट काटा, उसका आने वाला वक्त चैन से नहीं कटेगा, क्योंकि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा

आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव में मैं भी एक टिकटार्थी था, लेकिन चुनाव समिति ने दूसरे आवेदक को चुनाव चिह्न आवंटित कर उसे प्रत्याशी बना दिया। इस तरह मुझ जैसे एक सर्वगुण संपन्न, समर्पित और निष्ठावान उम्मीदवार की 'उम्मीदों' पर 'वार' हुआ है। चुनाव क्षेत्र में मेरी प्रतिष्ठा की मारक मिसाइलें पार्टी की परमाणु क्षमता के आगे पटाखों जैसी फुस्स हो चुकी हैं। आप भी जानते ही हैं कि न आप इजरायल हैं और न ही मैं ईरान हूं। फिर भी वर्तमान परिस्थितियां हमें वैसी समरभूमि की ओर ही धकेल रही हैं। आखिरकार चुनाव भी तो युद्ध जैसा ही होता है। इसीलिए हम इसे लोकतंत्र का संग्राम कहते हैं।

मान्यवर, न आप चुनाव लड़ रहे हैं और न ही आपने मुझे लड़ने दिया। खैर, आपकी तो जमानत भी नहीं बचती। मैं अपनी तो बचा ही सकता था! आपने मेरा टिकट काटा। अब आपका आने वाला वक्त चैन से नहीं कटेगा। मुझे भी कमतर मत आंकिएगा। मुझे तो पहले दिन से ही आप पर संदेह था। फिर भी, मैंने आपके आश्वासन पर विश्वास किया, मगर आपने मेरी जगह अपने खासमखास को टिकट पकड़ा दिया। सर्वविदित है कि वह आपका चमचा है। उसे तो चमचा कहना भी इस सात्विक शब्द का घनघोर अपमान है! वह तो पिट्ठू है, एक नंबर का पिछलग्गू। चमचों का भी एक स्टैंडर्ड होता है। उनको यह तो पता होता है कि कहां पर कमर झुकानी है और कहां घुटने टेकने हैं। आपके इस फैसले से लोकतंत्र का सिर शर्म से झुक गया। शीश मेरा भी झुका हुआ है, लेकिन वह चुनाव के समय अपने क्षेत्र की जनता के प्रति मेरा कृत्रिम और अवसरजन्य विनम्र झुकाव है।

श्रीमन, मैं अभी तक यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिरकार मेरा टिकट कटा तो क्यों कटा? क्या मेरी दावेदारी इतनी नरम थी! मेरी दावेदारी खरबूज और उनकी पत्थर! जो आप लोगों के काटे न कटी। इस बार पार्टी ने एक पत्थर को पूजा है। देखिएगा, मैं भी ईंट से ईंट बजा दूंगा। मेरी तो छवि भी खराब नहीं। छवि तो उसकी खराब होती है, जिसकी हो। मैं आपके ही आश्वासन पर आपकी पार्टी में शामिल हुआ था। घर में आए मेहमान के साथ ऐसी बदसुलूकी भारतीय परंपरा के खिलाफ है। होना यह चाहिए था कि घर वाले बाद में खाते, पहले मेहमानों के आगे छकने के लिए थालियां परोस दी जातीं। यहां उलटा किया गया। जिस दल को अपनी परंपरा से प्यार न हो, मैं उसे ठुकराता हूं।

महोदय, मुझ जैसे सुयोग्य, समर्थ और दमदार इंसान को टिकट न मिलने से इस देश की राजनीति कलुषित हुई है। पार्टी का विधान कलंकित हुआ है और मेरी निजी निष्ठाओं को आघात पहुंचा है, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य की कोख में है। इस घोषित सूची से मुझे और मेरे क्षेत्र की जनता को गहरा सदमा लगा है। वैसे मैं दूसरे दल से भी खड़ा हो सकता था। इसकी मुझे आदत भी है, लेकिन इस बार मामला जरा टेढ़ा फंस गया है। सीबीआइ ने विवश कर रखा है और ईडी ने पाई-पाई का 'नीडी' कर दिया है। आप तो सियासत के उस्ताद हैं। आपके सामने ज्ञान बघारना राजनीति के पंडित को चुनावी वर्णमाला का ककहरा पढ़ाने के समान होगा। फिर भी मैं आज खुद को विनम्रतापूर्वक निवेदन करने के लिए विवश पा रहा हूं। अपने से बड़ों की इज्जत तो कभी भी की जा सकती है। चुनाव के समय अपने से छोटे की इज्जत करना ही धर्म है, अन्यथा खुद की इज्जत भी उतर सकती है। मनुष्य का लचीलापन ही उसे अवसर प्रदान करता है। जो उस अवसर का लाभ उठा लेता है, वह सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ता, सीधा लिफ्ट से टाप फ्लोर पर पहुंच जाता है। अपने यहां विनम्रता को सद्गुण कहा गया है। मैं भी कठोर नहीं हूं। मैं अबकी अपने बूते पर खड़ा हो रहा हूं और जनता के आशीर्वाद और अपनी तिकड़म से जीत भी सुनिश्चित कर लूंगा। फिर जब आपको सरकार बनाने में पूर्ण बहुमत के लिए एक सदस्य की कमी पड़ेगी, मैं ही सबसे पहले याद आऊंगा। यह और बात है कि आज जिसे आप दस रुपये का तुड़ा-मुड़ा नोट समझ रहे हैं, तब उसकी वैल्यू करोड़ों में होगी।

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

तथ्य-कथ्य

पिछले लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों की महिला प्रत्याशियों का प्रदर्शन

ऊर्जा

अहंकार

अहंकार एक ऐसा नकारात्मक भाव है जो बड़े से बड़े गुणवान व्यक्ति को भी पतन की राह पर मोड़ देता है। अहंकार भी नाना प्रकार का होता है। किसी को ज्ञान का अहंकार होता है, जो वास्तव में अज्ञान ही होता है। किसी को बल या अपनी शक्ति का अहंकार होता है। हालांकि वर्तमान में धन-संपदा और भौतिकता के प्रदर्शन का अहंकार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। विशेषकर अचानक से धनी बने लोगों का व्यवहार उनके दंभ को उजागर कर देता है। जब व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है तो वह यही सोचने लगता है कि उसके पास सब कुछ है। वह दूसरों को अपने से हीन समझने लगता है। अगर उस व्यक्ति ने अनैतिक कार्यों से धन अर्जन किया हो तो उसके अहंकारी होने की आशंका और प्रबल हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश निश्चित होता है। महर्षि दयानंद ने यथार्थ ही कहा कि अहंकारी मनुष्य का पतन निश्चित है और जिसमें अहंकार भर जाता है वह दूसरों के बारे में शायद ही कोई अच्छी बात कहे। अगर कोई धन के प्रति अहंकार करता है तो उसके बुरे दिनों में कोई भी उसकी सहायता करने से संकोच करता है।

अहंकार का एक और रूप होता है, जिसे यूनानी भाषा में ईब्रिस कहते हैं। यूनानी विद्वान विलियम बार्कले के अनुसार ईब्रिस से आशय ऐसे अहंकार से है, जिसमें क्रूरता भरी हुई हो। यह अहंकार का ऐसा स्वरूप है, जिसमें लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उनकी भावनाओं का दमन करते हैं। ऐसे सोच के लोगों में क्रूरता आ ही जाती है। स्मरण रहे कि धन या बल से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु मान-सम्मान और चरित्र नहीं। महात्मा गांधी ने भी इस संबंध में कहा है कि 'ऐसा मानिए कि जो हम करते हैं, वह दूसरे भी कर सकते हैं। यदि हम ऐसा न मानें तो अहंकारी ठहराए जाएंगे।' मानव इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा है, जहां बड़े से बड़े विद्वान और शूरवीरों को भी अपने अहंकार का मूल्य चुकना पड़ा।

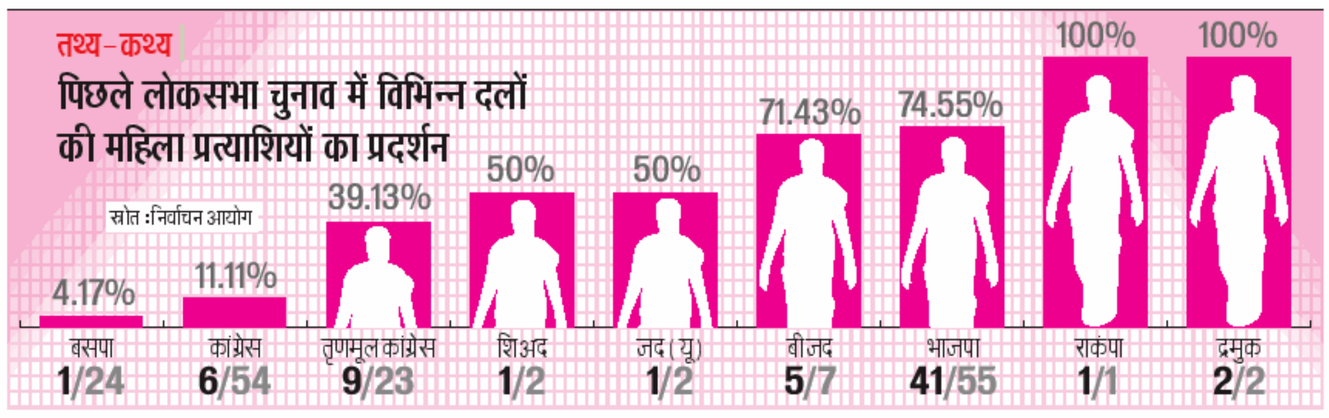

नृपेंद्र अभिषेक नृप

चुनावी उत्सुकता

शुरुआती दो चरण के मतदान के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के अपने-अपने दावे हैं। स्वाभाविक है कि दोनों खेमे अपनी बढ़त तो दूसरे के कमजोर पिच पर होने के दावे कर रहे हैं। दोनों चरणों में वोटिंग प्रतिशत में आई गिरावट ने भी सियासी विश्लेषकों के लिए मतदाताओं के मिजाज की गहराई भांपने की सिरदर्दी बढ़ा दी है। वहीं, देश की नौकरशाही से जुड़े कुछ लोग चुनाव की जमीनी नब्ज टटोलने में अचानक रुचि लेने लगे हैं। नौकरशाही में जगी इस दिलचस्पी को वैसे तो बेहद सतर्कता के दायरे में ही रखा गया है, मगर ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए सियासी रूप से कुछ जागरूक लोग राज्यों के चुनावी दौरे कर रहे अपने जानकार पत्रकारों-राजनीतिक विश्लेषकों से अनौपचारिक चर्चा के बहाने थाह लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे। वैसे चुनाव को लेकर जगी उनकी ताजा जागरूकता की वजह चाहे जो हो, मगर इसकी रोचक चर्चाओं का दौर केवल सार्वजनिक रैलियों में ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे भी जारी है।

निगाहें नई कैबिनेट पर

अभी लगभग सभी केंद्रीय मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। अधिकतर मंत्री स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं या फिर पार्टी की तरफ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद मंत्रालय से उनका वास्ता छूट गया है। वैसे भी, इन मंत्रियों को पता है कि चुनाव के बाद उन्हें पुराना मंत्रालय मिलता है या मंत्रिमंडल से ही उनकी छुट्टी हो जाएगी, इसका वह आकलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मंत्रालय का मोह छोड़ दिया है। इस बीच, एक ऐसे भी मंत्री हैं, जो चुनावी पारा चढ़ने के इस मौसम में भी मंत्रालय में बैठ रहे हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं। देर रात तक वह मंत्रालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और नई सरकार के गठन के बाद होने वाले फैसले की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास तीन-तीन मंत्रालयों का भार है और हाल ही में उन्हें फिर से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया है। तभी उनके विभाग के अधिकारी दबी जुबान में यह कहने से नहीं हिचकते कि मंत्री जी यहां बैठकर अगली कैबिनेट में आने का चुनाव लड़ रहे हैं।

राजरंग

गेहूं और वोट

लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत में कमी के बीच सत्तापक्ष के सियासी खेमे में चर्चा है कि हेमा मालिनी को 'पारिश्रमिक' देने में वोटरों ने इस बार कंजूसी कर दी। चिलचिलाती धूप में कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनकर खेतों में गेहूं की फसल काटना भी काम नहीं आया। इसी अंदाज में पिछले चुनाव में भी उन्होंने गेहूं की फसल काटी थी। तब उन्हें अच्छी 'मजदूरी' यानी राजनीतिक आशीर्वाद मिला था। 60.48 प्रतिशत वोटर बूथों तक पहुंचे थे। जो आए उनमें से भी करीब 60 प्रतिशत ने हेमा को पसंद किया था। ड्रीमगर्ल को इस बार भी पुराने फंडे से उम्मीद थी। इसीलिए तपती गर्मी में भी किसानों के साथ गेहूं काटने के लिए खेतों में उतर गईं, मगर वोटरों को इस बार हेमा का रोल पसंद नहीं आया। वोट का आंकड़ा 50 प्रतिशत भी पार नहीं कर पाया। देश में दूसरे चरण की 88 सीटों पर सबसे कम मतदान मथुरा में ही हुआ। ऐसे में विपक्षी खेमा तंज कस रहा कि स्वप्न सुंदरी अब कोई दूसरा रोल करें। दर्शक उनसे अलग-अलग भूमिका की अपेक्षा करते हैं, लेकिन हेमा बार-बार सिर्फ गेहूं की फसल काटते हुए ही पोज देती हैं। एक रोचक टिप्पणी आई कि वोट प्रतिशत बढ़ाना है तो हेमा को अगली बार गेहूं नहीं, बल्कि धान या मक्के की फसल काटने का पोज देने की तैयारी कर लेनी चाहिए।

साहब हुए गायब

चुनाव तो वैसे भी सियासी चर्चाओं का स्वर्णिम काल होता है, मगर दक्षिण भारत की एक सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि वहां एक राष्ट्रीय गठबंधन के साथी दो प्रमुख दलों के उम्मीदवार आमने-सामने हैं। इसमें एक प्रमुख विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता के खिलाफ अबकी बार मैदान में उतरी एक महिला उम्मीदवार की भी चर्चा कम नहीं है। महिला उम्मीदवार जिस पार्टी से चुनाव मैदान में उतरी हैं, उनके पति उस पार्टी के प्रमुख पद पर हैं। ऐसे में लोग मानकर चलते हैं कि पत्नी के चुनाव में नेता जी तो जरूर दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी बेटी तो प्रचार में जी-जान से जुटी रहीं, मगर नेता जी के नदारद होने की कानाफूसी ने धीरे-धीरे जोर पकड़ लिया। सभी पूछते रहे कि मैडम चुनाव चरम पर आ गया, मगर साहब कहां गायब हो गए?

पोस्ट

ईवीएम पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का यह शेर बहुत सटीक है, 'जिसने मेरे सर पर तोहमत रखी है, मैंने उसके भी घर की लाज रखी है।' परिणाम ही प्रमाण है।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

सुनने में आया है कि पंजाब की टीम ने शशांक सिंह को गलती से खरीदा था। इसी तरह अगर वह 'गलती' से भारतीय टीम में भी आ जाएं तो बात बन जाए।
गौरव कालरा@gauravkalra75

पहले चरण की वोटिंग में इस नैरेटिव को फैलने/फैलाने में मदद मिली थी कि कम वोटिंग से भाजपा को नुकसान हो सकता है, लेकिन दूसरे चरण में ऐसा लगता है कि भाजपा ने उसकी भरपाई कर ली है। एक-दो प्रतिशत की क्षति भाजपा के लिए बड़ी क्षति नहीं है। यह क्षति अगर पांच प्रतिशत हो जाए तो पार्टी के लिए चिंता की बात होगी।
सुशांत झा@jhasushant

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहली बार महिला वीसी मिली हैं। पिछले 10 साल में जामिया, कश्मीर, जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पहली महिला वीसी मिलीं। अभी बीएचयू और डीयू जैसी कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पहली महिला वीसी मिलना बाकी है। उम्मीद है वहां भी उनका नंबर जल्द आएगा।
रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

जनपथ

ईवीएम पर कोर्ट ने किया ठीक इंसाफ,
भाई अब तो कीजिए बेचारी को माफ।
बेचारी को माफ करोगे खुद ना मेहनत,
अरु होने पर हार लगाते उस पर तोहमत!
होती बैंड जुबान बने जब अपना सीएम,
जब हो जाए हार खाय गाली ईवीएम!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 17

हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान अनुभव से पैदा होता है।

- मारिया फज

21वीं सदी की तरफ बढ़ते हुए आपको एहसास होगा कि पहली बड़ी जंग के बावजूद जर्मनी में दुनिया का सबसे उन्नत सामाजिक सुरक्षा ढांचा बन गया था। जर्मनी के इन प्रयोगों ने पूरे यूरोप को प्रेरित किया। 1909 में ब्रिटेन में ओल्ड एज पेंशन लागू कर दी गई। ओटो फॉन बिस्मार्क ने बुजुर्गों की दुनिया बदल दी। पेंशन अब सरकारों की जिम्मेदारी बन गई थी।

बिस्मार्क ने बुजुर्गों की दुनिया बदल दी

भयानक आर्थिक मुसीबतों के बीच रानी एलिजाबेथ को नई व्यवस्था करनी पड़ी है। दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी साम्राज्य में ऐसे कानून बनाए गए, जो गरीबों के लिए थे। तख्त के हुक्म पर उन लोगों की पहचान की गई, जिन्हें शासन से मदद दी जानी है। इनमें बेहद गरीब बुजुर्ग और विकलांग शामिल हैं।

अंशुमान तिवारी
वरिष्ठ लेखक-पत्रकार

भारत में पेंशन को लेकर बड़ी ले-दे मची है। चुनावों की गुणा-गणित के बीच राजनीतिक दल तय नहीं कर पा रहे हैं कि भारत की बुजुर्ग और निर्धन आबादी को क्या सामाजिक सुरक्षा दी जाए। कांग्रेस, जिसने कर्मचारी पेंशन की पुरानी प्रणाली को विधानसभा चुनाव में जीत का जरिया बनाया था, वह लोकसभा चुनाव में खुलकर इस स्कीम का वादा नहीं कर रही। इधर भाजपा जो नई पेंशन प्रणाली लागू कर रही है, उसे लग रहा है कि पुरानी प्रणाली के एक हिस्से यानी गारंटीड पेंशन की व्यवस्था को नई प्रणाली में जोड़ा जा सकता है।

पुरानी पेंशन, यानी जिसमें सरकारें अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को एक निर्धारित पेंशन की गारंटी देती हैं, जो उनके आखिरी वेतन का लगभग आधा होती है। नई पेंशन में कर्मचारी के पेंशन-योगदान का बाजार में निवेश होता है और रिटर्न के आधार पर कर्मचारियों को पेंशन मिलती है।

यानी होते-करते दुनिया का सबसे रोमांचक, जी हां, सबसे सनसनीखेज सामाजिक सुरक्षा सुधार भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में अपनी जगह बना रहा है। दुनिया के कई देशों में बजटों की तस्वीर बदल दी थी इस अनोखे प्रयोग ने, जिसे पेंशन कहते हैं।

आइए, टाइम मशीन का इंजन गुर्रा रहा है।

पकड़िए अपनी सीट और उड़ चलते हैं 16वीं सदी की ओर, जब ब्रिटेन के तख्त पर रानी एलिजाबेथ प्रथम विराज रही थीं। महारानी एलिजाबेथ की प्रजा अकाल से जूझ रही है। चौतरफा बेरोजगारी है और आर्थिक संकट।

इस वक्त तक राजाओं और सम्राटों की योजना और नीतियों में गरीब-गुरबों की कोई जगह नहीं है। यह जिम्मेदारी सामंतों पर थी कि अपने-अपने गुलामों या मजदूर-किसानों की फिक्र करें। भयानक आर्थिक मुसीबतों के बीच रानी एलिजाबेथ को नई व्यवस्था करनी पड़ी है।

क्या आप उस एलान को सुन पा रहे हैं, जिन्हें पुअर लॉज कहा जा रहा है। दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी साम्राज्य में ऐसे कानून बनाए गए, जो गरीबों के लिए थे।

तख्त के हुक्म पर उन लोगों की पहचान की गई, जिन्हें शासन से मदद दी जानी है। इनमें बेहद गरीब, बुजुर्ग और विकलांग शामिल हैं। मगर जरा ठहरिए, यह भी देखिए कि इन्हीं कानूनों के आधार पर साम्राज्य ने नए टैक्स लगाने की व्यवस्था भी शुरू की है। 16वीं सदी के ब्रिटेन में विचरते हुए आपको मुश्किल से यह भरोसा होगा कि यही कानून अगले 250 साल तक इस्तेमाल होने वाले हैं।

अब टाइम मशीन की रफ्तार बढ़ाते हैं। 19वीं सदी की तरफ बढ़ते हुए आपको पता चल रहा होगा कि ब्रिटेन में पुअर लॉज तो बन गए, मगर इसके बावजूद तत्कालीन दुनिया के पास लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी।

अब हम 19वीं सदी में हैं। यह ब्रिटेन का विक्टोरियन युग है, जहां औद्योगिक क्रांति से आर्थिक ताना-बाना बदलने लगा है। मशीनों और विज्ञान की प्रगति के बावजूद इस युग में आर्थिक असमानता बढ़ रही है।

टाइम मशीन अब प्रशा (आज का जर्मनी) की तरफ बढ़ रही है। 21वीं सदी के जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, रूस, चेक गणराज्य, पोलैंड और लिथुआनिया इसी जर्मन राज्य से निकले थे। आपको नजर आएगा कि यहां बड़े राजनीतिक बदलाव खदबदा रहे हैं। ठीक पहचाना आपने इस शख्सियत को। यकीनन यह ओटो फॉन बिस्मार्क ही हैं। प्रशा के मिनिस्टर प्रेसीडेंट और जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करने वाले। अब हम 1881 में हैं। प्रशा में बिस्मार्क का सूर्य तप रहा है। राजनीतिक आबोहवा में सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव के बीच जोरदार खींचतान चल रही है। समाजवादी साम्यवादी राज्य की कल्पना जर्मनी के लोगों को उत्साहित कर रही है।

टाइम मशीन

अतीत से सुनें वर्तमान की धड़कन ■ हर पखवाड़े

जर्मनी की संसद में कुछ अभूतपूर्व होने वाला है, जो अब तक दुनिया में कभी नहीं हुआ। ओटो फॉन बिस्मार्क ने यहां एक प्रस्ताव पेश कर तहलका मचा दिया है। वह देखिए, बिस्मार्क की तरफ यह प्रस्ताव कौन रख रहा है? जी यकीनन, यह जर्मन सम्राट विलियम द फर्स्ट हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जर्मन समाज के बुजुर्ग लोगों को जिंदगी की शाम गुजारने के लिए मदद दी जानी चाहिए, यानी कि उन्हें रिटायर होने का मौका दिया जाना चाहिए।

आप तो 21वीं सदी से आए हैं न, जहां रिटायरमेंट अब कानून का हिस्सा है। इसलिए शायद आपको इस प्रस्ताव की क्रांतिकारी ऊर्जा का एहसास नहीं होगा, मगर 19वीं सदी तक के यूरोप में लोग जब तक जीवित रहते थे, काम करते थे।

आप जिस जर्मनी में हैं, वहां रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सुना नहीं, बिस्मार्क क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को आप सोशलिस्ट कहें या कुछ और, मगर जनता के लिए यह जरूरी है।

यह 1890 है। बिस्मार्क जर्मन राज्य के पहले चांसलर बन गए हैं। दुनिया की पहली सार्वजनिक पेंशन प्रणाली शुरू कर दी गई है। अब सरकार बुजुर्गों को पेंशन देने वाली थी। शुरुआत में इस पेंशन की पात्रता के लिए 70 साल की उम्र तय की गई थी। बाद में जर्मनी में इसे घटाकर 65 साल कर दिया गया।

पेंशन की चर्चाओं के बीच 1884 में जर्मनी में वर्कर्स कंपनसेशन कार्यक्रम लागू हो चुका था। कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा जैसी व्यवस्था भी आ गई थी। पेंशन की लहर चली, तो जर्मनी ने कर्मचारियों के लिए उनके योगदान पर आधारित पेंशन प्रणाली भी लागू कर दी। इन स्कीमों में नियोक्ता और कर्मचारी, दोनों योगदान करते थे। अब विकलांगों को भी बजट से मदद मिलने लगी है। इसके बाद 1927 में जर्मनी में बेरोजगारी बीमा का प्रयोग भी हो गया।

21वीं सदी की तरफ बढ़ते हुए आपको एहसास होगा कि पहली बड़ी जंग के बावजूद जर्मनी में दुनिया का सबसे उन्नत सामाजिक सुरक्षा ढांचा बन गया था। जर्मनी के इन प्रयोगों ने पूरे यूरोप को प्रेरित किया। 1909 में ब्रिटेन में ओल्ड एज पेंशन लागू कर दी गई।

ब्रिटेन से गुजरते हुए आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एच एच एक्विथ और वित्त मंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज दिखेंगे, जिन्होंने पेंशन देने के लिए दो बार अपनी सरकार गंवा दी। 1935 में अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी शुरू हुई। 1965 में बुजुर्गों के लिए मेडिकेयर आया। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका में निजी पेंशन प्लान का प्रचलन शुरू हो गया था।

ओटो फॉन बिस्मार्क

ओटो फॉन बिस्मार्क ने बुजुर्गों की दुनिया बदल दी। पेंशन अब सरकारों की जिम्मेदारी बन गई थी।

टाइम मशीन अब रोम में उतरेगी, क्योंकि हम रोमन सम्राट ऑगस्टस की यादों के साथ यह सफर खत्म करना चाहते हैं। ईसा पूर्व 13वीं सदी में सम्राट ऑगस्टस अपने सैनिकों को बीस साल की सेवा के बाद पेंशन देते थे। इसके लिए अमीरों पर विरासत टैक्स लगाया जाता था।

रोम में टहलते हुए भारत में सार्वजनिक पेंशन की उम्मीद पर बहस कीजिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने बताया है कि 2030 तक करीब 20 करोड़ लोग और 2050 तक वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन भारत की आबादी में करीब 21 फीसदी होंगे। फिर मिलेंगे अगले सफर पर...

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।

अर्थात् क्या वह हमारा है या बाहरी व्यक्ति है? ऐसी बात छोटे मन वाले लोग पूछते हैं। उदार मन वाले लोग तो पूरे संसार को अपना परिवार ही समझते हैं।

- विष्णु शर्मा कृत पञ्चतन्त्र

प्रस्तुति : **शास्त्री कोसलेंद्रदास**

बड़ी बहन आपसे नाराज क्यों रहती है?

कैथरीन पियर्सन
न्यूयॉर्क टाइम्स

'एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम' मानता है कि जन्म का क्रम ही हमारे व्यक्तित्व और तौर-तरीकों को निर्धारित करता है।

क्या आपने 'एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम' के बारे में सुना है? यह एक भावनात्मक बोझ है, जिसे कई परिवारों में बड़ी बेटियां कम उम्र से ही उठाने लगती हैं। छोटे भाई-बहनों की देखभाल, रोजमर्रा के कामों में मदद, बीमार माता-पिता की देख-रेख जैसी घरेलू जिम्मेदारियां अक्सर बड़ी बेटियां छोटी उम्र से ही उठाने लगती हैं। कैलिफोर्निया में एक शादीशुदा और फैमिली डॉक्टर केटी मॉर्टन, जो स्वयं अपने परिवार में सबसे छोटी हैं, भाई-बहन के जन्म के क्रम पर विचार करते हुए कहती हैं कि व्यक्तित्व एक लंबे समय के घटनाक्रमों का नतीजा होता है। कई लोगों का ख्याल है कि पहले जन्मे बच्चे विश्वसनीय और उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले, बीच के बच्चे मिलनसार व नटखट और सबसे छोटे बच्चे आकर्षक और चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय की एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक रोडिका डेमियन भी कहती हैं कि बड़ी बहन अधिक जिम्मेदार या बुद्धिमान लग सकती है, क्योंकि वह छोटे भाई-बहनों की तुलना में अधिक परिपक्व होती है।

2015 में जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका द्वारा किए गए अध्ययनों में जन्म के क्रम और व्यक्तित्व के लक्षणों के बीच कोई संबंध नहीं मिला। हालांकि शोधकर्ताओं को इसके सबूत जरूर मिले कि बड़े बच्चों का आईक्यू स्तर अधिक होता है। डॉ. डेमियन ने एक अलग अध्ययन पर काम किया। इसमें व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता में थोड़े अंतर पाए गए, लेकिन अंतर इतने छोटे थे कि वे मूलतः अर्थहीन थे। कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर सारा स्टेनिजई, जो एक चिकित्सक हैं, एक आभासी थेरेपी ग्रुप संचालित करती हैं। इसकी साप्ताहिक बैठकों में प्रतिभागी इस बात पर विचार-विमर्श करते हैं कि जन्म क्रम उन्हें, उनके जीवन, दोस्ती और कॅरिअर को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह स्टेनिजई के व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरित था, जो परिवार में सबसे बड़ी थीं और इस कारण वह अपने छोटे भाई-बहनों और माता-पिता के प्रति कुछ हद तक जिम्मेदार महसूस करती थीं। स्टेनिजई का मानना है कि जन्म-क्रम बहुत उपयोगी है और इसने उनके पारिवारिक जीवन को आकार दिया है। खासकर तब, जब आप कुछ अपेक्षाओं से घिरे हुए या दुखी महसूस करते हैं। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आपके घर में आपका जन्म किस क्रम में हुआ है, उसका व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। कुंडली और जन्म-क्रम तो बस विचार हैं। ये कोड की तरह हैं, जिनके जरिये लोग अपने अनुभवों का वर्णन करने की कोशिश करते रहते हैं।

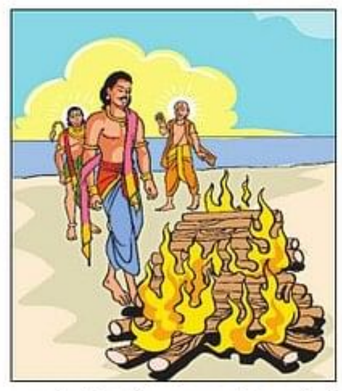

©The New York Times 2024

जानना जरूरी है

संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

अर्जुन घबराया हुआ था। उसने बाणों से सेतु बनाने से पहले श्रीकृष्ण का स्मरण किया। इसके बाद युवक के संकेत पर हनुमान पुल पर चढ़ गए। परंतु इस बार पुल गिरा नहीं, अपितु मजबूती से टिका रहा।

विष्णु ने तोड़ा हनुमान और अर्जुन का अहंकार

अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत अहंकार था। एक दिन वह रामेश्वरम पहुंचा, जहां भगवान श्रीराम ने वानर-सेना के सहयोग से लंका तक सेतु का निर्माण किया था। अर्जुन ने कहा, 'श्रीराम जैसे धनुर्धर को पुल बनाने के लिए वानरों से सहायता क्यों लेनी पड़ी? यदि मैं उनके स्थान पर होता, तो बाणों द्वारा समुद्र पर सेतु बांध देता!' उसी समय हनुमान, वानर का रूप धरकर अर्जुन की बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा, 'तुम्हें अपनी धनुर्विद्या पर बहुत अहंकार है और तुम मूर्ख भी हो! श्रीराम बाणों से पुल तो बना सकते थे, किंतु बाणों से बना सेतु, वानर-सेना का भार सहन नहीं कर पाता।'

अर्जुन ने हनुमान को साधारण वानर समझकर हंसते हुए कहा, 'मूर्ख मैं नहीं, तुम हो! अभी तुमने मेरे बाणों की शक्ति नहीं देखी। मेरा बनाया पुल कितना भी भार सहन कर सकता है।'

धूप आने दो

हनुमान ने अर्जुन का अहंकार तोड़ने का निश्चय किया। वह बोले, 'तुम पुल बनाओ। मैं उसकी जांच करूंगा। यदि तुम्हारा सेतु मेरा भार सहन कर पाया, तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। परंतु पुल टूट गया तो?'

अर्जुन ने आवेश में उत्तर दिया, 'यदि मेरा बनाया पुल टूट गया, तो मैं प्राण त्याग दूंगा!' यह कहकर अर्जुन ने गांडीव-धनुष संभाल लिया। अंहकार से ग्रस्त अर्जुन ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और फिर बाणों की ऐसी सतत वर्षा की कि बाण, पानी की सतह पर फैल गए और कुछ ही देर में बाणों का सेतु बनकर तैयार हो गया।

सेतु को देखकर हनुमान मुस्कराए और पुल की ओर चल पड़े। हनुमान ने ज्यों ही पुल पर पहला पैर रखा, सेतु चरमराकर ढह गया। यह देखकर अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। एक वृद्ध वानर के पैर रखने से संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का बनाया सेतु ढह गया! अर्जुन लज्जित महसूस कर रहा था। यह उसके लिए अपमान से कम नहीं था। वह शर्त हारने पर प्राण त्यागने का वचन दे चुका था।

● अर्जुन अपने लिए चिता तैयार करने लगा। हनुमान ने अर्जुन को रोकने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि हनुमान चाहते थे कि अर्जुन को अहंकार का दंड मिले। अर्जुन चिता में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी एक नवयुवक आ पहुंचा।

युवक ने अर्जुन से उसके प्राण त्यागने का कारण पूछा, तो अर्जुन ने युवक को पूरी घटना विस्तार से बताई, जिसे सुनकर युवक बोला, 'तुम दोनों की शर्त का कोई साक्षी नहीं था, इसलिए वह शर्त वैध नहीं ठहरती। अब मैं साक्षी हूं। मेरे सामने तुम एक बार फिर अपने बाणों से पुल बनाओ। फिर मैं इस वानर को अपनी शक्ति प्रदर्शन का अवसर दूंगा। उसके बाद ही शर्त का निर्णय होगा।'

हनुमान और अर्जुन ने युवक की बात मान ली। इस बार अर्जुन घबराया हुआ था। उसने बाणों से सेतु बनाने से पहले श्रीकृष्ण का स्मरण किया। इसके बाद युवक के संकेत पर हनुमान पुल पर चढ़ गए। परंतु इस बार पुल गिरा नहीं, अपितु मजबूती से टिका रहा। हनुमान जोर-जोर से सेतु पर कूदने लगे। परंतु सेतु तनिक भी नहीं हिला। उन्होंने जिस रूप में लंका जाते समय छलांग लगाई थी, वही उग्र और विशाल रूप धारण कर लिया। अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हनुमान ने कई बार पुल तोड़ने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली।

अर्जुन और हनुमान दुविधा से भरे एक-दूसरे को देख रहे थे, जबकि पास खड़ा युवक मुस्करा रहा था। दोनों समझ गए कि वह साधारण युवक नहीं था। फिर युवक ने अपना असली रूप प्रकट किया, तो पता लगा कि वह दरअसल, भगवान विष्णु थे!

विष्णु ने अर्जुन और हनुमान से कहा, 'मैंने जब देखा कि मेरे दोनों भक्त अहंकार से पीड़ित हैं, तो मुझे यह लीला करनी पड़ी।'

अध्ययन कक्ष

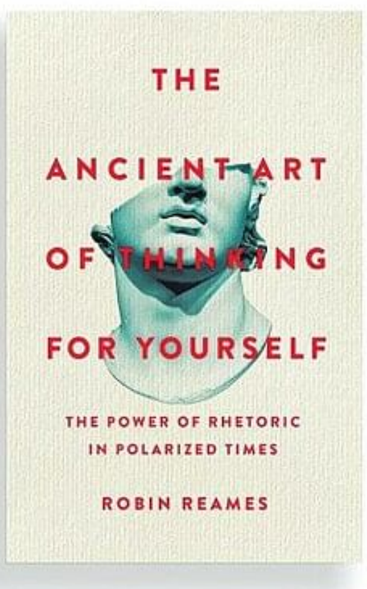

द एंशिएंट आर्ट ऑफ थिंकिंग फॉर योरसेल्फ

द पावर ऑफ रेटोरिक इन पोलराइज्ड टाइम्स

लेखक : रॉबिन रीम्स

प्रकाशक : बेसिक बुक्स

मूल्य : 1921 रुपये

हार्डकवर

आज के भाषणबाज यूनानी भाषणशास्त्रियों से कुछ सीख सकते हैं?

वर्तमान विमर्श की सामान्य सोच को जाहिर करते हुए रीम्स की पुस्तक प्राचीन यूनानी संवादों की मिसाल देती है। असल बात यह है कि तर्क और कुतर्क की बात बाद में आती है, पहले जिसका विरोध कर रहे हैं, उस पर भरोसा तो हो।

शिकागो के इलिनॉय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर रॉबिन रीम्स की जब भी अपने पिता से राजनीतिक बहस होती, तो वे निराश हो जाती थीं, क्योंकि उन्होंने कॉलेज में उदारवादी विचार अपनाए थे। वह अब भी कई लोगों की तरह वामपंथी और दक्षिणपंथी आदर्शों की विशाल, अंधी खाई से निराश हैं और इसलिए उनकी पुस्तक *'द एंशिएंट आर्ट ऑफ थिंकिंग फॉर योरसेल्फ'* मौजूदा दौर में संवाद करने में मदद करना चाहती है।

रीम्स मानती हैं कि हमारी राय अकाट्य सत्य से उत्पन्न होने के बजाय हमारे पहले के विश्वासों से निर्धारित होती है। उन्हें उम्मीद है कि हम प्राचीन यूनानियों और रोमनों की परिष्कृत अलंकारिक तकनीकों से सीख सकते हैं, जिनके राजनीतिक विमर्श में तर्क-वितर्क की कला को उस हद तक उन्नत किया गया, जो आज लगभग अकल्पनीय है। यूनानियों और रोमनों को उम्मीद थी कि राजनीतिक भाषण तर्क के आधार पर तैयार किए जाएंगे। रीम्स लिखती हैं, 'अगर प्राचीन भाषणशास्त्री इन दिनों हमारे कुछ सार्वजनिक विवादों को सुनते, तो उन्हें लगता कि हमने अपना दिमाग खो दिया है।' उन्होंने लिखा कि उस वक्त एक वक्ता से साधारण भाषण के जरिये सदन को एकजुट करने की अपेक्षा नहीं की जाती थी, बल्कि उम्मीद की जाती थी कि वह हर बार सभा को संबोधित करते समय एक नया, अपना स्थायी तर्क गढ़े। जबकि आज के युग में ऐसे लोग प्रशंसा के पात्र हैं, जो नारेबाजी के बजाय विचारों पर गंभीरता से बहस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर भी रीम्स यह दिखाने में सफल नहीं हुईं कि यूनान की प्राचीन तकनीकें आज कितनी मददगार होंगी।

अब जो चीज अक्सर हमारे तर्कों को नष्ट कर देती है, वह यह है कि हम चिंताओं को साझा नहीं करते हैं, बल्कि हम उन्हें अलग-अलग तरीके से देखते हैं। रीम्स फ्रांस की इस बहस का हवाला देती हैं कि क्या मुस्लिम महिलाओं को स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस मामले में किसी की राय इस बात पर निर्भर करती है कि कोई धर्मनिरपेक्षता को धार्मिक प्रतिबद्धता से ऊपर या नीचे रखता है या नहीं।

किताब के अनुसार, समस्या यह नहीं है कि हम अपनी धारणाओं से 'चिपके' रहते हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें प्राकृतिक नियम मान लेते हैं। आज के वामपंथी श्वेतवाद और सामाजिक वर्चस्व से लड़ने को मानवीयता के लिए जरूरी मानते हैं। भले ही वे जानते हों कि अन्य लोग इस लड़ाई को उतना ऊंचा दर्जा नहीं देते, जितना वे देते हैं। रीम्स बताती हैं कि यूनानियों ने परस्पर विरोधी विचारों को सह-अस्तित्व की अनुमति दी थी।

रीम्स की यह पुस्तक शानदार है और अच्छे इरादे से लिखी गई है, लेकिन ध्रुवीकृत विमर्श के दौर में यह अपनी उपयुक्तता साबित कर पाएगी, यह देखने वाली बात होगी।

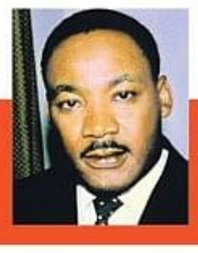

अभियान
amarujala.com
अमर उजाला

"सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और जुनून की जरूरत होती है।"
- मार्टिन लूथर किंग जूनियर

गोल चबूतरा

Hindi@mithelesh
■ मिथिलेश बारिया

निकल जाते हो सड़कों पर
मोमबत्तियां लेकर,
अमा कभी वोट डालने भी जाया करो...

धूप बहुत तेज थी, कसाई ने बकरियां,
पेड़ के नीचे बांध दी...

रिश्तों की धूप न मिले,
तो घर भी मर जाते हैं...

आईट्यूंस स्टोर पर मिलने लगे गाने

झरोखा
28 अप्रैल

आज ही के दिन सन 2003 को एपल ने आधिकारिक तौर पर अपना 'आईट्यूंस' म्यूजिक स्टोर लॉन्च किया था। कंपनी के सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स के प्रयासों से म्यूजिक का ऑनलाइन डाटा उपलब्ध होना शुरू हुआ था। वह संगीत के लिए डिजिटल बाजार खोलना चाहते थे। शुरुआत में आईट्यूंस म्यूजिक स्टोर में यूजर्स के लिए करीब 2,00,000 गाने थे। यूजर्स इनमें से अपना पसंदीदा गाना चुनकर आसानी से डाउनलोड कर सकते थे। इस नए विकल्प ने उस समय आईपॉड म्यूजिक प्लेयर्स की लोकप्रियता को भी अधिक बढ़ा दिया था। लोग बड़ी संख्या में आईपॉड खरीदने लगे। कहते हैं कि म्यूजिक सॉफ्टवेयर के रिलीज के पहले दिन ही करीब 2,75,000 गाने डाउनलोड किए गए थे। पांच दिन बाद आईट्यूंस की बिक्री 1 मिलियन से अधिक गानों तक पहुंच गई थी। अगले दिसंबर तक एपल ने खुलासा किया कि म्यूजिक स्टोर ने आधिकारिक तौर पर 25 मिलियन से अधिक ट्रैक बेच चुका था। आईट्यूंस स्टोर अधिकांश एपल डिवाइस पर उपलब्ध है, जिसमें मैक (म्यूजिक एप के अंदर), आईफोन, आईपैड, आईपॉड टच और एपल टीवी के साथ-साथ विंडोज (आईट्यूंस के अंदर) भी शामिल हैं।

■ गुरुग्राम से मोहन राय

एक तरफ तो खाद्य पदार्थों के भाव आसमान छू रहे हैं, दूसरी तरफ उनमें मिलावट भी की जा रही है। नतीजतन हमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। गंभीर बात यह है कि मिलावटखोरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?

मिलावटखोरों पर कार्रवाई हो !

सेहत से खिलवाड़ क्यों?

चिट्ठी 1

खाद्य पदार्थों में मिलावट की खबरें समाचार पत्रों में छपती रहती हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे स्थिति बदले। दूध, पानी, तेल, घी, खोया, दवा, आटा, बेसन, दही और मिठाई आदि में मिलावट की खबरें आती रहती हैं। ऐसा कोई खाद्य पदार्थ नहीं, जिसमें मिलावट न की जा रही हो। यह मिलावट का ही परिणाम है कि लोगों में तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं और उनकी जान जा रही है। इस वजह से हर आदमी कम उम्र में ही किसी न किसी रोग से पीड़ित हो रहा है। प्रायः देखा गया है कि मात्र दिवाली, दशहरा और होली जैसे अवसरों पर ही संबंधित विभाग अभियान चलाते हैं और अपने दायित्वों का निर्वाहन करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों का नमूना लेते हैं और कुछ विशेष प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करते हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि यह छापेमारी और नमूने लेने की कार्रवाई क्यों की जाती है? चूंकि, स्वास्थ्य मानव जीवन की सबसे बड़ी नेमत है, इससे खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो। इसलिए जरूरी है कि शासन-प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसा सख्त और कारगर कदम उठाए कि ऐसा घिनौना कार्य करने से पहले वह कई बार सोचें। वे सजा के डर से ही मिलावटखोरी को हमेशा के लिए छोड़ देने को विवश हो जाए। निःसंदेह ऐसा होने से लोग कम बीमार पड़ेंगे, परिणाम स्वरूप अस्पतालों पर कम दबाव पड़ेगा और लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। आमजन की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे खाद्य पदार्थों का चयन सावधानीपूर्वक करें। किसी भी ऐसी जगह से खानपान की वस्तुएं न खरीदें, जहां मिलावट होने की संभावना अधिक हो। स्वस्थ खाएं और स्वस्थ रहें।

■ रतन कुमार श्रीवास्तव 'रतन', लखनऊ

बड़ा खतरनाक है 'ब्लू व्हेल गेम' !

चिट्ठी 2

अमेरिका में कुछ समय पहले एक भारतीय छात्र की जान चली गई थी। अब पता चला है कि छात्र ने एक गेम खेलते हुए अपनी जान दे दी थी। ऐसी आशंका जताई गई थी कि मौत के पीछे 'ब्लू व्हेल चैलेंज' गेम हो सकता है। इसे सुसाइड गेम भी कहा जाता है। ब्लू व्हेल चैलेंज गेम एक ऑनलाइन गेम है, जिसमें प्रतिभागियों को एक चैलेंज दिया जाता है। सूत्रों के अनुसार, इस चैलेंजर गेम को खेलते हुए छात्र ने 2 मिनट तक सांस रोक रखी थी।

यह गेम काफी खतरनाक कहा जाता है तथा इसका बच्चों पर काफी समय तक मानसिक असर रहता है। इसके भय से वह काफी गुमसुम और लोगों से काफी दूर-दूर रहने लगते हैं। आपको बता दें कि भारत में कई साल पहले ब्लू व्हेल गेम पर प्रतिबंध की बात चली थी, परंतु इसके बावजूद भी केवल एक एडवाइजरी जारी कर छोड़ दिया गया था। 2017 में जारी एडवाइजरी में कहा गया था कि ब्लू व्हेल गेम लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला गेम है, इसीलिए बच्चों को इससे दूर रहने की सलाह दी गई थी। सर्वविदित है कि 2015 से लेकर अब तक ब्लू व्हेल गेम से कई मौतें हो चुकी थीं। अभी भी हम सचेत नहीं हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए इस गेम पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं और एक नया व कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि हमारी नई युवा पीढ़ी को इस खतरनाक गेम से सुरक्षित रखा जा सके। माता-पिता को भी चाहिए कि वे इस बात की जानकारी रखें कि उनके बच्चे कौन-सा गेम खेल रहे हैं। ऐसा न हो कि पता चलने से पहले स्थित खराब हो जाए।

■ एमएम राजावतराज, शाजापुर

सेहत व सम्मान की बात है...

चिट्ठी 3

विश्व मजदूर दिवस (01 मई) मजदूरों के सम्मान और उनके उचित अधिकारों की सुरक्षा, कल्याण के लिए समर्पित है। मजदूर वर्ग की अवहेलना करना विश्व को संकट में डाल सकता है। इस वर्ष मजदूर दिवस का विषय 'सामाजिक न्याय और सभी के लिए सभ्य कार्य' रखा गया है। अगर हम वैश्विक स्तर पर विकास क्रम के पथ पर नजर दौड़ाएं, तो बीते कुछ सालों में वैश्वीकरण ने रोजगार की परिभाषा बदल दी है। काम करने के तरीके भी बदले हैं। कोरोना काल तो एक तरह से रिमोट वर्किंग का रूप बनकर आज भी बीते दिनों की याद दिलाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि देश के कुल मजदूरों में से 93 प्रतिशत मजदूर असंगठित रूप से कार्यरत हैं। विशेषकर दिहाड़ी मजदूर की स्थिति दयनीय है। किसी दिन काम है तो किसी दिन नहीं। ऐसे में दिहाड़ी मजदूर के परिवार का पालन-पोषण, बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा आदि उसके लिए चिंता का विषय बन जाता है। उसे किसी भी प्रकार का न्याय और सहायता नहीं मिलती। अगर हम मजदूर के स्वास्थ्य की बात करें तो आज भी अधिकांश मजदूर बुखार, दर्द या अन्य परेशानी के बावजूद कार्य करने से पीछे नहीं हटता है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा बीते सप्ताह जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व के 70 फीसदी मजदूरों पर बदलती जलवायु का स्वास्थ्य संबंधी खतरा मंडरा रहा है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते विश्व स्तर पर मजदूरों के स्वास्थ्य और उनके सम्मानजनक जीवन के लिए लाभकारी योजनाएं बनाई जाएं।

■ अशोक वार्ष्णेय, हल्द्वानी

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं
लखनऊ से नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, जालंधर से राजेश कुमार चौहान, फिरोजाबाद से नितिन रावत, बरेली से दिलीप कुमार गुप्ता, फिरोजाबाद से शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, मेरठ से डॉ. नरेन्द्र टोंक, बाड़मेर से मुकेश बोहरा अमन, मेरठ से मनोज पुरुषार्थी, लखनऊ से निखिल रस्तोगी, आजमगढ़ से अवनीश कुमार गुप्ता, बिलासपुर से लकेश चंदेल, अमरोहा से डॉ. महताब अमरोहवी।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

चमत्कारों से भरा बेताल का दरबार

पृथ्वी पर भैरव ने कुमाऊं क्षेत्र को अपना प्रथम निवास स्थल बनाया। कहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम बेतालघाट है।

नैनीताल का बेतालघाट इलाके के पास ढेर सारी कहानियां हैं, जो कई बार अविश्वसनीय भी लगती हैं। लेकिन इस इलाके में बेताल के किस्से लोग बड़े चाव से सुनते और सुनाते रहे हैं।

लगभग 30-40 साल पहले इस इलाके में स्थानीय निवासियों द्वारा निकाली गई बेताल की बारात का समाचार सुर्खियों में रहा था। तब से इस भूभाग को विशेष रूप से प्रसिद्धि मिली। विक्रम व बेताल की कहानी किस्से इतिहास में जितने रोमांचकारी है, उतने ही रोमांचकारी यहां बेताल बुबू के किस्से है। आज भी देशभर में जितने भी प्राचीन स्थलों के नाम के साथ 'घाट' शब्द जुड़ा है, वहां भगवान शिव का महान गण 'बेताल' भिन्न-भिन्न नामों से विराजमान है तथा जन-जन से पूजित है। कहते हैं, बेताल घाट में 'बेताल' ने सर्वप्रथम पदार्पण किया तथा अपने मूल स्वरूप में ही साक्षात् विराजमान हैं। जिन्हें अब 'नकुआ बूबू' कहा जाता है।

वैसे बेताल के संबंध में शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में वर्णन मिलता है। उसके अनुसार, मां पार्वती के श्राप के कारण महादेव के परम भक्त भैरव को बेताल बनकर पृथ्वी लोक आना पड़ा। पृथ्वी पर भैरव ने कुमाऊं के बेतालघाट क्षेत्र में कौशिकी गंगा नदी के तट को अपना प्रथम निवास स्थल बनाया। बेताल देवता ने अपने आराध्य शिव की बेतालेश्वर रूप में स्थापना की। यह जगह नैनीताल से करीब 50 किलोमीटर दूर है। इतने मोड़ हैं कि यहां आने तक रहस्यमय अनुभव होने लगता है। दूर-दराज से आने वाले पर्यटक, साधक, शोध छात्र, फोटोग्राफी करने वाले और रोमांचक पहाड़ी यात्रा के शौकीन यहां पतित पावनी कौशिकी गंगा (कोसी) नदी के पावन तट पर लोग उनके चमत्कारिक दरबार में जैसे ही माथा टेकते हैं, और एक अनोखे अनुभव से भर जाते हैं।

■ हरीश चंद्र पांडे, नैनीताल

पहले-पहले पोर्टेबल हेयर ड्रायर

यह तस्वीर 'पोर्टेबल हेयर ड्रायर' की है। इसमें एक महिला हेयर ड्रायर की मदद से अपने बाल सुखा रही है। हालांकि, उस वक्त यह मशीन ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर पाई थी।

■ हरिद्वार से राधा वर्मा

छायानट

प्रोमो एडिटिंग से फिल्म बनाने तक का सफर

राजकुमार हिरानी को हिंदी सिनेमा के बड़े निर्देशकों में गिना जाता है। क्या आप जानते हैं कि एडिटिंग के गुर ने ही उनके फिल्मी कॅरिअर की बुनियाद रखी थी। जब विधु विनोद चोपड़ा '1942 ए लव स्टोरी' बना रहे थे तो उस फिल्म का और फिल्म 'करीब' का प्रोमो हिरानी ने बनाया था। साल 2000 में 'मिशन कश्मीर' की एडिटिंग का मौका हिरानी को मिला था। वहीं से हिरानी ने फैसला किया कि वह अपनी फिल्म बनाएंगे। करीब एक साल तक उन्होंने कोई दूसरा काम नहीं किया। वह सिर्फ एक कहानी पर काम करते रहे। कहानी उनके उन असल दोस्तों के इर्द-गिर्द थी, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते थे। अभिनेता अनिल कपूर, विवेक ओबरॉय से लेकर शाहरुख खान तक होते हुए राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त के साथ अपनी पहली फिल्म 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' बनाई। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में संजय दत्त शुरू में वह रोल कर रहे थे, जिसे बाद में जिमी शेरगिल ने किया।

■ विवेक कुमार, दिल्ली

कांग्रेस के घोषणापत्र में क्या है?

लोकसभा चुनाव का मतदान जारी है। इस बार 'कांग्रेस के वादे' और 'मोदी की गारंटी' के बीच मतदाता किधर हैं? कांग्रेस के घोषणापत्र को लेकर जो सियासी घमासान मचा है, उसे क्या कांग्रेस की रणनीतिक जीत माना जा सकता है?

पी चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय मंत्री

ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सद्भावना और सहयोग के अभूतपूर्व संकेत के तौर पर कांग्रेस के घोषणापत्र को एक बार फिर से अपनी ओर से लिखने और अपने विचारों को उसमें शामिल करने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। उनका मानना है कि राजनीतिक संवाद को बेहतर बनाया जाए। बीते सप्ताह जितना कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा उसके बाद मेरी राय तो यही है।

इस राजनीतिक परिदृश्य के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 14 अप्रैल को जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी किया गया था, यह स्पष्ट हो गया था कि मोदी, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज से खुश नहीं थे। समिति ने भी चुपचाप इस बात को स्वीकार कर लिया कि यह किसी राजनीतिक दल का घोषणापत्र नहीं है, बल्कि किसी एक आदमी की महानता को श्रद्धांजलि है, जिसने पार्टी को तैयार किया है। समिति ने उस दस्तावेज को मोदी की गारंटी का नाम देकर अपनी कृतज्ञता जाहिर कर दी। हालांकि पीएम मोदी ने 'जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं' और मोदी की गारंटी वाली बात इसके जारी होने के कुछ ही घंटों के बाद गायब हो गई। आज न तो कोई भाजपा के घोषणापत्र की बात करता है और न ही अब मोदी की गारंटी की गूंज सुनाई देती है।

मूल घोषणापत्र पर टिप्पणी

पीएम मोदी भी अब मोदी की गारंटी को नकार नहीं सकते और न ही मसौदा तैयार करने वाली समिति को अक्षम बता सकते हैं। अब उन्होंने नई चाल चलते हुए कांग्रेस के घोषणापत्र पर अपनी टिप्पणी करके इस घोषणापत्र को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। यह भारतीय साहित्य की उन महान परंपराओं की तरह ही है, जहां टिप्पणियां किए गए कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मोदी द्वारा कांग्रेस के घोषणापत्र की नए सिरे से राजनीतिक व्याख्या में निम्नांकित तथ्य शामिल हैं :

- कांग्रेस लोगों की जमीन, सोना और अन्य कीमती सामान मुसलमानों में बांटेगी।
- कांग्रेस व्यक्तियों की संपत्ति, महिलाओं के पास मौजूद सोने और आदिवासी परिवारों के पास मौजूद चांदी का मूल्य निर्धारण करने और उन्हें छीनने के लिए सर्वेक्षण कराएगी।
- सरकारी कर्मचारियों की जमीन और नकदी कांग्रेस द्वारा जब्त और वितरित की जाएगी।
- डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला दावा मुसलमानों का है और जब डॉ. सिंह ने यह बात कही तो मैं (गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में) मौजूद था।
- कांग्रेस आपका मंगलसूत्र और स्त्रीधन छीन लेगी और उन लोगों को दे देगी, जिनके अधिक बच्चे हैं।
- अगर आपके पास गांव में घर है और आप शहर में एक छोटा सा फ्लैट खरीदते हैं, तो कांग्रेस उनमें से एक घर छीन लेगी और किसी और को दे देगी।

साथ काम करने वालों के बीच प्रतिस्पर्धा

पीएम मोदी के भरोसेमंद सिपहसालार और सलाहकार, अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मंदिरों की संपत्तियों को जब्तकर लोगों में बांट देगी, जबकि राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस लोगों की संपत्ति हड़प लेगी और उन्हें घुसपैठियों को फिर से बांट देगी। अगले ही दिन, राजनाथ सिंह ने अपनी टिप्पणी में यह कहकर एक और रत्न जड़ दिया कि कांग्रेस ने सशस्त्र बलों में धर्म-आधारित कोटा शुरू करने की योजना बनाई थी।

जैसे-जैसे टिप्पणीकारों की संख्या बढ़ती गई , वे एक-दूसरे से आगे निकलते गए। दूसरी तरफ मोदी को पता चला कि कांग्रेस 'विरासत कर' लागू करने की योजना बना रही थी और उन्होंने इस कर के खिलाफ आवाज उठाई। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी टिप्पणी वाले रणक्षेत्र में कूद पड़ीं और 'विरासत कर' को लेकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। हालांकि उन्हें जानकारी के अभाव में इस बात के लिए माफ किया जा सकता है कि संपत्ति शुल्क (एक प्रकार का विरासत कर) को 1985 में कांग्रेस सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था और संपत्ति कर 2015 में भाजपा सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यह देखना मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस के घोषणापत्र पर एक साथ हमला क्यों और कब शुरू हुआ ? 19 अप्रैल को पहले दौर के मतदान के बाद ही पीएमओ और भाजपा में घबराहट फैल गई है। पीएम मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में जो हमला शुरू किया, वह उसके बाद से रुके नहीं।

भाजपा ने जिन काल्पनिक लक्ष्यों की सूची बनाकर कांग्रेस पर हमला शुरु किया, वह अटपटा सा था। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी खूब शब्दबाण छोड़े। इस बात को लेकर मीडिया का कर्तव्य बनता था कि वह इस पागलपन को रोकने के लिए आवाज उठाए, लेकिन इसके बजाय, समाचार पत्रों ने विवादास्पद विषयों की 'व्याख्या' की और एक से बढ़कर एक संपादकीय लिखे। टीवी चैनलों ने राजनीतिक पंडितों के साक्षात्कार ले -लेकर चर्चा की। पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया नकली युद्ध कई गुना बढ़ गया।

क्या उम्मीद की जा सकती थी?

5 से 19 अप्रैल के बीच कांग्रेस का घोषणापत्र पूरे भारत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया था। खासकर उसके निम्नलिखित वादों ने लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ी थी -

- सामाजिक-आर्थिक और जाति सर्वेक्षण;
- आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाना;
- मनरेगा श्रमिकों के लिए 400 रुपये दैनिक वेतन;
- सबसे गरीब परिवारों के लिए महालक्ष्मी योजना;
- कृषि उपज के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी;
- कृषि ऋण माफी पर सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति;
- युवाओं को प्रशिक्षण का अधिकार;
- अग्निवीर योजना की समाप्ति;
- डिफॉल्ट किए गए शिक्षा ऋणों की माफी और
- केंद्र सरकार में 30 लाख रिक्तियां एक साल में भरने का वादा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जब कांग्रेस के घोषणापत्र को 'लोकसभा चुनाव का हीरो' बताया, तब वे निशाने पर आ गए। स्टालिन के बयान ने पीएम को आहत जरूर किया, इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र को एक 'खलनायक' के रूप में देश के सामने लाने का निर्णय लिया। उनके लिए दुर्भाग्य की बात यह रही कि कांग्रेस के घोषणापत्र के किसी भी हिस्से को गलत नहीं ठहराया जा सका। इसलिए, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणापत्र को एक 'भूत' द्वारा लिखा गया बताकर उसे रद्दी में डालने का फैसला किया। मेरे विचार से, यह एक भाजपाई प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस के वास्तविक घोषणापत्र को दी जाने वाली सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है! अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आती है तो उससे किस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को इन घोषणापत्रों को दोबारा लिखने में सफलता हासिल मिल जाती है तो वे भारत के संविधान को भी फिर से लिख सकते हैं।

Licensed by
The Indian Express Limited

कर्मों की बैलेंसशीट में हानि या लाभ !

डॉ. निर्मल जैन

खुला आकाश

बढ़ती उम्र हमारे चेहरे पर वरिष्ठता के जो निशान छोड़ती है, उनसे अपने को ऊर्जावान दिखाने के लिए चुस्त-दुरुस्त और सेहतमंद बनाए रखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा है।

बढ़ती उम्र का हर वर्ष अच्छा, बुरा या नया अनुभव देकर जाता है। जो कुछ अप्रिय था, उसकी पुनरावृत्ति न हो इसको लेकर हम कितने सतर्क रहे हैं? माता-पिता, भाई-बहन, नाते-रिश्तेदार, मित्र और जीवनसाथी जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को छुआ है। इनमें से कुछ की छुअन अंदर तक मिठास दे गई, यानी 'पॉजिटिव' रही। वहीं, कुछ ऐसे भी संपर्क में आए, जिन्होंने स्वाद को कसैला कर दिया, यानी एक नकारात्मक अनुभूति देकर गए। मिठास भरी सकारात्मकता से हम आगे बढ़े हैं और कड़वाहट भरी नकारात्मकता ने हमें सावधान किया है। मगर आपने इनके प्रति कृतज्ञता भाव रखा या भूल गए?

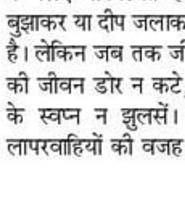

इस सब आकलन के साथ क्या हमको और बेहतर जीवन के लिए यह सावधानियां बरतनी जरूरी नहीं हैं? चढ़ती उम्र हमारे चेहरे, शरीर पर वरिष्ठता के जो निशान छोड़ती है, उनसे कोई शर्मिंदगी नहीं अपितु अपने को ऊर्जावान दिखाने के लिए चुस्त-दुरुस्त और सेहतमंद बनाए रखने के प्रयास करने होंगे। प्रभु के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करें कि इतने लंबे समय तक सबके साथ रहने और ज्ञान अर्जित करने का उपहार हमें मिला। कोशिश करें कि बिना किसी सहारे और अवरोध के अपने बच्चों के साथ ही नहीं, बच्चों के बच्चों के साथ भी ज्यादा दूर तक चल सकें। पूरी उमंग के साथ घुलने-मिलने का उत्साह बना रहे। बदलते परिवेश में परिवार के मुखिया के रूप में नहीं, अपितु माली बनकर उसकी देखभाल करनी है। प्रत्येक पल जो बीत रहा है, उससे हमारा जीवन-वाहन का 'मॉडल' पुराना होता जा रहा है, इसलिए दिल और दिमाग पर अनावश्यक बोझ न डालें। कम खाकर कोई नहीं मरा है। स्वस्थ रहना अपने खुद के लिए ही नहीं, परिवार और समाज के लिए सुखकारी। किस तरह मरेंगे, यह तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इतना तो अपने वश में है कि जन्म की तरह मृत्यु में भी हंसी-खुशी वाला जश्न हो। इसके लिए सतर्क रहें, सजग रहें। सेहतमंद इंसान की तरह दूसरों के लिए एक उदाहरण बनकर विदा लेने के लिए संकल्पित हों। जन्मदिन केक काटकर, मोमबत्ती बुझाकर या दीप जलाकर मनाएं, इसमें विकल्प चुना जा सकता है। लेकिन जब तक जीवन शेष है हमारे किसी कृत्य से किसी की जीवन डोर न कटे, आशा की ज्योत बुझे नहीं और किसी के स्वप्न न झुलसें। वह दिन न देखना पड़े कि अपनी लापरवाहियों की वजह से दूसरों पर बोझ बन जाएं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कल्पमेधा

प्रगतिशील समाज संगठनों की उपयोगिता से आगे निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार, जैसे बच्चों की पोशाकें छोटी पड़ जाती हैं।
- हेनरी जार्ज

कांग्रेस के घोषणापत्र का पुनर्लेखन

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

कांग्रेस को प्रधानमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उन्होंने लोगों को यह सब बताया कि अगर भाजपा (मोदी साहब के नेतृत्व में) तीसरी बार जीतती है, तो किस तरह की विकृतियों, झूठ और दुर्व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है।

अभूतपूर्व सहयोग और सद्भाव का परिचय देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वेच्छा से कांग्रेस के घोषणापत्र के पुनर्लेखन और अपने अंदर के विचारों और चिंतन को जाहिर करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। उनका मानना है कि इससे राजनीतिक विमर्श समृद्ध होगा। गुजरे हफ्ते जो कुछ हुआ, उसकी मैं यही सबसे उदार व्याख्या कर सकता हूं।

इस बयान के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। 14 अप्रैल को, जब भाजपा का घोषणापत्र जारी किया गया, तो करीबी राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने नोट किया कि भोलेभाले राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किए गए भाजपा के उस दस्तावेज से मोदी साहब खुश नहीं थे। समिति ने चुपचाप स्वीकार कर लिया था कि यह किसी राजनीतिक दल का घोषणापत्र नहीं, बल्कि उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है, जिसने 'पार्टी का मूल' स्वरूप तैयार किया। इसलिए समिति ने दस्तावेज को 'मोदी की गारंटी' कहकर उचित सम्मान दिया। हालांकि, जैसा कि मोदी साहब ने सही अनुमान लगाया था, 'मोदी की गारंटी' जारी होने के कुछ घंटों के भीतर ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। आज कोई भी भाजपा के घोषणापत्र के बारे में बात नहीं करता, यहां तक कि मोदी साहब भी नहीं। 'मोदी की गारंटी' की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है।

मूल पर टिप्पणी

मोदी साहब न तो 'मोदी की गारंटी' को रद्दी की टोकरी में फेंक सकते हैं और न मसौदा समिति को उसकी अयोग्यता या मलिन मंशा के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ऐसे में, मोदी साहब ने कांग्रेस के घोषणापत्र को विशेष रूप से उठाने और उस पर अपनी टिप्पणी के साथ उसकी दृश्यता और पाठक संख्या बढ़ाने का फैसला किया। यह भारतीय साहित्य की उस महान परंपरा के अनुरूप था, जिसमें मूल कार्य से अधिक उस पर की गई टिप्पणियां महत्त्वपूर्ण होती हैं।

मोदी साहब ने कांग्रेस के घोषणापत्र की साज-सज्जा में निम्नलिखित रत्न जड़े हैं:

- कांग्रेस लोगों की जमीन, सोना और अन्य कीमती संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी।
- कांग्रेस व्यक्तियों की संपत्ति, महिलाओं का सोना और आदिवासी परिवारों के पास मौजूद चांदी का मूल्य निर्धारण करने और उन्हें छीनने के लिए सर्वेक्षण कराएगी।
- कांग्रेस, सरकारी कर्मचारियों की जमीन और नकदी जब्त कर बांट देगी।
- डा मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला दावा मुसलमानों का है, और जब डा सिंह ने यह बात कही तो मैं (गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में) मौजूद था।
- कांग्रेस आपका मंगलसूत्र और स्त्रीधन छीन कर उन लोगों को दे देगी, जिनके अधिक बच्चे हैं।
- अगर आपके पास गांव में घर है और आपने शहर में भी एक छोटा-सा फ्लैट खरीद रखा है, तो कांग्रेस उनमें से एक घर छीन लेगी और किसी और को दे देगी।

सहयोगियों में प्रतिस्पर्धा

मोदी साहब के भरोसेमंद सिपाही और सलाहकार, अमित शाह ने कहा: कांग्रेस मंदिर की संपत्तियों को जब्त कर उन्हें वितरित कर देगी। राजनाथ सिंह ने यह कहकर अपना योगदान दिया कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति हड़प कर उसे घुसपैठियों को फिर से वितरित कर देगी। अगले दिन, राजनाथ सिंह ने एक और नगीना पेश किया: कांग्रेस ने सशस्त्र बलों में धर्म-आधारित कोटा शुरू करने की योजना बनाई है।

जैसे-जैसे टिप्पणीकारों की संख्या बढ़ती गई और वे एक-दूसरे से आगे निकलते गए, मोदी साहब को पता चला कि कांग्रेस 'विरासत कर' लागू करने की योजना बना रही है और उन्होंने इस कर के खिलाफ आवाज उठाई। निर्मला सीतारमण भी इसमें कूद पड़ीं और विरासत कर के विचार में अपनी बुद्धिमत्ता का योगदान दिया। हालांकि उनकी इस अज्ञानता के लिए माफ किया जा सकता है कि संपत्ति शुल्क (एक प्रकार का विरासत कर) कांग्रेस सरकार ने 1985 में समाप्त कर दिया था और संपत्ति कर 2015 में भाजपा सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

यह देखना मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस के घोषणापत्र पर समन्वित हमला क्यों और कब शुरू हुआ। 19 अप्रैल को पहले दौर के मतदान के बाद पीएमओ और भाजपा में घबराहट फैल गई। मोदी साहब ने 21 अप्रैल को राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में हमला शुरू किया और फिर रुके नहीं। उनके काल्पनिक लक्ष्यों की सूची विचित्र थी। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी अंधाधुंध गोलीबारी की। मीडिया का कर्तव्य था कि वह इस पागलपन को रोकने का आह्वान करे। मगर इसके बजाय, अखबारों ने इन विवादास्पद विषयों की 'व्याख्या' की और उन पर विद्वतापूर्ण संपादकीय लिखे। टीवी चैनलों ने 'पंडितों' के साक्षात्कार प्रसारित किए और 'पैनल चर्चा' आयोजित की। मोदी साहब द्वारा शुरू किया गया छद्म युद्ध कई गुना बढ़ गया।

उम्मीद की सूरत

पांच से 19 अप्रैल के बीच कांग्रेस का घोषणापत्र पूरे भारत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया था। उसमें किए गए निम्नलिखित वादों ने लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ी थी।

- सामाजिक-आर्थिक और जाति सर्वेक्षण;
- आरक्षण पर 50 फीसद की सीमा समाप्त करना;
- मनरेगा श्रमिकों को 400 रुपए दैनिक मजदूरी;
- सबसे गरीब परिवारों के लिए महालक्ष्मी योजना;
- कृषि उपज के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी;
- कृषि ऋण माफी पर सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति;
- युवाओं के लिए शिक्षुता यानी अप्रेंटिशशिप का अधिकार;
- अग्निवीर योजना की समाप्ति;
- बकाया शिक्षा ऋणों की माफी; और
- केंद्र सरकार में 30 लाख खाली पदों को एक साल में भरने का वादा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जब कांग्रेस के घोषणापत्र को 'लोकसभा चुनाव का नायक' बताया, तो वे निशाने पर आ गए। इससे मोदी साहब अवश्य आहत हुए होंगे, उन्होंने दस्तावेज को खलनायक के रूप में चित्रित करने का फैसला किया। मगर उनका दुर्भाग्य कि कांग्रेस घोषणापत्र के किसी भी हिस्से को गलत नहीं ठहराया जा सका। इसलिए, मोदी साहब ने एक भूत द्वारा लिखे गए घोषणापत्र की कल्पना की और उसे रद्दी की टोकरी में डालने का फैसला किया। मेरे विचार से, यह एक भाजपा प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस के वास्तविक घोषणापत्र को दी जाने वाली सर्वोत्तम आदरांजलि है!

कांग्रेस को प्रधानमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उन्होंने लोगों को यह सब बताया कि अगर भाजपा (मोदी साहब के नेतृत्व में) तीसरी बार जीतती है, तो किस तरह की विकृतियों, झूठ और दुर्व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है। घोषणापत्रों को दुबारा लिखने में कामयाबी हासिल करने के बाद, नरेंद्र मोदी भारत के संविधान को फिर से लिख सकते हैं।

हुए ऐसे दोस्त जिनके...

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

राहुल गांधी शायद भूल रहे हैं कि उद्योगपतियों के पैसे से चलती हैं सरकारों की विशाल समाज कल्याण योजनाएं और इनके चलने से गरीबी कम हुई है भारत में। इसलिए जब पित्रोदा जैसे लोग जबरदस्ती पैसा वसूलने की सलाह देते हैं कांग्रेस पार्टी के मुखिया को, तो वे उनका भला नहीं कर रहे हैं। सच पूछिए तो समझना मुश्किल है कि राहुल गांधी इस किस्म के सलाहकार अपने करीबियों में रखते क्यों हैं।

जब से कांग्रेस पार्टी के असली मुखिया और गांधी परिवार के वारिस ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके सलाहकारों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में उनके लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहा है। पिछले सप्ताह जब सैम पित्रोदा सामने आए, तो मेरे लिए इस रहस्य का पर्दा उठ गया। पित्रोदा साहब अभी तक कहीं छिपे बैठे थे, लेकिन ऐन वक्त पर टीवी पर आकर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के भले के लिए जरूरी है उस पुराने विरासत कर को वापस लाना, जिसके लाने के बाद सरकार का हक होगा भारतीय नागरिकों की आधी संपति पर उनकी मौत के बाद।

पित्रोदा साहब ने कहा कि ऐसा कर अमेरिका में भी है, इसलिए भारत में क्यों न हो! यहां उन्होंने आधा सच बोला, पूरा नहीं। अमेरिका के कुछ राज्यों में ऐसा विरासत कर है, लेकिन अमेरिकी सरकार ऐसा कोई कर नहीं लगाती है। पित्रोदा ने अपने इस साक्षात्कार में स्पष्ट नहीं किया कि यह कर सिर्फ अमीरों के लिए होना चाहिए। तो मोदी ने इसका फायदा उठाकर अपनी अगली आमसभा में कहा कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है इस लोकसभा चुनाव के बाद तो माताओं-बहनों का सोना, उनके मंगलसूत्र को उनसे छीन लिया जाएगा। राहुल गांधी की बहन ने अपने खास अंदाज में दहाड़ते हुए कहा 'मोदी झूठ बोलते हैं'। आगे याद दिलाया कि उनकी दादी ने अपना मंगलसूत्र देश को दान कर दिया था और उनकी माताजी का मंगलसूत्र देश के लिए बलिदान हो गया था। लेकिन जो नुकसान पित्रोदा के बयान ने किया था, वह 'हुआ तो हुआ'।

ऊपर से जब अगले दिन ही राहुल गांधी ने हैदराबाद में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना करवाना उनके लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, उनके जीवन का 'मिशन' बन गया है, तो तकरीबन साबित हुआ कि पित्रोदा साहब हवा में नहीं बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपने कई भाषणों में स्पष्ट किया है कि इस जनगणना के बाद वे संकल्प लेते हैं कि जातियों के आधार पर देश का धन बांट दिया जाएगा। स्पष्ट किया कि मोदी ने जो अपने 'धनवान दोस्तों' के कर्जे माफ किए हैं, उसी पैसे से किसानों का कर्ज माफ होगा, गरीबों में बांटने का काम होगा। राहुल गांधी की समस्या यह है कि वे समझे नहीं कि धन पैदा करनेवाले कौन हैं। सरकार का अपना पैसा तो है नहीं! कुछ हम-आप देते हैं कर चुका कर। मगर अधिकतर पैसा आता है उनसे, जिन्होंने इतना धन कमाया हो कि सरकार की तिजोरियों को भरने के काम आ सके। हमारे-आप में यह क्षमता कहां है! तिजोरियां भरने वाले सिर्फ वे लोग हैं जो बड़े-बड़े उद्योग चलाते हैं। कुछ धन अपने लिए रखते हैं और कुछ सरकार के हवाले करते हैं।

मेरी उम्र के लोगों ने वे दिन देखे हैं, जब भारत सरकार के पास पैसा इतना थोड़ा होता था कि काफी हद तक धनी विकसित देशों की मदद पर निर्भर था भारत। वे दिन थे लाइसेंस राज के दिन, उद्योगपतियों पर सत्तानबे फीसद कर लगने के दिन। कर का बोझ इतना था कारोबारियों पर कि काला धन पैदा होना शुरू हुआ। निजी क्षेत्र का खून चूसने का काम करती थी सरकार। बड़े उद्योगपतियों का हाल यह था कि उधार लेकर कर चुकाते थे। यानी न धन पैदा हो रहा था देश में, न मध्यवर्ग की जगह बनी थी। गरीबी की बेड़ियों में बंधे रहते थे भारत के आधे लोग। अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो भारत में उतने ही गरीब लोग थे, जितने उनके शासनकाल समाप्त होने के बाद।

गरीबी भारत में तब हटने लगी जब लाइसेंस राज को समाप्त करके उद्योगपतियों को धन कमाने के मौका दिया गया और वह भारत सरकार की तिजोरियां भरने लायक हुए। माना कि कुछ पैसा राजनेताओं को खुश रखने में दिया जाता है आज और काफी पैसा चंदे के तौर पर देते हैं बड़े उद्योगपति, सत्ताधारी राजनीतिक दलों को। मगर राहुल गांधी शायद भूल रहे हैं कि उद्योगपतियों के पैसे से चलती हैं सरकारों की विशाल समाज कल्याण योजनाएं और इनके चलने से गरीबी कम हुई है भारत में। इसलिए जब पित्रोदा जैसे लोग जबरदस्ती पैसा वसूलने की सलाह देते हैं कांग्रेस पार्टी के मुखिया को, तो वे उनका भला नहीं कर रहे हैं। सच पूछिए तो समझना मुश्किल है कि राहुल गांधी इस किस्म के सलाहकार अपने करीबियों में रखते क्यों हैं।

इसी पित्रोदा ने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तथाकथित धर्मनिरपेक्षता को घोर नुकसान तब पहुंचाया जब उन्होंने 1984 वाले सिखों के जनसंहार के बारे में कहा था 'हुआ तो हुआ'। याद रखना जरूरी है कि जो 1984 में हिंसा हुई थी, वे दंगे नहीं थे। उस हिंसा में एक भी हिंदू नहीं मारा गया था, सिर्फ सिख मारे गए थे हजारों की तादाद में। उनको मारने वाले थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और उनको इजाजत दी थी राजीव गांधी की सरकार ने। दिल्ली में हिंसा की मैं गवाह हूं। देखा मैंने अपनी आंखों से कि किस तरह तीन दिन तक छूट मिली थी सिखों का खून बहाने के लिए। उसके बाद ही सरकार ने देश की राजधानी में सेना तैनात की और हिंसा फौरन रुक गई थी। ऐसी हिंसा के बारे में कहना कि 'हुआ तो हुआ' दर्शाता है कि पित्रोदा इस देश की राजनीति को बिल्कुल नहीं समझते हैं।

गांधी परिवार के करीबियों में एक और बंदा है जिसने 2014 के चुनावों में मोदी की बहुत मदद की थी उनको नकारात्मक तरीके से 'चायवाला' कह कर। इसलिए इन दिनों दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में लोग मजाक उड़ाते कह रहे हैं, 'पित्रोदा सिर्फ झांकी हैं, मणिशंकर अभी बाकी है'।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

स्त्री के पीड़ादायी पल

समाज

रंजीता सिंह

एक वैश्विक शोध के मुताबिक, माहवारी के लक्षणों के कारण महिलाओं के काम के घंटे कम हो जाने से सालाना 1.8 अरब डालर तक का नुकसान होता है। अगर वे नौकरी छोड़ने की हालत में नहीं होती हैं, तो उन्हें छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। ये स्थितियां बिगड़ते स्वास्थ्य की भी निशानी होती हैं।

रोजी-रोजगार की जटिल चुनौतियों के बीच कामकाजी महिलाओं को माहवारी के दौरान दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में ब्रिटेन और आयरलैंड ही शायद ऐसे चुनिंदा देश हैं, जहां ऐसी मनोदशा के दौरान महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखी जाती है। इसके अंतर्गत महिलाओं को अवकाश के दिनों का भी वेतन मिलता है। हाल के दिनों में ऐसे कई शोध सामने आए हैं, जिनमें माहवारी के दौरान माइग्रेन पीड़ित कई महिलाओं में हृदय रोग और आघात के लक्षण पाए गए। ऐसी महिलाओं को माइग्रेन होता है, उनमें बाद में लगातार रजोनिवृत्ति का खतरा अधिक होता है। शोधकर्ता हिदायत देते हैं कि ऐसी हालत में महिलाओं को अधिक से अधिक नींद लेनी चाहिए। स्वस्थ भोजन करना चाहिए। ऐसा न करने पर उनका हृदय संबंधी जोखिम बढ़ जाता है।

अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ सभी महिलाओं को एक जैसे अनुभव नहीं होते हैं। कई महिलाएं उन जोखिमों को नियंत्रित कर सकती हैं, जो बाद में हृदय रोग और आघात की संभावना बढ़ा सकते हैं। माइग्रेन और रजोनिवृत्ति के लक्षणों वाली महिलाएं हृदय संबंधी जोखिम के बारे में जो चिंता और भय महसूस करती हैं, वह वास्तविक परिस्थितिजन्य है, मगर इन निष्कर्षों से पता चलता है कि रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने और अस्वास्थ्यकर आदतों और जोखिम कारकों को ठीक करने से ज्यादातर महिलाओं को मदद मिल सकती है। अध्ययन में शामिल मध्यम आयु वर्ग की तीस फीसद से अधिक महिलाओं का कहना था कि उन्हें लगातार रात में पसीना आता है। उनमें से, 23 फीसद ने माइग्रेन होने की भी सूचना दी थी। यह एकमात्र समूह था, जिसमें आघात, दिल के दौरे या अन्य हृदय संबंधी लक्षण परिलक्षित हुए। अध्ययन में शामिल पचास वर्ष की उम्र वाली 43 फीसद महिलाओं में ऐसे लक्षणों का न्यूनतम स्तर रहा और 50 और 60 की उम्र वाली 27 फीसद महिलाओं में समय के साथ वीएमएस में वृद्धि का अनुभव किया गया। बाद के दो समूहों में कोई अतिरिक्त हृदय संबंधी जोखिम नहीं था, चाहे उन्हें माइग्रेन था या नहीं।

खासकर भारत में बंद सामाजिक स्थितियों में झिझक के कारण महिलाओं का दुख-दर्द और भी ज्यादा पीड़ादायी हो जाता है। पहले तो वे इस बारे में जुबान खोलने तक से परहेज करती रही हैं, लेकिन जैसे-जैसे वर्जनाओं की कुंठा कम हो रही है, अब धीरे-धीरे ऐसे मिजाज में परिवर्तन दिखने लगा है। कितना विचित्र है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां महिलाओं को अपनी नौकरी छोड़ने तक के लिए विवश कर देती हैं, जिसका सीधे तौर पर श्रमशक्ति पर भारी दबाव देखा जा रहा है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक, 82 फीसद कामकाजी महिलाओं की काम की स्थितियों पर माहवारी का असहनीय असर पड़ता है। लगभग 26 फीसद महिलाएं माहवारी के दौरान छुट्टी ले लेती हैं और 18 फीसद इस दौरान तकलीफ सहकर भी काम करने को मजबूर होती हैं।

इस स्थायी किस्म के मर्ज के शुरुआती दिन किसी भी युवती या महिला के लिए सहज नहीं होते। दिल-दिमाग तरह-तरह की उलझनों से जूझता है। वे अकेलापन महसूस करती हैं। कुछ महिलाओं को महीने में कई बार माहवारी हो जाती है और उन्हें काम पर जाने से बचना पड़ता है। इस दौरान काम पर जाना और काम करना कठिन होता है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक, लगभग 23 फीसद महिलाएं इसी मानसिकता से गुजरती हुई नौकरी छोड़ने को लेकर गंभीर हो जाती हैं, उनमें से अनेक महिलाएं नौकरी छोड़ देती हैं। हर दस में से नौ महिलाएं कार्यस्थल पर संवेदनशीलता की उम्मीद करती हैं, जो प्रायः संभव नहीं रहता। बेचैनी और भावुकता में प्रायः ऐसी ही महिलाएं, आर्थिक नुकसान उठाते हुए नौकरी छोड़ देती हैं।

एक वैश्विक शोध के मुताबिक, माहवारी के लक्षणों के कारण महिलाओं के काम के घंटे कम हो जाने से सालाना 1.8 अरब डालर तक का नुकसान होता है। अगर वे नौकरी छोड़ने की हालत में नहीं होती हैं, तो उन्हें छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। ये स्थितियां बिगड़ते स्वास्थ्य की भी निशानी होती हैं। वे अपने काम के घंटे कम कर देती हैं या फिर तरक्की के मौके उनके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे हालात से गुजर रही जिन महिलाओं को हर रोज दफ्तर जाना पड़ता है, उन्हें कितनी तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है, वही जानती हैं। अपनी हालत न बता सकने की वजह से वे दिमागी तौर पर झुंझलाहट और बेचैनी से भरी रहती हैं। उनकी ऐसी स्थिति को न घर वाले समझना चाहते हैं, न कार्यस्थल के सहकर्मी आदि।

एक सर्वेक्षण के मुताबिक, भारत में 29 से 34 वर्ष उम्र की चार फीसद महिलाएं वक्त से पहले माहवारी का सामना करती हैं। 35 से 39 वर्ष की करीब आठ फीसद महिलाएं समय से पहले माहवारी की यातना का सामना करती हैं। जो महिलाएं वक्त से पहले ऐसी स्थितियों से गुजरती हैं, उनकी चुनौतियां कहीं अधिक पीड़ादायी होती हैं। कई तो कोई कामकाज करने लायक नहीं रह जाती हैं। कार्यस्थल पर संस्थान भी उनकी इस परेशानी के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें अवकाश देने की कोई व्यावहारिक व्यवस्था नहीं होती है। आमतौर पर कामकाजी महिलाएं अपने परिजनों, बच्चों आदि के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने के कारण अपनी सेहत पर अपेक्षित गौर नहीं कर पाती हैं, जबकि ऐसी पीड़ा के दिनों में उन्हें सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य को संभालना जरूरी हो जाता है।

एक आत्महंता आस्था

बाखबर

सुधीश पचौरी

एक एंकर ने पूछा कि क्या संपत्ति का सर्वे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ही है! फिर कहा कि ये 'अव्यावहारिक समाजवाद' है... ये कांग्रेस का 'एक खतरनाक आइडिया' है। उसने इस पर केंद्रित एक जोरदार चर्चा भी की।

बीता सप्ताह 'कांग्रेस घोषणापत्र' के नाम रहा। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने ही एक रैली में कांग्रेस के घोषणापत्र पर हमला बोला कि अगर ये सत्ता में आए तो हिंदुओं का सोना छीनकर मुसलमानों में बांट देंगे... मंगलसूत्र बांट दिया जाएगा! इसके बाद बहसों की गर्मी देखते ही बनती थी। एक कांग्रेस पक्षधर कहिन कि ये खुली सांप्रदायिकता है। दूसरे ने कहा कि ये भाषा देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देती। तीसरे कहे कि ये ध्रुवीकरण की कोशिश है... पहले दौर के कम मतदान से पैदा हुई निराशा है।

एक विश्लेषक कहिन कि ये ध्रुवीकरण कभी न कभी होना ही था, अब हो गया और क्या? एक पूछे कि क्या ये नए क्रांतिकारी अपनी संपत्ति को पहले बांटेंगे या दूसरों की लेकर ही बांटेंगे! एक अन्य कांग्रेस पक्षधर कहिन कि ये घोषणापत्र 'क्रांतिकारी' है। राहुल का कहना है कि यह देश में बराबरी लाने के लिए जरूरी है... हम करके रहेंगे... पहले जाति गणना करेंगे, फिर क्रांतिकारी कदम उठाएंगे! जवाब में एक भाजपा पक्षधर कहिन कि ये 'माओ पोलपोट' का घोषणापत्र है। दूसरे कहिन कि ये 'लेनिन माओ' का घोषणापत्र है। जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत से कमाया उसकी संपत्ति छीनकर ये घुसपैठियों को दे देंगे। एक कहिन कि कांग्रेस आजकल 'अर्बन नक्सलों' के नियंत्रण में है। एक कांग्रेसी पूछे कि ये बताएं कि घुसपैठिए कौन हैं, तो जवाब आया कि रोहिंग्या हैं।

एक इस्लामी नेताजी एक रैली में गरजे कि क्या हम घुसपैठिए हैं! हमने ताजमहल दिया है... लाल किला दिया... ये मुल्क हमारा था है और रहेगा।

एक भाजपा प्रवक्ता बोला कि कांग्रेस तो पहले ही देश को पांच बार बांट चुकी है। सैंतालीस में बांटा, फिर तब, तब और तब बांटा और ये अब फिर बांटने की सोच रहे हैं। एक एंकर कहिन कि ये मोदी जी का अपने कार्यकर्ताओं को 'तिकतिकाने' के लिए है। चैनल राहुल के घोषणापत्र वाले बयान को बार-बार बजाते रहे, जिसमें वे कहते दिखते कि हम जातिगणना कराएंगे... आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे... क्रांतिकारी कदम उठाएंगे।

एक एंकर ने हवाला दिया कि क्या संपत्ति का सर्वे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ही है! फिर कहा कि ये 'अव्यावहारिक समाजवाद' है... ये कांग्रेस का 'एक खतरनाक आइडिया' है। उसके बाद उसने इस पर केंद्रित एक जोरदार चर्चा भी की। एक अल्पसंख्यक नेताजी कहिन कि मोदी हिटलर की तरह बोल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में नए-नए तरीके से बोलते रहे। एक रैली में वे फिर गरजे कि साहबजादे विदेश से एक्सरे मशीन लाए हैं। वे कह रहे हैं कि आपकी जायदाद का एक्सरे करेंगे और अपने वोट बैंक को बांट देंगे।

एक एंकर की लाइन रही कि राहुल का यह कहना कि हम क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। इसमें वे फंस सकते हैं। एक अन्य एंकर कहिन कि पहले जातिगणना की बात की, फिर संपत्ति गणना की बात की, फिर संपत्ति 'वितरण' की बात की। ये 'वितरण' शब्द अपने आप में चिंताजनक है। 'वितरण' को वे 'ऐतिहासिक कर्तव्य' कहते हैं। फिर एक एंकर ने लाइन दी कि ये 'तुष्टीकरण का हारर' है। राहुल को समझना होगा कि आप लोगों के जीवन भर की गाढ़ी कमाई को यों ही नहीं बांट सकते। ये कांग्रेस का 'आत्महत्यात्मक कदम' है। इतने में सैम पित्रोदा का 'विरासत टैक्स' वाला उवाच कि ये टैक्स अमेरिका में है। पैसे वाले मृतक की कमाई का पचपन फीसद सरकार ले लेती है। सिर्फ पैंतालीस फीसद उसके वारिसों को मिलता है। यही भारत में होना चाहिए।

पित्रोदा का इतना बोलना था कि मोदी ने तुरंत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 'संपत्ति पर अल्पसंख्यकों का पहला हक' वाले बयान, फिर राहुल के घोषणापत्र के एलान और पित्रोदा के इस बयान को जोड़ कर जड़ा कि अब ये विरासत पर भी कर लगाएंगे। जब ये तूफान आगे बढ़ा तो एक कांग्रेसी प्रवक्ता को कहना पड़ा कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं।

एक चैनल ने 'हैशटैग' मारा कि ये कांग्रेस का खतरनाक 'स्नेच मनी' षड्यंत्र है। ये 'आत्महंता मिशन' है। एंकर ने कहा कि आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी... अल्पसंख्यकों को दे दी जाएगी। ये किसी भी प्रकार की उद्यमिता को खत्म कर देंगे। ये नीति 'एंटी कैपिटलिस्ट', 'एंटी मार्केट' और 'एंटी ग्रोथ' है।

इसी बीच एक दिन कर्नाटक से 'लव जिहाद और हत्या' बरक्स 'प्रेम कहानी और हत्या' की खबर चैनलों में छाई रही। मृतक नेहा के पिता एक चैनल पर आकर कहते दिखे कि ये 'केरला स्टोरीज' की तरह हुआ है... सीबीआइ जांच करे, लेकिन राज्य ने कहा कि उसकी पुलिस जांच के लिए काफी है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने 'सौ फीसद वीवीपैट पर्ची की मांग' को खारिज करके विवाद को अंतिमतः शांत कर दिया। मोदी जी ने तुरंत कहा कि आज का दिन लोकतंत्र की विजय का दिन है। और क्यों न हो! शुक्रवार के दिन 88 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान सुबह से होता दिखा। बूथों पर भीड़ दिखी।

www.readwhere.com

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आर्थिक न्याय फार्मूले और उनके सहयोगी सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स के विचार ने आम चुनाव के दौरान राजनीतिक तूफान ला दिया है। भाजपा को बैठे-बिठाए कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि उसकी सरकार आएगी तो जाति जनगणना होगी। उसके बाद आर्थिक सर्वे होगा। राहुल ने कहा कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की सम्मिलित आबादी करीब 90 फीसदी है, जिनकी देश की संपत्तियों में प्रॉपर हिस्सेदारी नहीं है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग और आजादी के बाद डॉ. भीमराव आंबेडकर ने आनुपातिक हिस्सेदारी की मांग उठाई थी, जिसे उस वक्त कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। राहुल के विचार में आंबेडकरवादी व साम्यवादी विमर्श का घालमेल है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। विरासत टैक्स की बात करें तो वर्ष 1953 में इस्टेट ड्यूटी की शुरूआत हुई थी, वर्ष 1985 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने खत्म कर दिया था। वर्ष 1998 उपहार टैक्स व वर्ष 2015 में वेल्थ टैक्स समाप्त किया जा चुका है। आर्थिक सिद्धांत के मुताबिक संपत्ति पुनर्वितरण और विरासत टैक्स जैसे आइडिया से आर्थिक असमानता दूर नहीं की जा सकती है, आर्थिक नीतियों के सुचारू संचालन से ही आर्थिक खाई पाटी जा सकती है। संपत्ति पुनर्वितरण व विरासत टैक्स के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस को आक्रामक तरीके से घेरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों मुद्दों पर कांग्रेस ने एक बार फिर से सेल्फ गोल कर लिया है। इन मुद्दों के राजनीतिक असर का विश्लेषण करता आजकल का यह अंक...

‘विरासत’ कर के बवंडर का सच

विश्लेषण
अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

संपत्तियों के सर्वे और वितरण संबंधी विवाद कांग्रेस की स्वयं की देन है। इसे लेकर उठे बवंडर के बीच विदेश में कांग्रेस पार्टी की इकाई ओवरसीज कांग्रेस ऑफ इंडिया के प्रमुख सैम पित्रोदा ने उत्तराधिकार कर का बयान देकर इसे लोकसभा चुनाव के एक बड़े मुद्दे के रूप में स्थापित कर दिया है। स्वाभाविक है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित समूची भाजपा कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि वह लोगों के घरों में घुसकर संपत्तियों का सर्वे करेगी तथा समान वितरण के नाम पर अपने चाहत के अनुरूप समुदाय विशेष के बीच बांट देगी उस समय यह बयान बवंडर को और बढ़ने वाला ही साबित होना था। सैम पित्रोदा के बयान को व्यक्तिगत कह कर खारिज करना आसान नहीं है।

कांग्रेस के रणनीतिकारों का जो भी मानना हो, लेकिन उसके विचार एवं व्यवहार इन दिनों लगातार आम व्यक्ति को हैरत में डालते हैं। अनेक गंभीर लोग बातचीत में प्रश्न करते हैं कि आखिर कांग्रेस को हो क्या गया है? संपत्तियों के सर्वे और वितरण संबंधी विवाद कांग्रेस की स्वयं की देन है। इसे लेकर उठे बवंडर के बीच विदेश में कांग्रेस पार्टी की इकाई ओवरसीज कांग्रेस ऑफ इंडिया के प्रमुख सैम पित्रोदा ने उत्तराधिकार कर का बयान देकर इसे लोकसभा चुनाव के एक बड़े मुद्दे के रूप में स्थापित कर दिया है। स्वाभाविक है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित समूची भाजपा कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि वह लोगों के घरों में घुसकर संपत्तियों का सर्वे करेगी तथा समान वितरण के नाम पर अपने चाहत के अनुरूप समुदाय विशेष के बीच बांट देगी उस समय यह बयान बवंडर को और बढ़ने वाला ही साबित होना था। सैम पित्रोदा के बयान को व्यक्तिगत कह कर खारिज करना आसान नहीं है। आखिर वह कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं और सोनिया गांधी परिवार के निकटतम लोगों में माने जाते हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समानांतर विदेशों में प्रोजेक्ट करने , जगह-जगह उनका भाषण और पत्रकार वार्ताएं करने की पूरी कमान उनके हाथों में होती है। वह कह रहे हैं कि जब हम सामान वितरण की बात करते हैं तो हमें अमेरिका जैसे इन्हेरिटेंस टैक्स यानी उत्तराधिकार कर पर भी विचार करना चाहिए। उनके अनुसार यहां कई राज्यों में पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति की विरासत संभालने वाले को 55 प्रतिशत तक कर देकर उसके हिस्से शेष 45 प्रतिशत आता है। इससे स्वाभाविक ही यह शंका गहरी हुई कि कांग्रेस सत्ता में आने पर वाकई विरासत कर भी लगा सकती है।

नहीं मिलता मुद्दा

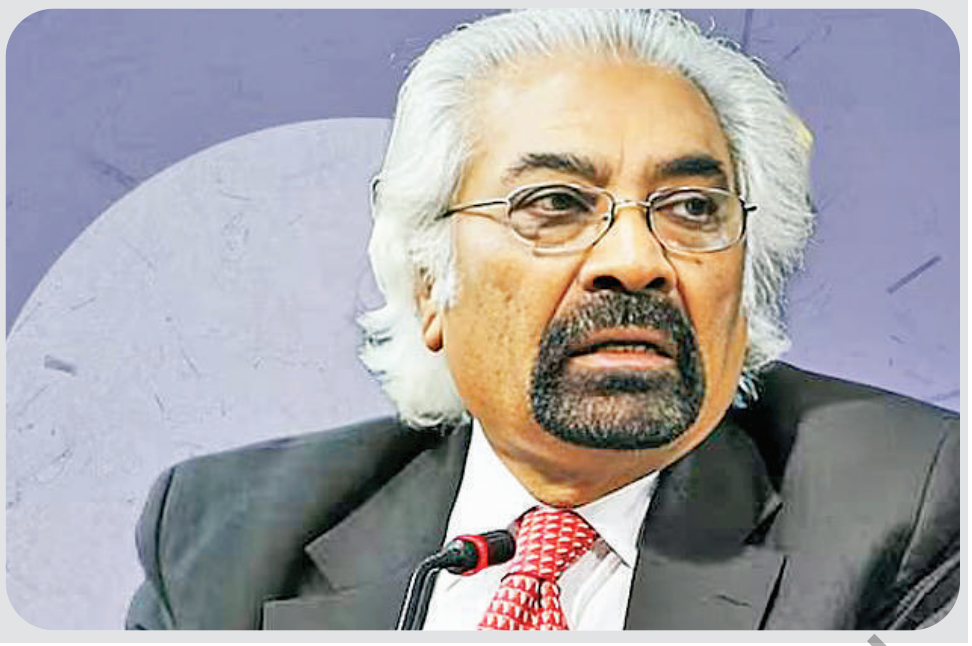

अगर राहुल गांधी ने अपने भाषणों और वक्तव्यों में लगातार जाति जनगणना के साथ वित्तीय एवं आर्थिक सर्वे की बात नहीं करते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा को इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने का अवसर नहीं मिलता। उनके भाषण और वक्तव्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिनमें वह कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने पर जाति जनगणना करेंगे और उसके बाद क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, संपत्ति के समान वितरण के लिए वित्तीय सर्वेक्षण करा कर देखेंगे कि किसके पास किस वर्ग के पास कितनी संपत्ति है। इसके बाद जितना जिसका हक होगा उतना उसको दिया जाएगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र यानी न्याय पत्र जारी होने के पूर्व और बाद में भी वह इस पर बोलते रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि आप से मिलना चाहता हूं ताकि मैं आपको अपना घोषणा पत्र समझा सकूं। खड़गे सहित कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई यह कहने को तैयार नहीं है कि हम वित्तीय और आर्थिक सर्वे नहीं करेंगे तथा समान वितरण की भी बात हमारे एजेंडे में नहीं है। इसकी बजाय कांग्रेस के नेता प्रवक्ता लगातार भारत में उद्योगपतियों, अरबपतियों को निशाना बनाते हुए इनमें से कुछ के हाथों धन सिमट जाने के वक्तव्य दे रहे हैं। अगर सर्वेक्षण होगा तो फिर सर्वेक्षणकर्मी लोगों के घर में जाएंगे। घर वाले चाहें न चाहें उनकी एक-एक चीज देखी जाएगी। इसके अलावा अगर सर्वेक्षण का कोई तरीका कांग्रेस के पास है तो उसे बताना चाहिए। मंगलसूत्र जैसे शब्द व्यंग्यात्मक शैली में होते हैं। इनका इतना ही अर्थ है कि महिलाओं के आभूषण तक भी सर्वे में जाने जाएंगे। संपत्ति के विवरण के वैधानिक प्रावधानों में आभूषणों आदि की पूरी सूची और उसके मूल्य बताने ही पड़ते हैं। चूंकि राहुल गांधी अपनी घोषणा पर कायम हैं और कांग्रेस इससे पीछे नहीं हट रही तो सैम पित्रोदा के उत्तराधिकार कर से देश में भय पैदा हो गया है। कुछ लोगों ने तो यह भी तलाश लिया कि पहले भी भारत ने विरासत कर था और स्वयं पित्रोदा कोई नई बात का नहीं कह रहे हैं। प्रकारांतर से यह स्वयं पित्रोदा के विचार का समर्थन करना ही है । निश्चित रूप से था और यह अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था जो व्यवहार में नहीं उतर पाया तथा सरकारी विभागों में इतने मुकदमे हुए, जिनके खर्च उससे प्राप्त से ज्यादा हो गया। हालांकि प्रधानमंत्री का आरोप है कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्रीत्व काल में उसे इसलिए हटाया गया, क्योंकि उन्हें बिना कर दिए अपनी मां की संपत्ति का उत्तराधिकार लेना था। सच है कि पारिवारिक संपत्ति में से संजय गांधी के परिवार को शायद ही कुछ प्राप्त हुआ हो। यह ऐसा मुद्दा रहा है जिसे आरंभिक दिनों में मेनका ने उठाया था।

बहरहाल, भले अर्थव्यवस्था, समाज और देश के बारे में समझ रखने वाले इसे उचित न मानें लेकिन कांग्रेस के अंदर भाव यही है कि राहुल गांधी की इन घोषणाओं का देश के आम लोगों पर बड़ा प्रभाव है और उन्हें लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के धनी और संपन्न लोगों की संपत्तियां लेकर हमारे बीच बांटा जाएगा। वह मानते हैं कि इससे उनका वोट काफी बढ़ेगा और सत्ता में भी आ सकते हैं।

न्याय और गारंटी तर्कसंगत नहीं

पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस की नीति और व्यवहार में पुरानी शैली के वामपंथियों की तरह संपत्तिवानों, उद्योगपतियों आदि के विरुद्ध घृणा और गुस्सा साफ परिलक्षित होता रहा है। उनको निशाना बनाया जाता है। पांच न्याय और 25 गारंटी में कांग्रेस ने ऐसी-ऐसी बातें की है जिनको धरातल पर उतारना भारतीय अर्थव्यवस्था के बूते की बात नहीं है, लेकिन इस समय कांग्रेस के थिंक टैंक या सोनिया गांधी परिवार को सुझाव देने वाले मानते हैं कि कांग्रेस को पुराने वामपंथियों की तरह क्रांतिकारी तेवर धारण करना चाहिए तभी वह अपना खोया हुआ जनाधार वापस ला सकती है तथा भाजपा को हरा सकती है। सैम पित्रोदा ने जो कहा है वह इसी सोच का विस्तार है। हमारी आपकी दृष्टि में अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, लेकिन क्रांति हुए बिना वहां वामपंथियों की ताकत हमेशा सशक्त रही है। वहां ये सत्ता, प्रशासन, न्यायपालिका , मीडिया से लेकर पूरे थिंक टैंक पर हावी हैं। वहां के बड़े-बड़े पूंजीपति जिनमें जार्ज सोरोस जैसे लोग शामिल है, भी अपने प्रकट लक्ष्यों और घोषणाओं में आधुनिक वामपंथी ही है। उनकी दृष्टि की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उनकी ही सोच की अर्थव्यवस्था, समाज के बीच संपत्ति का विभाजन, अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार आदि के लक्ष्य से भारत जैसे विकासशील देश में बदलाव के लिए अपने थिंक टैंक विकसित करते हैं और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उनका लक्ष्य ऐसे देश को सशक्त करना तो नहीं हो सकता।

विदेशों में उनके भाषण होते हैं, इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राहुल गांधी, कांग्रेस के दूसरे नेता या सैम पित्रोदा के साथ उनके संवाद नहीं होंगे। इस अतिवादी वाम सोच में ही अल्पसंख्यकों के लिए वैसे विशेष प्रावधानों की घोषणाएं हैं, जिन्हें देखकर भाजपा के लिए यह आरोप लगाना आसान हो गया है कि संपत्ति के सर्वे के पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस का इरादा अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों के बीच ही उसे वितरीत करना है। इस पर बहस हो सकती है तथा पहली दृष्टि में कहा जा सकता है कि भाजपा जानबूझकर कांग्रेस को मुस्लिमपरस्त साबित करने के लिए ऐसा कर रही है, किंतु कांग्रेस ने अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया है कि उसकी मंशा मुसलमानों को विशेष तौर पर धन के वितरण में या आरक्षण आदि में शामिल करना नहीं है। यूपीए सरकार के दौरान आप देखेंगे कि केंद्र से राज्यों की कांग्रेस सरकारों ने मुसलमानों के लिए अनेक प्रावधान किए, अनेक संपत्तियां अलग-अलग इस्लामी संस्थाओं को दी गई और उनके लिए सरकार के नियम कानून तक बदले गए। बाद में दूसरी सरकारों ने उनमें से कई संपत्तियां वापस ली और इनमें न्यायालय का भी साथ मिला।

अराजकता की आशंका

भारतीय सभ्यता संस्कृति की परंपरागत व्यवस्था में संपत्तियों के अधिक संग्रह का आदेश नहीं था। परिश्रम से अर्जित करने पर रोक नहीं था, लेकिन उसके स्वामित्व की सीमाएं रहीं हैं तथा अर्जित संपत्तियों को भी सहकारी जीवन की तरह मिल बांटकर खाने की व्यवस्था रही है। वर्तमान युग में अपनी क्षमता, प्रतिभा की बदौलत उत्तरोत्तर आर्थिक प्रगति पर किसी भी बंधन की स्वीकार्यता नहीं है। इससे समाज के विकसित होने की मानसिकता कमजोर होती है तथा यह पूरे देश की प्रगति को उल्टी दिशा में मोड़ना है। इसलिए संपत्ति पर कैप लगाना या उसके एक बड़े हिस्से का राष्ट्रीयकरण कर लोगों में बांटना या एक सीमा से ज्यादा संपत्ति पर जरूर से ज्यादा कर लगाकर उसकी आय को बांट देने की सोच का कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। इससे भयावह अराजकता की स्थिति पैदा होगी जिसे संभालना कठिन होगा। चूंकि कि चुनाव के बीच यह मुद्दा आ गया है इसलिए देश के लोगों को तय करना है कि वह इसके साथ है या विरोध में।

वर्तमान युग में अपनी क्षमता, प्रतिभा की बदौलत उत्तरोत्तर आर्थिक प्रगति पर किसी भी बंधन की स्वीकार्यता नहीं है। इससे समाज के विकसित होने की मानसिकता कमजोर होती है तथा यह पूरे देश की प्रगति को उल्टी दिशा में मोड़ना है। इसलिए संपत्ति पर कैप लगाना या उसके एक बड़े हिस्से का राष्ट्रीयकरण कर लोगों में बांटना या एक सीमा से ज्यादा संपत्ति पर जरूर से ज्यादा कर लगाकर उसकी आय को बांट देने की सोच का कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। इससे भयावह अराजकता की स्थिति पैदा होगी जिसे संभालना कठिन होगा। चूंकि कि चुनाव के बीच यह मुद्दा आ गया है इसलिए देश के लोगों को तय करना है कि वह इसके साथ है या विरोध में।

विपक्ष के मुद्दे सत्तापक्ष के आगे बेअसर

मुद्दा
प्रणय यादव
वरिष्ठ टीवी पत्रकार

मौसम गर्म हो गया है। पारा चालीस डिग्री के पार चला गया है, लेकिन दो चरण के मतदान के बाद भी चुनावी गर्मी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों और नेताओं के भाषणों में तो हीटवेब दिख रही है, लेकिन जनता में जो उत्साह होना चाहिए और चुनाव के वक्त जैसा होता है वो इस बार नहीं दिख रहा है। फर्स्ट फेज में कम वोटिंग के बाद चुनाव आयोग ने, नेताओं ने और सामाजिक संगठनों ने मतदाताओं को पोलिंग बूथ्स तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करने की कोशिशें की, लेकिन दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत और गिर गया। ये लोकतन्त्र के लिए अच्छा नहीं है। मतदाताओं का वोट डालने न जाना राजनातिक दलों के लिए भी परेशानी का सबब है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों इसे अपने-अपने लिए फायदेमंद बता रहे हैं। लेकिन परेशान दोनों पक्ष हैं। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद मुद्दे, भाषा और अंदाज एनडीए का भी बदला है और इंडिया अलायन्स का भी।

पहले चरण के बाद मुद्दे बदले

वोटिंग का दौर शुरू होने से पहले विकास बड़ा मुद्दा था। दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत, आतंकवाद, पाकिस्तान को सबक, आर्टिकिल 370 और राम मंदिर, ये बीजेपी के मुख्य मुद्दे थे। विपक्ष बेरोजगारी, मंहगाई, जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरूपयोग, विपक्ष की सत्ता वाले राज्यों के साथ भेदभाव, जातिगत जनगणना, भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी जैसे मुद्द उठा रहा था, लेकिन फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद अचानक बीजेपी ने गियर बदल दिया। अब सांप्रादियकता का मुद्दा, हिन्दू मुसलमान की बात सेंटर स्टेज में आ गई है। असल में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है। उसमें आर्थिक समानता के लिए संपत्ति के सर्वे की बात कही गई है। जातिगत जनगणना का वादा है और उसके बाद आरक्षण की सीमा पर लगी पचास परशेंट की पाबंदी को हटाने की बात है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ साफ तो नहीं लेकिन घुमाफिरा कर ये संकेत दिया गया है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का भी इस मामले में ख्याल रखेगी। बस बीजेपी ने इसी बात को पकड़ लिया। इसे समुदाय विशेष के आरक्षण से जोड़ दिया। बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफ कहा कि कांग्रेस देश के लोगों की संपत्ति छीनकर अपने चहेतों को देना चाहती है। कांग्रेस दलित पिछड़े और आदिवासियों के हक का आरक्षण को छीनेगी और मुसलमानों को दे देगी। इसके बाद ये बड़ा मुद्दा बन गया। कांग्रेस और उसके साथी दल रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। कांग्रेस के साथ असली दिक्कत ये है कि उसे मुस्लिम वोट भी चाहिए और हिन्दुओं के वोट के बगैर के उसका काम नहीं चलेगा, इसलिए कांग्रेस के नेता न ये कह सकते हैं कि वो मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे और न ये कह सकते हैं कि देंगे। इसी स्थिति का फायदा बीजेपी उठा रही है। पहले मोदी ने आन्ध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन का हवाला दिया और फिर कर्नाटक का केस जनता के सामने रख दिया। कांग्रेस इस बात से इंकार नहीं कर सकती कि कर्नाटक में सभी मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिल रहा है। हालांकि कर्नाटक में मुस्लिम जातियों को आरक्षण कांग्रेस के जमाने में नहीं

मिला। 1994 में ये फैसला हुआ था उस वक्त कर्नाटक में एचडी देवेगौड़ा की सरकार थी। देवेगौडा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। जो अब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लोगों को ये बात नहीं समझा पा रही। क्योंकि इस वक्त तो कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है। कांग्रेस का तर्क ये है कि मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मिल रहा है, लेकिन फिर सवाल ये है कि कुछ जातियों गरीबी और पिछड़ेपन का शिकार हो सकती है कि आरक्षण के दायरे में सारी जातियों को क्यों लाया गया। कांग्रेस का तर्क है कि तीस साल में 16 साल बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी ने कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण खत्म क्यों नहीं किया। हकीकत ये है कि बीजेपी ने बहुत ही चालाकी से 2023 के चुनाव से पहले मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके वोकालिंगा और लिंगायत समाज को दो दो फीसदी आरक्षण दिया था। मुस्लिम जातियों के लिए नई कैटेगरी बना दी, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और अब तक मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिल रहा है इसीलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर घिर गई है। अब कॉमन सिविल कोड, सीएए, एनआरसी भी चुनाव के बड़े मुद्दे बन गए हैं। बीजेपी के नेता उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू होने के हवाला देते हैं। देश भर में सीएए को सख्ती से लागू करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि सीएए का हमारे देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, ये कानून सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से भागकर आए हिन्दू सिख बौद्ध जैन और पारसियों के लिए है, लेकिन विपक्ष इसे मुसलमानों के खिलाफ बताकर इसका विरोध कर रहा है।

मुद्दों की काट

असल में बीजेपी ने बहुत ही कारगर रूप से विपक्ष के उन मुद्दों की काट खोजी है जिनसे बीजेपी को नुकसान की आशंका थी। कांग्रेस जातिगत जनगणना करवा कर भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी देने का दावा कर रही थी। मतलब दलित पिछड़े और आदिवासी वोट बैंक पर खतरा था। अखिलेश यादव भी यूपी में पीडीए को मुद्दा बना रहे थे। कांग्रेस ने आर्थिक सर्वे करवा कर संपत्ति के समान बंटवारे का वादा किया था। लेकिन बीजेपी ने इसे हिडेन एजेंडा बता दिया। कांग्रेस के आर्थिक सर्वे के वादे को मंगलसूत्र से जोड़ दिया। अब मनोमहन सिंह के बयान का वीडियो भी घुमाया जा रहा है जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों, अल्पसंख्यकों खासतौर पर मुसलमानों का है। मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो, राहुल गांधी के भाषण और मनमोहन सिंह के बयान को निकाल कर जो घुट्टी बनाई है। वो कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गई है।

कुल मिलाकर चुनाव वोटिंग के शुरूआती चरण में ही सांप्रदायिकता पर आ गया। जो चुनाव विश्लेषक हैं, शुरूआत में वो कह रहे थे कि इन मुद्दों के सेंटर स्टेज पर आने से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। पोलराइजेशन होगा और दोनों तरफ से मतदाता बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, लेकिन सेकेन्ड फेज की वोटिंग में इसका उल्टा हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, बंगाल और कैरल जहां पोलराइजेशन का असर सबसे ज्यादा दिखना चाहिए था वहां मतदान प्रतिशत गिरा। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम वोटर्स तो बड़ी संख्या में पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा लेकिन बीजेपी का वोटर घर से नहीं निकला। दूसरा अंदाजा ये है कि देश में जिस तरह का माहौल है और दस साल की सरकार के बाद जब वोटिंग कम होती है तो इसका फायदा सत्ताधारी दल को होता है। हकीकत में क्या होगा ये तो चार जून को पता लगेगा, लेकिन अब तक कैंपेन में जो दिखा उससे इतना तय हो गया है कि हमारे देश में विकास की बातें कितनी भी हों, योजनाएं कितनी भी अच्छी हों लेकिन चुनाव हिन्दू-मुसलमान के इश्यू के बगैर नहीं होता।

राहुल-पित्रोदा इंडी गठबंधन पर भारी पड़ेंगे

असर
मनोज कुमार अग्रवाल
वरिष्ठ पत्रकार

कांग्रेस की तरफ से उछाले गए संपत्ति पुनर्वितरण और विरासत टैक्स के विचार कांग्रेस के साथ-साथ इंडी गठबंधन को भी भारी पड़ सकते हैं। भाजपा ने जिस तरह से कांग्रेस को घेरा है, अगले पांच चरण के चुनाव में इसका असर अवश्य दिखाई देगा। कहते हैं कि इंसान में अनुभव से समझ विकसित हो जाती है, लेकिन कांग्रेस के नेता व कथित नेहरू गांधी परिवार के चश्मे चिराग राहुल गांधी पर यह बात लागू नहीं होती है। हालांकि इस बार उन्होंने होमवर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जुबान से निकल रहे बयान कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर ही भारी पड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के एक सलाहकार और मास्टर माइंड सैम पित्रोदा ने ऐसे समय में माता पिता से मिलने वाली संपत्ति पर विरासत टैक्स लगाने की बात कहकर सारे खेल को ही बिगाड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसको हाथों हाथ लिया है और प्रहार किया है है कि ‘कांग्रेस का मंत्र लूट है, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। राहुल और उनके सलाहकार देश के मध्यम वर्ग पर और अधिक टैक्स लगाने की योजना बना रहे हैं। माता-पिता से मिलने वाली सम्पत्ति पर भी विरासत टैक्स लेने की कांग्रेस की योजना है। कांग्रेस का पंजा आपके बच्चों का अधिकार छीनने के लिए व्याकुल है’।

चुनावी माहौल देखकर ऐसा लगता है मानो विपक्षी दलों का कुनबा इंडी गठबंधन सत्ताधारी दल से मुकाबला करने में जूझ रहा है। मतदाताओं को लुभाने के लिए वे किसी तरह की कमी नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस ने तो गरीब महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए 1-1 लाख रुपये देने की घोषणा भी कर डाली है। आरक्षण की सीमा तोड़कर 50 प्रतिशत से आगे ले जाने, जाति आधारित जनगणना जैसे वादे भी कांग्रेस कर रही है। दूसरी ओर, भाजपा ने हर बात को इस तरह पेश किया है कि कांग्रेस जो भी कह या कर रही है, वह देश के लिए अत्यंत खतरनाक है।

बार-बार ऐसी गलतियां

वामपंथी सोच वाले सलाहकारों से घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी अति-उत्साह में कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं, जिनसे भाजपा को बड़ा मुद्दा मिल जाता है। एकाध बार हो जाए तो वह चूक या गलती मानी जा सकती है, किन्तु राहुल से बार-बार ऐसी गलतियां होती हैं, जिनका लाभ भाजपा उठाती है। अब चुनावी सभा में राहुल ने कह दिया कि सत्ता में आने पर अमीरों का धन लेकर गरीबों में बांट देंगे। 7 अप्रैल को हैदराबाद में राहुल ने कहा, 'हम पहले यह निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करेंगे कि कितने लोग अन्य ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। उसके बाद, धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत हम एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएंगे।' अब भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी

की नजर आम आदमी की कमाई पर है, वह उसे छीनना चाहती है।

विपक्ष पर हमला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'ताला नगरी' अलीगढ़ में चुनावी जनसभा में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन (इंडिया) पर बेहद गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा, ‘मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई और संपत्ति पर है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी)का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी संपत्ति है, उसकी करेंगे। इतना ही नहीं, वह कहते हैं कि यह जो संपत्ति है उसको अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी। यह उनका चुनाव घोषणा पत्र है। वह सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा कर्मचारी हैं, उनकी कितनी संपत्ति है। यह सर्वे कराकर कांग्रेस सरकार के नाम पर संपत्ति को छीन कर बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक कह रही है कि अगर आपके पास दो घर हैं तो एक घर छीन लेगी। यह कम्युनिस्टों की सोच है, ऐसा ही करके कितने ही बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन में लागू करना चाहते हैं।’ भाजपा ने यह भी कहना शुरू कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह कहते थे देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, अब कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनको बांटने की तैयारी कर रही है।

सवाल यह भी है

कल्पना कीजिए कि यदि महिला वर्ग में यह धारणा घर कर गई कि कांग्रेस की नजर वास्तव में उनके गहनों पर है, तो क्या कोई महिला कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देगी? केवल महिलाएं ही क्यों, यदि उच्च मध्यम वर्ग एवं अभिजात्य वर्ग में भी यह विचार आ गया तो वे भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। यह तो असल में अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। बची कसर उनके तकनीकी गुरु सैम पित्रोदा ने कर दी है, जो इन दिनों अमेरिका में हैं। उनके बयान भी पैतृक सम्पत्ति पर कर लगाने की बात कर रहे हैं। पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस की फजीहत और बढ़ा दी है। एक और कांग्रेस अपने नेता के बयान पर सफाई देने में जुटी थी इस बीच पित्रोदा भी फूट पड़े और सारा रायता दोबारा बिखर गया है।

शब्दों का चयन

राहुल को अपने शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करने की जरूरत है। उन्होंने धन के बंटवारे का जो शिगूफा छोड़ा है, वह न व्यावहारिक है और न ही उचित। यदि परिश्रम कर कमाने वालों का धन छीनकर निठल्लों को देने लगे तो देश में क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना मात्र डराने वाली है। ऐसी अराजकता पैदा करने वाली योजनाओं के बारे में सार्वजनिक दावे कोई भी राजनीतिक तौर पर परिपक्व नेता तो नहीं करेगा। रूस, वेनेजुएला की हालत लोग देख चुके हैं। अब भाजपा इसे मुद्दा बनाएगी और कांग्रेस सफाई देती रह जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के मंजे खिलाड़ी हैं, उनका मुकाबला कर पाना राहुल जैसे नौसिखिए और समय की नजाकत से बेख़बर उनके कांवेंट शिक्षित सलाहकारों के वश की बात नही है। ऐसे कमजोर रणनीतिक माहौल में उन क्षेत्रीय दलों का भी नुकसान हो सकता है, जो अपने बूते पर मतदाता के बीच वजूद रखते हैं, लेकिन अपने गठबंधन के नेता के ऐसे बयान उनके वोटर्स को भी भ्रमित कर सकते हैं ऐसे गठबंधन को कौन वोट देगा, जिसके नेता माता पिता की सौंपी विरासत पर टैक्स लगाने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस की सोच सही समय पर सामने आ गई है अब इंडी और कांग्रेस दोनों की लुटिया डूबनी तय है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid